Thursday, July 28, 1977
Sravana 6, 1899 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Sixth Series)

Vol. V

[*July 16 to 28, 1977/Asadha 25 to Sravana 6, 1899 (Saka)*]

Second Session 1977/1899 (Saka)

(*Vol. V contains Nos. 31—40*)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 40, Thursday, July 28, 1977/Sravana 6, 1899 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions :	
*Starred Questions Nos. 665 to 668	1—26
Short Notice Question No. 26	26—37
Written Answers to Questions:	
Starred Questions Nos. 669 to 672 and 674 to 684	37—48
Unstarred Questions Nos. 5144 to 5178, 5180 to 5213, 5215 to 5240 and 5242 to 5303	48—201
Papers Laid on the Table	201
Re. Calling Attention Notice.	201
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Strike in Kiriburu Iron Ore Mines	202—205
Shri C. K. Chandrappan	202,204-205
Shri Biju Patnaik	202—204, 205
Matters Under Rule 377—	
(i) Dismissal of the Ministry in Tripura	206
(ii) Reported Conflicting Statements by Ministers about Use and Repeal of MISA	207-208
(iii) Famine Conditions in North Bihar due to failure of rains	209-210
Statement *Re.* Availability of Cement—	
Shri George Fernandes	208-209
Business Advisory Committee—	
Fourth Report	210—212
Lokpal Bill—	
Motion to Introduce	212—215

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Shri Charan Singh . . . . . 212—214

Shri Annasaheb Gotkhinde . . . . . 212—214

Motions *Re.* Unemployment Problem—*Withdrawn*—

Shri Morarji Desai . . . . . 215—24

Shri Jyotirmoy Bosu . . . . . 224—27

Shri C. K. Chandrappan . . . . . 227—30

Motion *Re.* Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. . . . . 230—98

Prof. Madhu Dandavate . . . . . 230—31

Shri Hitendra Desai . . . . . 232—44

Shri Suraj Bhan . . . . . 250—63

Shri Kanwar Lal Gupta . . . . . 263—72

Shri A. Murugesan . . . . . 273—77

Shri Keshavrao Dhondge . . . . . 277—85

Shri Yuvraj . . . . . 285—92

Shri Mangal Deo . . . . . 292—98

Half-an-Hour Discussion—

Working of Vijaya Bank. . . . . 298—310

Shri K. Lakkappa . . . . . 299—304

Shri K. P. Unnikrishnan . . . . . 304—305

Shri Kondaji Basappa . . . . . 305—306

Shri A. R. Badri Narayan . . . . . 306—307

Shri A. K. Kotrashetti 307

Shri H. M. Patel . . . . . 307—10

Message from Rajya Sabha . . . . . 310—12

Finance (No. 2) Bill, 1977—As returned by Rajya Sabha . . 312

LOK SABHA

Thursday July 28, 1977/Sravana 6, 1899 (Saka)

Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Propagation of Family Planning

*665. DR. BAPU KALDATY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have engaged Family Welfare Social Workers for propagation of family planning;

(b) if so, their number all over the country; and

(c) what remuneration is offered to them?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) 30 जून, 1976 को काम कर कर रहे विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की संख्या के बारे में राज्यों और संघशासित क्षेत्र-प्रशासनों से जो सूचना मिली है, उसके अनुसार ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में 4,416 विस्तार शिक्षक और 12,868 परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक थे। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों में 497 विस्तार-शिक्षक और 860 परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे। प्रसवोत्तर

केन्द्रों में 189 स्वास्थ्य शिक्षक/विस्तार शिक्षक / सामाजिक कार्यकर्ता और 192 परिवार कल्याण कार्यकर्ता थे और जिला परिवार कल्याण ब्यूरो में 503 जिला विस्तार शिक्षक थे।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित प्लान योजना है और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित पैटर्न के अनुसार जितना व्यय किया जाता है, वह सारा भारत सरकार द्वारा प्रतिपूरित कर दिया जाता है। किन्तु, परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यन्वयन के लिए नियुक्त कर्मचारी सम्बंधित राज्य सरकारों / संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन सेवा करते हैं और उन पर राज्य सरकार की ही सेवा शर्तें लागू होती हैं। वे कर्मचारी उन्हीं वेतनमानों और भत्तों के पात्र हैं जो राज्य सरकार के अधीन उसी वर्ग के कर्मचारियों को देय होते हैं। प्रत्येक राज्य के कर्मचारियों का वेतन भिन्न भिन्न होता है और उसके ब्योरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। इस सूचना को एकत्र करने में भी काफी समय लग जाएगा।

डा० बापू कालदाते : अध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार की नीति परिवार नियोजन में सख्ती करने की नहीं है। इसका मतलब यह है कि कम्पलसरी स्टैरिलाइजेशन की नहीं है, जिसका मतलब यह होता है कि हम लोगों को शिक्षा के ऊपर और इन्सेन्टिव्ज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बल देने की जरूरत होती है। और परिवार नियोजन भी अति आवश्यक है इस बात को हम लोग मानते

हैं। अगर यह दोनों बातें ख्याल में रखी जायें तो फिर सवाल यह होता है। कि आज भी आंकड़े मंत्री महोदय ने दिये हैं, उससे लगता है कि करीबन साढ़े 19 हजार लोग इस काम में लगे हुए हैं। अतः सरकार की इस नई नीति को शिक्षा और प्रेरणा की नई नीति को, ध्यान में रखते हुए इस पर कोई एक अलग ढंग से विचार किया जाय और इनमें जो भी सोशल वर्कर हैं उनको सेन्टर की तरफ से गाइडलाइन्स या कोई एक अलग संगठन या इसकी अलग दिशा दी जाय इस बारे में सरकार ने क्या कुछ सोचा है?

श्री राज नारायण : श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना आप से पहले ही कर दूं कि हमारे सम्मानित सदस्य ने बहुत ही सुन्दर प्रश्न किया है। मगर अब इस का जवाब लम्बा होगा तो सम्मानित सदस्य उस पर एतराज नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने नई योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात की है। तो नई योजना अब कैसे चलेगी इसको मैं थोड़े में बताये देता हूं। यह सही है कि वर्तमान सरकार जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक स्तर पर इस बात को जोर के साथ कह दिया है कि किसी भी तरह की कम्पलसरी, जबरदस्ती जोर के साथ स्टरिलाइजेशन की योजना नहीं चलेगी।

जोर जबरदस्ती नहीं होगी। स्वेच्छा से अगर कोई चाहे तो भी, हमने उसमें कहा हैं कि उसको बाकायदा लिख कर देना पड़ेगा कि हम स्वेच्छा से अपनी नसबन्दी कराना चाहते हैं। उसके दस्तखतों को बाकायदा वैरीफाई करना पड़ेगा कि कहीं नकली तो नहीं है। हर स्तर पर हमारी सरकार यह प्रीकौशन लेगी कि कहीं भी किसी प्रकार से जोरजबरदस्ती न हो। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, हम सजग हैं। जब जबर्दस्ती हम नहीं करेंगे और परिवार सीमित करना है तो, हम पहले भी इस सदन में बता चुके हैं कि हमको बड़ा प्रचार करना पड़ेगा। उसमें सरकार की सारी मशीनरी, चाहे शिक्षा विभाग की हो, कृषि विभाग, पी० डब्ल्यू० डी० या अन्य किसी विभाग की हो. सभी के कर्मचारियों से हम यह उम्मीद करेंगे कि वह इस कार्य में लगें। 2 अक्तूबर गांधी जी के जन्म-दिवस से हमारी यह नई योजना शुरू होगी। पहले से जो 28 जिले हैं, उसमें हर ब्लाक पर यह योजना होगी, बाकी हर जिले में एक ब्लाक हम लेंगे इस साल। देश में 5,372 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और इनके अन्तगत 37,775 उपकेन्द्र हैं। प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से ही अधिकांश परिवार कल्याण केन्द्र जुड़ रहे हैं, जिनके बारे मे पहले ही मैं कह चुका हूं। हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर में 2 या 3 डाक्टर और इनके नीचे 40,42 अन्य पैरामैडिकल कर्मचारी हैं। इनके कुछ नाम निम्न हैं। मलेरिया वर्कर्स, चेचक वैक्सीनेटर, स्वास्थ्य सहायक, आर्डिनरी नर्सेज, मिडवाइफ इत्यादि इत्यादि। एक योजना दो साल से चल रही है, उसके अनुसार इन कर्मचारियों के बहुद्देशीय .. (अन्तर्बाधाएं) .. मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे सम्मानित सदस्य जानकारी चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया है। (अन्तर्बाधाएं)

एक माननीय सदस्य : सभापटल पर रख दीजिए।

श्री राज नारायण : अगर हमारे सम्मानित सदस्य चाहें कि मैं पटल पर रख दूं, तो मुझे तो उसमें आसानी है। परन्तु जैसे कांग्रेस की सरकार ने 30 साल तक उत्तरों में लोगों को गुमराह रखा, देश की जनता को अन्धकार में रखा, मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हू कि पूरा उत्तर दूं। (अन्तर्बाधाएं) ध्यान से सुनिये, मैं निवेदन कर रहा हूं कि घबड़ाइये नहीं, धीरज रखिये।

एक योजना जो दो साल से चल रही है, उसके अनुसार इन कर्मचारियों को बहुद्देशीय बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग 28 जिलों में दी जा चुकी है और 64 अन्य जिलों में चलाई जा रही है। हमें यह नई योजना गांधी जन्म-दिवस से प्रारम्भ करनी है।

MR. SPEAKER: You have given the full detail.

श्री राज नारायण : 777 प्राइमरी हैल्थ सेंटर, जिसमें 31,000 जनस्वास्थ्य रक्षक होंगे। इसमें पीपल्स इन्वाल्वमैंट होगा। उनका चुनाव जनता करेगी। जन-स्वास्थ्य रक्षक की कल्पना इसके पूर्व सरकार के दिमाग में नहीं थी, यह नई योजना जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की है।

MR. SPEAKER: You have given the full answer now.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: May I submit to you that whenever his question is there, a separate question hour may be allotted to him; it should not be clubbed with the other questions. He takes one or two hours; a separate hour may be allotted.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: You are always telling us to be brief. You have to pull him up if he does like this.

MR. SPEAKER: I have told him also to be brief.

डा० बापू कालदाते : मैं यह जानना चाहता हू कि पिछली सरकार ने इस योजना पर 30 जून, 1976 तक कितना खर्च किया ?

श्री राज नारायण : माननीय सदस्य ने पहले प्रश्न में यह पूछा था कि जो नई योजना चल रही है, उस में सरकार क्या करने जा रही है। अगर मैं प्रश्न का उत्तर न दूं, तो मैं पापी हूं। मैं इस सदन में पापी नहीं बनना चाहता हूं। हमारे श्रुति शास्त्र में कहा गया है कि पहले तो विधान-निर्मात्री परिषद् में जाओ नहीं, और यदि जाओ, तो बराबर सत्य का पक्ष ग्रहण करो, वर्ना तुम्हें इस संसद् में बैठने का हक़ नहीं है। इस लिए मैं सत्यवादी हूं और जो जानकारी मेरे पास है, उसे देने के लिए तैयार रहता हूं। (**व्यवधान**) मैं माननीय सदस्य को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सवाल को समझा। इसी लिए उन्होंने उत्सुकता जाहिर की कि "बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले", आगे जनता पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। इस लिए मैंने यह जानकारी दी।

MR. SPEAKER: Please answer the second question. How much money are you spending?

श्री राज नारायण : पूरे खर्चे का टोटल करने के लिए नोटिस की जरूरत है।

SHRI A. BALA PAJANOR: Sir, on a point of submission.

MR. SPEAKER: This is question Hour and no point of order is allowed according to rules. If once you establish a precedent then this will be referred to and other points will be raised.

SHRI A. BALA PAJANOR: The hon. Minister gives a lecture. In the Janata Government, ministers should set an example so that others could follow ....*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: He has given the full answer. No more supplementaries. Next question—No. 666.

AN HON. MEMBER: On a point of order.

MR. SPEAKER: I am now on my legs. No point of order is allowed under the rules during question hour. The full answer has been given to this question and so, I am not allowing any further question.

श्री राज नारायण : श्रीमन्, अब मुझे क्या करना है यह बताया जाय । मैं कोई पार्लियामेंट का नया सदस्य नहीं हूं । आप कृपा करके हमें गाइड करें कि अब मुझे क्या करना हैं ? या तो आप एक व्यवस्था इस सदन में कर दीजिए कि मंत्री लोग पूरी तैयारी के साथ न आएं और सदस्यों को गुमराह कर के चले जाया करें ।

मैं एक जानकारी आप के द्वारा दे देना चाहता हूं पहले सवाल के बारे में जो उन्होंने पूछा था—

MR. SPEAKER : I have called Q. No. 666.

Stocks of mis-labelled and mis-branded injections

*666. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Food and Drug Administration, Bombay had seized large stocks of mis-labelled and mis-branded injections manufactured and distributed by a Nagpur firm;

(b) if so, the names of medicines and injections seized; and

(c) whether Government have got any plan for surprise checks of firms manufacturing medicines to prevent adulteration?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स सोसाइटी जनरल और मेडिकल स्टोर, बाइकुल्ला, बम्बई को मेसर्स विम्सन्स इंस्टीट्यूट मेडिका, नागपुर द्वारा बनाए गए एमिनो फ्लाइन इंजेक्शन आई० पी० (बैच नं० 144) के 50 एम्पूलों का बक्सा मिला जिस बक्से पर निम्नलिखित लेबल लगा था "एमिनोफिलीन इंजेक्शन आई० पी० बैच नं० 144, प्रत्येक 10 मिली लि० वाले 50 एम्पूल" । जब बक्सा खोला गया तो उन्होंने देखा कि उसके अन्दर जो एम्पूल थे उन पर निम्नलिखित लेबल लगे हुए थे "कैल्सियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन आई० पी० प्रति 10 प्रतिशत 10 मि० लि०, बैच नं० 146" । बाद में किए गए विश्लेषण से पता चला कि इन एम्पूलों में एमिनोफिलिन था, यानी उस में थोड़े में लिखा था कैल्सियम ग्यूकोनेट मगर जब खोल कर देखा गया तो उसमें था "एमिनोफिलिन" ।

(ग) खाद्य और औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र के अधिकारियों ने इन दवाइयों को आगे बांटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और नागपुर फर्म की निर्माणशाला के भी कई निरीक्षण किए हैं । औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत औषधि निरीक्षकों की दवाइयां बनाने वाली फर्मों के अचानक निरीक्षण करने होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औषधियां ठीक स्थिति में बनाई जाएं और उन्हें बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक नियंत्रण बरते जाएं और कच्चे माल और तैयार माल का परीक्षण किया जाए ।

SHRI VAYALAR RAVI: I hope you will agree with me that it is a very serious matter. Unfortunately I could follow only half of the reply. But I do not want to insist on the language question now. I would like to quote only one sentence from a press report.

> "FDA sources said that the mis-branded injection if administered, would have caused instantaneous death of the patients."

This is very serious. The medicines have been mislabelled and sent to the different parts of the country. We are more concerned about the steps the Government will be taking. This is not the first occasion that this House has had to see this kind of thing. Even in the last Parliament, a matter concerning a Kanpur firm was raised. The Government said "we will make enquiries." But they escaped..

MR. SPEAKER: The longer the question the longer will be the answer. (*Interruptions*)

SHRI VAYALAR RAVI: I am putting the question. Every one of us is concerned with this. Mr. Sanjeevi Rao, a Member of Parliament took his wife to a hospital and she died on the spot after injection within five minutes. It is a very serious matter. The reply of the minister to part (c) is evasive and not concrete. I want to know whether the government will amend the Drugs Act to the extent that the inspectors and other officers can carry out surprise checks and inspections of big firms including muti-nationals, seize the medicines and take penal action against the concerned people, including the manufacturers, Chairman and Managing Director of the company?

श्री राज नारायण : श्रीमन्, अब मैं आपसे पहले विनम्र निवेदन कर दूं कि इस प्रश्न के पूछने में कितना समय लगा ? हम तो नहीं बोलते कुछ लेकिन मैं चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य अधिक से अधिक जानकारी हम से लें। हम मंत्री हैं, सरकार का पैसा खर्च होता है, हम सरकार के नौकर हैं इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि हम जानकारी दें। (*व्यवधान*) एमिनोफिलीन किस काम में आती है ? सांस की नली जो सिकुड़ जाती है उसको चौड़ी करने के काम में आती है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। यह तो काम हैं एमिनोफिलीन का। कैलशियम ग्लूकोनेट कैलशियम की कमी दूर करने के काम में आती हैं।

SHRI R. V. SWAMINATHAN: That was not his question. He asked whether you are going to take action against these people and whether you are going to amend the Act.

श्री राज नारायण : सवाल यह था कि दवाई के परिवर्तन से मृत्यु हुई इसलिए यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि दवाई के क्या गुण है। क्या इन दोनों दवाइयों के ऐसे गुण हैं कि उनमें मृत्यु हो सकती है ? इसलिए मैं बताता हूं कि एमिनोफिलीन के क्या गुण हैं और कैलशियम ग्लूकोनेट के क्या गुण हैं। इसमें मृत्यु का प्रश्न नहीं आता।

हां, हमारे मित्र ने एक बात कानपुर के ग्लूकोज़ के बारे में कही और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। कानपुर में जिस बुरे ढंग से ग्लूकोज़ की सुई लगाई गई और बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई उसकी अच्छी जांच-पड़ताल, मुझे पता नहीं, क्यों नहीं की गई। मेरी अपनी जानकारी यह है कि उसके जो कर्ता-धर्ता बानी-मुबानी थे वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी थे। वे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मशहूर नेता थे। उनके बीच में आ जाने से उसकी जांच-पड़ताल दबा दी गई और कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि ऐक्ट को अमेण्ड करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं तो ऐक्ट को अमेण्ड करने के लिए मस्विदा तैयार कर लिया है। अभी तो मौजूदा कानून में जहां कहीं इस तरह की बंगलिंग देखी जाए उसमें एक से लेकर दस साल की सज़ा की गुंजायश है मगर हम एक अमेंडमेंट प्रसारित करने जा रहे हैं कि अगर दवा की गड़बड़ी से इन्सान की मृत्यु हो तो जान के बदले जान--यह बात होनी चाहिए। आप तो श्रीमन्, जज रह चुके हैं, आप जानते हैं 302 दफ़ा उसी पर चलती है जिसके ऊपर साबित हो चुका हो कि उसने दूसरे की जान ली है। अगर दवा की खराबी से किसी की जान जाती है तो जिसने दवा की गड़बड़ी पैदा की उसकी भी जान जानी चाहिए। तो इस तरह का अमेंण्डमेंट हम प्रपोज़ कर रहे हैं कि दवा की खराबी से किसी की मृत्यु हो तो उसके दोषी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए।

SHRI VAYALAR RAVI: I can assure the hon. Minister who is sitting on that side because he made a reference to the Congress. You punish anybody who is corrupt. We support you. My question is that the Drug Act provided Inspectors to inspect the firms and may I know from the hon. Minister whether he is aware of this. These inspectors who are expected to inspect and make surprise checks are lacking in their duty and because they are subjected to some kind of corrupt practice, will you amend the Act in Such a way that even the Managing Director of a firm will be punished and also the inspectors who are not discharging their duties properly will be punished?

श्री राज नारायण : मैं सम्मानित सदस्य के इस सुझाव से अर्ध-सहमत हूं। यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के जो इंस्पैक्टर फर्मों में जा कर जांच करते हैं—दवाइयां बनाने की, उन का कर्त्तव्य है कि वे यह भी देखें कि वहां जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, दवाइयों के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, वे समुचित रूप से ठीक है या नहीं। अगर वे इस को नहीं देखते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो वे सजा के भागी हैं। उन के ऊपर उचित और सख्त-से-सख्त कार्यवाही की जायगी। इस बारे में कोई भी सन्देह सम्मानित सदस्य के दिमाग में नहीं उठना चाहिए।

SHRI K. MALLANNA: I want to speak in my own language.

MR. SPEAKER : We will appoint translators for various languages.

SHRI VAYALAR RAVI: We are grateful for your announcement to appoint translators for as many languages as possible.

(Interruptions)

SHRI A. BALA PAJANOR: I want to congratulate you for arranging to appoint translators. Even after 30 years of Independence we are not able to solve this problem. For the past half-an-hour, I am trying to understand what is going on here.....

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: May I suggest a compromise solution? As a symbolic gesture, the Speaker may possibly interpret this question.

SHRI A. BALA PAJANOR: Sir, for the past half-an-hour I am trying to understand what is going on here and for the Question Hour we are spending lakhs and lakhs of rupees.

(Interruptions)

श्रीमती अहिल्या पो० रांगनेकर : अध्यक्ष महोदय, यहां मराठी का इन्तजाम भी नहीं है, इस लिए मराठी में भी इन्तजाम होना चाहिए। श्री यशवंतराव चव्हाण यहां इतने साल रहे, फिर भी मराठी का इन्तजाम नहीं है।

श्री उग्रसेन : अध्यक्ष महोदय, अपनी भाषा में बोलने की हर एक को इजाजत होनी चाहिए, इन को अपनी भाषा में प्रश्न पूछने दीजिए।

MR. SPEAKER: Let me explain the position. We are trying to appoint as many translators as possible; but the difficulty is that we don't get good translators. We have written to the government departments; we have written to the State governments to recommend suitable names for translators.

AN HON. MEMBER: The State government has nothing to do with all these things. *(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Don't record anything, excepting what I say. *(Interruptions)** Please sit down. Why don't you hear me? *(Interruptions)* I have explained to you. We have written to every State government. We are also trying to get people from other sources. We are trying to test them. We are trying to get as many good translators in all the regional languages as possible. But one thing I will not do. I will neither request the Leader of the Opposition to translate, nor will the Speaker translate.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: For Heaven's sake, please save us from this English translator. We don't hear and he does not know English. Please appoint somebody who knows it.

SHRI A. BALA PAJANOR: The translator is all right. I don't agree with Mr. Nair. The translator is not bad.

*Not recorded.

श्री उग्रसेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप के बारे में ही कह रहा हूं। आप ने अभी कहा है कि जो कुछ पहले हो गया है, वह रिकार्ड नहीं होगा, मैं जानना चाहता हूं कि आप ने जो कहा है उसके बाद का रिकार्ड नहीं होगा या पहले का भी काट दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

SHRI K. MALLANNA: Is it a fact that the manufacturers are allowed to manufacture adulterated drugs, and that government allowed these manufacturers to sell at a lower prices? What is the reaction of the government when prices are lower or when they decrease? What steps have been taken?

श्री राज नारायण : जहां तक भारत सरकार की जानकारी है, न तो उन के बनाने में एडल्टरेशन करने की अनुमति दी जाती है और न कम कीमत पर बेचने की इजाजत दी जाती है।

SHRI VAYALAR RAVI: But they are doing it.

SHRI RAJ NARAIN: We are going to take action against them.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि पिछली बार मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर में बहुत बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाने वाले कारखाने पर छापा डाल कर, दवाइयां पकड़ी गई थीं और उसकी सी० बी० आई द्वारा जांच की गई थी। अब तक उस के क्या रिजल्ट्स सामने आए हैं। मंत्री महोदय बहुत होशियार हैं और साफ बात कहना चाहते हैं, इसलिए मैं इस का जवाब 25 मिनट में चाहता हूं।

श्री राज नारायण : श्रीमन् माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नागपुर की फर्म है या कानपुर की फर्म है या इसी तरह की जितनी दवाई निर्माता कम्पनियां हैं, क्या उन को छः महीने पहले लाइसेन्स दिया गया था और पिछली सरकार ने लाइसेन्स दिया था ? अगर दिया था तो उस समय के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध आप की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज नारायण : यह सही है कि यह लाईसेंस पहले की सरकार के द्वारा दिये गये थे। मैं सम्मानित सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र जी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कल 29 जुलाई से सारे देश—चाहे संघ शासित क्षेत्र हों, चाहे राज्य हों—के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। कल 11 बजे से स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन होगा जिसमें विचार किया जाएगा कि ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और आगे क्या कार्यवाही हो सकती है। इसमें ऐसे उपायों पर भी विचार किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। स्वास्थ्य चूंकि राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए हम उनसे निवेदन करते रहते हैं और जब जब अवसर आता है हम राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन और सचिवों का सम्मेलन बुलाया करते हैं। पिछले चार महीनों में इस तरह की दो बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक में हमने डा० कर्णसिंह जी को और डा० सुशीला नायर को भी आमन्त्रित किया है। लेकिन डा० कर्ण सिंह जी ने हमें सूचित किया है कि वे कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए

वे इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। इस तरह हम उनके गुणकारी और लाभकारी सुझावों से वंचित रह जाएंगे।

डा० बलदेव प्रकाश : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में है कि यह जो एडल्ट्रेशन हो रही है वह एडल्ट्रेशन बिना इंस्पैक्टर्स की कनाइवेंस के नहीं हो सकती है। यह जो आप नया एक्ट बना रहे हैं जिसमें एडल्टरेटर्स के लिए आजीवन कारावास का प्रोविजन होगा, क्या आप उसमें एडल्टरेटर्स के साथ सुपरवाईजर्स और इंस्पैक्टर्स को भी शामिल करेंगे जिनकी लापरवाही के कारण ऐसी ड्रग्स बनायी जा रही हैं? उनकी लापरवाही के बगैर तो यह हो ही नहीं सकता है।

श्री राज नारायण : सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम नये विधेयक पर विचार कर रहे हैं, उसका मसविदा अभी विचाराधीन है। अभी तो पुराना एक्ट ही लागू है। हमारा प्रस्ताव है कि ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिले। बिल द्वारा इस सदन के सामने आयेगा उस समय डा० बलदेव प्रकाश अपना संशोधन रख सकते हैं। अगर उस संशोधन को सदन मान लेगा कि उसमें सुपरवाइजर और इंस्पैक्टर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो सदन की राय सर्वोपरि होगी और हमें उसके मानने में कोई ऐतराज नहीं होगा। मगर मात्रा भेद और गुणभेद, अर्थात् क्वान्टिटेटिव चेज और क्वालिटिटेटिव चेंज में बराबर हम को विवेक के साथ विचार करके कानून की व्यवस्था करनी होगी।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि आयुर्वेद की अनेक शास्त्रीय औषधियों को अनेक प्रकार के नये नाम देकर के उनका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से खरीदारों का शोषण होता है और दवाओं का विकेंद्रीकरण किया जाता है? क्या सरकार इसके बारे में कोई ध्यान देगी?

श्री राज नारायण : पंडित यज्ञदत्त शर्मा जी हमारे परम मित्र हैं। पंडित जी के सवाल का जवाब मैं क्यों न दूं यद्यपि इस प्रश्न से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। (**व्यवधान**) अब अगर खींच कर इसका सम्बन्ध जुड़ जाता है तो बात अलग है। हमने पहले ही सम्मानित सदस्यों को अवगत करा दिया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाने के लिए हम रानीखत में एक कारखाना खोल रहे हैं और वहां हिमालय की पहाड़ियों पर जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी खोज करके, उनको सुधार करके समुचित रूप से अच्छी दवाओं का निर्माण किया जाएगा। जितने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में दवाओं का निर्माण होगा उतना ही ज्यादा उनका गुणकारी, लाभकारी प्रभाव होगा। जहां तक मिलावट का प्रश्न है उसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील है।

India Population Project

*667. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government launched India Population Project;

(b) if so, with whose assistance?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: May I know the details of the project?

श्री राज नारायण : मैं फिर आपकी शरण में आ रहा हूं। आज तक किसी मंत्री महोदय के उत्तर से दस साल तक संसद् में विरोधी पक्ष घबराता नहीं रहा लेकिन हमारे उत्तर से विरोधी पक्ष इसलिए घबराता है कि वह सोचता है कि तीस साल तक सारे

कारनामे जो स्वास्थ्य विभाग के रहे हैं कहीं उनका उद्घाटन न हो जाए। इसलिए वह घबराता है। जितना सवाल पूछा गया है उसका उत्तर आप सुनें।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो विश्व बैंक के जरिये या स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के जरिये रुपया मिलता है उसको कैसे कैसे कहां कहां ब्योरे से खर्च किया जाता है।

डा० कर्ण सिंह : संक्षिप्त बता दें।

श्री राज नारायण : संक्षिप्त नहीं होता है।

डा० कर्ण सिंह : समद में संक्षिप्त करना पड़ता है।

श्री राज नारायण : जो छिपाना चाहता है, जो देश की जनता को गुमराह करना चाहता है वह संक्षिप्त करता है जो सदस्यों को सच्ची बात बताना नहीं चाहता है वह ऐसा करता है।

भारत जनसंख्या परियोजना एक प्रायोगिक परिवार नियोजन परियोजना है जो विश्व बैंक के माध्यम से स्वीडन सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के छः जिलों अर्थात् लखनऊ, सुलतानपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली तथा कर्नाटक के पांच जिलों अर्थात् बंगलौर, शिमोगा, चित्रदुर्गा, कोलार और तुमकुर में चलाई गई है। एक करार के अधीन पहली अप्रैल 1973 से पांच वर्ष की अवधि के लिए परियोजना के चलाने हेतु स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के जरिये स्वीडन सरकार ने 106 लाख डालर का अनुदान दिया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 212 लाख डालर का ऋण दिया है। भारत सरकार को सामान्य पटर्न के अनुसार परियोजना जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को नियमित रूप से चलाने के लिए सहायता जारी रखनी होगी तथा अतिरिक्त धन को विशिष्ट साज सामान हेतु उपयोग में लाया जाएगा। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं माननीय कर्ण सिंह के सुझाव को मान कर चल रहा हूं। परियोजना के मुख्य घटक निम्नलिखित है;

विभिन्न स्तरों पर परिवार कल्याण और प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण करते हुए नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रसूति पर आधारित परिवार कल्याण कार्यक्रम।

उत्तर प्रदेश के चार जिलों लखनऊ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, सुलतानपुर, मुजफ्फरनगर और प्रतापगढ़ तथा कर्नाटक के तीन जिलों—बंगलौर शहर और गांव दोनों, शिमोगा और तुमकुर में भारत सरकार का एक समुचित पैटर्न कार्यक्रम (**व्यवधान**) सुन लीजिये, क्यों घबरा रहे हैं। प्रत्येक राज्य के दो जिलों–उत्तर प्रदेश में रायबरेली और सहरानपुर तथा कर्नाटक में चित्रदुर्ग और कौलार में गहन ग्रामीण कार्यक्रम, एवं लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और बंगलौर (कर्नाटक) में नगरीय कार्यक्रम। आगे और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था, प्रेरणा, प्रशिक्षण, सेवाओं और अतिरिक्त फील्ड कर्मचारियों के रूप में की जानी है।

शुरू में एक विशेष पोषाहार कार्यक्रम रायबरेली के ग्रामीण गहन जिले के एक ब्लाक में तथा बाद में, भारत और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ। स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा संयुक्त समीक्षा के पश्चात् तीसरे वर्ष में इसका विस्तार किया जाना है। इस कार्यक्रम के द्वारा यह निश्चय किया जाना है कि पूरक पोषाहार का परिवार कल्याण सेवाओं को स्वीकार करने में प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ा...

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य जान लें यह रुपया बाहर से लिया जाता है। तो उस रुपये का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है इसको सदन और सदन से बाहर दुनिया के लोगों को बताना आपका कर्त्तव्य है। अभी विश्व बैंक के लोग आये थे 1966 में जांच करने। यानी जो पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता था रायबरेली में वह पूर्व सरकार ने बाद में देना बन्द कर दिया। उसमें दिया जाता था गेंहू का आटा, चने का आटा, मूंगफली, गुड़। यह सब मिलाकर के बच्चों को खाने के लिये दिया जाता था। मगर बच्चों के नाम पर बच्चे खा गये।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व बैंक मिशन अक्तूबर 1976 में परियोजना के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिये भारत आया था और उसने भारत सरकार तथा कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था। मिशन ने परियोजना क्षेत्रों में समय रूप से प्राप्त की गई उपलब्धियों के प्रति अपनी संतोष व्यक्त की है।

MR. SPEAKER: I would request both the Questioners and the Minister to be precise and to the point. Otherwise we are taking a lot of time of the House. I am not referring to any particular Member. I am sure, both the Leader of the House and the Leader of the Opposition will help me in this regard.

श्री हरिकेश बहादुर : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आज़ादी को नियंत्रित करने के लिये सरकार अब कौन सी पद्धति अपना रही है और क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि पुरानी सरकार द्वारा किये गये कुकृत्यों को यह सरकार नहीं दोहरायेगी?

श्री राज नारायण : जी, जिस समय से जनता की सरकार आयी है और स्वास्थ्य मंत्रालय का भार मुझको दिया गया हैं तभी से प्रधान मंत्री ने, जनता की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, जनता पार्टी ने बहुत ही मज़बूती से कह दिया है कि ज़बरदस्ती, जोर जुल्म के साथ नसबन्दी नहीं चलायी जायेगी। अब हमारे मित्र यह जानना चाहते हैं कि अगर हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो परिवार सीमित कैसे होगा? इस का उत्तर देना हमारा कर्त्तव्य है। तो मैं चाहता हूं कि जरा आप भी सुन लें क्योंकि यह सारे देश और विश्व का सवाल है और दुनिया के हर मुल्क के राजदूत आते हैं हमसे मिलते तो यही प्रश्न पूछते हैं कि :

How are you going to control the growth of population ?

यह उनके शब्दों को दोहराया है। मैंने पहले ही कह दिया है कि जब टेंशन होता है तो मैं कभी-कभी अंग्रेज़ी बोल देता हूं। यह हमारी गलती है, क्षमा करें--इस का उत्तर मैं देता हूं कि :

"देखिये ब्रह्मचर्य की मैं शिक्षा दूंगा, स्वास्थ्य मंत्रालय शिक्षा देगा ब्रह्मचर्य की, इन्द्रिय निग्रह की, आत्म नियंत्रण की और योग की। जो प्राचीन पद्धति रही है बच्चे पैदा करने के लिये, पति और पत्नी में, जो मासिक धर्म होता है, उसके कितने दिन के बाद सम्भोग हो, जिससे गर्भ रहे और गर्भ न रहे। यह प्राचीन पद्धतियां हैं। (**अन्तर्बाधाएं**) इसी के साथ-साथ अनेक दवाएं हैं और हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे हमने निवेदन किया है कि वह कुछ ऐसी दवाएं निकालें, जिससे बिना शरीर और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े हुए, गर्भ का निरोध हो सके।"

मैं कहना चाहता हूं कि 10,10 लाख की सभाएं हुई हैं और उनमें हमने इस बात को दोहराया है कि हमारे आदर्श राम और कृष्ण हैं, युधिष्ठिर और हजरत मोहम्मद साहब पैगम्बर हैं। राम के दो बच्चे लव और कुश क्यों? भरत को दो बच्चे (**व्यवधान**)

और मोहम्मद साहब के केवल एक बेटी और उसके केवल दो बेटे । इसलिए प्राचीन ऋषियों-मुनियों की बातों को लोगों को समझायें और बतायें कि कम-से-कम संतान रहने से परिवार सुखी रहेगा । (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Next Question.

DR. KARAN SINGH : I have a submission to make.

MR. SPEAKER : I have already gone to the next Question.

DR. KARAN SINGH : I want to make one submission. I am not questioning your decision. I am not putting a question. I am just making a submission.

This is a question about India Population Project. It is a very important question. Rs. 60 crores a year are spent on it. We wanted to have some clarifications about this project. The hon. Minister, for 15 minutes, was propagating a very interesting theory on population control. That is also interesting. But that should not deprive us of asking some very important questions and clarifications with regard to the past project.

MR. SPEAKER : There are other ways of raising it also. I am sorry I have gone to the next question.

DR. KARAN SINGH : This is very unfair. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : You are taking away another 2 minutes. I am not allowing.

श्रीमति अहिल्या पो० रांगनेकर : अध्यक्ष महोदय, इस संसद में हम औरतें बैठी हुई हैं, जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात हैं । इससे आपको बचना चाहिए । यहां औरतें बैठी हुई हैं ।

MR. SPEAKER : I will look into the matter.

SHRI K. LAKKAPPA : This is a very important Question. I want to put a supplementary.

MR. SPEAKER : I am not allowing. (*Interruptions*)

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : The hon. lady Member has drawn your attention to this thing....

MR. SPEAKER : I will examine the record.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : Otherwise, I am afraid, all the lady Members of Parliament would have to boycot the questions relating to his Ministry.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I shall examine the record.

चौधरी बलबीर सिंह : ये लोग सैक्स एजूकेशन का समर्थन करते हैं, मगर अब ये एतराज़ कर रहे हैं, हालांकि मिनिस्टर साहब ने कोई ख़ास बात नहीं कही है । (व्यवधान)

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : This is even more objectionable.

MR. SPEAKER : I shall examine the record and if there are any objectionable things, I shall get them expunged.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करने वाले एकक की स्थापना

*668. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् की कार्यकारी परिषद् की 4 अगस्त, 1973 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सिद्धान्ततः सहमति प्रकट की गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करने वाले एक एकक की स्थापना की जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी स्थापना कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय चिकित्सा एवं होम्यो-पैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् की कार्यकारी समिति ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में औषधीय पदार्थों का सर्वेक्षण करने वाला एक एकक स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो। किन्तु धन के अभाव के कारण यह योजना अब तक शुरू नहीं की जा सकी है। इस यूनिट के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों को लाने का विचार था, यह कार्य क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) झांसी कर रहा है।

झांसी में जो आयुर्वेद का अनुसंधान संस्थान है, वह यूनानी का भी कार्य कर रहा है। इसलिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय में यूनिट खोल कर जो काम होना, उसे हम झांसी के संस्थान के द्वारा कर रहे हैं।

श्री नवाब सिंह चौहान : भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेडिकल प्लांट्स, औषधीय पौधों, के अनुसंधान के लिए एक यूनिट की स्थापना कर के ऐसे पौधों की खोज की जाये, जिस से गरीबों के इलाज में सहायता मिले। यह प्रश्न 1973 से ले कर अब तक केवल इस बात पर अटका रहा है कि धन नहीं है, जब कि करोड़ों रुपये अन्य कामों पर खर्च कर दिये गये हैं। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह उन के जमाने की बात नहीं है। लेकिन अब तो यह उनके जमाने की बात है। मंत्री महोदय के बारे में यह विश्वास है कि वह जो कुछ कहते हैं, वह करते हैं। जब उनके सामने यह प्रश्न आया है, तो क्या वह विचार करेंगे कि इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में भी इस यूनिट को खोला जाये, ताकि वहां पर अनुसंधान-कार्य शुरू किया जाये?

श्री राज नारायण : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह सही हैं। बहुत सोच-विचार के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह यूनिट खोलने का निर्णय लिया गया था, ताकि जड़ी-बूटियों और अन्य पदार्थों की खोज कर के यूनानी की अच्छी अच्छी दवायें बनाई जायें। यह सही है कि यह योजना 4 अगस्त, 1973 को स्वीकृत की गई थी। तब से चार साल बीत गये हैं। मार्च, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब हम जरूर इस बात पर विचार करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह यूनिट खोल कर हम जो कार्य करना चाहते थे, क्या झांसी का आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान उसे पूरा कर रहा है या नहीं। अगर झांसी का आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान उस कार्य को पूरा नहीं कर रहा होगा, तो अवश्य ही इस के बारे में कोई दूसरी व्यवस्था की जायेगी, जिस से जो उपलब्धि हम चाहते थे, उस में कोई बाधा न पड़े।

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों की आज और कल जो बैठक हो रही है, उस में इस प्रश्न पर विचार होगा कि जिन निर्णयों को पहले किसी न किसी बहाने टाला जाता रहा है, उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जाये, और जनहित की जो उपेक्षा हुई है, उसे किस प्रकार दूर करें इस की हम बराबर कोशिश कर रहे हैं।

MR. SPEAKER : Short Notice Question.....

PROF. P. G. MAVALANKAR : Sir, on a point of order. My dear and esteemed friend, the hon. Health Minister, has naturally the enthusiasm to answer questions in detail and many Questions are therefore, not reached. I do not mind it ; I am not making a complaint of that. I know, you have ruled that both must be brief. My Question today was 676 and it could not be reached because there were many supplementaries. My point of order is different.

I have been finding in the last couple of weeks that Ministers who are supposed to answer for their respective departments or Ministries are unfortunately not present either because they are concurrently engaged in the other House or because they are sometimes out of Delhi and in some cases even out of India. I want to ask with all respect whether this is in tune with Parliamentary practice—Ministers going out of Delhi and even out of India sometimes when the House is in session. Is it right ?

I am raising two questions, Sir. The Prime Minister—I wish he were here—should really expand his Council of Ministers as early as possible so that his colleagues who are already over burdened will have some relief and persons could be deputised to act on behalf of their senior collegues. But that is not my question in the sense that Government is free to appoint whomsoever they like and at whatever time they wish. My point as a Member of this House is about the difficulties involved if a Minister is absent and if some one else is to reply on his behalf. Of course, some time back, the Prime Minister replied on behalf of the Minister of External Affairs, and I must say that the Prime Minister replied most competently and efficiently. Mr. Ravindra Varma may have replied today, and I am sure he will have replied competently and efficiently. But that is not the question. The question is what kind of attention and respect is paid to this House by the Ministers and by Government as a whole. We wanted to ask supplementaries, but we could not get the time today. If we had got the time, I do not know what kind of answers my dear friend, Mr. Ravindra Varma would have given to the supplementaries because he would not know all the details about that Ministry for which temporarily he is answering on a particular day. So, I request you, Mr. Speaker, to tell the Government that, at least, the Council of Ministers should be expanded as early as possible and also those Ministers who are to answer questions should not be out of Delhi and out of Parliament when Parliament is in session and expects them to answer questions personally. I want your ruling and guidance on this point because I feel that the whole parliamentary procedure and practice demand that the House must get respect and attention from the Government, both in letter and in spirit.

MR. SPEAKER : I am sure, the Minister of Parliamentary Affairs will convey Mr. Mavalankar's suggestion to the Prime Minister.

So far as the Minister of External Affairs is concerned, he had written to me earlier before leaving the country. The case of Minister of External Affairs perhaps, stands on a different footing from those of other Ministers. I entirely agree with Mr. Mavalankar that, so far as the other Ministers are concerned, when Parliament is sitting, they must be here. This House has a right over them.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : May I submit that even the hon. Prime Ministers, in the past, did not fix their tours abroad during Parliament sessions ? I would like to submit with all humility that the External Affairs Minister does not stand on a different footing at all. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Let us not have a debate on this.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : My humble submission is that the External Affairs Minister should not be treated on a different footing. The House did not treat the hon. Prime Ministers on a different footing, and all the Prime Ministers in the past did not fix their tours abroad during Parliament sessions.

SHORT NOTICE QUESTION

Bechtel Company Given Contract on Kudremukh

26. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether he is aware of the fact that Mr. Mc Cone, a former Director of C.I.A. is on the pay-roll of Bechtel Company ;

(b) whether the Takru Commission had passed serious strictures against this company and some very senior officers of the Government of India ; and

(c) Whether the said company had been given big contracts on Kudremukh (Karnataka) ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) No, Sir.

(b) The Takru Commission had made certain adverse observations about Bechtel Corporation and its subsidiaries and some officials of the Indian Refineries Limited/Indian Oil Corporation and the Department of Petroleum.

(c) Canadian Met-Chem Consultants Limited, Montreal who are the Mining Associate and Engineer Constructor for the Kudremukh Iron Ore Project have employed Bechtel as their sub-contractor for the design and engineering of the iron ore slurry pipeline and pumping system of the project. This is the only work assigned to this company.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I cannot quite understand his reply to my question (a) where he has said 'No'. Is it that he does not know or is it that it is not a fact ? That is what I want to know. He has only said 'No' Sir'. 'No' means what ? Is it that the Ministry did not care to know or is it that it is not a fact ?

I would like the hon. Minister to tell us today whether the Research and Analysis Wing, Foreign Intelligence Section, has given any report on Bechtel and if so, what it is, and if not, whether he would obtain it and place it before the House. At the same time, I would like the hon. Minister to get the information whether this Bechtel Company is an outlet for the CIA for dishing out funds in India for anti-Indian activities.

SHRI BIJU PATNAIK : If the hon. Member wishes to make out a James Bond, I do not think one exists. The fact of the matter is that Mr. Mc Cone, who was a former Director, Central Intelligence Agency, was a partner in Bechtel Corporation in his personal right...

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I know this man worked for CIA for ten years.

SHRI BIJU PATNAIK : The records available in the Petroleum Ministry reveal that it was brought to the notice of the Minister of Petroleum in the course of the discussions held on 4-5-1973 between the Minister of Petroleum and Chemicals, Mr. D. K. Barooah, and a delegation from the National Committee for assisting the pepelines inquiry headed by Shri Indrajit Gupta, M.P. Besides Mr. Indrajit Gupta, the Delegation included Shri Vasant Sathe, M.P, Shri Arun Roy Chowdhury, and Shri Shashi Bhushan, M.P. The relevant portion from the draft gist of the discussion is given below :

"Shri Arun Roy Chowdhury presented a book to the Minister which shows that there had been a business partnership between the former Chief of the CIA and the Bechtel Corporation. Minister said that he would go through the book."

I had asked whether I could get hold of that book. But that book seems to be missing now.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : This is about my questions (b) and (c).

The Takru Commission had said : on pages 84 and 85 of its report :

"In his statement/affidavit dated 7-10-1971, he wanted the Commission to make a full investigation and detailed inquiry about :

(1) the illegal gains and benefits derived by the various officers ;

(2) the assets, bank accounts, foreign travels, hotels they stayed, etc., of all these officers ;

(3) the education of Shri P. R. Nayak's children in M.I.T., U.S.A. and funds they held in USA ;

(4) who paid for Shri P. R. Nayak's luxury class tickets after 1963, and for his lavish entertainments, and whether these expenses were not from the reimbursable costs ;

(5) whether Shri P. R. Nayak stayed in George V Hotel in Paris in 1962 at Bechtel's costs ;

(6) the education of children of Shri M. Gopal Menon and Shri M. V. Rao abroad.

"In his statement/affidavit dated 31-7-1972, he wanted the Commission to investigate,

(1) whether the officers concerned entered into the various contracts with corrupt motives, and

(2) whether Messrs Bechtel Corporation of USA made payments to Shri M. V. Rao and exercised undue influence on him."

This is the sum and substance of the Takru Commission.

It also said :

"The only other question that remains to be answered is whether, and, if so, to what extent, Messrs. Bechtel Corporation of USA were responsible for those *mala fide* acts of Shri P. R. Nayak."

Then it says :

"But from the argument advanced more than once, by their learned, counsel, Shri S. L. Watel, namely that Messrs. Bechtel Corporation of USA.....come out expressly for the purpose of business, and making money, it can safely be inferred that they must have employed all the tricks of the trade to get what they had come out to India for. However, the extent to which they went in the pursuit of their objectives, remains as much a mystery....."

MR. SPEAKER : What is your question please ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : My question in that context is : what steps have been taken against those officers particularly, Shri Pathak, son of the erstwhile Vice-President and a Congress man, who is now employed by Bechtel in America and also the erstwhile Secretary of the Ministry whose cousin is still working in Bechtel in America ? In this Kudremukh contract, they have enhanced the cost by manipulating the design etc. I would like to have a clarification from the Government.

SHRI BIJU PATNAIK : The answer to the last question of Shri Jyotirmoy Bosu is in the negative. As far as the fist part of the question is concerned, what he has stated is factually correct. We have no control as to whom an American company is going to employ.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Why have you allowed him to come here again ?

SHRI BIJU PATNAIK : I would like to place a document on the Table of the House—"Iron Concentrate Slurry Pipeline" by two eminent engineering supervisors—from which Shri Bosu will find that Bechtel have the expertise to do this type of work.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : He is talknig from the commercial point of view ; I am talking from the national security point of view.

MR. SPEAKER : He is a very experienced Minister ; he understands your question.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Can you have American spies operating in the vital sector of the country ?

SHRI BIJU PATNAIK : I fully agree with the hon. Member and it is not the intention or the desire of this Government to allow spies to operate in the vital sector of the country. The hon. Member knows it very well ; we do not want CIA or the spy system of any other country to operate here.

The question here is that we are working on a very tight schedule covered by a heavy penalty clause. We have got to get the best expertise in the world. But as far as the Kudremukh authority is concerned, it is a Government authority and does not employ this firm directly. The consultants, Met-Chem have employed them as I have said in my answer as their subcontractors for the design and engineering of the iron ore slurry pipe-line and pumping system of the project. They have got the expertise for this and I am placing this before the House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : The Bechtel design is outdated after 1972 ; it is not latest method.

SHRI BIJU PATNAIK : That is not correct.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : He has not replied about Mr. Pathak's son, the chief of Engineers India Ltd. and Member of the Planning Commission in the Congress regime. We want to know what they have done to Mr. Pathak.

MR. SPEAKER : No, he has answered it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : No, he has not answered it as to how he is safeguarding national security and how he is preventing the CIA from operating in this country. I want to have an assurance in this regard.

SHRI BIJU PATNAIK *rose.*

MR. SPEAKER : Mr. Minister you should not answer questions which I do not allow.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : You are not concerned about national security.

MR. SPEAKER : I am very much concerned.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Let him say. I pray to you.....

MR. SPEAKER : No, please. I am not allowing. Whatever you may say will not be recorded.

Shri Lakkappa.

SHRI K. LAKKAPPA : I do not want to inject politics into this matter. But because it is Kudremukh Project which is involved and of which the Karnataka people are very proud, I would like to say that we are not sure if there are any CIA agents working either in this Ministry or in any other Ministry. I do not know how it was working. If there is any bad remark or bad antecedents about this company, you are free to deal with the matter. We have no objection. But I would like to know what are the important works entrusted to this company. What is the point of time by which they are going to implement this project and bring it to a fruitful completion to benefit the people of Karnataka ?

MR. SPEAKER : He has already answered about the works. Only the other part he may answer.

SHRI BIJU PATNAIK : The Kudremukh project will be ready for operation towards the end of 1980.

SHRI D. N. TIWARY : There is basically something wrong with regard to the Kudremukh project. They not only try to jeopardise the national security but also behave differently in commercial matters also. A few days ago I had drawn the attention of the hon. Minister to a big attempt to defraud the exchequer and the letter remains unreplied. I had written to the Minister on the 16th of this month and I would like to know what he has done in the matter.

SHRI BIJU PATNAIK : I do not know if it arises out of the main question. It is a competition between two contractors. That has been sent to the Kudremukh Project Board.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि बेक्टल्स और दूसरी जो इस तरह की विदेशी कम्पनियां हैं जहां पर सी० आई० ए० और के० जी० बी० के एजेन्ट्स हैं, वे इस देश में आपरेट करते हैं। वे कम्पनियां बड़े-बड़े लोगों के, मंत्रियों के, एम्बसडर्स के बच्चों को एम्पलाय कर के इस तरह से सरकार को इंफलयून्स करना चाहती हैं।

एक माननीय सदस्य : एम० पीज के भी हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : एम० पीज के भी होंगे।

मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बेक्टल्स बहुत बड़ी कम्पनी होगी लेकिन मुझे मालूम है कि इस तरह का गलत काम इन्होंने किया है। इसके अलावा दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अन्दर भी इसको एम्पलाय किया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देश की सेक्यूरिटी को सामने रखते हुए वे क्या कदम उठाएंगे कि इस प्रकार की बातें सी० आई० ए० या के० जी० बी० के द्वारा न हों और क्या वे इस सदन को विश्वास दिलाएंगे कि ऐसी कम्पनियों को कोई काम नहीं दिया जाएगा ?

SHRI BIJU PATNAIK : This is hardly a thing which the Government can agree to. We have to safeguard against the baneful influence of any foreign espionage system in our country. That is the business of any government. But when we have the only expertise available in the world which is the best, we must use it after taking the necessary precautions that it does not give them an approved entry for their spying system.

श्रीमती मणाल गोरे : यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए मैं मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहूंगी कि क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि भले ही यह एक्सपोर्ट

कमेटी हो और भले ही वे ऐसा करते हों कि यह कांट्रेक्ट से नहीं बल्कि सब-कांट्रेक्ट से संबंधित है, लेकिन जब यह निश्चित रूप से मालूम है कि वह सी० आई० ए० के ऐजेन्ट हैं तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि एक्सपर्ट कम्पनी होते हुए भी, इन की सर्विसेज उस में नहीं लगानी चाहिए? इस प्रकार से मंत्री महोदय नहीं सोचते हैं?

SHRI BIJU PATNAIK: I do not think the hon. member understood my answer. I said that the Bechtel Company has a share holder who was formerly a Director of CIA. He is no longer in the service of the CIA.

SHRI VAYALAR RAVI: Officially he is not in service.

SHRI BIJU PATNAIK: He retired from service. Our RNJ has still a former Director after he has retired. I have nothing to add.

SHRI VASANT SATHE: I was one of those who had gone on deputation to Takru Commission. We had pointed out to the Minister then that Bechtel along with SNAM of Italy another Company had laid the pipeline in Barauni. It is observed from the Report of Takru Commission that that pipeline was laid through a track which is so dangerous that any time....

MR. SPEAKER: Please come to the question.

SHRI VASANT SATHE: This is part (b) of the question. Knowing fully well that this is dangerous to the defence interest of this country, the realignment as recommended has not been done yet. It is in public interest. When it had been pointed out earlier that CIA agents were there, it was laughed away. Now when you know the Director himself was the Head of the CIA and CIA admitted this, knowing the antecedents of the Company, I would like to know was there no other Company who could lay the pipeline? If some other Company could do it, what is the reason for giving it to Bechtel when there was risk involved in it?

SHRI BIJU PATNAIK: An hon. member who was himself a Member of the Commission has made these observations. I have already answered earlier.

SHRI VASANT SATHE: You have not recommended Takru Commission's Report.

SHRI BIJU PATNAIK: Talk of laying the pipeline is dangerous to the security or defence of the Nation—I do not agree at all. That is a matter between the Petroleum Ministry and the contractors. They should have decided then which way the pipeline could have been taken.

MR. SPEAKER: The question is—knowing fully well the antecedents of Bechtel Company, was there no other Company which could have done the job? If there are any other companies, why did you not entrust the work to them?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: When was the contract given?

SHRI BIJU PATNAIK: This project was before the advent of the Janata Government.

SHRI VASANT SATHE: He is defending it.

SHRI BIJU PATNAIK: The former Government was incharge.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: That is an illegitimate baby.

SHRI BIJU PATNAIK: I am holding nobody's baby.

SHRI VASANT SATHE: You have fallen in love with the baby.

SHRI BIJU PATNAIK: Hon. Sathe disowns his own baby.

It is a fact.

It is a fact that in respect of this type of pipelines for transmission of iron-ore they are the most leading processers and pesigners.

श्री उग्रसेन: साफ तौर पर यहां बताया गया है कि इस कम्पनी के एक डायरेक्टर सी० आई० ए० के प्रमुख थे। इस बात को जानते हुए कि वह सी० आई० ए० के एक प्रमुख हैं उनको प्रशासक बनाया गया। क्या आप स्पष्ट बताएंगे कि पहले वाली जो सरकार थी उसने उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की और आपने अभी तक कौन सी कार्रवाई की है?

श्री बीजू पटनायक : पहली सरकार ने क्या कार्रवाई की यह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो पहले डायरेक्टर थे, एक पार्टनर थे, उन से हम को बहुत डर होना चाहिए।

I wish to assure him that Janata Government is strong enough to defend the cause of the nation.

SHRI BEDABRATA BARUA : The question was whether there could have been another party who would have taken it up—may be an Indian or Indian registered party. He has persistently refused to reply to it. In view of the strictures, it is obligatory on the part of the Government to go into the matter and not simply to take shelter behind the contractors. So I would like to know whether the Government has examined all the implications of this contract from the indigenous as well as from the security angle and whether the Government would put its feet down on this contract.

SHRI BIJU PATNAIK : My categorical answer is that in respect of the previous association five years back of a former Director of CIA, the security of the country is certainly not involved. The CIA agent has nothing to do with what happened in India. Government has taken every care on that account. Secondly, this cannot be done unless you cancel the Canadian agreement because they are the principal consultants whom you have to dismiss. That means, holding the operations back by three or four years. It is not possible because the Government of India is faced with a stiff penalty clause. There is a 630 million dollar loan for this project.

चौधरी बलबीर सिंह : जो डायरेक्टर वापिस चले गए हैं और जो सी० आई० ए० के एजेंट थे उनके बारे में आप कोई इंक्वायरी करेंगे और पता लगाएंगे कि पहले जो सत्ताधारी दल था उसमें से किन किन का उनके साथ ताल्लुक रहा है और क्या आप उन लोगों का रिकार्ड चैक करेंगे कि पहले वाली सत्ताधारी पार्टी ने सी० आई० ए० का जो एजेंट यहां पर रहा उसके साथ क्या ताल्लुकात रखे और उन लोगों के एक्शन वगैरह को चैक करके आप देखेंगे कि कांग्रेसी पार्टी वालों को उस एजेंट से कोई पैसा तो नहीं मिला है या इन्होंने हिन्दुस्तान के बारे में कोई . . .

अध्यक्ष महोदय : नो, नो।

चौधरी बलबीर सिंह : यह सवाल बिल्कुल रेलीवेंट है। एक आदमी जो मान लिया है कि वह सी० आई० ए० का एजेन्ट था और वह चला गया, उसने वहां पर कुछ काम किया, तो जिन लोगों से उसका सम्बन्ध था, बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि अगर किसी को पता लगे जैसे जर्मनी का जो चांसलर था उसका ताल्लुक ईस्ट जर्मनी के किसी स्पाई से हुआ तो उसको रिजाइन करना पड़ा यानी चांसलर को रिजाइन करना पड़ा जो अपने मुल्क में बहुत लोकप्रिय था। इस देश में जिन लोगों का, सत्ताधारी दल जो पहले था कांग्रेस वालों का, मिनिस्टरों का या उनसे ताल्लुक रखने वालों का उस सी० आई० ए० एजेंट के साथ ताल्लुक रहा है उन सब के अकाउन्ट के बारे में चैकिंग कर के मंत्री जी इनक्वायरी करेंगे ताकि मुल्क को पता चल सके कि कांग्रेस पार्टी ने, मिनिस्टरों ने और उनके साथियों ने इस देश की सुरक्षा के बारे में कितनी धांधलियां की हैं और उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाएगा?

SHRI BIJU PATNAIK : Government will certainly look into this.

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं, यह सवाल सिर्फ एक कम्पनी और व्यक्ति का नहीं है, बल्कि यह सवाल नीति का है। क्या भारत में ऐसे लोगों को, चाहे वह रूस का हो या अमरीका का, जो भारत की स्वतन्त्रा के लिये खतरा बन सकते हों और इसकी जानकारी सरकार के नोटिस में आ जाय तो सरकार क्या उनके साथ आम शहरियों जैसा व्यवहार करेगी या उनसे जो खतरा देश को है उससे बचाने के लिये कोई विशेष कार्रवाही

करेगी ? अगर हां, तो गृह मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी स्पष्टीकरण करें । सिर्फ एक इकाई का सवाल नहीं है, समस्त देश की जनता की विचारधारा रूसी और अमरीकी ऐजेन्सियों से घबरायी हुई है, तो गृह मंत्री जी, या प्रधान मंत्री जी स्पष्टीकरण करें कि ऐसे जो भी जाल बिछे हुए हैं उनको तोड़ने के लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

SHRI BIJU PATNAIK : I have already said that Government has taken and shall take all precautions.

श्री मनी राम बागड़ी : यह एक इकाई का सवाल नहीं है, मेरा राष्ट्रीय स्तर की नीति के बारे में प्रश्न है, माननीय गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं वह स्पष्टीकरण करें ।

MR. SPEAKER : All ministers speak for the government.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : I want to know from the Minister when this Bechtel company was founded and when Mr. Mc Cone became the shareholder of this company? Is it after his retirement as CIA agent or is it earlier to that?

SHRI BIJU PATNAIK : He was a shareholder of this company when he was still in service.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Stainless Steel Sheets

*669. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN :
SHRI R. V. SWAMINATHAN :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have reduced the customs duty on stainless steel sheets used in manufacture of utensils and for re-rolling purposes;

(b) if so, the facts thereof and impact it has made on the prices of steel utensils;

(c) whether the All India Small Scale Stainless Steel Re-rollers, Association has expressed their concern over this step for it may lead to the closure of about 1500 cottage and small scale units;

(d) whether public sector units such as H.S.L. and M. I. X. L. manufacturing indigenous raw materials for small re-rollers also will have to be closed down or suffer heavy loss as a result of this cut in customs duty; and

(e) the details thereof and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) and (b): The customs duty on stainless steel sheets (10 BG and thinner) was reduced from 320% to a range between 40% and 120% *ad valorem* w.e.f. June 18, 1977. Subsequently, on July 15, 1977, the duty rates were revised to 220% *ad valorem*. The impact of the change will be evident only after the new duty rates have been in operation for sometime. However as a result of the revision of import duty, M.M.T.C. has reduced its price for imported stainless steel sheets of 26 gauge to Rs. 57 per kg.

(c) Yes, Sir, when the duty was originally reduced from 320% to 120%.

(d) and (e). Public Sector Plants will not be closed. However, they are likely to suffer losses which will be known only after some time.

Exodus of Indian Doctors

*670. SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that more than 3 thousand medical graduates leave India every year for employment opportunities and for study; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN : (a) The Government of India are not maintaining any records regarding the number of doctors going abroad for employment or for higher studies.

(b) There are no restrictions on issue of passports to doctors.

Desk Officers

*671. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Administrative Reforms Commission had recommended introduction of Desk Officer System in the Central Secretariat for efficiency in administration.

(b) whether after long persuation of the Administrative Reforms Department the System has been only partially implemented in his Ministry;

(c) if so, the number of sections where it has been decided to introduce it; and

(d) what are the hindrances in its full implementation and by when it will be introduced fully?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) to (d). Based on the recommendations of, and in accordance with the guidelines issued by the Department of Administrative Reforms, the Desk Officer System is being introduced in the Ministry of Communications in a selective and phased manner. This System has so far been introduced in one Section, and it has been decided to introduce the System in three more Sections.

Meeting of Indo-Pakistan Malaria Eradication Co-ordination Conference

*672. SHRI K. A. RAJAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether a two-day Indo-Pakistan Malaria Eradication Coordination Conference was held in New Delhi recently; and

(b) if so, the gist of the deliberations that took place and the outcome thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE : (SHRI RAJ NARAIN : (a) Yes, Sir. An Indo-Pakistan Malaria Eradication Conference was held at New Delhi on the 27th and 28th June, 1977.

(b) A copy of the resolutions adopted at the Conference is laid of the Table of of the Sabha [Placed in Library]. *See* No. LT 854/77

Height of Indians

*674. SHRI D. B. CHANDER GOWDA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state;

(a) whether in the last one or two generations Indians have become shorter; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE : (SHRI RAJ NARAIN) (a) and (b). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

देश में योग चिकित्सा केन्द्र खोलना

*675. **श्री लालजी भाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में योग चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न स्थानों पर योग चिकित्सा केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर उनका मंत्रालय विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां उपरोक्त केन्द्र खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं। किन्तु योग द्वारा कुछ रोगों का इलाज करने के लिए कई केन्द्रों में क्लिनिकी अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के परिणामों को देखते हुये योग उपचार केन्द्र खोले जा सकते हैं।

(ख) एक योग उपचार व अनुसंधान केन्द्र जयपुर में खोला गया है।

Simplification of Procedure for Issuing Passports

*676. PROF. P. G. MAVALANKAR :

SHRI RAM DAS SINGH :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are actively considering a proposal to simplify the procedure of issuing passports;

(b) if so, main indication thereof; and

(c)when will the new simplified procedure be implemented and how?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An examination is now being done to simplify procedures and processes relating to police verification, delegation of more powers to Passport Officers, easy availability of application forms, liberalised endorsement policy, simplified application form, as well as enlarging the categories of persons who can sign verification certificates. The new simplified procedures and processes will be introduced as soon as the examination is over and the decisions on these are arrived at.

Telecommunication Delegation to Pakistan.

*677. SHRI PRASANNBHAI MEHTA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a three-member telecommunication delegation from India had gone to Pakistan for talks;

(b) if so, the subjects discussed;

(c) whether due to the change of Government in Pakistan the delegation could not meet with any success; and

(d) if not, the outcome?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) Yes, Sir.

(b) Talks covered review of operation of existing telephone, telegraph and telex services *via* landline links and the establishment of a satellite link between India and Pakistan.

(c) No, Sir.

(d) As a result of these discussions an understanding has been reached on various points. A formal agreement is expected to be signed in the near future.

Iron ore Supply to Visakhapatnam, Salem and Vijayanagar Steel Plants

*678. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether mines have been identified and earmarked for supply of iron ore to the proposed three new steel plants at Visakhapatnam, Salem and Vijayanagar;

(b) if so, the facts thereof and steps taken in prospecting the mines for producing required quantities of ore by each plant; and

(c) the financial provisions made in the current year for the work?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Yes, Sir.

(b) The requirements of iron ore for the Visakhapatnam Steel Plant are proposed to be met from the new mine at Bailadila Deposit No. 4 and from the existing mine at Bailadila Deposit No. 5. The requirements of the Vijayanagar Steel Plant were originally proposed to be met from the Kumaraswamy Deposits in Karnataka. In the case of the Karnataka Steel Plant, however, an alternative site at Mangalore Port is under consideration. The field investigations and laboratory tests on these iron ore deposits have been completed and work for preparation for project reports has been taken up.

The first phase of Salem Plant does not provide for iron making facilities and in the second phase it is proposed to initially use iron ore from the Mines in the Bellary-Hospet Sector. Samples of ore have also been tested from the Etina-Hatti deposits and the use of Kanjamalai ore is also under consideration.

(c) For the preparation of detailed project report and engineering studies, the following provisions have been made in the Budget :—

Bailadila Deposit No. 4	Rs. 6·10 lakhs.
Kumaraswamy 'C' Block	Rs. 6·40 lakhs.

Scheme to Bring Back Indians Living Abroad.

*679. SHRI SHIVSAMPATI RAM : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Government are of the view that Indians abroad, including those

holding foreign passports, would be welcomed back home in case they decide to return to their motherland;

(b) the facilities Government propose to provide to them; and

(c) the steps taken to create an atmosphere to help them to come back to India?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) There is no bar to Indians who are abroad from returning to India; those with foreign passports will have to go through appropriate formalities before taking up permanent residence.

(b) Government will continue to provide facilities which have been available so far.

(c) No new steps are contemplated.

परिवार नियोजन सम्बन्धी नई योजना

*680. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के बारे में ऐसी कोई नई योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसमें अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों आदि का सहयोग लिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों से किस प्रकार का सहयोग लेने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को पत्राचार एवं सम्पर्क पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या समस्या के बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई एक योजना विचाराधीन है।

(ख) इस योजना में अध्यापकों को सीधे सक्रिय परिवार नियोजन कार्य में लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, प्रशिक्षण लेने के फलस्वरूप अध्यापक स्वयं ही जनसंख्या समस्या के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो जाएंगे और इस प्रकार वे अपने विद्यार्थियों को जनसंख्या समस्या और छोटे परिवार के लाभ के समबन्ध में सही जानकारी देने में समर्थ हो जाएंगे।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों संबंधी सेवा नियमों में संशोधन

*681. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों संबंधी नियमों को बहुत पहले बनाया गया था और अब उनसे विभाग के सुचारू रूप से कार्य करने में अनेक रुकावटें पैदा हो रही हैं ;

(ख) यद्यपि उनमें संशोधन समय-समय पर किए जाते रहे हैं परन्तु क्या अब भी उनमें अनेक कमियां हैं और उनका पूर्ण पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नियमों को अद्यतन बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख). जब से डाक-तार विभाग की स्थापना हुई है, विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण किया जाता रहा है। जब कभी यह देखा जाता है कि नियमों में खामी के कारण विभाग के सुचारू रूप से कार्य करने में रुकावट आती है, तो नियमों का पुनरीक्षण कर उनमें तदनुसार संशोधन किया जाता है।

(ग) और (घ). सेवा संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप और समय समय पर लिये गए निर्णयों को नियमों में समाविष्ट करने के लिए इन नियमों को बराबर अद्यतन बनाया जाता है।

Job to a member in each Family

*682. SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether he is aware that there are families in which at least one member is employed and that there are numerous families of several members where none is employed; and

(b) whether Government have any census of such second categories of wholly unemployed families so that other things being the same, same and equal preference for employment can be given to members of those families in which there is total unemployment?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b): No census of the type referred to by the Hon. Member has been conducted. Government, however, are conscious of the widespread unemployment situation and poverty prevailing in the country and have stated that it would endeavour to remove destitution within 10 years. Towards this end Government propose to adopt an employment-oriented strategy for development. The Planning Commission have also been asked to formulate the Sixth Five Year Plan keeping the above objective in view.

Aid to Mozambique

*683. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the United Nations Security Council has appealed to all States to give immediate aid to the Maputo Government in Mozambique;

(b) if so, what decision has the Government taken; and

(c) the type of aid, material assistance and the value thereof being considered by India to assist Mozambique?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c) : In pursuance of the United Nations Security Council resolution of 30th June, 1977 calling upon Member States to extend immediate material assistance to the Government of the People's Republic of Mozambique, the U.N. Secretary General has despatched a mission to that country on July 12 to ascertain their requirements. On the basis of the findings of this mission the U.N. Secretary General is expected to issue an appeal to all Member States indicating the nature of assistance that is required. Government will consider the question of extending assistance to Mozambique once the Secretary-General's report is available. It would be recalled that in March 1976 the Government had announced a contribution of U.S. $ 100,000 in the form of commodities and services for Mozambique when it imposed economic blockade against Southern Rhodesia.

Intensification of Triple Antigen Programme

*684. SHRI P. V. PERIASAMY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state;:

(a) the extent of implementation of the Triple Antigen Programme to prevent diseases like Diptheria, Tetanus and Whooping Cough; and

(b) the salient features of the programme and the proposed time-schedule for intensification of the programme on a wide front?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) The scheme for immunizing children against Diptheria, Tetanus and Whooping Cough by giving triple vaccine was taken up by the Ministry of Health and Family Welfare in the 4th Five Year Plan and is being continued during the current plan. The number of children targeted and immunized is given below:—

Year	Children at risk (0—11 years)	Children targeted	Children immunized
		(Figures in lakhs)	
1974-75	1530·00	107·70	17·22*
1975-76	,,	107·70	37·32
1976-77	,,	150·00	58·67*
1977-78	,,	180·00	
1978-79	,,	200·00	

*The figures are incomplete.

(b) The salient features of the programme are:—

(i) The triple vaccine is provided by the Department of Family Welfare and the State Governments implement immunization programme;

(ii) Besides the State Health Departments, voluntary organisations working for mothers and children are also involved in giving the immunization;

(iii) Priority is given to children living in tribal areas, backward rural areas and urban slums.

(iv) The objective is to cover unprotected children in the age group of 0—11 years who are vulnerable to these diseases. Children below 5 years are immunized against diptheria, whooping cought and tetanus. Older children enrolled in primary schools are given immunization against diptheria and tetanus only.

(v) In urban areas immunization is given through the children's clinics attached to the hospitals and Maternity & Child Health Centres. In the rural areas the vaccination is provided at the Primary Health Centres and Subcentres. In addition, children are collected at convenient places in villages like the office of the Mahilla Mandal, Panchayat office etc. and health personnel from the Primary Health Centres visit these places on fixed days and immunize the children.

(vi) Before taking the vaccine to the villages the health personnel undertake educational work to inform the community about the diseases and the advantages of immunization in order to clear misunderstandings and fears in their minds.

The effort in the 6th Five Year Plan will be to immunize the new-born infants that will be added every year. The aim will be to immunize about 80.85% of the new born infants by the end of the 6th Five Year Plan period.

Extension of service of Deputy Assistant Directors General, C.G.H.S.

5144. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether two Deputy Assistant Directors General in the Directorate of C.G.H.S. at present were given extension of service beyond their due retirement dates during the emergency due to their political influence;

(b) whether these officials were involved in a number of cases like ill treatment to patients, death of certain patients due to negligence and misappropriation of medicines, while working in the C.G.H.S. Dispensaries;

(c) whether these two officials were managing the affairs of the Directorate of C.G.H.S. and the dispensaries thereunder arbitrarily during the emergency causing harassment to doctors working there; and

(d) if so, details of the case and what action is being taken against them?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) (a) The extension was given during the period of the former Minister, Dr. Karan Singh. Till now there is no information as to whether there was any political influence behind this.

(c) to (d): It will take some time to ascertain the facts.

Opening of Post Offices in Villages

5145. SHRI CHAUDHARY MOTIBHAIR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:—

(a) whether his attention has been drawn to the fact that the villages in which Post Office facilities are not available have to make payment to Postal Department for ten years to make up for losses in order to avail of the postal facilities; and

(b) whether Government propose to open new Post Offices in such villages which could not get this facility and are mostly in the backward area and if so, whether the practice of receiving continuation from such villages in the name of compensation for losses would be abolished?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) : (a) Post Offices which fulfil Departmental norms are opened without taking any payment.

Post Offices which do not fulfil Departmental norms are opened after getting a Non Returnable Contribution as per details given in the enclosed statement.

(b) Government have drawn up plans for opening 865 post offices in villages in very backward, tribal and hilly areas during the current financial year. For the present, it is not proposed to abolish the practice of obtaining Non-Returnable Contribution in cases where Post Offices, which do not fulfil the Departmental norms, are to be opened to meet specific requests.

Statement

Conditions for opening of Post Offices in rural areas

(A) NORMAL RURAL AREA:

(i) Distance of the proposed Post Office from the nearest existing post office should not be less than 3 miles except in cases of villages which are the Headquarters of Administrative units like Tehsils, Talukas, Thanas, Community Projects or N.E.S. Blocks or Gram Panchayats or having schools run by District Boards or Local Boards or schools approved or receiving aid from State Government. In case of such villages the distance from the nearest existing post office should not be less than two miles.

(ii) The permissible limit of loss should not exceed Rs. 750/- per annum per post office if population to be served within a radius of 2 miles is 2,000 or more;

(iii) The permissible limit of loss should not exceed Rs. 500/- per annum where population to be served within a radius of 2 miles is less than 2,000.

(iv) The proposed post office should not result in its parent office having to work at a loss beyond the permissible limit of loss of Rs. 500/- and

(v) The minimum guaranteed income of the post office should not be less than 25% of the cost.

(B) VERY BACKWARD AREA :

(i) The permissible limit of loss is relaxed from Rs. 500/- or Rs. 750/- to Rs. 1000/- and in exceptional cases even upto Rs. 2500/-

(ii) The minimum guaranteed income should be 15% of the cost.

(C) HILLY AREA:

The minimum guaranteed income should be 10% of the cost.

Post Offices to be opened on Non-Returnable Contribution

If the above noarms are fulfilled, the P&T Department bear the loss upto the permissible limit of loss and a post office is opened. However, if the loss exceeds the permissible limit of loss, than the amount of loss in excess of permissible limit of loss is to be paid by the sponsoring party as Non-Returnable Contribution and the post office is opened. The review of the loss is done every year and the post office is retained so long the sponsoring party continues to bear the loss in excess of permissible limit of loss.

These post offices are run as experi-

mental post offices and are retained for 10 years on annual review basis. If after a period of 10 years of the opening of the experimental post office, the post office is found to work within the permissible limit of loss;

(i) of Rs. 240/- per annum provided that no post office exists within the distance of 2 miles; or

(ii) Rs. 360/- per annum provided that no post office exists within the distance of 3 miles; or

(iii) beyond Rs. 360/- but within Rs. 500/- per annum provided that no post office exists within the distance of 5 miles.

The post office is made permanent and no compensation becomes due from the sponsoring party. If, however, the loss is beyond the permissible limit of loss of Rs. 240, 360, 500, then the post office is to be closed down.

In case the Departmental norms are not fulfilled and the Post Office is to be opened to meet the specific requirements of sponsoring party, the party has to bear the Non-Returnable Contribution of an amount equal to the entire anticipated loss of the proposed post office.

Employment opportunity to Nurses

5146. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of unemployed nurses in the country and the details of employment opportunities that exist at present and likely to arise during the ensuring year; and

(b) the steps taken by Government to counteract the trend of brain-drain in respect of trained nurses?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) The cases are examined on merits and the general policy is not to encourage foreign assignment on a mass scale of para-medical personnel in which there is a definite shortage.

Diamond drilling at Kolihan Copper Mine

5147. SHRI S. G. MURUGAIYAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether due to wrong planning of Additional Chief Geologist, Kolihan Copper Mine the Diamond Drilling work had stopped at K.C.M.; and

(b) action taken in this regard?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) No, Sir. The underground diamond drilling at Kolihan Mine is far ahead of the requirement of exploration for ore production, and this activity has been temporarily suspended until new drilling faces are available at the next mining level viz. at 306 metre level horizon.

(b) Does not arise.

बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्राइवेट मेडिकल कालेजों को अपने अधिकार में लेना

5148. डा० रामजी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य के पांच प्राइवेट मेडिकल कालेजों को अपने अधिकार में लिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन कालेजों में लगभग चार हजार विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने उन्हें मान्यता नहीं दी है ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता दिलाने के विचार से अपने अधिकार में लिया है ;

(घ) क्या उन्होंने नालन्दा और श्री कृष्ण मेडिकल कालेजों का निरीक्षण किया था तथा क्या उन्होंने उनकी कठिनाइयां दूर करने का भी आश्वासन दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां, बिहार प्राइवेट मेडिकल कालेज (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश केन्द्रीय सरकार की सहमति से जारी किया गया था।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् एक सांविधिक निकाय है जो यह तसल्ली हो जाने के बाद कि उनमें शिक्षण संबंधी मानदण्ड और अन्य सुविधाएं परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप ही हैं मेडिकल कालेजों को मान्यता देती है। इन पांच कालेजों में से जमशेदपुर मेडिकल कालेज को परिषद् ने पहले ही मान्यता दे दी है । परिषद् ने अन्य चार कालेजों का निरीक्षण पहले कर लिया है और अगले कुछ महीनों में विश्वविद्यालय परीक्षा के समय इनका निरीक्षण फिर से किया जा रहा है। इन्हें मान्यता देने के प्रश्न पर इन कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं तथा परीक्षाओं के स्तर को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

(ग) बिहार सरकार ने इन कालेजों के प्रबंध को अपने हाथ में ले लिया है ताकि वहां पर चिकित्सा के उप-स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। ऐसा करने से बिहार सरकार का यह भी इरादा है कि इन कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की प्रथा बन्द हो जाए।

(घ) और (ङ). स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बिहार के नालन्दा तथा श्री कृष्ण मेडिकल कालेजों का दौरा किया था। बिहार सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गए प्राइवेट मेडिकल कालेजों को चलाने के लिए वार्षिक राज्य योजना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार अभी भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Sterilisation operations performed in Orissa

5149. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of sterilization operations performed during emergency in Orissa;

(b) number of such cases in Tribal areas of Orissa;

(c) number of deaths reported during post-operation period; and

(d) steps taken to give relief to the bereaved families?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) The number of sterilisations performed in the State of Orissa during the years 1975-76 and 1976-77, which cover the emergency period are 125,040 and 320, 264 respectively. The figure given for the year 1976-77 is provisional.

(b) The number of sterilisations performed in the six districts of Orissa where more than one-fourth of the population are tribals viz. Keonjhar, Mayurbhanj, Phulbani, Kalahandi, Sambalpur and Sundargarh, are given below:—

1975-76 . .	47,611
1976-77 . .	113,045 (Provisional)

(c) According to the information received from the State Government, deaths occurred in 51 cases of sterilisation performed during 1975-76 and 1976-77. On investigation 38 deaths were found to be related to sterilisation complications and the remaining 13 were not.

(d) The State Government reported in May 1977 that the question of exgratia payment to the bereaved families was under consideration. The state Government has been requested to expedite the payment.

Accommodation rented by Undertakings of Ministry of Steel and Mines

5150. SHRI SHEO NARAIN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been laid down by his Ministry for renting of private accommodation for Guest Houses by the various Undertakings under his Ministry like the H.S.L., M.A.M.C. and others in the Capital, if so, what;

(b) the particulars of the accommodation rented by these Undertakings, the monthly rent and advance rent paid, the area and location of the Guest Houses and the incidental expenditure like the wages of the staff kept and day-to-day maintenance and the period for which rented and the maintenance of staff cars; and

(c) the difficulties which lie in the way of these Undertakings especially the smaller one like the M.A.M.C. in pooling accommodation so as to economise expenditure in the context of Finance Ministry's recent orders?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) While no guidelines as such have been issued by the Ministry of Steel and Mines in this regard, the Undertakings are expected to exercise due economy in the matter.

(b) The Public Undertakings under the administrative control of Department of Steel have only three Guest Houses in Delhi—two of Hindustan Steel Limited and the other one of Hindusten Steelworks Construction Limited. Their particulars are given below:—

Hindustan Steel Limited.

Name	*Location*	*Floor area*	*Monthly rent*	*Period of lease*
(i) Parliament Street Guest House	10, Parliament Street, New Delhi.	1547 sq. ft.	Rs. 506/- per month	No lease (LIC building).
(ii) Sunder Nagar Guest House	60, Sunder Nagar, New Delhi.	3600 sq. ft.	Rs. 2000/- per month	5 years expiring on 4-7-1979.

Hindustan Steelworks Construction Limited

Guest House	A-1, Hauz Khas Enclave, New Delhi.	406 sq. meters	Rs. 2000/- per month	Three years from 8-1-76.

Wages and Maintenance

	Wages	*Maintenance*
Hindustan Steel Limited	Rs. 5194·42 per month (average)	Rs. 777·75 per month (average)
Hindustan Steelworks Construction Limited .	Rs. 953·64 per month	Rs. 2,700/- per month.

Maintenance of Staff Cars

Hindustan Steel Limited

(i) No. of Staff Cars	Three.
(ii) Maintenance expenditure	
(a) POL and Repairs	Rs. 2722·25 per month (average)
(b) Salaries	Rs. 2305·58 per month (average)

Hindustan Steelworks Construction Limited

(i) No. of staff cars	Two.
(ii) Maintenance+POL+Salaries of drivers . . .	Rs. 5,000/- per month.

Similar information in respect of Public Undertakings under the administrative control of Department of Mines is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) These three Guest Houses serve not only the officers of the undertakings concerned but also of various other subsidiaries of Steel Authority of India Limited. The reciprocal arrangements also exist with other public sector undertakings. Mining and Allied Machinery Corporation is under the Department of Heavy Industry.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्ति

5151. **श्री धन्ना सिंह गुलशन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है ; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना जो संलग्न विवरण में दी गई है, 31-12-1976 को राज्यवार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या के संबंध में है।

(ख) सरकार का प्रस्ताव रोजगारोन्मुख नीति अपनाने का है और योजना आयोग से कहा गया है कि वह बहुत उच्च रोजगार तत्व सहित छठी पंचवर्षीय योजना को सूत्रबद्ध करें। उचित अभिकरणों के साथ परामर्श करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए आयोग उचित समय में ठोस नीतियों और कार्यक्रमों का सुझाव देगा।

विवरण

क्रमांक	राज्य संघ-शासित क्षेत्र	31-12-1976 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
राज्य			
1	आन्ध्र प्रदेश	63,926	6,905
2	असम	11,438	12,207
3	बिहार	86,794	72,537
4	गुजरात	51,349	19,128

1	2	3	4
5	हरियाणा	40,943	27
6	हिमाचल प्रदेश	15,862	1,611
7	जम्मू व काश्मीर	2,904	2
8	कर्नाटक	45,781	1,100
9	केरल	55,086	4,964
10	मध्य प्रदेश	61,907	30,976
11	महाराष्ट्र	1,42,574	22,797
12	मणिपुर	410	12,471
13	मेघालय	151	4,497
14	नागालैण्ड	17,17	1,426
15	उड़ीसा	23,242	2 ,696
16	पंजाब	64,244	3
17	राजस्थान	35,356	13,805
18	सिक्किम*	..	..
19	तमिलनाडु	1,15,577	1,615
20	त्रिपुरा	2,881	4,062
21	उत्तर प्रदेश	1,73,894	750
22	पश्चिम बंगाल	1,02,535	18,260
संघ-शासित क्षेत्र			
1	अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
2	अरुणाचल प्रदेश*	..	..
3	चण्डीगढ़	9,398	22
4	दादर व नागर हवेली*	..	..
5	दिल्ली	28,737	853
6	गोआ, दमन व दीव	327	2
7	लक्षद्वीप	4	1,423
8	मिजोरम	शून्य	5,262
9	पाण्डिचेरी	1,694	4
	अखिल भारतीय योग	11,37,031	2,64,405

नोट : 1. *इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है।

2. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।

3. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार, सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

वियतनाम के औद्योगिक विकास और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये सहायता

5152. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम के औद्योगिक विकास और आर्थिक पुनर्निर्माण कार्य में भारत द्वारा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दोनों के बीच बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों के विकास में सहायता दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). भारत सरकार को वियतनाम के नेताओं के साथ विचार-विनिमय के अनेक अवसर मिले हैं। वियतनाम के प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री फान ह्यन फरवरी 1977 में दिल्ली आए थे। वियतनाम के विदेश मंत्री अप्रैल 1977 में हुई गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की बैठक के दौरान दिल्ली में ही थे। इन यात्राओं के दौरान भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक सहयोग की संभावना पर विचार-विमर्श किया गया। वास्तव में जिन क्षेत्रों में इस प्रकार का सहयोग संभव समझा जाएगा उन पर वियतनाम सरकार के साथ आगे परामर्श करके, निर्णय किया जाएगा। वियतनाम का एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल निकट भविष्य में भारत आयेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चेम्बर महासंघ के तत्वावधान में गैर-सरकारी भारतीय उद्योग-पतियों के, एक प्रतिनिधिमंडल ने वियतनाम में संयुक्त उद्यम की स्थापना में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में वियतनाम की यात्रा की थी।

इण्डोनेशिया में गांधी स्मारक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता

5153. **श्री मनोहर लाल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया में गांधी स्मारक प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए भारत से वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ख) इण्डोनेशिया में गांधी स्मारक प्रतिष्ठान की मुख्य गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और इस के लिए इण्डोनेशिया की सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए कितनी सहायता किस रूप में दिये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जकार्ता स्थित गांधी मेमोरियल फाउण्डेशन ने, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी, गांधी मेमोरियल इन्स्टीट्यूट की स्थापना के लिए भारत सरकार से सहायता मांगी है जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल होगा और एक अनुसंधान केन्द्र, पुस्तकालय, सभा-भवन, योग एवं प्राकृतिक उपचार केन्द्र आदि भी होंगे।

(ख) अभी तक इस फाउण्डेशन ने कोई कार्य-कलाप नहीं किया है। भारत सरकार को यह बताया गया है कि इण्डोनेशियाई प्राधिकारियों ने इस फाउण्डेशन को कुछ वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है।

(ग) फाउण्डेशन की प्रार्थना अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और इस पर विचार किया जा रहा है ।

विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा

5154. **श्री चतुर्भुज** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जुलाई, 1977 के दूसरे सप्ताह में नेपाल की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो नेपाल सरकार से किन-किन विषयों पर बातचीत हुई; और

(ग) दोनों देशों के बीच मित्रता सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अपनी नेपाल यात्रा के विषय में विदेश मंत्री जी 26 जुलाई, 1977 को एक विस्तृत वक्तव्य दे चुके हैं और इस प्रश्न में जो बात उठाई गई है उसके बारे में उक्त वक्तव्य में बताया जा चुका है ।

Tubectomy and Vasectomy operations during 26th June, 1975—20th March, 1977

5155. SHRI RASEED MASOOD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the State-wise break-up of Vasectomy and Tubectomy operations performed during the 26th June, 1975 and 20th March, 1977; and

(b) what is the amount of expenditure incurred by different States on such operations including the money paid to the motivators?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: (SHRI RAJ NARAIN): (a) A statement giving the required information for the period July, 1975-March, 77 which roughly coincides with the period for which information is required is attached herewith.

(b) The figures of expenditure are maintained on financial year basis and are furnished in the attached statement.

Statement

Number of Vasectomy and Tubectomy operations performed during July, 1975-March, 1977.

Sl. No.	States/U.Ts.	Vasectomy	Tubectomy	Total
1	Andhra Pradesh	595,414	286,359	881,773
2	Assam	324,867	38,230	363,097
3	Bihar	578,816	157,742	736,558
4	Gujarat	284,617	170,558	455,175
5	Haryana	217,709	56,280	276,025*
6	Himachal Pradesh	86,293	30,727	117,020
7	Jammu & Kashmir	12,184	7,640	24,038**
8	Karnataka	252,313	283,838	536,151

* Sex-wise break up of 2,036 cases is not available.

** Sex-wise break up of 4,214 cases is not available.

1	2	3	4	5
9	Kerala	220,776	130,351	351,127
10	Madhya Pradesh	949,831	153,849	1,103,680
11	Maharashtra	862,877	575,162	1,438,039
12	Manipur	6,214	804	7,018
13	Meghalaya	7,419	1,865	9,284
14	Nagaland			..
15	Orissa	220,245	216,016	436,261
16	Punjab.	77,124	111,365	188,489
17	Rajasthan	373,558	69,670	443,228
18	Tamil Nadu.	547,589	265,678	813,267
19	Tripura	15,857	520	16,377
20	Uttar Pradesh	743,794	215,200	958,994
21	West Bengal	839,955	235,844	1,075,799
22	A & N Islands	903	737	1,640
23	Arunachal Pradesh	234	57	291
24	Chandigarh	1,311	2,187	3,498
25	D & N Haveli	823	101	924
26	Delhi	118,960	39,812	158,781
27	Goa, Daman & Diu	1,409	6,420	7,829
28	Lakshadweep	199	4	203
29	Mizoram	86	1,294	1,380
30	Pondicherry	6,715	5,402	12,117
31	M/o Defence	24,677	14,183	38,860
32	M/o Railways	84,563	27,284	111,847
	ALL INDIA	7,457,341	3,105,179	10,568,770 *

* Sex-wise break up of 6,250 cases is not available.

Statement

Details of Expenditure on Compensation for Sterilisation (both Male and Female) and IUD (including payment to motivator) during 1975-76 and 1976-77

(Rs. in lakhs)*

	State	Departmental figure of expenditure on compensation during 1975-76	Provisional payment sanctioned for compensation during 1976-77
1	Andhra Pradesh	88·75	715·90
2	Assam	56·98	221·18
3	Bihar	78·72	603·54
4	Gujarat	84·20	308·44
5	Haryana	30·03	202·56
6	Himachal Pradesh	9·77	94·49
7	Jammu & Kashmir	4·29	10·40
8	Karnataka	79·35	424·70
9	Kerala	67·55	198·44
10	Madhya Pradesh	63·45	947·86
11	Maharashtra	323·62	863·40
12	Manipur	0·37	7·30
13	Meghalaya	0·26	7·73
14	Orissa	64·15	297·38
15	Punjab	31·77	127·55
16	Rajasthan	38·62	350·00
17	Tamil Nadu	229·70	574·31
18	Tripura	1·22	13·31
19	Uttar Pradesh	65·27	705·24
20	West Bengal	110·80	880·56
21	Nagaland		0·05
22	Sikkim	..	0·24
	TOTAL	1428·87	7554·58

*These figures represent the financial assistance provided by Govt. of India to the State Governments for meeting the expenditure on Compensation for Sterilization & IUD including payments to motivators. The figures of actual expenditure are not yet available.

नई दिल्ली के विलिंगडन और सफ़दरजंग अस्पतालों के कर्मचारी

5156. **श्री राम सागर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित विलिंगडन और सफ़दरजंग अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों; ग्रेडों और पदों में कितने कर्मचारी हैं और इन अस्पतालों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या क्रमश: कितनी है ;

(ख) उक्त अस्पतालों में कितने अस्थायी कर्मचारी हैं और उन में से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों के है और अगर अनुसूचित जाति के कुछ अस्थायी कर्मचारी हैं, तो उन्हें कब तक स्थायी बना दिया जाएगा ;

(ग) इन अस्पतालों में विभिन्न पदों पर काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है और क्या इन कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1972 में इन अस्पतालों में की गई पदोन्नतियों और सेलेक्शनों में आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति की गई और क्या उनमें गैर-संवर्गीय कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है और यदि हां, तो इस बारे में पद-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (घ). विलिंगडन अस्पताल के बारे में सूचना 'क', 'ख' और 'ग' विवरणों में और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के बारे में सूचना 'घ' और 'ङ' विवरणों में दी गई हैं, जो सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल-टी-855/77]।

Building of Harnai Post Office in Depoli Taluka in Ratnagiri District

5157. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Post Office at Harnai in Depoli Taluka in Ratnagiri District in Maharashtra is at present housed in a old rented building which is most unsuitable for office purposes;

(b) whether a plot of land was purchased for the construction of departmental Post Office building at Harnai in the year 1970-71 and since then the plot is lying vacant;

(c) whether the Government propose to implement the 'Rural uplift' policy of Government and start costruction of the said post office building; and

(d) if so, when ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Harnai Post Office is housed in an old, but suitable, rented building which has recently been renovated.

(b) Yes, Sir. The plot of land was acquired in 1968.

(c) and (d) It is not possible to take up construction of this building during the Fifth Five Year Plan period due to paucity of funds. It is proposed to take up this work during the Sixth Plan period, subject to availability of funds.

दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन

5158. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या संचार मंत्री 14 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1977 तक दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक टेलीफोन

एक्सचेंज में ओ० वाई० टी० सामान्य और विशेष—तीनों श्रेणियों में पृथक-पृथक कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे; और

(ङ) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के अधीन पृथक्-पृथक् प्रत्येक श्रेणी में श्रेणीवार चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख). यह सूचना विवरण में दे दी गई है ।

दिए जाने वाले टेलीफोनों का श्रेणीवार ब्यौरा नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणी के अन्तर्गत कितनी अर्जियां प्राप्त होंगी । उपलब्ध कनेक्शनों में से 75 प्रतिशत कनेक्शन ओ० वाई० टी श्रेणी में और 10 प्रतिशत कनेक्शन विशेष श्रेणी में अलाट किए जाते हैं ।

31 मई, 1977 को दिल्ली में एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची और वर्ष 1977–78 की बाकी अवधि के दौरान दिए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन कनेक्शनों की श्रेणीवार संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण-पत्र —

31–5–77 को प्रतीक्षा सूची—

क्रम सं०		ओ-वाई-टी श्रेणी	विशेष श्रेणी	सामान्य श्रेणी	वर्ष 1977-78 की बाकी अवधि के दौरान दिए जाने वाले संभावित कनेक्शनों की अनुमानित संख्या
1		2	3	4	5
1	शाहदरा पूर्वी (2)	10	12	172	100
2	शाहदरा (2)	215	611	2334	500
3	तीस हजारी (32)	662	389	3286	650
4	शक्तिनगर (24)	416	315	640	550
5	दिल्ली गेट (26'27)	—	38	1604	250
6	सचिवालय (37)	42	1	14	600
7	राजपथ (38)	188	12	96	450
8	कंटोनमेंट (39)	205	365	1134	200
9	करौलबाग (56'58)	1459	2481	8671	2300

1	2	3	4	5	6
10	जोरबाग (61/62 69)	1133	1152	3393	3700
11	ओखला (63)	728	467	1670	2000
12	चाणक्यपुरी (67)	11	184	678	350
13	हौजखास (65)	41	141	549	1200
14	नरेला (89)	—	—	—	इस समय कोई मांग नहीं है
15	नजफगढ़ (86)	—	—	—	इन एक्सचेंजों में क्षमता
16	जनपथ (31/32 34)	1	—	8	उपलब्ध नहीं होगी ।
17	कनाट प्लेस (4)	24	1	64	तथापि, यदि टेलीफोनों
18	ईदगाह (51 52)	—	478	3202	के बन्द होने / स्थाना-
19	अलीपुर (801)	1	3	13	न्तरण के फलस्वरूप कुछ
20	फरीदाबाद (81)	46	36	710	क्षमता खाली हुई तो
21	बदरपुर (82)	13	33	45	कुछ कनेक्शन दिए
22	बहादुरगढ़ (83)	3	38	55	जा सकेंगे ।
23	गाजियाबाद (85)	55	278	953	
24	नांगलोई (87)	6	7	18	
25	बल्लभगढ़ (88)	69	97	245	
26	बादली (802)	2	34	63	
27	जनकपुरी (803)	81	96	947	

टिप्पणी : जिन कनेक्शनों के दिए जाने की संभावना है, वे क्रासबार एक्सचेंजों के 60 प्रतिशत के प्रारम्भिक लोडिंग के आधार पर हैं। एक्सचेंजों के स्थायी होने जाने के बाद धीरे-धीरे और अधिक कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ।

Manufacture of Spurious Himacycline Capsules by HIMCO Laboratories Sonepat (Haryana)

5159. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether in 1973 a case of spurious Himacycline Capsules of M/s. HIMCO Laboratories, Sonepat (Haryana) was reported by the Zonal Officer of the Central Drug Standard Control Organisation to the Drugs Controller, Haryana for investigation and necessary action ;

(b) the result of the investigation ; and

(c) the names of the owners of the concern and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) The Drugs Controller (India) had referred a case of spurious Himacycline Capsules allegedly manufactured by M/s Himco Laboratories, Sonepat Haryana to the Drugs Controller, Haryana for investigation and necessary action.

(b) and (c) The case of spurious Himacycline Capsules related to a sample

of the product drawn by the Drugs Inspector, Hyderabad, Andhra Pradesh from the premises of a dealer in Hyderabad which was found to contain Oxytetracycline hydrochloride and not Tetracycline hydrochloride as labelled. The case was investigated by the Drugs Controller, Haryana. His investigations revealed that the pr duct manufactured by M/s Himco Laboratories, Sonepat, Haryana and pertaining to the same batch as that of the spurious drug was of standard quality i.e. it contained Oxytetracycline Hydrochloride as labelled. Further, it was found that the manufacturer had not made any supplies of this batch to any dealer in Hyderabad.

Further investigations regarding the sale of the spurious drug by the dealer in Hyderabad are in progress.

The owners of M/s Himco Laboratories, Sonepat, Haryana in 1973 were Shri Chaman Lal Bansal and Shri Ravi Prakash.

पट्टे पर देने के लिये बिहार की प्रस्तावित खानें

5160. **श्री राम देनी राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने चूना पत्थर, लोह अयस्क, बाक्साइट और लेटराइट की कितनी खानों का पट्टा देने के प्रस्तावों की सिफारिश की है और जो केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त प्रस्तावों में पट्टा देने और उन्हें शीघ्र वापस भेजने का है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) चूना पत्थर, लोह अयस्क और बाक्साइट के लिए पट्टों की मंजूरी के बारे में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 14 प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। लेटराइट के लिए पट्टे की मंजूरी के बारे में राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) : केन्द्र सरकार प्रस्तावों की जांच कर रही है और उन पर शीघ्र निर्णय हो जाने की आशा है।

पोरबन्दर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

5161. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने पोरबन्दर (गुजरात) में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के बारे में सरकार को कई अभ्यावेदन भेजे हैं और यदि हां, तो कब और किस प्रकार के अभ्यावेदन भेजे गये हैं ;

(ख) उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा अब किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पोरबन्दर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का काम कब शुरू होगा और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (ग) : पोरबन्दर चैंबर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज की ओर से सरकार के पास ऐसे अभ्यावेदन आये हैं, जिनमें उन्होंने पोरबन्दर के मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों को शीघ्र आटोमेटिक एक्सचेंज में बदलने के बारें में जोर दिया है। आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्करों की समूची उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए बड़े मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजों में बदलने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। आशा है कि पोरबन्दर के लिए उपयुक्त उपस्कर की व्यवस्था छठी योजना के दौरान की जा सकेगी। इस इमारत का निर्माण कार्य इस प्रकार शुरू किया जायेगा कि उपस्कर उपलब्ध होने तक यह इमारत तैयार हो जाय।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों को भुगतान

5162. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के चुनाव (1977) से दो मास पूर्व हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, शेक्सपियर सामी, कलकत्ता द्वारा स्थानीय ठेकेदारों को विशाल धनराशि का भुगतान किया गया था ताकि या यह धनराशि तत्कालीन सतारूढ़ दल को मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का भुगतान किया गया था और उसका क्या औचित्य है और इन भुगतानों के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है; और

(ग) क्या उसी अवधि के दौरान धनराशि की कमी के आधार पर छोटे ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया था ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी; नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

Shifting of Chasnala Mine Statutory seized Plan to New Delhi

5163. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is true that after Chasnala mine accident on 27-12-75, Shri K. V. Raghunatha Reddy and his Ministry officials had shifted one Chasnala mine important statutory seized plan to New Delhi;

(b) whether it is also true that this plan was sent to Chasnala accident Inquiry Officer at Dhanbad directly from New Delhi after over a month;

(c) whether this plan was found to show in pencil by dotted line the unknown channel which caused the accident and court of inquiry had not accepted those pencil lines existed on the plan before the accident on 27-12-75; and

(d) who got these lines marked and got tampered with the evidence and seized record and what role Shri Reddy played in this?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) A plan seized by the officials of Directorate General of Mines Safety from the Central Survey Office at Chasnala on the night of the accident at Chasnala Mine on 27-12-1975 was handed over by the Director of Mines Safety and Inquiry Officer of D.G.M.S. to a senior officer of the Ministry on the 2nd January, 76 for safe custody and for being passed on to the Court of inquiry at the appropriate time.

(b) The plan was passed on to the Court of Inquiry on the 21st February, 1976 direct from New Delhi.

(c) and (d). There were faint dotted lines in pencil on the seized plan. However, the Court of Inquiry appointed to enquire into the causes of and circumstances attending the accident which occurred at Chasnala Colliery on the 27th December, 1975 has not made any comments as to when or by whom the dotted lines were marked on the plan.

Role Played by Indian Embassy in U.S.A.

5164. SHRI K. N. DASGUPTA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what have been the main activities of the Indian Embassy in U.S.A., during the last three years, to project the image of India;

(b) apart from the routine work like distribution of pamphlets and brochures organising exhibitions, etc., what directives were given by the Head of the Mission to his Foreign Service Personnel who are highly talented to bring about better understanding between two countries; and

(c) do we have an annual account of the activities of our Embassy in U.S.A.?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): (a) The Embassy has been continuously in touch with the U.S. Administration, Senate and Congress, academic institutions, journalists and the general public. The Embassy brings out a weekly 4-page newspaper called "India News" which is distributed to 38,000 addresses in the United States. The officers of the Embassy participate in seminars and propagate Indias' views on current issues of common interest.

(b) The standing directive followed in the Embassy under the guidance of the Ambassador is to interact in a mutually beneficial manner with all organisations, and American organisations in particular, to bring about better understanding of India, its achievements and aspirations. A notable effort was the production of a special volume on Indo-US interaction entitled "The United States and India 1776-1976" to commemorate the American Bicentennial last year.

(c) Annual reports are received, as prescribed by the Ministry, covering political, economic, commercial and consular activities in the Embassy, apart from special reports on matters of specific interest.

स्वदेशी काटन मिल्स में श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के साथ किए गए अत्याचार

5165. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुरिया उद्योग के स्वदेशी काटन मिल्स के सभी एककों में श्रमिक संघों के पदाधिकारियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं और श्रमिकों को सेवा से हटाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों की इस श्रम विरोधी नीति के बारे में सरकार द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) . वस्तुत: यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया है। यदि संगत ब्योरों सहित विशिष्ठ मामले ध्यान में लाए जाते हैं, तो उन्हें भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया जा सकता है।

इस्पात का निर्यात

5166. **श्री मोहन जैन :**

श्री सुभाष आहूजा :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि ।

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने 1975-76 और 1976-77 के दौरान किन-किन देशों को तथा कितना इस्पात अलग-अलग निर्यात किया तथा उन्हें किस दर पर निर्यात किया गया ;

(ख) आयातक देशों ने निर्यातित इस्पात का कितना भाग रद्द कर दिया ;

(ग) रद्द किया गया इस्पात बाद में किस दर पर बेचा गया ;

(घ) क्या इस इस्पात को निर्यात करने के लिए कमीशन एजेंटों की सहायता ली गई थी अथवा क्या इसको सीधे निर्यात किया गया; और

(ङ) कमीशन के रूप में कितनी राशि दी गई तथा इस्पात रद्द होने के कारण कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) एक विवरण तैयार किया जा रहा है और जब जानकारी प्राप्त हो जायगी तो इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) आयात करने वाले देशों ने निर्यात किये गये इस्पात के किसी भाग को अस्वीकार नहीं किया था ।

(ग) से (ङ). ऊपर दिये गये भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के विलिंग्डन अस्पताल में रोगियों की संख्या में वृद्धि

5167. **डा० महादीपक सिंह शाक्य**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में रोगियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है और इसके कारण डाक्टरों को अपना कार्य करने में असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो वहां वर्ष 1974 से अब तक रोगियों और डाक्टरों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) . जी हां । रोगियों की सख्या बढ़ गई है ।

(ख) 1974 से लेकर रोगियों तथा डाक्टरों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	अन्तरंग रोगी	बहिरंग रोगी	मेडिकल स्टाफ
1974 .	30,630	55,696	203
1975 . . .	36,930	84,334	203
1976 . . .	37,077	97,382	203
1977 . . (जून तक)	20,211	41,711	203

Charging of Capitation Fees by Medical Colleges in Bihar

5168. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of medical colleges in Bihar and the number of students studying there;

(b) whether all the medical colleges have been recognised by Medical Council of India;

(c) how many colleges, name-wise, out of the colleges recognised by the Medical Council have been charging capitation fees from the students;

(d) whether some of such colleges have been denying admission to the students after charing capitation, fees; and

(e) if so, the action taken by the Government?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) There are 9 Medical Colleges in Bihar with total admission capacity of 949.

(b) No.

(c) Out of the 4 Medical Colleges recognised by the Medical Council of India, namely,

1. Darbhanga Medical College, Laheriasrai;
2. Patna Medical College, Patna;
3. Rajendra Medical College, Ranchi;
4. M. G. M. Medical College, Jamshedpur.

only the M.G.M. Medical College has been charging capitation fees from the students.

(d) No such allegation regarding denial of admission to the students after charging capitation fees has come to the notice of the Government.

(d) Does not arise.

प्रोग्रेसिव प्रोवीडेंट फण्ड स्टाफ यूनियन

5169. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि कार्यालय, कानपुर में कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से प्रोग्रेसिव प्रोवीडेंट फण्ड स्टाफ यूनियन नामक एक जाली यूनियन कार्य कर रही है जिसके कारण उक्त यूनियन के पदाधिकारी कार्यालय का वातावरण बिगाड़ रहे हैं तथा जातिवाद का विष घोल रहे हैं; और

(ख) क्या उपर्युक्त यूनियन के पदाधिकारी अपने मासिक वेतन से अधिक राशि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में लेते हैं तथा यह यूनियन उन्हीं अनियमितताओं को छुपाने के लिए बनाई गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) प्रोग्रेसिव प्रोवीडेण्ट फण्ड इम्प्लाईज यूनियन, उत्तर प्रदेश के नाम से एक यूनियन भविष्य निधि कार्यालय, उत्तर प्रदेश में 6 जून, 1977 को बनाई गई । लेकिन इसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने इन्कार किया है ।

(ख) उपर्युक्त यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा दावा की गई चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघर खोलने की योजना

5170. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के आदिवासी क्षेत्रों, विशेष रूप से, जनजातीय विकास खण्डों में टेलीफोन एक्सचेंज तथा डाकघर खोलने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण पटल सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आदिवासी क्षेत्र में वर्ष 1977–78 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों और डाकघरों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1	आन्ध्र	कोई नहीं	20
2	असम	2	50
3	बिहार	कोई नहीं	53
4	गुजरात	9	43
5	हरियाणा	कोई नहीं	कोई नहीं
6	हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं	7
7	जम्मू कश्मीर	कोई नहीं	कोई नहीं
8	कर्नाटक	कोई नहीं	कोई नहीं
9	केरल	4	8
10	मध्य प्रदेश	4	308
11	महाराष्ट्र	कोई नहीं	20
12	मणिपुर	3	13
13	मेघालय	7	16
14	नागालैण्ड	1	13
15	उड़ीसा	2	89
16	पंजाब	कोई नहीं	कोई नहीं
17	राजस्थान	2	20
18	सिक्किम	कोई नहीं	कोई नहीं
19	तमिलनाडु	कोई नहीं	56
20	त्रिपुरा	2	24
21	उत्तर प्रदेश	कोई नहीं	15
22	पश्चिम बंगाल	2	—

1	2	3	4
संघ शासित क्षेत्र			
1	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह .	कोई नहीं	11
2	अरुणाचल . . .	4	22
3	चंडीगढ़ . . .	कोई नहीं	कोई नहीं
4	दादर नगर हवेली . .	कोई नहीं	कोई नहीं
5	दिल्ली . . .	कोई नहीं	कोई नहीं
6	गोआ दमण दिऊ . .	कोई नहीं	कोई नहीं
7	लक्षद्वीप . . .	कोई नहीं	कोई नहीं
8	मिजोरम . . .	2	8
9	पांडिचेरी . . .	कोई नहीं	कोई नहीं
	योग	44	777

Telephone Exchanges and Public Call Offices in Sangli

5171. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the broad details of the proposed programme of :—

1. the expansion and/or conversion of various telephone exchanges,
2. installation of Telex exchanges,
3. opening of long distance public call offices,
4. new exchanges, and
5. combined offices

during the current year in the jurisdiction of the Divisional Engineer Telegraphs, Sangli, Maharashtra State; and

(b) the steps taken to ensure that the said programme does not suffer for want of requisite stores?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) The following is the programme for providing telecom. facilities in Sangli Engineering Division of Maharashtra Circle during 1977-78:

1. Expansion of nine telephone exchanges increasing the capacity by 660 lines.
2. Nil.
3. Four long distance Public Call Offices.
4. One small automatic exchange of 25 lines capacity.
5. Seven combined offices.

(b) Necessary steps are being taken to arrange stores for the above programme.

N.M.D.C. Laboratory at Hyderabad

5172. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether National Minerals Development Corporation Limited is constructing its own Office and Laboratory building at Hyderabad;

(b) if so, total estimated expenditure;

(c) whether N.M.D.C. Limited has paid huge advance to the extent of Rs. 15 lakhs to Rs. 20 lakhs to one contractor for this purpose who is related to the present Managing Director;

(d) details of the estimates, buildings and advances paid to the contractor; and

(e) whether the building will be on lease from this contractor or N.M.D.C. property ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) to (e). The National Mineral Development Corporation is constructing a building in Hyderabad for their R & D Laboratory at an estimated cost of Rs. 26.75 lakhs, including cost of land. This building will be N.M.D.C.'s property.

The N.M.D.C. have also entered into an agreement for hiring of office accommodation of approximately 48,000 sq. ft. of floor area on lease basis in a new building to be constructed for the purpose by M/s. Pioneer Commercial Enterprises. In terms of the agreement, N.M.D.C. are to make an advance of Rs. 16 lakhs, bearing interest at N.M.D.C.'s rate of borrowing from Banks. This building is expected to be ready by October, 1977 and an amount of Rs. 15.4 lakhs has already been advanced.

The contractor/lessor for these buildings are not related to the present Managing Director of N.M.D.C.

Price of Corrugated Iron Sheets

5173. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the prices of corrugated iron sheets, mostly used for roofing in the North Eastern Region are exorbitantly high; and

(b) if so, steps Government propose to take to bring down the prices of such sheets ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir. While the producers' prices are fixed, due to larger demand, market prices have gone up all over the country including in the North Eastern Region.

(b) Government is endeavouring to maximise production in Rourkela Steel Plant. SAIL have already taken steps to despatch larger tonnages to meet seasonal needs of North Eastern Region.

Flights by U.S.A. over Indian Ocean

5174. SHRI DINEN BHATTACHARYYA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the recent moves of flights on the Indian Ocean by the USA which is causing concern for peace; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) U.S. aircraft like aircraft of other countries have been flying over the Indian Ocean for many years and the Government is not aware of any recent development in this regard which should cause us concern.

(b) Does not arise.

Settlement of Sino-Indian Border Dispute

5175. SHRI P. K. KODIYAN : Will the MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Chinese Foreign Minister has said that the border issue between India and China can be settled through peaceful negotiations ;

(b) if so, whether Government propose to take any initiative in this direction and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Government's attention has been drawn to a news report in which it had been reported that the Vice Foreign Minister of China Yu Chan, during the course of an interview with an Indian journalist in Peking stated that the border issue between India and China can be settled through peaceful negotiations.

(b) If there are any initiatives to solve outstanding problems between India and China, including the border question, India will be prepared to examine these consistent with the Five Principles and India's honour and dignity. The position of India on the border question is well known.

(c) Does not arise.

Shortage of Medicines and Accommodation in Malviya Nagar C.G.H.S. Dispensary

5176. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether prescribed medicines are never available in CGHS Dispensaries in Delhi especially in Malviya Nagar Dispensary ;

(b) whether there is no proper accommodation available for the said dispensary ; and

(c) if so, the steps Government propose to take in the matter to avoid the unnecessary harassment to a large number of patients ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) : No, Sir.

(b) and (c). The C.G.H.S. dispensary Malviya Nagar is housed in a old rented building and the space therein is insufficient to cope with the increase in the number of beneficiaries. Efforts are being made to obtain suitable alternative accommodation.

Revision of Minimum Wages

5177. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the minimum wages prevailing in various industries and States have not been revised since long ,

(b) if so, whether Government would consider directing the State Governments to revise the minimum wages for unskilled labours engaged in organised and unorganised sector like Agriculture suitably to safeguard the interest of the workers ;

(c) whether the existing arrangement for ensuring payment of minimum wages by the employers to the workers is grossly inadequate to ensure effective implementation of the Minimum Wages Act ; and

(d) if so, what effective steps are being taken to safeguard the interest of workers ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b). The matter predominantly falls in the State sphere. However, the State Governments have been advised from time to time to revise minimum wages in their sphere. Almost all the State Governments have revised minimum wages for agricultural workers. As far as the Central sphere is concerned minimum wages have been revised during 1976 in all mining employments added to the schedule, and also in agriculture.

(c) and (d). The minimum Wages Act, 1948 contain necessary provisions for the implementation and enforcement of the Act. Further, State Governments have been advised from time to time to take steps for effective implementation of the notified minimum wages.

पटना में कैंसर संस्थान की स्थापना किया जाना

5178. **श्री युवराज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कैंसर अस्पताल में 150 कैंसर रोगियों का होना ध्यान में रखते हुए सरकार पटना में कैंसर संस्थान की स्थापना की आवश्यकता महसूस करती है; और

(ख) यदि हां, तो संस्थान कब तक स्थापित किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Analysis of Samples of Foodstuffs by Central Food Laboratory, Delhi

5180. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) how many samples of foodstuffs the Central Food Laboratory in Delhi undertakes analysis monthly ; and

(b) the findings and the improvements therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) There is no Central Food Laboratory in Delhi.

(b) Does not arise.

Increase in Seats in Medical Colleges of Bihar

5181. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the State Government of Bihar have asked for Central Government's permission to increase the seats in the medical colleges in the State ; and

(b) if so, the reaction of the Government thereon ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

बिहार मे श्रमिकों की मांगें

5182. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार यात्रा के दौरान वह कुछ श्रमिकों से मिले थे और उन्होंने उनकी मांगों के बारे में उनके साथ बातचीत की थी और कुछ निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सार क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). केन्द्रीय श्रम मंत्री के दौरों के दौरान कुछ श्रमिक या उनकी यूनियन के प्रतिनिधि उनसे मिलते रहे हैं और अपनी शिकायतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते रहे हैं । ऐसी शिकायतों पर यथास्थिति केन्द्र या राज्य में सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

Gold deposits in Nilamboor, Kerala

5183. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Geological Survey of India is conducting survey to find out the quality and quantity of gold ore deposits in Nilamboor, Kerala ;

(b) whether they are conducting survey to find out the quantity of mineral deposits on the beach of Kerala near Chavara ;

(c) if so, the findings thereof ; and

(d) whether Government have taken up any scheme for the exploitation of these deposits ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) No survey is being presently conducted by Geological Survey of India for Gold in the Nilamboor area of Kerala. During 1964-65 the Geological Survey of India estimated 69,590 ounces of Gold as the possible reserve from gravel and river sands in Nilamboor Valley.

(b) GSI is not doing any survey at Chavara.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिये भवनों का खरीदा जाना

5184. **श्री भागीरथ भवर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के भवनों को क्रय करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी देश-वार ब्यौरा क्या हैं और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ख) ऐसे देश कितने हैं जहां इस समय भारतीय दूतावासों के निजी भवन हैं ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां भवनों का निर्माण करने या क्रय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) विदेशों में कार्यालय और आवास के लिए भवन खरीदना/का निर्माण करना भारत सरकार की नीति है जो वित्तीय साधनों की उपलब्धि और प्रत्येक कार्य की आर्थिक सम्भाव्यता पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) . अपेक्षित सूचना दो विवरणों में दी गयी है, जो सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिय संख्या LT—856/77.]

विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये रक्षित पदों का भरा जाना

5185. **श्री राम विलास पासवान :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : समूह (क), (ख) और (ग) में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सीधी भर्ती के मामले में क्रमश: 15 और 7½ प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। ये आरक्षण समूह (क), (ख) और (ग) में पदोन्नतियों पर भी लागू होते हैं। अगर अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध न हो सकते हों तो जितनी भी शेष रिक्तियां होती हैं वे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नियमों के अनुसार, जो समूचे भारत सरकार पर लागू होते हैं, आगे ले जायी जाती हैं।

Ferro-Manganese Plant

5186. SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Manganese Ore India Ltd. has requested for licence for setting up ferro-manganese plant ;

(b) if so, when the request was received and the decision taken in the matter, so far; and

(c) the hindrances, if any, for giving licence to this Company to set up ferro-manganese plant ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) to (c). Manganese Ore India Limited has submitted an application to the Ministry of Industrial Development on 25-7-1977 for the issue of an Industrial licence for production of ferro manganese. The application will be examined on merits.

Visit to Saudi Arabia for Haj

5187. SHRI AHMED M. PATEL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons who visited Saudi Arabia for Haj during the last three years *i.e.* 1974-75, 1975-76 and 1976-77; and

(b) the number of persons who applied for passports during the current year ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) The quota for pilgrims proceeding to Saudi Arabia for HAJ, as a result of lottery, by Mogul Line sailings and Haj Air Charters, on Pilgrim Passes for the years December-1974, 1975 and 1976 was 19,000, 17,000, and 17,500 respectively. However, the actual number of pilgrims who may have proceeded to Saudi Arabia for Haj on International Passports also would make the figures given above slightly higher. According to figures received from our Embassy in Jeddah these are 21,874, 18,863 and 17,510 respectively for the above years.

(b) The number of persons who have applied to the Haj Committee for current HAJ by Mogul Line sailings only has been placed at 21,831. This does not include applications for seats by HAJ Air Charters as these are announced later. The quota for current HAJ has been raised to 18,000.

Bokaro Steel Cold Rolling Mill Complex

5188. SHRI S. KUNDU : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether discussion was held with U.S.S.R. Government for a turn-key project for preparing design and construction of Cold Rolling Mill Complex at Bokaro Steel Limited;

(b) whether the talks broke down as the U.S.S.R. did not agree to the lowering of price of per tonne of equipment suggested by the Indian delegation;

(c) if so, facts thereof, *i.e.* when the talks were held, the prices suggested by both sides, other terms and conditions;

(d) whether the Bokaro Steel Ltd. has signed an agreement with MECON and Engineering Projects India and some firm in the U.S.A. for design and construction of the same cold rolling mill complex at Bokaro; and

(e) if so, whether the subsequent agreement with the MECON and EPI and with some firms in the U.S.A. will cost more than that it would have cost if the agreement was signed with U.S.S.R. and therefore whether the latter agreement is in the best interest of India, if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) No, Sir. Discussions were however, held this year with the representatives of the Soviet organisation V/o Tiajpromexport on price to be paid for supply of equipment of the main technological lines of the Cold Rolling Mill Complex (4MT stage) of Bokaro Steel Limited.

(b) No, Sir. At the negotiations held in January, 1977, the difference in the prices quoted by the Soviet and Indian sides was narrowed down considerably. Further talks were to be held in Moscow but in the meantime a decision was taken to entrust the job of setting up the Cold Rolling Mill Complex to Indian Organisation.

(c) The talks were held in January, 1977. The price finally quoted by the Soviet side was 3,000 roubles per tonne FOB, while the Indian side had offered the price of 2,750 roubles per tonne FOB. The Soviet side had also said that CIF price will be calculated by adding 13 1/2% to FOB price whereas the Indian side had offered to pay the actual expenditure on freight and insurance or what was agreed upon in the case of Bhilai Plate Mill *i.e.* 290 roubles per tonne.

(d) Bokaro Steel Limited has issued letters of intent to MECON and EPI for design, engineering and supply of equipment for the Cold Rolling Mill Complex. It has not signed any agreement with any firm in the U.S.A. in this behalf but both MECON and EPI have licence agreements with Weam United of USA for rolling Mills and processing lines respectively.

(e) No, Sir. Under the new arrangement Bokaro Steel Limtied will not be paying more than they would have paid if the project were to be completed with Soviet collaboration. The charge is indoubtedly in the best interest of India. The entrusting of the job to the Indian organisations will not only create a wide technical base but also lead to much greater self-reliance in an area of highly sophisticated techo-

logy in the steel sector. Indian organisations and Indian engineers will get an opportunity of setting up a sophisticated mill which they would not have otherwise got for many years. The options to use the best technology available are also now open to them.

रक्त दाताओं द्वारा रक्त में मिलावट

5189. **श्री मीठा लाल पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की जानकारी अथवा कोई शिकायत मिली है कि व्यावसायिक रक्त दाता जो देश के विभिन्न भागों में अस्पतालों को रक्त बेचते हैं रक्त में भी मिलावट करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा मिलावटी रक्त बेचने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Geological Survey of Salem District

5190. SHRI R. KOLANTHAIVELU : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether geological survey of Salem District in Tamil Nadu has revealed existence of minerals other than iron; and

(b) if so, the nature of minerals found the estimated reserves and the arrangements proposed for detailed prospecting?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Yes, Sir.

(b) The minerals found as a result of these surveys and their approximate reserves in million tonnes are as follows :

(a) Magnesite (43·0)

(b) Bauxite (8·0)

(c) Limestone (50·0)

(d) Chromite (0·2)

(e) Quartz (3·0)

(f) Felspar (1·0)

(g) Steatite (0·06)

Detailed survey of Bauxite has been completed. Investigations for Chromite and Magnesite are being taken up.

Problem of Unemployed Medical Graduates

5191. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether according to a recent study conducted by the Medical Council of India, there will be at least 14,000 unemployed doctors by 1980.

(b) if so, what are the facts thereof; and

(c) what action, if any, is proposed to be taken to meet this challenge ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The Medical Council of India has not conducted any study regarding the possible number of unemployed doctors in the country.

(b) and (c) : Does not arise.

Jobs to Technical Trainees

5192. SHRI ROBIN SEN : Will the MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether he is aware of the fact that trainees in different technical schools after completion of their training period remain unemployed; and

(b) if so, what steps Government propose to take to secure them employment in different industries ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b). Government is aware of the seriousness of the unemployment problem amongst trained technical personnel and proposes to follow an employment oriented strategy during the 6th Five Year

Plan. The Planning Commission will propose concrete policies and programmes in due course for tackling the problems of unemployment including those of educated and technical personnel in consultation with the appropriate agencies.

Location of Indian Satellite for Communications

5193. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the MINISTER OF COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) Whether there is any proposal under the consideration with other countries on the location of the proposed Indian Satellite for Communications ; and

(b) If so, the names of such countries which have extended their co-operation in this regard ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Yes.

(b) The location has been co-ordinated with USSR and the International Satellite Organisation, INTELSAT (USA). Dialogue is underway with Indonesia.

Minimum Wages for Workers

5194. SHRI A. MURUGESAN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased, to state :

(a) the position regarding determination of minimum wages for agricultural labour and labour, in agro-industries, cottage industries animal husbandry, poultry sheep trading, fisheries; and

(b) the period by which a comprehensive and firm policy in this regard can be expected ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b). The Minimum Wages Act, 1948 provides for the fixation as well as revision of minimum rates of wages in various employments, including those in agriculture, contained in or added to the Schedule to that Act.

Mosquitoes in Calcutta

5195. DR. SARADISH ROY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that due to the existence of large-scale cattle-Sheds (Khatals) and canals like morass in Calcutta, the breeding of mosquitoes is rampant; and

(b) if so, the steps taken to use the chemicals to kill mosquitoes ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) Yes.

(b) Mosquito larvicidal oil and other chemical larvicides have been supplied by the Government of India, to Calcutta Municipal Corporation for carrying out anti-larval operations under National Malaria Eradication Programme (Urban).

Extension of C.G.H.S. Facilities

5196. SHRI BIJOY KUMAR MONDAL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the reasons that the C.G.H.S. facilities are not being extended anywhere else excepting a few cities;

(b) the defects, drawbacks, or short comings in the working of scheme even in such places where it has been in existence for many years;

(c) whether the structure of the scheme is being or likely to be re-examined with a view to make it broad-based and applicable to places and towns not covered so far; and

(d) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) Cities having a concentration of 7,500 or more Central Government employees are considerd for being brought within the purview of C.G.H.S. subject to availability of resources, accommodation etc.

(b) While there is always a scope for improvement which is the constant endavour of the Govt., no particular defects or shortcomings in the working of the scheme have come to notice.

(c) and (d). There is no proposal for a review of the structure of the scheme. However, the question of extending the scheme to additional areas is reviewed from time to time.

1975–76 में महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण

5197. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975–76 में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ख) इस पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च होती है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). कुछ नहीं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान मई, 1977 में ही प्रारम्भ हुआ है।

Malangtoli Iron Ore feasibility Oxtoss

5198. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether an amount of Rs. 10,000/- was defalcated from Malangtoli Iron Ore Feasibility (Oxtoss) sometimes in January/March,1975 (a unit of N.M.D.C. Ltd., a Subsidiary of S.A.I.L.);

(b) how the Corporation has accounted for the defalcated amount in their Balance Sheet for the year 1974-75;

(c) steps taken by the Corporation to make good the amount from the defaulter; and

(d) a copy of the Balance Sheet for the year 1974-75 may be placed on the Table of the House?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.

(b) The amount was shown under the head 'Loans and Advances' in the Balance Sheet of N.M.D.C. as at 31st March, 1975.

(c) The Corporation is holding an amount of about Rs. 10,000 on account of the Provident Fund and other dues of the defaulter, whose services have been terminated.

(d) the Annual Report of 1974-75 of steel Authority of India Limited, incorporating *inter-alia*, the Balance Sheet of N.M.D.C. has already been laid on the Table of the Lok Sabha on 29-4-1976.

आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

5199. **श्री राघव जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार, कितनी जनसंख्या पर एक डाक्टर है ; और

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) 1–1–1975 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या पर एक डाक्टर है उसका राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) इस मामले पर 15 से 17 अप्रैल, 1976 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की तीसरी संयुक्त बैठक में विचार विमर्श किया गया था। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अधिकतम 50,000 जनसंख्या के लिए एक उप केन्द्र खोला जाए।

इस संकल्प के अनुसार इस मामले में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी कि वे आदिवासियों संबंधी उप योजनाओं को तैयार करते समय इस सुझाव को शामिल कर लें और आदिवासी

पर्वतीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मंजूरी देने के कार्य को प्राथमिकता दें। आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करने के मामले पर भारत सरकार विचार कर रही है।

विवरण

1-1-1975 को राज्यवार कितनी जनसंख्या पर एक डाक्टर है

राज्य संघ शासित क्षेत्र	कितनी जनसंख्या पर एक डाक्टर है (1-1-1975)
1. आंध्र प्रदेश	1:4425
2. असम	1:2790
3. बिहार	1:5975
4. गुजरात	1:5627
5. हरियाणा	1:6088
6. हिमाचल प्रदेश	1:6468
7. जम्मू व कश्मीर	1:5456
8. कर्नाटक	1:4836
9. केरल	1:5369
10. मध्य प्रदेश	1:10656
11. महाराष्ट्र	1:2941
12. मणिपुर	1:6964
13. मेघालय	1:7955
14. नागालैंड	1:5912
15. उड़ीसा	1:7989
16. पंजाब	1:2804
17. राजस्थान	1:9003
18. सिक्किम	1:8400
19. तमिलनाडु	1:2186
20. त्रिपुरा	1:7318
21. उत्तर प्रदेश	1:8234
22. पश्चिम बंगाल	1:1954
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1:2440
24. अरुणाचल प्रदेश	1:3067
25. चंडीगढ़	1:631
26. दादर और नागर हवेली	1:11286
27. दिल्ली	1:1323
28. गोवा, दमण और दीव	1:1425
29. लक्षद्वीप	1:2615
30. मिजोरम	असम में शामिल
31. पांडिचेरी	1:1580
भारत जोड़	1:4200

Project for linking Ganga with Brahmaputra

5200. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether during the meeting between the Prime Minister of India and the President of Bangladesh, the former suggested to the later for adoption of joint project for linking the Ganga with the Brahmaputra;

(b) whether such project was suggested for effectively dealing with the issue of supply of water through Ganga and Padma from the point of Farakka to the satisfaction of both West Bengal and Bangladesh;

(c) whether such project would have helped to tackle flood problems of Assam and Bangladesh as well; and

(d) if so, the reaction of the Government of Bangladesh thereabout and the reasons advanced therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): (a) to (d): The Prime Minister of India had discussions about bilateral and regional matters with the President of Bangladesh during their meeting in London at the time of the last Commonwealth Prime Ministers' Conference. The Government of India have all along been interested in the techno-economic studies of all the proposals for solving the long-term problem of augmenting the flow of the Ganga near Farakka and for achieving other important purposes such as flood control, power generation, irrigation, etc., in both the countries. This subject is an important element of the official level negotiations that are at present going on between the two countries.

सेवा से हटाए गए राजनीतिक बन्दियों के सम्बन्धी

5201. **श्री राम नरेश कुशवाह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीतिक बन्दियों के कितने सम्बन्धियों को सरकारी उपक्रमों में से नौकरी से निकाला गया ;

(ख) इस प्रकार निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी

5202. **श्री उग्रसेन** :

श्री मनोहर लाल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान देने के बारे में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त कार्य पर कितना आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय होगा, उक्त प्रयोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं कितनी धनराशि की सहायता देगा और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इस बारे में कोई पत्र व्यवहार हुआ है ; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). अनुमान यह लगाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में किसी भी अतिरिक्त भाषा की वहां की प्राधिकारिक भाषा बनाने के लिए लगभग 90 लाख रुपए का अनावर्ती व्यय आएगा । भाषान्तर और अनुवाद कार्य पर पहले वर्ष अनुमानतः 3.37 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होगा और इसके 7.5 प्रतिशत वार्षिक मुद्रा-स्फीति की दर से बढ़ते जाने की संभावना है । खर्च के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र में किसी भी अतिरिक्त भाषा को वहां की प्राधिकारिक भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीकारात्मक निर्णय की अपेक्षा होती है । इस बात का निर्णय करना संयुक्त राष्ट्र का काम है कि इस खर्च का कोई अंश वह संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से दे या नहीं ।

सरकार ने इस प्रस्ताव की सम्भाव्यता पर संयुक्त राष्ट्र के बजट और क्रियाविधि संबंधी दृष्टिकोणों से विचार किया है । इस दिशा में

आगे क्या कार्यवाही की जाए इसका निर्णय विदेश मंत्री की आगामी न्यूयार्क यात्रा के बाद किया जाएगा जहां कि वे संयुक्तराष्ट्र महासभा के 32 वें अधिवेशन में भाग लेने जायेंगे। इस बीच विदेश मंत्री ने 30 जून, 1977 को लोक सभा में यह बताया था कि उनकी इच्छा यह है कि संयुक्त राष्ट्र में वे अपना पहला भाषण हिन्दी में दें।

Bringing back poet Kazi Nazrul Islam to India from Bangladesh

5203. SHRI ROBIN SEN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he will enquire that General Secretary, Nazrul Academy, P.O. Churulia, District Burdwan, west Bengal wrote a letter under reference No. 3409 N.A. dated 17-7-1974 to erstwhile Prime Minister of India Shrimati Indira Gandhi, requesting her to negotiate with Bangladesh Government or bringing the Poet Kazi Nazrul Islam (now dead) back to India from Bangladesh;

(b) whether the then Government of India took any steps in this matter ; and

(c) if not, will the present Government make an enquiry why no step was taken by the then Government of India for bringing back the poet to India in spite of the fact that the relatives of the poet and his admirers in India feeling strongly for bringing him back to India as the poet was then living in much mental agony due to death of his younger son and none of his relatives to look after him at Dacca?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) (a) Yes, Sir.

(b) The matter was examined in consultation with Poets son Kazi Sabyasechi who expressed the view that it would not be advisable to bring back his father in that delicate state of his health and put him at the Academy in their native village where there were no medical facilities readily available. The matter was, therefore, closed at that stage.

(c) does not arise

Nature Cure

5204. SHRI BALDEV SINGH JASROTHA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the future policy of the Government regarding the propagation of Nature Cure in the country;

(b) when Nature Cure will be recognised as a system of healing like Ayurveda, Homoeopathy and Yoga;

(c) when the National Nature Cure Institute planned at Poona will be started;

(d) whether Government have any plan in near future to open a Nature Cure College to train Nature Cure doctors; and

(e) whether there is any programme to start Yoga and Natural Health Training in Schools and Colleges?

THE MINISTER OF THEALTH AND FAMILY WELFARE : (SHRI RAJ NARAIN) : (a) and (c): The Government of India agree to the propagation of Nature Cure to the extent possible. They have appointed a National Advisory Committee on Nature Cure to advise them in this regard. They propose establishing a National Institute of Naturopathy shortly. They also provide financial assistance to Nature Cure institutions or maintenance of study beds, research, training, purchase of necessary equipment library books etc.

(b) Nature Cure is a way of life rather than merely a system of cure. However, Nature Cure is recognised by some State Governments like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh etc. for registration of persons practising it.

(d) Facilities for Nature Cure training will be provided in the proposed National Institute.

(e) A draft syllabus for yoga education in schools and colleges has been prepared and is presently under consideration of the Yoga Assessment Committee set up by the Society for the National Institute of Physical Education and Sports under the Ministry of Education and Social Welfare.

Posting of General Manager Telepoones

5205. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether important field posts in the P&T Directorate have been properly classified as Level 1 and Level 2 in Senior Management Cadre;

(b) if not, how soon this will be done; and

(c) whether a Level 2 Junior Officer has been posted as General Manager Telephones which is a very senior Level 1 post?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). No specific senior administrative grade posts in the Posts and Telegraphs Department, viz. the Directorate, or in the field, have so far been classified as Level 1 or Level 2. For ensuring flexibility in administration such classification is not under contemplation at present.

(c) Does not arise.

Cultivating and developing of Ayurvedic plants and herbs in hilly region of Garhwal, U.P.

5206. SHRI JAGANNATH SHARMA Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have proposed to undertake a study to find out the feasibility of cultivating and developing Auurvedic plants and herbs in the hilly region of Garhwal in U.P. which abounds in natural resources; and

(b) if so, by what time a decision in the matter is likely to be taken?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The Central Council for Research in Indian Medicines and Homoeopathy already has an experimental garden attached to the Amalgamated Unit at Tarikhet (U.P.) where studies on growth pattern and yield percentage of some important medicinal plants and herbs of the hilly region have been undertaken.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय श्रम संस्थान में नियुक्ति पदोन्नति के लिये चयन समिति

5207. श्री रामजीलाल यादव : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम संस्थान को प्रत्येक विंग के कर्मचारियों के चयन नियुक्ति पदोन्नति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इसके द्वारा आज तक शुरु किए गए कार्यक्रमों का संक्षेप में लेखाजोखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी -857/77] ।

Amending the policy of Rural Health Programme

5208. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to various comments, regarding the Rural Health Programme (Bare Foot doctors), appearing in Press;

(b) whether in the light of these comments the Govrernment are thinking to amend the policy; and

(c) if not, what steps are being taken to implement this programme?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Scheme is still under consideration.

Murder of Senior Manager (Personnel) of Hindustan Construction Company

5209. SHRI MANORANJAN BHAKTA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Senior Manager (Personnel) of the Hindustan Construction Company murdered in Meerut on 6th

July, 1977 where he had gone to appear in a labour dispute before the Industrial Tribunal;

(b) if so, full facts of the happenings;

(c) whether this incident has created a great panic among employers and officers of companies; and

(d) if so, what immediate action is being taken for checking violence and lawlessness among factory workers and other employees?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) (a) to (d). The matter falls essentially in the State sphere. According to the information made available by the Govt. of U.P. Shri S. J. Gawankar, Dy. Personnel Manager of Hindustan Construction Compnay who had gone for evidence before the Industrial Tribunal, Meerut on July, 1977 was shot at and killed at the gate of the tribunal. A worker of the company is reported to have been arrested by the State Police Authorities on the charge of this murder and they are making further investigatons in the case.

Disparities among Homoeopathic, Ayurvedic and Allopathic Doctors

5210. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Homoeopathic and Ayurvedic doctors in the C.G.H.S. are not in receipt of Non-Practising Allowance, higher time-scale promotion and other benefits being given to their counterparts of the allopathic system of medicine;

(b) whether their promotional avenues are also very bleak in comparison to those of the allopathic doctors;

(c) whether some homoeopathic dispensaries in the Northern Zone of the C.G.H.S. have been put under the overall charge of the Incharge of the allopathic dispensary when both the systems of medicine are entirely different and have no relevance whatsoever; and

(d) if so, the reasons for such disparities in the functioning of both the systems of medicine and stepmotherly treatment being meted out to the homoeopathic and ayurvedic doctors, and the steps taken to open the avenues of their promotion to the higher and time-scale posts and other benefits?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) to (d). The Homoeopathic and Ayurvedic physicians are not in receipt of non-practising allowance. The grant of N.P.A. to them is still under consideration though the Third Pay Commission had recommended against the grant of any N.P.A. to these physicians. There does exist a disparity between the scales of pay of Homoeopathic/Ayurvedic physicians and allopathic doctors because the Third Pay Commission prescribed different pay scales on account of the differences in qualifications, period of training, and conditions of service of the two categories of physicians. However, post-graduate allowance is admissible to both categories of physicians.

The allopathic doctors are drawn from the C.H.S. cadre which is fairly large and has various grades and as such enjoy promotion prospects, available in the cadre. The number of Ayurvedic/Homoeopathic physicians being very small in comparison, there exists no cadre in their case and therefore the promotion prospects are bleak.

Homoeopathic dispensaries under the C.G.H.S. are of two types. Full-fledged homoeopathic dispensaries in Delhi are functioning in a completely independant manner. There are, however, two homeopathic units in Delhi and 10 such units outside Delhi which have been established as an integral part of allopathic dispensaries on an experimental basis. These units are under overall administrative control of the Medical Officer-in-charge of the Allopathic dispensary. However, for purposes of treatment, etc. the homoeopathetic physicians-in-charge of the units function in a completely independent manner.

Setting up of E.S.I. Hospital at Jagatdal (W.B.)

5211. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to set up a E.S.I. Hospital at

Jagatdal for the benefit of Jute Workers in Barrackpore Sub-division, West Bengal; and

(b) if so, the facts thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). The Employees' State Insurance Corporation have reported that there is a proposal to set up a hospital at Jagatdal or any other suitable place in North 24-Parganas. The selection of land and other details are awaited from the Government of West Bengal.

Kolihan Copper Mine Development

5212. SHRI S. G. MURUGAIYAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the development, per month of Kolihan copper mine is much less than the target fixed;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) when the decline at Kolihan copper mine will reach at 304 ML?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The decline at Kolihan copper mine has already reached 306 ML in April, 1977.

C.G.H.S. Dispensary in Trans-Yamuna Area

5213. SHRI S. G. MURUGAIYAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of Govrenment employees stay in Laxmi Nagar and Shakarpur (Trans-Yamuna) area;

(b) whether there is no C.G.H.S. dispensary in these areas; and

(c) if so, the steps taken in the matter?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) Yes, Sir. As per the information with the Government, there are about five-thousand Government employees residing in these areas.

(b) and (c). There are two dispensaries—one at Shahdara and the other at Gandhi Nagar—covering most of the Trans-Yamuna area. A proposal for setting up the third dispensary in the uncovered area is under consideration.

Conversion of Institute of Opthalmology of Aligarh Muslim University into a regional Institute

5215. SHRI RASHEED MASOOD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the expert Committee which was sent to determine the feasibility of the proposal of converting the Institute of Ophthalmology of the Aligarh Muslim University into a Regional Institute had recommended favourably on the proposal and suggested that the Gandhi Eye Hospital, Aligarh be attached to the proposed Regional Institute; and

(b) if so, the action taken on the recommendations?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). No expert Committee was sent by the Centre to determine the feasibility of the proposal of converting the Institute of Ophthalmology of the Aligarh Muslim University into a Regional Institute. However, under the National Plan for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness, it is envisaged that the existing six Institutes of Ophthalmology in the country including that at Aligarh could be developed into a Regional Institute.

Building of Depoli Post Office Building

5216. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Post Office at Depoli is housed in a departmental building which is 110 years old and is in a dilapidated condition and that the accommodation available in this building is too short of the minimum requirement considering the present strength of Office;

(b) whether a proposal of expansion and renovation of the building was taken up in the year 1971-72 and plans and estimates also were prepared and permission of Revenue Authorities were obtained for this purpose; and

(c) in what year the Government propose to start and complete the work of expansion and renovation of the building?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Depoli Post Office is housed in a departmental building which is more than 110 years old. It is in usable condition but the accommodation is inadequate.

(b) Yes, Sir. However, the work could not be taken up due to ban on construction of Post Office buildings. Even after the lifting of this ban in 1975-76, this work could not be taken up due to paucity of funds.

(c) It is proposed to take up this work during the Sixth Plan period subject to availability of funds.

Purchase of Shovels and Dumpers by Chandmari Copper Project

5217. SHRI S. G. MURUGAIYAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) amount spent so far on purchasing of all types of shovels and dumpers and on spare parts and maintenance of these machineries at Chandmari Copper Project so far;

(b) whether the working of the Dumpers and shovels has not been satisfactory; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) All types of Shovels and Dumpers .....Rs. 1.76 crores (approx.). Spare parts & maintenance of these machineries (upto 31-3-77) ....Rs. 37 lakhs (approx.).

(b) The working of the Dumpers and Shovels has been by and large satisfactory.

(c) Does not arise.

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

5218. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या संचार मंत्री दिल्ली डायरेक्टरी के बारे में 14 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 3574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों की पृथक पृथक कितनी प्रतियां प्रकाशित कराई गई हैं ;

(ख) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों की पृथक पृथक कितनी कीमत निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) क्या उक्त डायरेक्टरी की कीमत पहले कम थी और यदि हां, तो उसकी कीमत बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री ब्रजलाल वर्मा) : (क) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के अंग्रेजी संस्करण की 2,25,000 प्रतियां और हिन्दी संस्करण की 15,000 प्रतियां वर्ष 1977 में प्रकाशित की जायेंगी ।

(ख) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के अंग्रेजी या हिन्दी संस्करण का मौजूदा बिक्री मूल्य 12 रुपए प्रति कापी है ।

(ग) पहले अंग्रेजी व हिन्दी संस्करणों की हर एक प्रति का मूल्य 4 रुपए था । कागज, छपाई और मजदूरी के खर्च में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण, इसका मूल्य बढ़ाया गया है ।

घी का प्रयोग

5219. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति में घी को उच्च स्थान प्राप्त है और सुखी एवं दीर्घ जीवन के लिए इसे बहुत आवश्यक और बहुत पोषक गुणों का कहा गया है, परन्तु देश में इसकी मांग इतनी अधिक है कि एलोपैथी की बढ़ती लोकप्रियता अथवा

पश्चिमी विज्ञानों के बढ़ते प्रभाव और उनके द्वारा 'घी' की तीव्र आलोचना के बावजूद इसकी मांग पूरी करना बहुत कठिन है; और

(ख) क्या सरकार चिकित्सा विज्ञान संस्थान से अनुरोध करेगी कि चिकित्सा की सभी पद्धतियों के विशेषज्ञों तथा अनुसंधान संस्थानों की राय प्राप्त करे कि 'घी' का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है अथवा हानिकारक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) भारतीय आहार में घी को सामान्यत: उच्च स्थान दिया गया है । भारतीय चिकित्सा पद्धति में घी प्राय: दवाइयां खिलाने में इस्तेमाल किया जाता है । यह घी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और शुद्ध तथा औषधिकृत रूप में इस्तेमाल किया जाता है । वैसे घी महंगा होता है और देश में इसका उत्पादन दूध के उत्पादन से जुड़ा हुआ है । चूंकि देश में कुल मिला कर दूध सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए घी भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है । भारतीय चिकित्सा पद्धति में तो घी के इस्तेमाल की थोड़ी ही जरूरत पड़ती है इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रयोजन के लिए इसकी उपलब्धि कोई समस्या हो ।

(ख) हमारे देश और विदेशों दोनों में वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा किए गए अनेक अध्ययनों के परिणामों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि घी, जो स्नेह (फैट्स) की संतृप्त (सेचूरेटेड) प्रकार है, यदि अधिक मात्रा में खाया जाए तो इससे सीरम कोलेस्ट्राल का स्तर बढ़ सकता है । बढ़े हुए सीरम कोलेस्ट्राल स्तर भी एथिरीस्कलेरोसिस और हृदय रोग होने का खतरा रहता है । घी जब थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो इसका पौष्टिक महत्व अनिवार्यत: लगभग उतना ही है जितना अन्य वनस्पति स्नेहों (फैट्स) का होता है । सिवाय इसके कि इसमें विटामिन 'ए' और 'डी' कम मात्रा में होता है ।

Victimisation of Medical and Sales Representatives during Emergency

5220. SHRI K. A. RAJAN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether a number of medical and sales representatives have been victimised during emergency; and

(b) if so, the details thereof and the action taken for reinstating them ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b). All the State Governments/Union Territories have been advised to ensure that all employees in the public and private sectors who have lost their jobs as a result of the operation of the Maintenance of Internal Security Act 1971 and the Defence of Internal Security of India Rules, 1971 or because of their association with certain organisations which were either banned by the previous Central Government or towards which that Government was not favourably disposed, are reinstated forthwith in service by their employers. In respect of other employees, who were discharged or dismissed by employers during the emergency by taking advantage of the atmosphere of emergency and without going through the due process of law and the prescribed procedures and without following the principles of natural justice, the employers are required to review the cases and give the employees concerned an opportunity to defend themselves. These instructions apply to medical and sales representatives as well; such of the sales promotion employees in the pharmaceutical industry, as are covered by the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976, can raise industrial disputes with the concerned conciliation machinery in case they have not been reinstated in service. Some representations received regarding victimisation have been forwarded to State Govts./Administrtions concerned for necessary action.

Corruption in IISCO

5221. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : Will the MINISTER of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Government's attention has been drawn to the news appeared in the Business Standard dated 28th June, 1977 under the caption "Corruption" ruling the roost in IISCO; and

(b) if so, what is Government's reaction and details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Yes, Sir.

(b) The allegations made in the news item are not based on facts. The position with regard to the main allegations is as under:—

(i) It is not true that the officers against whom C.B.I. enquiries are pending have been promoted after the institution of such enquiries.

(ii) Supply of steel in "package deal" is a normal trade practice. It is adopted in order to get the best advantage of fast selling items having premium in the market along with slow moving materials which would not sell otherwise: however, this matter is being reviewed.

(iii) The allegations relating to partiality shown to some traders are also not borne out by facts. There was no offer, nor is there any at present, for the supply of 1845 tonnes of GC sheets to any particular trader.

(iv) At present there is no facility of clean credit; credit is given to traders only against bank guarantees. This is being followed uniformly in all cases.

एच० एस० सी० एल० द्वारा इस्पात की बिक्री

5222. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एस० सी० एल० के प्रबन्धकों ने भिलाई में स्टील स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए मैसर्स शम्मी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, नेशनल फेब्रीकेशन और मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी को 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से इस्पात बेचा था जब कि इसी प्रकार के काम के लिए वर्ष 1977 में मैसर्स वीके इंजीनियरिंग कारपोरेशन को यह 1400 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बेचा गया था, यदि हां, तो कम्पनी को कितने रुपये का घाटा हुआ और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है; और

(ख) क्या सरकार का इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के बिरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Deaths due to Food Adulteration

5223. Shri D. B. CHANDRE GOWDA : Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of the persons died in the country, State-wise, due to food adulteration during last three years; and

(b) the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर की बोर्ड की बैठक पर हुआ व्यय

5224. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय संकट के समय 27 और 28 जून, 1977 को दिल्ली में आयोजित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर की बोर्ड की बैठक पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) इस बैठक के अवसर पर, तारीखवार, कितनी कारें भाड़े पर ली गई थीं; और

(ग) क्या इस बारे में जानकारी सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान जिंक लि० ने 27 और 28 जून को नई दिल्ली में अपने बोर्ड की बैठक पर रु० 9219·21 खर्च किए । इसमें अन्य खर्च के साथ-साथ कम्पनी के निदेशकों व अन्य अधिकारियों का, जिन्हें बैठक में उपस्थित होना था, यात्रा व दैनिक भत्ता तथा नीचे लिखी विभिन्न तारीखों पर भाड़े पर ली गई कारों का खर्च शामिल है :—

तारीख	भाड़े पर ली गई कारों की संख्या
25-6-1977	2
26-6-1977	3
27-6-1977	7
28-6-1977	7

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, द्वारा जिंक कथोड की बिक्री

5225. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1973 में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, द्वारा किन-किन पार्टियों को जिंक-कैथोड बेचा गया था और जिंक कैथोड कितनी मात्रा में बेचा गया था और किस दर पर बेचा गया था ;

(ख) क्या ये सभी लघु उद्योग अथवा कंपनियां, जिन्हें यह जिंक-कैथोड बेचा गया था, बोगस थीं अथवा वे उद्योग अथवा कंपनियां इसे खरीदने के पूर्व ही बंद हो गई थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की हैं; और यदि हां, तो उन्हें बाद में बंद करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रखा गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल-टी-885/77]**

(ख) छोटे तथा बड़े पैमाने की विभिन्न पार्टियों को जिंक कैथोड की सप्लाई उनके प्रायोजक प्राधिकरणों अर्थात् तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा लघु उद्योग विकास आयुक्त की सिफारिश पर की गई थी जो सामान्यतया अपनी देख-रेख वाली तथा अपने यहां दर्ज इकाइयों की जरूरतों की संवीक्षा करते हैं ।

(ग) हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा सितम्बर, 1973 के दौरान की गई जिंक कैथोड की बिक्री के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है और न उन्होंने कोई जांच पड़ताल की है ।

Indo-Soviet Seminar on International Law

5226. SHRI R.V. SWAMINATHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Indo-Soviet seminar on International Law was held in Moscow; and

(b) if so, the outcome of the seminar?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) Yes, Sir. The Indo-Soviet seminar on international law was held in Moscow from June 27th to July 4th, 1977.

(b) The seminar on international law was in the nature of exchange of views at purely scientific and academic level between the delegations of the Indian Society of International Law and the Soviet Association of International Law and the Academy of Sciences on the following subjects of international law: (i) progressive development and codification of international law; (ii) law relating to outer space activities; (iii) law of international organisations, and (iv) law of the sea.

Seventh American Fleet in Indian Ocean

5227. DR. BAPU KALDATY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the activities of the Seventh American Fleet have recently increased in the Indian Ocean;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps have been taken by Government to protest against the activities?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b). The Government are not aware of any significant increase in the level of U.S. naval activity in the Indian Ocean.

(c) Under International law, no littoral state can object to the movement of foreign war ships in the high seas. The question of protest, therefore, does not arise.

Agitation Notice by All India Engineering Employees Union Divisional Branch, Ujjain

5228. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA :

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

SHRI SUBHASH AHUJA :

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the serious situation arising out of agitation notice given by the All India Engineering Employees Union Divisional Branch, Ujjain in support of their demands; and

(b) if so, their reaction thereto?

THE MINISTER OF PARLIAMENTRY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b). The matter falls essentially in the State sphere and has been brought to the notice of the Govt. of Madhya Pradesh.

नकली दवाएं के दंडित व्यक्ति

5229. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कितने नकली दवा निर्माता पकड़े गए हैं तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को इसके लिए सजा मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Sanction of Amount to Patients of Maharashtra under Employees State Insurance Scheme

5230. DR. BAPU KALDATY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether under Employees State Insurance Scheme in Maharashtra, the hospital gets Rs. 12 per day per patient;

(b) Whether there is a demand from different hospitals or medical organisations to increase this amount;

(c) how much do they expect per day per patient; and

(d) the decision taken in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:

(a) Yes. The hospitals in Bombay are being paid reservation charges at the rate of Rs. 12/- per day per patient in respect of the beds reserved for the E.S.I. beneficiaries.

(b) The Corporation has no information in the matter. They have also not received any proposal from the State Government, who are responsible for administration of medical care under the E.S.I. Scheme, for enhancement of the rates of reservation charges.

(c) and (d). Do not arise.

Talks with Representatives of Trade Unions in Steel Industry

5231. DR. BAPU KALDATY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the representative of the Trade Unions of workers in steel industry were invited to Delhi for talks on 5th July, 1977;

(b) if so, what was the agenda; and

(c) who were invited for the discussion?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) to (c). Six Working Groups have been constituted to study various aspects of the working of the steel industry as indicated below and to make available to Government their recommendations/ suggestions for its improved functioning:—

(i) Production and Productivity.

(ii) Workers participation at all levels.

(iii) Welfare and social objectives.

(iv) Marketing, pricing and finance.

(v) Modalities of having one Union for each plant, and one Union for the steel industry at the national level.

(vi) Perspective of expansion of steel plants and setting up of new steel plants on the basis of funds obtained from outside.

The Groups consist of representatives of Steel Plants Managements and of Trade Unions (Central Trade Unions, namely, INTUC, AITUC, CITU, HMS. B.M.S. UTUC, UTUC, (Lenin Sarani) and NFITU and recognised and registered trade unions at the steel plants.

The Groups had met earlier in April and May, 1977. They again met at Delhi from 5th to 7th July, 1977 to continue their deliberations.

Extra Departmental Employees

5232. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2281 on the 30th June, 1977 and state:

(a) the total extra departmental employees who have been taken as Class IV cadre in P&T during the last three years; and

(b) whether Government propose to relax the rules to take more Extra departmental employees to P & T department?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Information is being collected and will be laid on the table of Lok Sabha in due course.

(b) No Sir.

राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित स्टाफ सेमीनारों पर हुआ व्यय

5213 श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय श्रम संस्थान की जनवरी 1977 की बुलेटिन के पृष्ठ 46 पर स्टाफ सेमीनार शीर्षक के पैरा 4 व 5 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इन सेमिनारों में किन किन प्रमुख लोगों ने भाग लिया तथा इस सम्बन्ध में उनके अलग अलग क्या विचार थे; और

(ग) क्या सरकार इन सेमिनारों की विस्तृत कार्यवाही का विवरण एवं आय व्यय का लेखा जोखा प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय श्रम संस्थान में ऐसे स्टाफ सेमिनारों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नामों की कोई सूची और इन सेमिनारों की कार्यवाही का कोई रिकार्ड रखने की प्रथा नहीं है । दो सेमिनारों का कुल व्यय लगभग 46/- रुपये था ।

कांकरोली नगर, राजस्थान में डाक तथा तार का प्रधान कार्यालय खोला जाना

5234. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर (राजस्थान) के कांकरोली नगर में डाक तथा तार का प्रधान कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है और यदि हां, तो कब; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस नगर में 35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया जे० के० का टायर कारखाना चल रहा है फिर भी इस नगर में डाक तथा तार का प्रधान कार्यालय नहीं है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) कांकरोली उप-डाकघर का दर्जा बढ़ा कर उसे मुख्य डाकघर बनाने के आदेश 22-7-77 को जारी कर दिये गय हैं।

(ख) सरकार इस नगर के महत्व को जानती है और इसलिए वहां मुख्य डाकघर खोलने के लिए कार्रवाई की गई है ।

Leave for Extra Departmental and Delivery Agents

5235. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any prescribed leave for Extra Departmental and Delivery Agents; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA) (a) and (b). The extra-departmental agents are not governed by the rules and regulations meant for the full time departmental employees. They are, however, eligible for leave for 180 days during a year.

The extra-departmental delivery Agent is required to provide his own substitute and the allowances are paid to the substitute during the leave.

Organisation for Rescue services in Coal Mines

5236. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether there is any organisation to organise rescue services in coal mines;

(b) if so, the name of the organisation; and

(c) the work it has done to minimise dangers in the mines ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes. Sir.

(b) The Central Coal Mines Rescue Stations Committee constituted under the Coal Mines Rescue Rules, 1959.

(c) A statement is attached.

Statement

The Central Coal Mines Rescue Stations Committee is charged with the responsibility of establishment, maintenance and proper functioning of the Rescue Stations in all the Coalfields in the country. There are 12 Rescue Stations functioning under the Committee. The function of these Stations is to train mine workers in rescue and recovery work in the underground, maintain rescue apparatus and other equipments, conduct rescue and recovery work in mines and to take all practicable steps to minimise danger in mines after any explosion or outbreak of fire or dangerous eruption of noxious or inflammable gases.

2. Immediately after an accident in a coal mine where the atmosphere becomes irrespirable, the rescue-trained persons who are the first to enter the mines contrive the affected parts of the mine, carry out rescue and recovery operations. Such operations help to obtain vital informtion, which is necessary to minimise further danger to the mine. Such operations are only possible by properly trained rescue persons. The Committee has so far trained 4336 workers in the mines in rescue and recovery work. In addition to meeting emergencies involving danger to the lives of the persons employed in the mines, the rescue organisation has been attending to calls from the mines whenever there was fire in the mine even though men were not involved. On such occasions, rescue-trained persons assisted the mine management in dealing with fire safely and expeditiously. The speedy isolation of underground fires results in saving the rest of the mine and minimising further danger to the rest of the mine and even the adjacent mines. Till date the Rescue Organisation rescued 98 persons who had been entrapped in foul atmosphere after explosions. Timely and speedy recovery operations conducted by the Organisation have resulted in the recovery of over 241 million tonnes of coal.

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी के प्रयोग में व्यय

5237. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **विदेश** मंत्री विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में सरकारी काम के लिए राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग न किए जाने के बारे में 30 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण करने की व्यवस्था करने में जो 6 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया गया है, उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या छोटे सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने देश की राजभाषा में नहीं बोल सकते; और

(ग) क्या उन्हें भी इसी प्रकार की खर्चीली व्यवस्था करनी पड़ती है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) . संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को यह छूट है कि वे अपनी पसन्द की किसी भी भाषा में भाषण दें, और इस पर कुछ खर्च नहीं होगा, बशर्ते कि संयुक्त राष्ट्र की किसी भी आधिकारिक भाषा में उस भाषण के अनुवाद की अग्रिम प्रतियों की व्यवस्था दुभाषियों के लिए कर दी जाए।

बहरहाल, यह अनुमान लगाया गया है कि किसी भी नई भाषा को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा बनाने पर लगभग 90 लाख रुपए का खर्च आएगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भाषांतर और अनुवाद पर पहले वर्ष में अनुमानतः 3.37 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च आएगा जो 7.5 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति की दर से बढ़ सकता है।

खर्च के अलावा किसी भी नई भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीकारात्मक निर्णय की अपेक्षा होती है।

बेलाडिला परियोजना

5238. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने बेलाडिला परियोजना के लिए प्रारंभ में कितने व्यय का तखमीना बनाया था तथा उसको पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया था ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है तथा कितना व्यय और होने का अनुमान है ;

(ग) पहले प्रति टन लौह अयस्क के खनन का व्यय का तखमीना कितना बनाया गया था तथा इस समय प्रति टन कितना व्यय आ रहा है; और

(घ) इस अन्तर का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा वर्ष 1969 में तैयार की गई प्रायोजना रिपोर्ट में 38.25 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत परिव्यय से बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 के विकास की परिकल्पना की गई थी। आरम्भ में बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार इस प्रायोजना का कार्य वर्ष 1973 के मध्य तक पूरा किया जाना था।

(ख) संशोधित अनुमानों के अनुसार इस प्रायोजना पर 67.49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 30-6-1977 तक 61.55 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे और शेष 5.94 करोड़ रुपए अभी खर्च किए जाने हैं।

(ग) आरम्भिक अनुमानों और क्षमता के 100 प्रतिशत उपयोग के आधार पर खनिज डलों के खनन-व्यय का अनुमान 20.50 रुपए प्रति टन लगाया गया था। लागत के संशोधित अनुमान तथा क्षमता के 90 प्रतिशत उपयोग के आधार पर अब खनिज डलों का खनन-व्यय 42.20 रुपए प्रति टन होने की संभावना है।

(घ) पूंजीगत लागत में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) निर्माण अवधि बढ़ जाने के कारण हुई वृद्धि,

(2) उपस्करों के मूल्यों तथा मजूरी में वृद्धि,

(3) कार्य क्षेत्र में वृद्धि, और

(4) क्वान्टिटी में वृद्धि।

प्रायोजना की निर्माण अवधि में वृद्धि मुख्यतः दरारों वाली और कठोर चट्टानों के बीच से एक 2025 मीटर लम्बी सुरंग खोदने में आई प्रौद्योगिक समस्याओं तथा देशीय निर्माताओं द्वारा आवश्यक उपस्करों की सप्लाई में हुए बिलम्ब के कारण हुई है।

Committee to Review Workers' Education Scheme

5239. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) Whether a Committee to review the Workers' Education Scheme was appointed in accordance with the recommendations of the Fourth Report of the Estimates Committee (Fifth Lok Sabha);

(b) Whether this Committee has submitted its reports ;

(c) if so, will the report be laid on the Table of the House and distributed among the members ; and

(d) what action has been taken on these recommendations ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b). Yes.

(c) Copies of the Report have been placed in the Parliament Library.

(d) The recommendations are under examination and decisions there on may be expected soon.

All India Mineral Conference

5240. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) Whether an all India Mineral Conference took place in Delhi recently ;

(b) Whether a decision has been taken to have unified growth of mining industry in the country; and

(c) if so, the facts there of and steps taken in that direction ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) The Council of State Mineral Corporations (COSMIC), which is a non-official body, held their first all India Mineral Conference at New Delhi on 2nd and 3rd July, 1977.

(b) and (c) The Government of India policy in the mineral sector is to have orderly and unified development of mineral industries where not only the Central and State Mineral Corporations but also private leaseholders will have a role to play. This has been clarified not only to the Council of State Mineral Corporations but also to the private mine owners association, and they have been asked to develop mines in their respective spheres, consistent with national objectives.

जूनागढ़ शहर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के लिए भवन का निर्माण

5242. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के लिए एक नए भवन का निर्माण करने का है ; यदि हां, तो इसके निर्माण में अनुमानित लागत क्या आएगी तथा उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान उस पर कितना व्यय आएगा; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क), (ख) और (ग). बड़े मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजों में विभिन्न चरणों में बदलने के कार्यक्रम के अनुसार, जूनागढ़ में एक आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना पर कार्रवाई चल रही है। आशा है कि आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्करों की समूची उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस एक्सचेंज के लिए उपयुक्त उपस्कर वर्ष 1981 के आरम्भ में उपलब्ध हो जाएंगे।

इस कार्य की पूर्ति के लिए, करीब 31 लाख की लागत की एक आटोमेटिक एक्सचेंज की इमारत के निर्माण के लिए नक्शे तैयार कर लिए गए हैं। इमारत का निर्माण कार्य वस्तुतः अगले वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया जाएगा ताकि एक्सचेंज की स्थापना के लिए यह इमारत समय पर तैयार हो जाए।

Vacancies in Medical Services

5243. SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of vacancies in the State/Central Medical Services, State-wise and Union Territory-wise; and

(b) the number of posts likely to be created and the number of doctors required during the next 3 years ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). The information is being collected and will laid on the Table of the Sabha.

Proceedings re. acquisition of Land premises at Chowringhee Road, Calcutta.

5244. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Directorate General of Posts and Telegraphs had advised in the year 1975 to the State of West Bengal to drop the proceedings relating to acquisition of land premises number 33/A, Chowringhee Road, Calcutta;

(b) if so, whether the concerned department is yet to act on the said advice; and

(c) if so, the reasons therefor and what further step is contemplated to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The position is being ascertained from the State Government and will be furnished in due course.

Export of Pig Iron to China

5245. SHRI NIHAR LASKAR:
SHRI R. V. SWAMINATHAN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether India is considering to export pig iron to China;

(b) if so, whether any agreement has been reached; and

(c) if so salient features of the same ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

दिल्ली के अस्पतालों में लिफ्टों की व्यवस्था

5646. **श्री लालजी भाई**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के अधिकतर बड़े बहु-मंजिले सरकारी अस्पतालों में या तो लिफ्टों की व्यवस्था ही नहीं हैं अथवा जहां इनकी व्यवस्था है वहां वे केवल रोगियों के लिए ही सुरक्षित होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो आम जानता के लिए लिफ्टों की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) राजधानी के विभिन्न बहु-मंजिले सरकारी अस्पतालों में लिफ्टों की व्यवस्थां की गई हैं। ये मुख्यत: केवल रोगियों के लिए होती हैं और ऐसा उन पर लिखा भी होता है।

(ख) चूंकि अस्पतालों में लिफ्टों के इस्तेमाल करने सम्बन्धी रोगियों की जरूरतें सर्वोपरि हैं। अत: यह आवश्यक समझा जाता है कि अस्पतालों में उपलब्ध लिफ्टें रोगियों के उपयोग के लिए हर समय उपलब्ध रहनी चाहिएं। इसीलिए रोगियों के अलावा लोगों को लिफ्टों की उपयोग करने के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाता है। रोगियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए अतिरिक्त लिफ्टें लगाना व्यावहारिक भी नहीं है।

हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा तालाबन्दी के लिए अनुमति मांगा जाना

5247. **श्री लालजी भाई** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, रेनूकूट (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्धकों ने मई, 1974 में एक महीने की तालाबन्दी करने की सरकार से अनुमति ली थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) वर्ष 1974 में स्टाफ एसोसिएशन के कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और ऐसा करने के मुख्य मुख्य कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

'हिन्डालको', रेणुकूट; उत्तर प्रदेश के सेवा से निकाले गये कर्मचारियों के बारे में मध्यस्थ निर्णय

5248. **श्री लालजी भाई** । क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) की सेवा से निकाले गए कर्मचारियों के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मध्यस्थ अपना निर्णय कब तक देगा ;

(ग) क्या प्रबन्धकों के मध्यस्थ के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है; और

(घ) क्या सरकार ने मध्यस्थ को निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) यदि सम्बन्धित पक्ष सहयोग दें तो विवाचक द्वारा 1977 के अन्त तक अपना निर्णय दिए जाने की आशा है ।

(ग) चूंकि अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

Opening of Passport Offices in States

5249. SHRI LALJI BHAI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi and Bombay cities only have passport offices as a result of which common man has to incur considerable expenses on both way journey and undergo many sorts of inconveniences in getting a passport;

(b) if so, whether Government would consider opening of such offices in different States ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): (a) No, Sir. Regional Passport Offices are located in the following 9 cities in India:

Office	From
1. Delhi 2. Bombay 3. Madras 4. Calcutta 5. Lucknow	February, 1956
6. Chandigarh	October, 1969
7. Ahmedabad	November, 1969
8. Ernakulam	April, 1975
9. Hyderabad	September, 1976

(b) Regional Passport Offices are opened in different States as and when the work-load justifies it.

Sending of Officers of telecommunication Research Centre to Japan for Telecommunication Seminar.

5250. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether some officers of Telecommunication Research Centre were sent to Kyoto in Japan to attend a Telecommunication Seminar there, in or around October, 1976;

(b) if so, their full names, qualifications, experience, etc. and whether any of the said visiting officers sent abroad happened to be a close relation of the Secretary, Ministry of Communications;

(c) the concrete benefits accrued to the Government by sending the said team to Japan, and the total cost thereof; and

(d) whether a good number of P&T officers were already in Japan for training when the seminar was held in that country and if so, the reasons for not deputing one or more of the said trainees to the Kyoto seminar and the reasons for specially sending the personnel from India?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) Yes, a team of three officers from the P&T Department was deputed, of which two were from the Telecommunication Research Centre (TRC) and one from the P&T Directorate.

(b) The full names of the officers, their qualifications, experience, etc., are:—

(*i*) Shri Gandu Bandopant Meemamsi, B.Sc. (Hons.), D.I.I.S.C., Additional Director, Telecommunication Research Centre, joined the Telegraph Engineering Service Class I in 1954. He is an expert in telephone switching system and electronic switching systems and techniques.

(*ii*) Shri Vijay Kumar, B.Sc., B.E., Deputy Director, Telecommunication Research Centre, joined Telegraph Engineering Service Class I in 1963. He is an expert in telephone switching systems and electronic switching systems and techniques.

(*iii*) Shri Dinkar Radhakrishna Mahajan, B.E., Director in the Planning Branch of the P&T Directorate, joined Telegraph Engineering Service Class I in 1957. He is an expert in telephone switching systems and electronic switching systems and techniques.

Of the three officers, Shri Vijay Kumar is related to the Secretary, Ministry of Communications.

(c) The International Switching Symposium is held once every three years. It was held in Kyoto in 1976 and the main theme of the symposium was electronic switching systems and techniques. 1100 experts from 50 countries participated in the said symposium.

Development of electronic switching systems is of considerable importance to India and the design and development of such systems suitable for Indian needs has been under the charge of the Telecommunication Research Centre. A stored programmed control type of electronic exchange based on TRC design is already under installation in Delhi.

Exposure to the latest world developments in the field of electronic switching, and inter-action with the other countries' experts is, therefore, of considerable importance to our own experts who are engaged in the development and planning of electronic switching systems.

The team that visited Kyoto actively participated in the deliberations of the symposium. The team from the Telecommunication Research Centre also presented a paper on the electronic switching system being developed by them in India, which was very well receiveed and evoked considerable interest and disscussions. The team took advantage of its visit to Japan to see electronic exchanges and to have discussions with experts. The team also actively participated in the deliberations of a Study Group of the CCITT which was dealing with electronic switching and signalling techniques.

The visit of this team has been of considerable benefit in furthering the design and development work of electronic exchanges being undertaken by these experts in India.

The total cost involved was Rs. 51,805.

(d) The other Posts and Telegraphs officers in Japan at that time were undergoing training in the techniques of

crossbar switching systems. As they were not involved in the development or planning of the electronic exchange systems, the question of their participation is an international symposium on this subject did not arise.

Indo-U.S. Joint Commission

5251. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Indo-U.S. Joint Commission was set up as a result of fruitful negotiations between the then U.S. Secretary of State, Dr. Henry Kissinger, and the former Minister of External Affairs of India;

(b) if so, the full facts of the composition and functions of the said commission as also of its three sub-commissions and the broad details of their meetings and decisions so far;

(c) whether the new Janata Government have reconstituted the personnel of all the said Joint and Sub-commissions, if so, full facts thereof; and

(d) broad details of the meetings of the various Sub-commissions which took place in India and/or U.S.A. between March and June, 1977 ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). A statement is laid on the table of the House.

Statement

The Indo-US Joint Commission was established on 28th October, 1974, through an agreement signed by the then Foreigh Minister (Shri Y.B.Chavan) on behalf of the Government of India and the then Secretary of State (Dr. Henry Kissinger) on behalf of the Government of United States of America. This covers bilateral proposals for cooperation in economic, commercial, scientific, technological, educational and cultural matters. Its two co-Chairmen are the Minister for External Affairs of India and the U.S. Secretary of State. There are three Sub-commissions under the Joint Commission to deal with the concerned matters in detail :

(1) Indo-US Sub-Commission on Education & Culture.

(2) Indo-US sub-Commission on Science & Technology.

(3) Economic and Commerce Subcommission.

There is also an Indo-US Joint Business Council consisting of businessmen from Chambers of Commerce in both the countries.

With the changes in Government in USA and India this year, there are two new Co-Chairmen of the Joint Commission, namely, Shri Atal Bihari Vajpayee, Minister of External Affairs, Government of India, and Mr. Cyrus Vance, U.S. Secretary of State.

Under the Indo-US Commission, particular areas of cooperation are identied and specfic schemes for collaboration, such as research projects, are drawn up in detail. When these are approved by the governments concerned, further steps are taken by both sides to implement the decisions.

The first meeting of the Joint Commission was held in Washington in October '75. The Indian delegation, which included leaders of the 3 Sub-commissions, was led by the Former Minister for External Affairs. The U.S. delegation was led by the former Secretary of State and included the American leaders of the 3 Sub-commissions.

The second meeting of the Joint Commission could not be held in 1976 and was postponed due to the U.S. Presidential elections. Dates for the meeting in New Delhi have yet to be decided through mutual consultations between the two sides. It is, however, expected that a meeting of the Joint Commission can be held at New Delhi later this year.

(i) *Economic and Commercial sub-commission.*

Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, heads this Sub-commission on the Indian side. Two meetings to the Sub-commission have taken place so far : the first in Washington in January 1975 and the second in New Delhi in March 1976. The third meeting is scheduled to be held in Washington later in the year.

A Working Group on Agricultural Inputs under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Chemicals and fertilizers has been set up under the Sub-commission to review international trends relating to the supply, demand and price of Fertilizers and pesticides, with particular reference to India and U.S.A. Three

meetings of this Group have already taken place so far, the last on 27 March 1976 in New Delhi.

(ii) *Educational and Cultural Sub-commission.*

Shri G. Parthasarathi, formerly Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University and subsequently Chairman, Policy Planning, Ministry of External Affairs, until March 1977, was nominated Leader of this Sub-commission on the Indian side. Shri M. Mukherjee, Additional Secretary, Ministry of Education and Social Welfare, was the alternate leader. Three meetings of this Sub-commission have been held so far, the first in New Delhi in February 1975, the second in New York in May 1976 and third in New Delhi in May 1977. The Indian Council for Cultural Relations provides the Secretariat for this Sub-commission.¶

(iii) *Science and Technology Sub-commission.*

Dr. B.D. Nag Chaudhari, Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, was named the Leader of this Sub-commission on the Indian side with the Secretary, Department of Science and Technology, as the alternate leader.

Three meetings of this Sub-commission have taken place so far, the first in Washington in January 1975, the second in New Delhi in January 1976 and the third in Washington in June 1977.

After the new Government came into office in March 1977, the Indo-US Sub-commissions and their work were reviewed by the Minister of External Affairs. It was decided that the Sub-commissions should continue to fuction, though some changes should take place in the membership on the Indian side. Two of the Sub-commissions, *viz*; The Educational and Cultural Sub-commission and the Science and Technology Sub-commission have met in New Delhi and Washington respectively since March 1977. A brief account of the decisions at the meeting is given below.

The present composition of the Indian side of the Educational and Cultural Sub-commission is as follows :

Prof. M.S. Gore, Leader. Prof. P.G. Mavalankar, MP and Director of the Harold Laski Institute of Political Science, Prof. A. N. Bose, Vice-Chancellor of Jadavpur University, Prof. M.N. Srinivas of the Institute of Social and Economic Change, Prof. Raj Krishna of the Delhi School of Economics, Prof. Manzur Alam of Osmania University, apart from officials.

The composition of the Science and Technology Sub-commission on the Indian side (as of June 1977) is as follows :

Dr. A. Ramachandran, Secretary, Department of Science and Technology, Leader. Dr. C. Gopalan, Director General, Indian Council for Medical Research, Dr. D.R. Bhumbla, Deputy Director General, Indian Council for Agricultural Research, Dr. R.D. Deshpande, Director, Department of Science and Technolcgy, besides officials of the Indian Embassy in Washington.

Decisions of the Education and Cultural Sub-commission May 1977 :

The Sub-commission agreed that there is need for greater cooperation and exchanges in this field. The Sub-commission did not want to confine the endeavours to academic and intellectual circles only but wanted to evoke an interest in public at large in both countries. The Sub-commission reaffirmed its support for exchanges of fellows and visitors for the coming year. The Sub-commission expressed satisfaction over the seminars held during the past year and expressed a desire for continuity and contact and follow-up programmes to these seminars. Subjects for 3 seminars for the next year have been accepted. These include University Research and Science, Research in Education Learning and Ethnic Mobilisation in Culturally Diverse Societies. The Sub-commission appreciated the work done by the Joint Museum Committee. An exhibition on the history of American industrial technology is due in India this year. An Indian exhibition on "Pre-Industrial Technology" is to be presented in USA. There was agreement on the scope for cooperation in film, radio and television.

Decisions of the Sub-commission of Science and Technology :

After the Sub-commission meeting in mid-June 1977 in Washington, which was held in an extremely cordial atmosphere, the following decisions were reached. The United States proposed four new fields of c operative research : wildlife and habitat, solar activity related to weather phenomena, oceanography, and earth sciences, including seismology, geology, hydrology and arid lands research. India

proposed cooperative research in small industrial technologies and new initiatives in the previously-agreed priority areas of health, agriculture and water resources, and energy. Specialised panels of the Subcommission met to coordinate plans for the Joint efforts in agricultural and water resources, energy, environment and natural resources, health, metrology, materials and electronics, information science and institutional exchanges.

Sending Lorry Driver to Oman as Telephone Exchange Technician

5252. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a lorry driver in Delhi Telephones was sent as a telephone exchange technician to Oman or/and any other country in West Asia;

(b) if so, the reasons for sending the said person in preference to the trained and experienced technicians already working in the department;

(c) whether there are any such untrained or semi-trained/semi-skilled personnel working in Delhi Telephones and P&T Directorate whose appointments have been more on the basis of nepotism than on merit; and

(d) if so, the steps Government are taking to curb the said improper practice ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). No, Sir. However, one lineman/driver from Delhi Telephones was selected by a team from Oman, which interviewed a number of P&T Officials.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Mineral Development Plan

5253. SHRI PRASANNBHAI MEHTA:

SHRI R. V. SWAMINATHAN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether mineral development plan got serious set back owing to centralisation of decision making process even in matters pertaining to the State Mineral Corporation;

(b) what are the other reasons for set back of mineral development;

(c) whether many state mineral cooperatives have not been able to take up new mineral projects for want of required capital; and

(d) steps being taken to improve the mineral development in the country ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) This is a matter within the sphere of State Governments.

(d) The Fifth Five Year Plan (1974-79) provides for increased outlay for Central programmes and schemes for mineral development. The States as well as private investors are being encouraged to develop mineral resources in a co-ordinated way, in the light of the long term interests of conservation and use of low grade ores.

Demand of Non-Ferrous Metals

5254. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the estimated demand for non-ferrous metals in the current year;

(b) the actual production last year and the targets fixed for the current year; and

(c) the steps taken to remove bottlenecks in achieving the targets ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). Information in respect of major non-ferrous metals is given in a statement attached.

(c) The main constraint in production of *aluminium* is inadequate power supply to the aluminium smelters. The Central Government has taken up the matter regarding maintaining and increasing power supply for aluminium production with the concerned State Governments/Electricity Boards.

The constraints being faced by Hindustan Copper Ltd. at present in achieving the target for *Copper* production are :—

(1) Inadequate power supply for which the Government is pursuing the matter with the concerned State Governments and Electricity Boards; and

(2) Technological problems of the smelter at Khetri. For overcoming these problems, Hindustan Copper Ltd. is arranging to obtain the services of a well known firm of foreign metallurgical consultants.

No major difficulties are anticipated in achieving the targets for *zinc and lead.*

Statement

Demand of non-ferrous Metals.

Sl. No.	Name of Non-ferrous metal	Actual production last year i.e. 1976-77 (in tonnes)	Estimated Demand in the current year i.e. 1977-78 (in tonnes)	Targets of production fixed for the current year i.e. 1977-78 (in tonnes)
1	2	3	4	5
1.	Aluminium	2,08,687	2,20,000	2,23,000
2.	Copper	22,424	65,000	27,670
3.	Lead	6,181	49,000	10,050
4.	Zinc	27,033	1,05,000	42,400 (ingots) 17,100 (Cathodes)

Ore Shipments by N.M.D.C.

5255. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the figures of production, despatches and shipments made by N.M.D.C. of different ores in 1976-77 and how they compare with the previous year;

(b) the financial working results for 1976-77 and the year before; and

(c) the targets set for mineral exploitation in the current year both for internal consumption and for exports?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) The production, despatches and shipments of iron ore by N.M.D.C. during 1975-76 and 1976-77 are given below :

(in lakh tonnes)

Year	Production	Despatches	Export shipments
1975-76	70·25	69·19	48·19
1976-77	81·98	77·26	51·14

(b) The financial results of N.M.D.C.'s operating projects during 1975-76 showed a profit of Rs. 67.7 lakhs. The financial results for the same projects during 1976-77 indicate a profit of Rs. 116 lakhs. However, due to inclusion of the new project at Bailadila Deposit No. 5 into the revenue accounts towards the end of the year, N.M.D.C.'s provisional accounts for 1976-77 show a loss of Rs. 176.7 lakhs.

(c) The targets of production of iron ore (lump and fines by N.M.D.C.

for 1977-78 are as follows :

(in lakh tonnes)

(i) for internal consumption	25·80
(ii) for exports	88·12
TOTAL	113·92

चालू पंचवर्षीय योजना में नये अस्पतालों का खोला जाना

5256. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 500 या उससे अधिक शय्या वाले कितने अस्पताल हैं; और

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार का कितने नये अस्पताल खोलने का लक्ष्य था और इसमें कहां तक सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) (क) देश में 500 या इससे अधिक पलंगों वाले अस्पतालों की संख्या 110 है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 40,000 और पलंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना में नए अस्पतालों के खोलने के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Homoeopathic Doctors/Colleges in the Country

5257. **SHRI S. S. SOMANI:** Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of homoeopathic doctors registered in each State at present;

(b) the number of homoeopathic colleges and hospitals in each State at present; and

(c) the number of homoeopathic colleges and hospitals proposed to be opened by Government during the Fifth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) A statement showing the number of Homoeopathic doctors registered in the States in which legislation for the purpose has been enforced as reported by the respective State Governments, is attached.

(b) The number of recognised Homoeopathic colleges as on 31-5-1976 in the States from which reports have been received is as follows:

Andhra Pradesh	4
Assam	1
Bihar	19
Delhi	1
Gujarat	2
Karnataka	4
Kerala	4
Madhya Pradesh	14
Maharashtra	16
Orissa	2
Rajasthan	1
Tamil Nadu	1
Uttar Pradesh	16
West Bengal	8
TOTAL	93

The information regarding the number of Homoeopathic hospitals State-wise is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as it becomes available.

(c) The Central Government have established the National Institute of Homoeopathy at Calcutta which will provide facilities for Homoeopathic education, research as well as medical care. Information in respect of State Government proposals is not available with the Centre.

Statement

No. of Homoeopaths registered with Homoeopathic Boards/Councils

Name of States	Registered Quali-fied	Nn ex-perience basis	Total
1	2	3	4
Andhra Pradesh As on 31-1-77	339	803	1142
Assam As on 1-1-77	46	1805	1851
Bihar As on 1-1-77	2745	13242	15987
Chandigarh As on 25-1-77	22	224	246
Delhi Upto 4-4-77	980	276	1256
Gujarat Upto 1-2-77	164	225	389
Haryana Upto 4-4-77	9	1053	1062
Karnataka	218	1220	1438
Kerala Upto 10-2-77	1393	1489	2882
Madhya Pradesh As on 1-6-76	2592	4647	7239
Maharashtra As on 1-1-77	3772	2043	5815
Orissa As on 1-6-76	204	1355	1559
Punjab Upto 1-1-77	60	2823	2883
Rajasthan up to 1-1-77	70	2441	2511
Tamil Nadu Upto 1-1-77	26	11574	11600
Uttar Pradesh As on 1-6-76	1799	13251	15050
West Bengal As on 1-6-76	3730	11637	15367

राज्यों में कुष्ठ-रोगी

5258. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से कुष्ठ रोगियों की संख्या की जानकारी ली है;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है और किस राज्य में गत तीन वर्षों से इनकी संख्या बढ़ रही है; और

(ग) इस भयावह रोग के निवारणार्थ सरकार क्या उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) (क) और (ख) जी हां, अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

चूंकि कुष्ठ रोग की दर का पता लगाने के लिए अभी तक पर्याप्त संख्या में अध्ययन नहीं किए गए हैं, अतः यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि गत तीन वर्षों में किसी राज्य में यह रोग बढ़ा है या कम हुआ है । तथापि, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई अच्छी व्यवस्था के कारण कुष्ठ के और रोगियों का पता लगाया जा रहा है और उनका उपचार किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्र पोषित योजना के रूप में मंजूर किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 364 कुष्ठ नियंत्रण एकक, 4480 सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र, 285 नगरीय कुष्ठ केन्द्र, 56 पुनर्रचना शल्य चिकित्सा एकक तथा 124 अस्थायी वार्ड खोले गए हैं जिनमें से प्रत्येक में वास्तविक रोगियों और कुष्ठ के जटिल रोगियों के अन्तरंग उपचार के लिए 20 पलंग हैं। इस कार्यक्रम के लिए चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 37 कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। पिछले वर्ष से इस कार्यक्रम को लक्ष्य प्रधान कार्यक्रम बना दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

(आंकड़े लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-3-71 को कुष्ठ के अनुमानित रोगी	31-3-1977 तक पता लगाए गए कुष्ठ रोगी	31-3-1977 तक उपचार के लिए लाए गये कुष्ठ रोगी
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	6.28	3.000	2.535
2. असम	0.12	0.045	0.043
3. बिहार	3.39	1.236	1.226
4. गुजरात	0 25	0.301	0.266
5. हरियाणा	0.01	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	0.15	0.060	0.058
7. जम्मू और कश्मीर	0.05	0.044	0.044
8. कर्नाटक	1.74	0.863	0.843
9. केरल	0.75	0.608	0.487
10. मध्य प्रदेश	0.32	0.689	0.170
11. महाराष्ट्र	2.80	2.606	1.880
12. मनीपुर	0.06	0.051	0.030
13. मेघालय	0.05	0.017	0.011
14. नागालैण्ड	0.05	0.055	0.015
15. उड़ीसा	2.37	0.906	0.906
16. पंजाब	0.02	0.006	0.006
17. राजस्थान	0.10	0.031	0.015
18. सिक्कम	0.016	0.015	—
19. तमिल नाडू	7.83	5.662	4.550
20. त्रिपुरा	0.10	0.020	0.019
21. उत्तर प्रदेश	1.68	1.600	1.494
22. पश्चिम बंगाल	3.80	2.474	1.002

1	2	3	4
23. अण्डेमान और निकोबार द्वीप	0.01	0.002	0.002
24. अरुणाचल प्रदेश . .	0.01	0.008	0.008
25. चण्डीगढ़ . .	—	—	—
26. दादरा और नगर हवेली .	0.001	0.0004	0.004
27. देहली . . .	0.01	0.004	0.004
28. गोवा, दमन और दीव .	0.05	0.014	0.014
29. लक्ष्यद्वीप . .	0.01	0.005	0.005
30. मिज़ोरम . .	0.01	0.002	0.002
31. पांडिचेरी . .	0.19	0.123	0.115
भारत . .	32.237	20.3924	15.7504

चासनाला खान दुर्घटना में मरे मजदूरों के परिवारों को अदा किया गया मुआवजा

5259. **श्री हरिकेश बहादुर ।**

श्री पी० एस० रामलिंगम :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चासनाला खान दुर्घटना में मरे मजदूरों के परिवारों को मुआवजा अदा किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को मुआवजा अदा किया गया है और कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 500 रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले 93 श्रमिकों के आश्रितों को, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन 1976 में इसमें किये गये संशोधन से पहले मुआवजे की दरों के अनुसार उनकी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास पाने वाले 270 मृतक श्रमिक पहले कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन नहीं आते थे। फिर भी, इन श्रमिकों के आश्रितों को प्रति श्रमिक 10,000 रुपये की दर से अनुग्रह पूर्वक अदायगी भी की जा चुकी है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मजूरी सीमा को 500.00 रुपये से 1000.00 रुपये तक कर्मकार प्रतिकर संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्व व्यापी तारीख 1-10-1975 से बढ़ा दिया गया है। अधिनियम के अधीन मुआवजे की दर को भी उसी तारीख से बढ़ा दिया गया है। फलस्वरूप, 500 रुपये प्रतिमास तक पाने वाले श्रमिकों के आश्रित मुआवजे की पुरानी दरों और नई दरों के बीच अन्तर की बकाया राशि पाने के हकदार हो गए हैं। 501 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास मजूरी पाने वाले श्रमिकों के आश्रित अधिनियम के अधीन मुआवजे के भी पात्र हैं।

यह बताया गया है कि नियोजक ने 500 रुपये प्रतिमास तक मजूरी पाने वाले श्रमिकों के देय मुआवजे के अन्तर की पूरी राशि और 501 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास मजूरी पाने वाले श्रमिकों की देय मुआवजे की राशि को अनुग्रह पूर्वक अदायगी की राशि घटाकर पहले ही जमा करा दिया है। नियोजक द्वारा काटी गई अनुग्रह पूर्वक अदायगी की राशि की वसूली आश्रितों के मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई संबंधित कर्मकार प्रतिकर आयुक्त द्वारा की जा रही है।

Payment of Special Allowance to Head Sorters, Railway Mail Service

5260. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the head sorters working in the Railway Mail Service are given special allowance whereas the S.R.Cs. are not paid this allowance whereas their work load is more than that of the head sorters and they are also senior officers to them; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove the anomaly in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir. All time-scale Head Sorters and Sub-record Clerks in the R.M.S. get special pay. They also get special pay when they are in the lower Selection Grade, provided they supervise another official of the same grade in their own office.

(b) Does not arise.

Policy for Telephone Connections

5261. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a sum of Rs. 1,200/- is demanded as advance from telephone subscribers for providing telephone connection;

(b) whether telephone connection is not provided for a long time, sometimes after one year, even after taking the above advance money; and

(c) if so, whether a definite policy will be laid down in this regard so as to ensure that people wanting telephone connections get them early?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir. the advance deposit in the larger telephone systems is Rs. 1,000/- for non-OYT applicants and Rs. 5,000/- in case of OYT applicants. In smaller systems, the advance deposit is less..

(b) and (c) Advance deposit is taken from all applicants at the time of registration of the applications. Applicants have to wait for telephones till capacity becomes available which in some exchange areas might take more than a year. To meet the demand, the capacities of the telephone exchange systems are being expanded on a continuing basis, to the extent possible, within the available resources.

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालिज, नई दिल्ली में कुप्रबन्ध

5262. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री रामलाल राही :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली के कुप्रबन्ध के बारे में बहुत सी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं जिनमें छात्रों को होने वाली कठिनाइयों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस कालेज की सम्बद्धता समाप्त किए जाने की बात कही गई है ;

(ख) क्या इस कालेज के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत अनुदान देती है ;

(ग) क्या कालेज के कुप्रबन्ध तथा प्राप्त सरकारी अनुदान एवं सहायता के दुरुपयोग के कारण कालेज का सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बारे में कालेज के छात्रसंघ की ओर से एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या तथ्य दिये गये हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) जी हां। छात्रों ने आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली के कुप्रबन्ध के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से इसकी सम्बद्धता समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) नहीं, परन्तु दिल्ली प्रशासन इस कालेज को काफी वित्तीय सहायता देता है।

(ग) जी हां।

(घ) छात्रों ने कालेज के कुप्रबन्ध के विरुद्ध और इस कालेज और इसकी सम्बद्ध संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के लिए अभ्यावेदन दिया है। 29-4-1977 को दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कालेज को अपने अधिकार में लेने के लिए सुझाव दिया था किन्तु 20-7-1977 को उन्होंने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार से तिब्बिया कालेज अधिनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन करने के लिए अनुरोध किया जाए ताकि इस कालेज को उक्त प्रशासन अपने अधिकार में ले सके।

Facilities to C.G.H.S. Pharmacists

5263. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there are no facilities and social activities given by the Pharmacy Council to the pharmacists working in various dispensaries and hospitals of Delhi;

(b) whether the amount of Rs. 25/-, as fee for such activities is being charged from them; and

(c) the steps Government propose to abolish the back-breaking fees?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). A sum of Rs. 25/-, has been prescribed as annual registration fee in respect of pharmacists. This fee is not intended for providing any facilities.

(c) The matter is under the consideration of Delhi Administration.

Cancer Patients cured by Krishna Ayurvedic Cancer Institute

5264. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Shri Krishna Ayurvedic Cancer Research Institute of Kurukshetra has cured a number of cancer patients; and

(b) if so, the total number of patients cured during the last two years and details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) The Institute claims to have cured cancer patients at the Institute but no evaluation has been made by the Government of India.

(b) According to the Institute, 21 patients have been cured during the last two years. A statement furnished by the Institute is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-859/77].

Engagement of Workers through contractors

5265. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether large number of workers are engaged through contractors in Iron Ore mines in public sector and that these contractors indulge in various malpractices and thrive at the cost of labour;

(b) if so, what is the percentage of such labour engaged and the action taken thereon; and

(c) whether Government propose to ban employment of workers in public sector mines through contractors?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). The employment of contract labour to total labour in public sector iron ore mines under various undertakings is indicated below :

(i) Bhilai Steel Plant	60·98%
(ii) Rourkela Steel Plant	47·52%
(iii) National Mineral Development Corporation Limited	55·86%
(iv) Bolani Ores (India) Limited	45·78%
(v) Indian Iron and Steel Company Limited	Varies from 12% to 17%

The terms and conditions of employment of the contract workers are regulated in accordance with the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and the Rules framed thereunder. The managements of Public Sector mines try to ensure that the interest of the contract workers are safeguarded and the statutory provisions are complied with.

Generally contract labour is employed in mechanised mines, in jobs which are not of permanent or perennial nature, and in semi mechanised or unmechanised mines. With the mechanisation of a mine, contract labour is replaced by departmental labour as would happen with the commissioning of the Dalli Mechanised Mines of Bhilai Steel Plant towards the end of this year when there would be no contract labour in drilling and raising operations. Even otherwise, the managements of public sector mines are alive to the need for replacing contract labour by departmental labour, to the extent possible, in a phased manner for jobs of permanent and perennial nature in accordance with the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

(c) The employment of contract labour in public sector mines as in other establishments is being governed and regulated by the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the rules thereunder.

Filling up post of Director General of Mines' Safety

5266. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is true that the post of Director General of Mines' Safety has not been filled up for the last three years in Bihar;

(b) if so, who is responsible for this; and

(c) when Government propose to fill up the post ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). The post of Director General of Mines Safety had been lying vacant since 26-8-74 and it could not be filled up by promotion due to the non-availability of a suitable candidate. The Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman of the U.P.S.C. found the then Deputy Director General of Mines Safety not yet fit for promotion as Director General. The post has temporarily been kept in abeyance since 12-10-76 and in its place another post of Deputy Director General of Mines Safety has been created. A suitable departmental officer has been appointed to the newly created post of Deputy Director General of Mines Safety who has been heading the organisation in the absence of Director General of Mines Safety since 19-10-76. With a view to making the selection for the post of Director General of Mines Safety broad based, the recruitment rules for the post are being revised. As soon as the revised recruitment rules are notified, the post of Director General of Mines Safety will be revived and filled up in accordance with the revised recruitment rules.

पटना कैंसर संस्थान की मशीनों की मरम्मत

5267. श्री युवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना कैंसर चिकित्सा केन्द्र की नौ उपयोगी मशीनों, अर्थात् कोबाट,

आइसोटेप, सिमुलेटर, डीप एक्सरे, सुफर-फिशियल एक्सरे, आदि में 6 वर्ष से जंग लग रहा है ;

(ख) यदि इन मशीनों में से एक मशीन कम मंगाई गई हो तो और शेष मशीनों के सभी यंत्र मंगवा लिये गये होते तो क्या कैंसर केन्द्र के लिये उपयोगी होता और अनेक रोगियों को लाभ हुआ होता ; और

(ग) यदि हां, तो इन नौ मशीनों का मूल्य क्या है और बेकार पड़ी मशीनों के शेष पुर्जे कब तक खरीद लिये जायेंगे और उनकी मरम्मत करा ली जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैंसर अस्पताल, पटना में रेडियम द्वारा चिकित्सा

5268. **श्री युवराज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कैंसर अस्पताल, पटना में कैंसर रोगियों की केवल रेडियम से चिकित्सा की जाती है ;

(ख) क्या पटना कैंसर चिकित्सा केन्द्र के रेडियम इंस्टीट्यूट में यह चिकित्सा पहले से ही हो रही है परन्तु सर्वांगीण चिकित्सा नहीं होती ; और

(ग) सर्वांगीण चिकित्सा के लिये कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी और यदि इसकी व्यवस्था नहीं की जायेगी तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरक्का बांध के बारे में भारत-बंगला समझौता

5269. **श्री युवराज :**

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री चित्त बसु :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के बारे में भारत और बंगला देश के बीच समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ढाका में 15 से 18 अप्रैल, 1977 तक मंत्रीस्तर पर जो बातचीत हुई थी उसकी समाप्ति पर इस संबंध में दोनों सरकारों के बीच एक संभव समझौते के तत्वों पर सहमति हो गयी थी।

(ख) दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत में समझौते के ब्यौरे पर विचार विमर्श चल रहा है। अधिकारियों के स्तर पर इस बातचीत का पहला दौर नई दिल्ली में 7 से 11 मई, 1977 तक हुआ था और दूसरा दौर 28 जुलाई, 1977 से ढाका में शुरू होना है।

Anti-Social activities of Bohra Priest in Tanzania

5270. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Over-seas Indians of Dawoodi Bohra community from Tanzania have written to him regarding anti-social activities of Bohra Priest who is an Indian citizen;

(b) if so, whether Government have inquired into the matter and ascertained facts; if so, tbe facts thereof; and

(c) the opinion expressed by the Indian High Commission at Dar-es-Salaam in the matter ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) We received a few letters from members of the Bohra community from Dar-es-Salaam, Tanzania containing allegations of collection by the High Priest of money and its transfer abroad through unofficial means and of harassment of the minority.

(b) and (c). Yes. From information available with us, we have no reason to believe that the allegations contained in the letter had been substantiated.

Punishment to food adulterators

5271. SHRI SAMAR MUKHERJEE : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of food adulterators 'life imprisoned' so far; and

(b) the nature and number of highest punishment given to the food adulterators; State-wise ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Technical aid to Vietnam

5272. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he had talks with the Foreign Minister of Vietnam, Mr. Nugyen Duy Trinh, on 12th April, 1977 regarding the technical aid to Vietnam; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). During the visit of the Vietnamese Foreign Minister, Mr. Nugyen Duy Trinh in April, 1977, our Foreign Minister had useful discussions on various matters of bilateral interest which included discussions on areas where both sides could benefit from exchange of technical know-how. Details are being worked out between the two governments.

Residential quarters for P&T employees in Bihar

5273. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether residential quarters for P&T Employees in the State of Bihar are far inadequate to meet the demand of the employees; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). The facility of residential quarters for the P&T employees in Bihar is in tune with that available elsewhere in the country. As on 31-3-1977 there were 2444 residential quarters in Bihar against a total departmental staff strength of 25,088.

Within the overall resources allotted for the purpose, construction of additional staff quarters is being taken up in Bihar also. 66 quarters are under construction, and another 266 have recently been sanctioned for construction.

Mining Cess Fund

5274. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether a Mining Cess Fund for development of mining areas is regularly maintained;

(b) if so, whether there is any proposal to construct a 50-bed hospital for mining labourers in Joda Iron Ore Mines in Keonjagarh, Orissa; and

(c) if so, estimated cost thereof and the progress achieved so far ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) No cess is collected by the Ministry of Labour for development of mining areas. How-

ever Iron Ore Mines Labour Welfare Fund has been constituted to supplement the efforts of the State Governments and the Employers in promoting the welfare of labour employed in the iron ore mines and their dependents. This Fund is financed by a levy of a cess @25p. per tonne on all iron ore consumed by steel plants or exported from the country.

(b) The construction work of the hospital is already in an advanced stage.

(c) The estimated cost is about Rs. 51·85 lakhs for the establishment of the Hospital Complex. The construction of the Hospital being undertaken by State P.W.D. is well in hand and is progressing satisfactorily.

बंगला देश और पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

5275. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के परिणामस्वरूप कितने शरणार्थी पाकिस्तान एवं बंगला देश से भारत में आये :

(ख) उनमें से कितने शरणार्थी अपने अपने देश लौट गये ;

(ग) शेष शरणार्थियों के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(घ) क्या उन्हें भारतीय नागरिकता देकर यहीं बसाया जायेगा अथवा वापस भेजा जायेगा ; और

(ङ) इन शरणार्थियों ने अपने-अपने देश को वापस न जाने के क्या कारण बताये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार को किसी भी ऐसे व्यक्ति की जानकारी नहीं है जो दिसम्बर, 1971 की लड़ाई के बाद शरणार्थी के रूप में बंगलादेश से भारत आया हो। पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आए उनकी संख्या 74,753 थी।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान से आए 53,117 शरणार्थी अभी भी भारत में रह रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 21,000 के लगभग शरणार्थी पाकिस्तान लौट चुके हैं।

(ग) से (ङ). ये शरणार्थी पाकिस्तान के नागरिक हैं। भारत सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे कि ये लोग सुरक्षा तथा सम्मान के साथ पाकिस्तान में अपने घरों को लौट सकें। जिन 5000 व्यक्तियों ने पाकिस्तान लौटने की इच्छा प्रकट की थी उनके नाम पहले पाकिस्तानी सरकार को भेजे गए थे लेकिन उधर से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है।

Indo-Pakistan meet

5276. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: SHRIMATI MRINAL GORE:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have tried to meet Pakistan leaders in order to strengthen freindship between the two countries; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): (a) and (b). There is no proposal at presennt for any such meeting of leaders of the two countries. The two governments do, however, keep in touch with each other on various matters in an endeavour to foster normal relations between the two countries.

Refugee Properties Declared as enemy property by Bangladesh Government

5277. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether properties of the migrants from former East Pakistan have been declared as enemy properties by the Bangladesh Government ;

(b) whether properties of the joint family of the Bangladesh miniorties have also been declared as enemy property if any of its members was found to have migrated to India;

(c) whether properties in Bangladesh which belonged to the migrants from former East Pakistan are being forcibly seized by the Government and some anti-minority public;

(d) if so, whether such developments are against the principles of Nehru-Liaquat Pact of 1950 and the Agreement reached between India and Bangladesh after later's liberation in 1971; and

(e) if so, details of the facts thereabout and the diplomatic steps taken by Government against the measures of the Bangladesh Government in regard to migrant's properties ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b). No Sir. However, the properties taken over by Government of Pakistan as Enemy Property were vested in Government of Bangladesh by Ordinances issued by that Government in 1974.

(c) The Government have received unconfirmed reports and complaints on this.

(d) and (e). This matter was taken up in general terms by India in official level talks with Bangladesh. However there is as yet no inter-governmental agreement between the two countries on the question of such properties.

Construction of Central and Regional office Building of E.P.F. Organisation

5278. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 7 lakhs were paid to the Works and Housing Ministry for a plot at Fire Brigade Lane, Barakhambha Road, New Delhi for construction of Central Office and Regional office Building of the E.P.F. Organisation in 1968-69;

(b) whether the Central Office expend a sum of Rs. 27,000/- for demolishing the structure on the plot and a sum of Rs. 16,000/- were charged as ground rent but the plot was not handed over to the Organisation and the money was paid without any interest; and

(c) if so, why and how the E.P.F. Organisation has been forced to bear the loss of such huge amount and what action Government propose to take to restore the plot and how much time it will take ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) A sum of Rs. 6,37,002·00 was paid to the Ministry of Works and Housing in August, 1970 as premium for a plot of land in Barakhamba Lane, New Delhi.

(b) In addition to the premium amount paid for the land, a sum of Rs. 27,379/- was paid towards cost of 2 old bungalows at the land. Out of Rs. 27,379/- a sum of Rs. 10,055 was realised by disposing material of bungalows. A sum of Rs. 31,850·10 was also paid towards ground rent for two years for the period 5-8-1970 to 4-8-1972, i.e. at the rate of Rs. 15,925·05 per annum.

The plot of land was handed over to the Employees' Provident Fund Organisation on 12-2-1971. The allotment was cancelled by the Ministry of Works and Housing in March, 1973 and possession of the land was taken back by them on 30-6-1973.

The amount of premium was refunded without interest.

(c) The Employees' Provident Fund Organisation claimed interest for the period for which the money remained with the Government at 7% per annum and other expenses, but the claim was rejected by the Ministry of Works and Housing.

Retrenchment of Family Welfare (Social) workers attached to C.G.H.S.

5279. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have issued circulars for the retrenchment of Family Welfare (Social) workers attached to C.G.H.S. ;

(b) if so, how many such workers have been retrenched ; and

(c) steps taken to provide them with alternative employment ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Committee on Steel workers' problems

5280. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to State :

(a) the changes made by Review Committee for steel workers' problems; and

(b) the names of members of the Committee ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) :

(a) and (b). No Review Committee for steel workers' problems as such has been appointed. However, six Working Groups consisting of representatives of Steel Plants' Managements and Trade Unions have been constituted to study various aspects of the working of the steel industry as indicated below and to make available to Government their recommendations/suggestions for its improved functioning :—

(i) Production and productivity.

(ii) Workers participation at all levels.

(iii) Welfare and social objectives.

(iv) Marketing, pricing and finance.

(v) Modalities of having one Union for each plant and one Union for the steel indutry at the national level.

(vi) Perspective of expansion of steel plants and setting up of new steel plants on the basis of funds obtained from outside.

संचार मंत्रालय में अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5281. **श्री राम विलास पासवान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बूजलाल वर्मा) : (क)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	45	12
समूह ख	327	18
समूह ग	46,487	11,835
समूह घ	18,264	4,182

(ख) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सभी तरह के उपाय किये जाते हैं।

जब कभी किसी ग्रेड में भर्ती होती है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित खाली स्थानों की सूचना केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों सहित संघ लोक सेवा आयोग/रोजगार कार्यालयों, जैसी भी स्थिति हो, को दी जाती है अथवा विज्ञापन दिया जाता है। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्याविधि के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का नाम भेजने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मान्यता प्राप्त संघों और संगठनों को भी सूचित किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का "रोस्टर" बाकायदा रखा जाता है।

Technical and Financial Collaboration Agreement with U.S.

5282. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether on the initiative of the previous Government, our telephone

industry entered into technical and financial collaboration agreements with the U.S. Multinational Corporation I.T.T. which was involved in the conspiracy to overthrow the Allende Government of Chile ;

(b) whether the financial collaboration agreement with the I.T.T. has not been terminated todate ;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) whether the Government will consider to forthwith terminate the said agreement ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): a) to (d). Two agreements were signed by the Government of India and the Indian Telephone Industries Ltd. (ITI), with the International Telephone and Telegarph Corporation (ITT) Group on the 21st May 1964.

The first agreement was with the International Standard Electric Corporation (which is a subsidiary of the ITT Group) of New York, for the licencing of manufacture of Pentaconta type of crossbar switching equipment in India and for the grant of a loan of one million US Dollars to the ITI, and investment of 1·25 million US Dollars in the equity capital of the ITI, for financing the Pentaconta crossbar equipment manufacturing project.

The second agreement was with the Bell Telephone Manufacturing Company of Antwerp, Belgium (which is subsidiary of the International Stardard Electric Corporation of the ITT Group), for the Supply of know-how and equipment for manufacture of Pentaconta crossbar exchange equipment in India.

Both the agreements were initially valid for a period of 7 years, from 21-5-64. In order to enable ITI to reach the manufacturing capacity envisaged in the agreement and to enable the Posts and Telegraphs Department to remove the difficulties encountered in the working of the Pentaconta crossbar exchanges, the agreements were extended twice by the periods of one year each beyond 20th May, 1971. During the extended period no royalty was paid by ITI to the ISEC.

The loan of one million US Dollars obtained from ISEC is repayable in three instalments commencing this year. First instalment was repaid by ITI on 23rd May 1977.

The question of purchase of equity shares held by ISEC in ITI is under consideration of Government.

Steps to Eradicate Mosquitoes in Calcutta

5283. DR. SARADISH ROY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware about the large-scale invasion of mosquitoes in almost all the localities in Calcutta; and

(b) if so, the steps taken to eradicate them ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, there is increase in mosquito nuisance in Calcutta.

(b) In the tropical climate eradication of mosquitoes may be difficult but measures to control the nuisance through anti-larval operations have been intensified. For this purpose mosquito larvicidal Oil and other chemical larvicidals have been supplied to Calcutta Municipal Corporation under the National Malaria Eradication Programme (Urban).

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान

5284. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान का यूनिट स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) इस पर कितना खर्च आयेगा और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के ग्रामीण संघटक को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और शहरी कार्यक्रम के समानान्तर एक पृथक परियोजना को सूत्रबद्ध करने के लिए स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से 1977-78 के दौरान एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है ?

Allocation of Aluminium to Karnataka State Electricity Authority

5285. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state whether Union Government propose to allocate aluminium directly to the Karnataka State Electricity Authority ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): No, Sir. There is no problem in regard to aluminium supply to manufacturers of cables and conductors who have firm orders from State Electricity Boards.

Sanjay Gandhi's visit to M.P.

5286. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) dates on which Shri Sanjay Gandhi visited places situated in Baster District of Madhya Pradesh and Singhbhum District of Bihar;

(b) whether N.M.D.C. provided facilities like vehicles, etc. on such occasions and partial holidays were declared in projects situated in those Districts; and

(c) if so, the facts thereof ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Shri Sanjay Gandhi, accompanied by the then Chief Minister of Bihar, visited Hatgomaria in Singhbhum District on 18th December, 1976, and, accompanied by the then Chief Minister of M.P. and the then Union Minister for I. and B., he visited Jagdalpur/Dantewara in Bastar District on 22nd/23rd January, 1977.

(b). and (c) On requisition from the respective State Government authorities, the following facilities were provided by N.M.D.C.:

At Hatgomaria	*At Dantewara/ Jagdalpur*
24 Vehicles	2 fire fighting vans
1 Ambulance	1 Dozer
4 Buses	4 Water tankers
3 Trucks	3 trucks
	1 Ambulance jeep
	Mike, Shyamianas, Sofa sets etc.

N.M.D.C. has preferred bills for Rs. 20,169 and for Rs. 17,998 to the authorities of the State Governments of Madhya Pradesh and Bihar respectively for providing the above facilities.

No holiday was declared, but the employees of N.M.D.C.'s projects in M.P. who were desirous of attending the meeting held at 1430 hours on 23-1-1977 at Dantewara, were allowed to do so.

करिम्चीपन माइका इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मजदूरों की मजूरी का भुगतान

5287. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स करिम्चीपन माइका इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, दोमचंच (बिहार) के स्वामित्व वाली एक बड़ी अभ्रक कंपनी के 8,000 मजदूरों को गत डेढ़ वर्ष से मजूरी नहीं दी गई है ;

(ख) क्या मजदूरों की मजूरी से काटा गया अंशदान तथा कुछ कम्पनी के भाग की 1967 से भविष्य निधि में जमा नहीं कराया गया है ;

(ग) क्या कम्पनी के सभी निदेशक एक ही परिवार के हैं और उनमें विवाद

तथा केन्द्रीय श्रम विभाग की अपेक्षा के कारण मजदूरों को मजूरी नहीं दी गई है और वे बेरोजगार हो गए हैं ;

(घ) क्या कम्पनी की 80 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली सैकड़ों खानें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और मजदूरों की संख्या कम हो रही है ; और

(ङ) क्या सरकार कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगी और यदि नहीं, तो हजारों मजदूरों के रोजगार की रक्षा करने तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) यह सूचित किया गया है कि मैसर्स क्रिसचियन माइका इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (सहायक प्रतिष्ठान) की अभ्रक खानों और अभ्रक कारखानों के लगभग 3,000 श्रमिकों को 6 मास से $1\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि क्रिसचियन माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के छः सहायक प्रतिष्ठानों से 18.76 लाख रुपये की राशि भविष्य निधि अंशदान की ओर देय है।

(ग) से (ङ). यह सूचित किया गया है कि अभ्रक-खानों और कारखानों का उत्पादन और आय कम्पनी के सभी दायित्वों और कर्मचारियों की मजूरी की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। नई दिल्ली में 30 जुलाई, 1977 को होने वाली सभी संबंधित पक्षों की बैठक में सभी सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श किए जाने का विचार है।

Issue of Drug Licences to Doctors

5288. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether prior to 1970, drug licences used to be issued to qualified private doctors for commercial purposes under the Drugs Act; and

(b) if so, whether the some practice is still being followed ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN):

(a) Yes.

(b) Yes.

नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

5289. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है और उसका वर्ष 1974, 1975 और 1976 का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस बारे में किन नियोक्ताओं तथा फर्मों की ओर दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है ; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). दो विवरण 'क' और 'ख' सभा की मेज पर रख दिए गए हैं ;

(ग) (i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में देय राशि की वसूली),

और धारा 14, 14क, 14कक (अभियोजन) के अधीन दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता (विश्वासघात और आपराधिक दुर्विनियोग) की धारा 406/409 के अधीन उनके द्वारा अभियोजन चलाये जाते हैं, जहां नियोजक कर्मचारियों की मजदूरी से भविष्य निधि का कर्मचारियों के भाग काट लेते हैं किन्तु भविष्य निधि में उसे जमा नहीं करते हैं। दोषी नियोजक अनिवार्य रूप से अच्छा वर्ताव करें, इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों की शरण ली जाती है।

(ii) उस तारीख से, जब से अधिनियम लागू हुआ, 31 मार्च, 1977 तक, अधिनियम के अन्तर्गत आये प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरूद्ध 77,412 अभियोजन मामले दायर किए गए। इसी अवधि के दौरान दोषी नियोजकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन 846 शिकायतें दायर की गई।

विवरण 'क'

छूट न प्राप्त कारखानों/प्रतिष्ठानों के नियोजकों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि
(लाख रुपयों में)

	नियोजक का हिस्सा	कर्मचारियों का हिस्सा	योग (2+3)
1	2	3	4
31-3-1974 को	1155.53	750.43	1905.96
31-3-1975 को	1143.95	789.95	1933.90
31-3-1976	1210.18	853.36	2063.54

विवरण 'ख'

ऐसे दोषी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम जिनकी ओर 31-3-77 को दस लाख या उससे अधिक रुपये बकाया थे।

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	प्रतिष्ठानों का नाम	बकाया राशि
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1	दि अजाम जाही मिल्स लि०, वारंगल . . .	17.88
	बिहार	
2	मैसर्स रेलायस फायर ब्रिक्स एण्ड फैक्टरी कं० . .	13.22

1	2	3
3	मैसर्स आर० बी० हरकुट्रोय मोतीलाल जूट मिल्लस .	32.98
	मध्य प्रदेश	
4	हिरा मिल्स, उज्जैन	21.89
5	इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स . . .	73.25
6	कल्याणमल मिल्स, इन्दौर . . .	17.51
7	न्यू भोपाल टैक्सटाईल मिल्स, भोपाल .	14.23
8	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इन्दौर .	12.10
	महाराष्ट्र	
9	दि अप्पोलो मिल्स	32.24
10	मैसर्स ब्रांडबुरी मिल्स लि० . . .	39.62
11	मैसर्स दिगविजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, बम्बई	11.70
12	मैसर्स भारत टेक्सटाईल बम्बई . .	14.94
13	मैसर्स इंडिया यूनाइउटेड ग्रूप्स आफ मिल्स, बम्बई	177.20
14	मैसर्स जय शंकर मिल्स वरसी लि०, शोलापुर .	10.09
15	मैसर्स न्यु प्रताप स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं०, भुलिया	10.46
16	मैसर्स केसर-ए-हिन्द स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बम्बई	16.15
17	मैसर्स ओस्मानशाही मिल्स लि०, नानडेड .	20.87
18	मैसर्स शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, शोलापुर	30.84
19	मैसर्स सक्सरिया कौटन मिल्स लि०, बम्बई	12.29
	तमिल नाडु	
20	केलीस्वरार मिल्स लि० . .	10.39
21	दि सोमासुन्दरम मिल्स लि० .	19.11
22	श्री भारथी मिल्स लि० . . .	13.87
	उत्तर प्रदेश	
23	मैसर्स ग्रर्यटन वेस्ट कं० लि०, कानपुर .	33.50
24	मैसर्स बिजली कौटन मिल्स लि० .	11.15
25	मैसर्स जसवंत शूगर मिल्स, मेरठ . . .	11.68
26	मैसर्स लक्ष्मी रत्तन कौटन मिल्स लि०, कानपुर . .	22.98
27	मैसर्स न्यु विक्टोरिया मिल्स लि०, कानपुर . .	35.96
	पश्चिम बंगाल	
28	मैसर्स बंगाल फाईन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० (फैक्टरी नं० 1)	10.42

1	2	3
29	मैसर्स बंगाल लक्ष्मी कौटन मिल्स . . .	20.89
30	मैसर्स बर्ड एण्ड कं०	14.31
31	मैसर्स कंटून कारपेंट्री वर्क्स	11.06
32	मैसर्स लक्ष्मी नारायन कौटन मिल्स एण्ड एच० ग्रोफिस .	10.77
33	मैसर्स नेशनल ग्रायरन एण्ड स्टील कं० . .	29.02
34	मैसर्स रामपूरिया कौटन मिल्स . . .	19.60
35	मैसर्स श्री महालक्ष्मी कौटन मिल्स . .	11.12
36	मैसर्स शालिमार वर्क्स लि० . . .	22.97
	योग	188.26

बिहार के नालन्दा जिले में बीड़ी मजदूरों की मजूरी का न दिया जाना

5290. **श्री वीरेंद्र प्रसाद** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में तथा बिहार में और नालन्दा जिले में अलग अलग कितने मजदूर बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं ;

(ख) क्या नालन्दा जिले में फैक्टरियों के मालिक बीड़ी मजदूरों को बहुत कम घण्टों का काम ही देते हैं और उनकी मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं करते जिससे मजदूरों की भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) से (ग). देश में बीड़ी उद्योग में नियोजित या काम कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि यह अनुमान है कि समूचे देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 30 लाख है। प्रश्न के अन्य भागों के बारे में सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही हैं और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

5291. **श्री भागीरथ भंवर :**
श्री राघव जी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार को पूरा करने के लिए क्या अवधि प्रारंभ में नियत की गई थी और उसकी पुनरीक्षित समयावली क्या है, और

(ख) क्या परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). आरम्भिक कार्यक्रम के अनुसार भिलाई के 40 लाख टन चरण का विस्तार कार्य दिसम्बर, 1976 में पूर्ण होना था। मई, 1974 में

डिजाइन, निर्माण आदि के विभिन्न कार्य-कलापों की समालोचनात्मक समीक्षा से यह पता चला कि इस कारखाने में उत्पादन 1979 तक होने लगेगा। इसके पश्चात् फरवरी, 1975 में, संसाधनों की उपलब्धि, कार्य की प्रगति, उपस्करों की उपलब्धि, विभिन्न स्रोतों से उपस्करों तथा अन्य आदानों की संभावित सुपुर्दगी और संथारकों से डिजाइन के आंकड़ों की प्राप्ति आदि, जैसे संबंधित तथ्यों को देखते हुए कार्यक्रम में संशोधन करके इसे दिसम्बर, 1981 कर दिया गया था।

सरगुजा में एल्यूमिनियम संयंत्र

5292. **श्री भागीरथ भवर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में निर्यात प्रयोजन के लिए एक एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर क्या प्रारम्भिक कार्रवाई की गई और इस संयंत्र की स्थापना के बारे में कब तक निर्णय लिया जाना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) से (ग). रूसी विशेषज्ञों ने मैनपत भंडारों पर आधारित निर्यात-प्रवण एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना हेतु अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया है कि एल्यूमिना के निर्यात की दृष्टि से इन भंडारों की खुदाई किफायतसार नहीं होगी। परिवहन समस्याओं और अन्तर राष्ट्रीय बाजार के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ इस निष्कर्ष से सहमत हैं। अतः सरगुजा में निर्यात-प्रवण एल्यूमिना संयंत्र कि स्थापना के बारे में आगे कार्यवाही करना संभव नहीं है।

मालंज खान्द तांबा परियोजना

5293. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश में मालंज खान्द में तांबा संयंत्र स्थापित करने के बारे में मई, जून, 1975 में एक विस्तृत प्रतवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजन के लिए धनराशि का नियतन करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 में इस काय के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) रूसी विशेषज्ञों व मध्य प्रदेश की मालंजखण्ड ताम्र परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दो किस्तों में, जनवरी, 1975 तथा जनवरी, 1976 में प्रस्तुत की थी।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) परियोजना हेतु वर्ष 1977-78 के दौरान 5.40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, वर्ष 1977-78 में मध्य प्रदेश सरकार को बंजर नदी योजना हेतु 20 लाख रुपये का ऋण देने का प्रावधान किया गया है जो कि मालंजखण्ड ताम्र परियोजना को पानी की आपूर्ति करेगी।

विवरण

रूसी परामर्शदाताओं द्वारा मालंजखंड ताम्र परियोजना पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रमुख बातें नीचे दी गई हैं :—

1. इस परियोजना की संभावित लागत 91.90 करोड़ रुपये होगी।

2. यह कठोर चट्टानों में स्थित देश की प्रथम खुली खदान होगी। सारा खनन कार्य मशीनों से होगा और मट्टी हटाने वाले भारी उपकरण लगाए जाएंगे।

3. खान के विकास में 16 महीने लगेंगे उसके बाद वास्तविक खान निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

4. निर्माण कार्य शुरू होने के चौथे वर्ष में 10 लाख टन प्रतिवर्ष अयस्क उत्पादन (15,200 टन धातु के बराबर) होने लगेगा। खान के निर्माण के प्रारंभ होने के छटवें वर्ष में उत्पादन बढ़ा कर 20 लाख टन (23,000 टन धातु के बराबर) हो जाएगा।

5. खान के अलावा ; एक सान्द्रक संयंत्र होगा। जिससे प्रतिवर्ष 20 लाख टन अयस्क परिष्कृत किया जाएगा। सान्द्रक का निर्माण, प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 10 लाख टन अयस्क के परिकरण के लिए होगा। जिसे बढ़ा कर बाद में 20 लाख टन कर दिया जाएगा।

6. सांद्रों को मालंजखंड से खेतड़ी प्रद्रावक भेजा जाएगा।

7. इस परियोजना के पूरी तरह चालू होने पर 1862 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है।

गुजरात के जूनागढ़, राजकोट तथा जामनगर जिलों में टेलीफोन केन्द्रों का निर्माण

5294. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जूनागढ़, राजकोट तथा जामनगर जिलों के कितने एवं किन किन नगरों, शहरों तथा गांवों में टेलीफोन केन्द्रों का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है और ये कार्य कब तक पूरे होंगे तथा प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र के अन्तर्गत कितने टेलीफोन लगाये जायेंगे ;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान कितने एवं किन किन स्थानों पर नये टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा उनका कार्य कब प्रारम्भ एवं पूर्ण होगा ; और

(ग) इन तीन जिलों के ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में नये टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) इन जिलों में इस समय किसी टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

(ख) और (ग). संलग्न सूची के अनुसार 27 स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये उनकी व्यवहार्यता का अध्ययन हो रहा है। यदि वित्तीय दृष्टि से लाभकारी हुआ तो इन स्थानों पर चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

स्थानों की सूची

जिला	क्रम संख्या	स्थान
जूनागढ़	1.	बागवादर
	2.	बेदान
	3.	भेंसा
	4.	दलासा
	5.	फाटाना
	6.	धन्दबाद
	7.	खिरसरा
	8.	रघोपुर
	9.	रांणाकंडोरना
	10.	सासनगिर
	11.	सुदारपडा
	12.	खिम्बी
राजकोट	13.	भुपगाढ़
	14.	दहीसारा
	15.	हालिन्द्रा
	16.	जियाना
	17.	खचिया
	18.	लाय
	19.	मकानसर
	20.	माधोपुर
	21.	मोविया
	22.	रिब्दा
	23.	सानोसरा
	24.	शिवराजगढ़
जामनगर	25.	बालाचढ़ी
	26.	बेट
	27.	जामवली

पूर्णिया बिहार में मेडिकल कालेज अस्पताल की स्थापना करना

5295. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है और विशेषकर कोसी अंचल की दशा शोचनीय है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्णिया जिले के मुख्यालय में एक मेडिकल कालेज और अस्पताल की स्थापना हेतु कोई कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख). बिहार राज्य में पहले से ही नौ मेडिकल कालेज हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास उपलब्ध 1975-76 की सूचना के अनुसार इन कालेजों में 1000 छात्रों ने दाखिला पाया था।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कोई नया मेडिकल कालेज खोलने की इस समय कोई योजना नहीं है, क्योंकि योजना आयोग के अनुसार वर्तमान मेडिकल कालेजों से पढ़ कर इतने डाक्टर निकल रहे हैं जो हमारी डाक्टरों संबंधी आवश्यकताओं के लिए काफी हैं।

भारत तथा ईरान के बीच यूरोप से भारत तक रेल परियोजना के बारे में बातचीत

5296. **श्री उग्रसेन :**
श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लंदन से प्रकाशित "फाइनेन्शल एक्सप्रेस" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ईरान के शाह ने यूरोप से कलकत्ता तक रेल परियोजना के बारे में ईरान और भारत के बीच बातचीत में गहरी रुचि प्रकट की है जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंध और आगे मजबूत बनाय जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में लंदन जाते हुए भारत के प्रधान मंत्री जब तेहरान में कुछ देर के लिए रूके थे उस समय उन्होंने ईरान के शहंशाह के साथ बहुत से विषयों पर चर्चा की थी जिसमें दोनों देशों के बीच रेल सहयोग के क्षेत्र में विस्तार करना भी शामिल था ताकि अन्ततः एक ऐसा स्थल-मार्ग विकसित हो सके जो भारतीय उप-महाद्वीप को ईरान से जोड़ दे । इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर दोनों सरकारें विचार कर रहीं हैं ।

News report captioned "Provident Fund Organisation Kind to Congress Friends"

5297. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the report in the Indian Express, dated the 8th June, 1977 with the heading "Provident Fund Organisation Kind to Congress Friends"; and

(b) if so, the reaction of Government thereon and the steps taken by Government on it ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Yes.

(b) The matter is being looked into.

Production of Steel Ingots.

5298. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) total production of steel ingots and saleable steel year-wise from 1974-75 to 1976-77;

(b) total quantity and value of unsold steel as at the end of 1974-75, 1975-76 and 1976-77;

(c) total quantity and value of each category of steel exported during the years 1975-76 and 1976-77;

(d) production cost per tonne of each category of steel exported in 1975-76 and 1976-77;

(e) price (per tonne) at which each category of steel was exported during 1975-76 and 1976-77; and

(f) total loss, if any, incurred by Government on account of steel export during the years 1975-76 and 1976-77 ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) The total production of steel ingots and saleable steel at the six integrated steel plants during the years 1974-75 to 1976-77 is indicated below:—

(In thousand tonnes)

Year	Steel Ingots	Saleable Steel
1974-75	6,264	4,900
1975-76	7,251	5,778
1976-77	8,427	6,922

(b) The total quantity and value of unsold steel with the integrated steel plants under the steel Authority of India Limited as at the end of 1974-75 1975-76 and 1976-77 is given below:—

Year	Quantity (in thousand tonnes)	Value (in Rs. lakhs)
1974-75	543.0	76,287.75
1975-76	1243.8	18,579.33
1976-77	1417.6	22,053.39

(c) The total quantity and value of each category of steel exported during 1975-76 and 1976-77 is indicated below:—

Category of Steel	1975-76		1976-77	
	Quantity in tonnes	Value in Rs. Crores	Quantity in tonnes	Value in Rs. Crores
Ingots/slabs	9,978	1·34	..	..
Billets	1,75,336	25·50	4,50,233	62·53
Bars & Rods	2,49,915	42·84	7,28,462	124·24
Structurals	45,408	9 61	83,493	16·73
Rails	16,198	4·81	1,15,497	39·48
HR/Plates/sheets strips			13,491	2·69
H.R. coils			2,986	0·55
C.R. coils			47	0·01
GP/GC sheets	8,271	2·42	1,265	0·39
Wires	1,035	0·39	9,841	2·93
HR silicon sheets				
Pipes			328	0·13
Tinplates			72	0·04
Special Steel	..		3,537	0.70
TOTAL	5,06,141	86·91	14,09,252	260·52

(d) & (e). Information regarding production cost per tonne of exported steel and the price at which it was exported is not disclosed in the commercial interest.

(f) In the overall position no loss was incurred on the export of iron and steel during 1975-76 and 1976-77.

Prosecution of Maruti Ltd. for violating Labour Laws

5299. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Maruti Ltd. were prosecuted for the violation of various labour laws;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether the infringement of Factories Act, Payment of Bonus Act, Payment of Minimum Wages Act etc. by Maruti Ltd. were brought to the notice of the authorities concerned; and

(d) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). The matter falls essentially in the State sphere. According to the information supplied by the Government of Haryana, so for as the Factories Act is concerned, no violations came to notice at the time of the inspections conducted by the State Inspectorate staff. Prosecutions are however being launched by the State Government for; (i) alleged wrongful termination of services of 28 workmen in violation of the provisions of the Industrial Disputes Act and (ii) alleged wrongful termination of services of a service engineer in violation of the provisions of the Industrial Employment (Standing Orders Act, 1946). Claim application regarding delayed payment of wages for the month of May, 1977 was also filed by the State Industrial Relations Machinery against the management on behalf of 440 workers for Rs. 1,08,659·05 p. before the Authority under the Payment of Wages Act but, the same is reported to have been withdrawn subsequently on the verbal request of the workers following compliance by the management with the reported Punjab and Haryana High Court direction that half wages should be paid to the workers for the months of May and June, 1977.

भारत और इंगलैंड के बीच सीधी टेलीफोन लाइन की सुविधा

5300. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और इंगलैंड के बीच सीधी टेलीफोन लाइन की सुविधा प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी और इंगलैंड के किन-किन शहरों के लिये यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख). प्रयोक्ता सीधी डायल टेलीफोन सेवा, इस समय भारतीय मानक समय के अनुसार बम्बई से लन्दन के लिए 0000/1200 बजे के बीच और नई दिल्ली से लन्दन के लिए 0100/1200 बजे के बीच सुलभ है। सितम्बर, 1977 के अन्त से इसे बढ़ाकर पूरे ब्रिटेन के लिए और 24 सों घंटे सुलभ करने का प्रस्ताव है।

देश में आयुर्वेदिक अस्पताल

5301. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा कितने आयुर्वेदिक अस्पताल चलाये जा रहे हैं और औषधियों, अस्पतालों, डाक्टरों, नर्सों मकानों और वितरण की दृष्टि से एलोपैथिक अस्पतालों के साथ उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करने के अतिरिक्त राज्यों में अस्पताल खोलने अथवा उन्हें चलाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की नहीं है। अत: किसी भी राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं चलाया जाता है। बाद वाले भाग का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूचियां

5302. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूचियों में व्यक्तियों की जिलावार संख्या कितनी है और उनके नाम कब से प्रतीक्षा सूचियों में है; और

(ख) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त हो जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख) . तारीख 1-7-77 को बंगलूर मेट्रोपोलिटन सिटी में टेलीफोन-कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 3863 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे और शेष कर्नाटक राज्य में 514 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। जिलेवार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

बंगलूर में सबसे पुरानी अनिर्णीत अर्जी दिसम्बर 1971 की है। शेष राज्य में 31-3-77 से पहले की केवल 63 अर्जियां अनिर्णीत पड़ी हैं। आशा है कि लम्बी दूरी के कुछ कनेक्शनों को छोड़ कर सभी वर्तमान आवेदकों को सितम्बर 1978 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1.	बंगलूर, मेट्रोपोलिटन टाउन को छोड़ कर .	3
2.	बंगलूर, मेट्रोपोलिटन टाउन . .	3863
3.	बेलगांव . .	57
4.	बेलारी . .	10
5.	बिदार . .	1
6.	बीजापुर . .	10
7.	चित्रदुर्ग . .	4
8.	चिकमंगलूर .	57
9.	कुर्ग . .	66
10.	धारवाड़ . .	43
11.	गुलबर्गा . .	कोई नहीं
12.	हसन . .	27
13.	कोलार . .	11
14.	मण्डिया . .	18
15.	मैसूर .	68
16.	उत्तरी कनारा .	9
17.	रायचूर .	9
18.	दक्षिण कनारा .	115
19.	शिमोगा	6
20.	तुमकुर . .	कुछ नहीं
	योग .	4377

Advertisements given by certain Foreign Embassies in Indian Newspapers

5303. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Russian, North Korean, Cuban and other Communist Embassies in India are freely permitted to give advertisements and supply news-items and other publicity materials to the Indian newspapers;

(b) if so, whether similar freedom is enjoyed by the Indian Embassies in the above Communist countries;

(c) if so, facts thereabout and the occasions when the Indian Mission in these countries issued advertisements, news-items of publicity materials to the newspapers of these countries;

(d) whether such materials supplied by the Indian Embassies were ever published in the newspapers of these countries; if so, facts thereabout; and

(e) if not, the reasons for giving unilateral freedom to the publicity drive in India by these Embassies ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Indian Missions abroad also enjoy this facility.

(c) and (d). As a matter of policy Indian Missions abroad do not conduct publicity though paid advertisements by the Government. Our Press Releases however are carried sometimes by the newspapers free of charge.

(e) Question does not arise.

12·34 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT ON THE VISIT OF FOREIGN MINISTER OF JAPAN TO INDIA AND ANNUAL REPORT OF CENTRAL COAL MINES RESCUE STATION COMMITTEE, DHANBAD FOR 1974-75

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, I beg to lay on the Table (1) A statement (Hindi and English versions) on the visit of the Foreign Minister of Japan to India from July 19 to 22, 1977. [*Placed in Library*, See No. LT-843/77].

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working of the Central Coal Mines Rescue Stations Committee, Dhanbad, for the year 1974-75. [*Placed in Library, See* No. LT-844/77].

RE. CALLING ATTENTION NOTICE

ठाकुर बलदेव सिंह (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, पुंछ सैक्टर में पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीयों के ऊपर पिछले छः दिनों फायरिंग की है। सात पाकिस्तानी और तीन भारतीय जख्मी हुए हैं—समाचार और पैट्रियट रिपोर्ट। पाकिस्तानियों द्वारा दर्जनों केसेज कैटल लिफ्टिंग के छम्ब-जोरियां सैक्टर में पिछले चन्द दिनों से हो रहे हैं। मैंने काल अटेंशन भी दिया और तीन बार शौर्ट नोटिस क्वेश्चन भी दिया लेकिन मुताल्लिका मिनिस्टर से कोई जवाब नहीं मिला। जम्मू-कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान के साथ है और लोगों को डर है कि 1971 की लड़ाई में जैसे छम्ब इलाका पाकिस्तान को दे दिया गया था वैसे ही फिर और कोई इलाका तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कोई ब्यान नहीं दिया है। सरकार से अनुरोध है कि इस पर कोई स्टेटमेंट दे, जिससे क्लेरिफिकेशन हो और शंका दूर हो।

12·35 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STRIKE IN KIRIBURU IRON ORE MINES.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): Sir, I call the attention of the Minister of Steel and Mines to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"Reported indefinite strike in the Kiriburu Iron Ore Mines of National Mineral Development Corporation following the failure of conciliation efforts."

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Kiriburu is one of the major mechanised iron ore mines of the National Mineral Development Corporation located in Singhbhum district of Bihar with about 1,600 employees. A scheme for expansion and modification of the scheme to produce annually 1.17 million tonnes of lump ore and 2.66 million tonnes of fines to meet the requirements of Bokaro Steel Plant has recently been completed and is undergoing commissioning trials.

The wages of N.M.D.C. workmen are being paid in accordance with the tri-partite wage settlement arrived at between the unions of N.M.D.C. and the Management in the presence of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central). As per this agreement the minimum wage paid to the lowest category is basic Rs. 290 per month, fixed D.A. Rs. 62 per month and variable D.A. Rs. 55.30 per month, totalling Rs. 407.30 per month. Additionally, the employees and their dependents are entitled to free medical facilities and free educational facilities for their children. Housing is also being provided for 70 per cent of employees at subsidised rent and those not provided with houses get house rent allowance. Transport facilities are provided from place of residence to worksite.

The Jharkhand Mazdoor Sargh, N.M.D.C. Workers Union, N.M.D.C. Shramik Sargh, Kiriburu jointly submitted on 1-6-77 a notice to go on strike from 18-7-77 if 46 demands presented by them were not acceded to. The Management initiated discussions with the Union representatives and the matter was also taken up in conciliation proceedings on 8th and 9th July, 1977 by the Assistant Labour Commissioner (Central), Chaibasa. The conciliation proceedings ended in failure but the

[Shri Biju Patnaik]

Management of the N.M.D.C. again held discussions with the Unions on 13-7-77 in an effort to resolve the dispute.

On 16-6-77 the Chairman, SAIL invited the Union representatives to come for discussions of their demands either at Delhi or Hyderabad and made an appeal to them not to precipitate matters and to put off the strike till the discussions were held. The Unions refused to put-off the strike and wanted all their demands to be conceded. The Management however discussed the 46 demands with the Union representatives and accepted 26 of them. On the night of the 16th July, 1977 the Unions informed that they could defer the strike provided eight demands were met, especially an *ad-hoc* payment of Rs. 2,000/- per workman.

On 17-7-77 the Unions further communicated that the most important demand to be conceded was the cash payment, which they reduced from Rs. 2,000 to Rs. 1,000, for all workers on an *ad-hoc* basis and without any justification. In an attempt to avert the strike the Management offered on 17-7-77 to pay 15 days wages to workmen on purely *ad-hoc* basis and to be adjusted against any amount due on account of final settlement of the various demands. Unfortunately, however, this offer was rejected by the Unions and they commenced the strike at Kiriburu on 18-7-77 at 06-00 hours.

The General Manager (Industrial Relation), SAIL accompanied by Director (Production) N.M.D.C. and the Regional Labour Commissioner, Dhanbad again visited Kiriburu on the 21-7-77 to hold renewed negotiations to call off the strike. The offer for payment of *ad hoc* advance of 15 days wages was reiterated and the Management also agreed to consider introduction of production based incentive bonus from the current year. The Unions however did not agree to call off the strike. A further round of negotiations is being held at Hyderabad on the 30th July, 1977 by the Chairman, SAIL and the Union leaders from Kiriburu have been invited for discussions.

1265 regular staff and 146 daily workers are involved in the strike. 207 workmen are attending to essential services. A total production of 60,000 tonnes valued at Rs. 16 lakhs has been lost upto 26th July, 1977.

The Management is exercising extreme restraint in dealing with the situation which has remained peaceful so far. However, there are reports of picketing on the roads leading to the Mines Office by the workers, provocative speeches by the Union Leaders instigating students to boycott schools and threats to supervisors attending to their duties etc.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I have gone through the statement made by the hon. Minister who tries to depict a rosy picture of the situation in the mines in Kiriburu. Certain basic factors which led to the situation had been ignored in the statement. Firstly, the local management is behaving in relation to the workers in an extremely arrogant manner. Most of them are tribal workers and that behaviour leads to the kind of tension all the time. All along the demand of the workers has been that the management should behave with them properly; that has never been looked into.

Secondly, government itself had given a direction in May 1975 that no more contract system should prevail in the mines; still contract system is prevailing even in those mines which are owned by the NMDC. Another important thing is that—this is a matter of national interest—even export is entrusted to Tatas and Dharamchand Jain and such big business houses. There are cases where even NMDC staff members had been beaten by the mine contractors. You can imagine what fate the poor workers will meet in the hands of contractors. A very arrogant management is often conniving with contractors. These facts never found mention in the statement. I was amused to hear the Minister's statement saying that the workers presented 46 demands and the government was prepared to concede 26. No solution can be found on a quantitative basis. The main points about bonus and incentive scheme which was taken away were not accepted. I should like the hon. Minister to enlighten this House on certain questions. The poor workers' representatives are called to Delhi and Hyderabad for negotiations. What prevents the Chairman of SAIL himself from going to Kiriburu along with senior officials and negotiate a solution there? Small officers who are sent do not have powers to settle the matter finally. The man with the authority is the chairman of SAIL and instead of representatives of the three unions and their advisers coming to Delhi, the chairman can go there and talk with the representatives. Would the hon. Minister direct the chairman to go to Kiriburu to conduct the negotiations?

Secondly, what are the important demands which the government cannot accept? Those are the most important demands on which the workers are agitated. Will the hon. Minister take a conciliatory attitude, as the workers have taken, to find a solution? The Minister read emphatically that the workers demanded Rs. 2,000 per head and they have come down to Rs. 1,000, as if to say: look, these are unreasonable demands. I must say that this is a conciliatory attitude shown by the workers and it is in that spirit you should negotiate with them. Mr. Fernandes will understand that. He should send a senior official including the Chairman to find a settlement. I hope Mr. Fernandes and Mr. Dandavate will support this.

SHRI BIJU PATNAIK: I have nothing more to add. I think the hon. Member, whose party heads that Union, has rather misfired in making this agitation. The Government and the NMDC would always be prepared to discuss and come to any reasonable settlement in the context of the social order. I made bold to mention yesterday in another debate on the employment question that if we take the total facilities available to the mine workers in NMDC, it would come nearly to Rs. 500 per month. They are entitled to ask for more. Anybody is entitled to ask for more, for that matter. But just two miles away from there, the workers in other mines, who do not belong to NMDC, hardly get Rs. 5 a day, without housing and such other facilities. Of course, it is within the rights of one set of workers to ask for more. I do not deny that. But there must be some reasonableness. In the social order, there cannot be high-paid staff and well paid Ministers or, MPs here and the lowest worker getting Rs. 2 a day. I would recommend to the hon. Member that instead of fighting for a lost cause, we should get round the table. I have instructed the Chairman of the SAIL. Hyderabad was chosen because it is the Head Office of NMDC and that is where all the papers will be available and the matter can be settled. The workers there, whom the hon. Member calls poor, are not so poor. But anyway, their travelling charges will be met by the NMDC.

12.45 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) DISMISSAL OF THE MINISTRY IN TRIPURA

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Speaker, Sir, this is a different matter which is regarding the dismissal of the Tripura Ministry and installation of a new Ministry there by the President under article 356 of the Constitution. I am least bothered about the internal quarrels of the Janata Party where their own Chief Ministers have been overthrown by their own party men and then coalition Janata-CPM forming new Ministries.

The Speakers' Conference has recommended that the strength of the Government or the majority enjoyed by the Chief Minister should be tested on the floor of the House. When the Congress Government was in power and whenever there was any dismissal of a Government, the hon. Members on that side, who were then in the Opposition, criticised us on this ground. But now, the Chief Minister has not been given an opportunity to prove his strength even though he claims to have a majority in the Assembly, and the Government has been dismissed.

The Constitution is very clear. The President has to take over the charge. He can proclaim President's rule. But that should be done on the basis of the report of the Governor to the President when the Assembly is not in session, and when the President is satisfied that there is no majority. Then, of course, he can direct the Governor to dismiss the Ministry and impose the President's rule there. But there is no provision in the Constitution giving the Governor the authority to dismiss the Government *suo-motu*. This is a vital question. When the House is in session, I think, propriety demands the Home Minister to come before the House and make a statement about the dismissal of the Government and the installation of a new Government in Tripura. This House has every right to know as to what happened in the State, and whether they have acted according to the Constitution. What is the policy of the Government to test the majority enjoyed by the Chief Minister. Is it done on the floor of the House or are you satisfied with the Governor's report? Will it not be proper on the part of the Home Minister to come and make a statement as to how a Government has been dismissed and how a new Government has been installed. This is my point.

(ii) REPORTED CONFLICTING STATEMENTS BY MINISTERS ABOUT USE OF AND REPEAL OF MISA

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, As directed by you I raise the following under rule 377 :—

It is reported that the Union Commerce Minister, Shri Mohan Dharia, told a meeting of the ruling Janata Party today that the government would have to think whether or not they should take recourse to some of the measures like MISA and DIR against the anti-social elements to check the rise in prices. In this context, Shri Dharia said that some elements are taking advantage of the liberal attitude of the government with regard to the use of the Preventive Detention Act and MISA. He also said that the government will not hesitate to take strong measures in this regard.

On the one hand, the above was said by the minister of the government; on the other hand Shri L. K. Advani, Minister for Information & Broadcasting, said in Rajya Sabha that the government stood by its commitment to repeal the MISA and the special committee of the Home Ministry was seized on the matter. This, Shri Advani stated 26-7-77.

The Janata Party is committed to repeal all preventive detention acts and in its election manifesto in page 9 para 3 it says "As a party wedded to the ideals of freedom and democracy, it believes that fearlessness is of the essence. It will therefore, take immediate steps to free the people from the bondage of fear. It will restore to the citizen his fundamental freedoms and to the judiciary its rightful role."

"To generate fearlessness and to revive democracy the Janata Party will:

(3) Repeal MISA, release all political detenues, and review all other unjust laws;"

This we expect that, after a lapse of 4 months now, there is no hesitation in the minds of Janata government that it us under obligation to repeal the MISA which is long overdue.

At the same time, we are also mindfull of the fact that blackmarketeers, hoarders, speculators, economic offenders and other anti social elements should be dealt with firmly. For this the government should enact suitable laws to deal with such persons who are enemies of the country and the people. We do not want that any detention without trial should be allowed to continue under any circumstances.

The Home Minister is here, Sir, and I have drawn his attention.

MR. SPEAKER : He is not getting up.

12.53 hrs.

STATEMENT *RE.* AVAILABILITY OF CEMENT

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : Sir, there have been innumerable complaints of non-availability of cement and also of blackmarketing in cement by the dealers. During the last few days, I have talked to many people in the cement industry and asked them to discipline the dealers. I have publicly asked the dealers not to indulge in black-marketing taking advantage of the shortage in cement supplies. I have told them that cement should be sold at the statutory price and when stocks run out, they should have a sign board to that effect.

The final answer to the present situation is more production of cement. But more production is not a short term solution, though I am trying my best to see that the industry improves its efficiency and performance and some more cement is produced. With the improvement in the power situation, there will be some more production in the normal course. The cement units that have perennial power problem are being allowed to put up small captive diesel power plants immediately.

While some of our export commitments on cement have to be fulfilled for more than one reason, I am looking into the possibility of deferring a few of our programmed exports. In this way, there can be some additional stocks available for domestic consumption.

There is one area where I need and seek your immediate help. There are about 50,000 stockists of cement in the country. While many of them are honest traders, some of them are obviously finding it difficult to unlearn their habit of black-marketing. It is these recalcitrant elements who are not only fleecing the people but also giving a bad name to the vast community of honest traders. I have asked the cement industry to issue immediate directions to the stockists to associate people's representatives with the distribution of cement. In precise terms, I have asked them to have their stockists to (1) display daily stock position; (2) to display the price of cement; and (3) to associate a committee of people's representatives of the locality with the distribution of cement.

I have written to the State Governments to bring these suggestions to the notice of all elected legislators so that they immediately involve themselves with the setting up of these committees. I have also asked them to direct the District Collectors to help in the formation of such committees.

Checking prices and policing those who try to take advantage of shortages to fleece the people is a non-partisan task. I would urge all Members of Parliament to help the government in this effort.

12.55 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377—*contd.*

(iii) FAMINE CONDITIONS IN NORTH BIHAR DUE TO FAILURE OF RAINS

MR. SPEAKER : I have overlooked one notice under Rule 377. Mr. (Hukmde) Narain Yadav may please speak.

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कई दिनों से इस प्रश्न को उठाने का प्रयास कर रहा था। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब दक्षिण बिहार में बाढ़ आती है तो उत्तर बिहार में सूखा पड़ता है और जब उत्तर बिहार में बाढ़ आती है तो दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। इस समय दक्षिण बिहार में पानी बरस रहा है, लेकिन उत्तर बिहार में जो हमारे नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, दरभंगा, मधुबनी में अकाल पड़ रहा है। मेरे पास लगातार वहां से टेलीग्राम आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं, टेलीफोन पर भी लोगों ने सूचना दी है—पानी न बरसने के कारण धान की खेती आबाद नहीं हो रही है। एक भी स्टेट ट्यूब-वैल चालू नहीं है। एमर्जेन्सी के दौरान जितनी नालियां बननी थीं, उन का सीमेंट ठेकेदार चुराकर ले गये। कमला एग्रीकट योजना के अन्तर्गत जो नहरें बनीं उन में पानी नहीं है, क्योंकि नदी में ही पानी नहीं हैं। तमाम कृषक, खेतिहर मजदूर बेकार हो जाने के कारण गांव छोड़ कर भाग रहे हैं। सरकारी गोदामों में गल्ला नहीं हैं। जो मजदूर खरीद कर खायेंगे—उन के पास इतनी क्रय-शक्ति नहीं है कि वे खरीद कर खा सकें। भयंकर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, उन के घर का अन्न समाप्त हो रहा है। इस लिये मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार जल्द से जल्द एक टीम वहां भेजे, जो उस इलाके में जा कर जांच करे, क्योंकि बिहार सरकार के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वह इस स्थिति का मुकाबला कर सके।

मैं एक बात साफ़ तौर से कहना चाहता हूं—हर पांच साल बाद हिन्दुस्तान पर अकाल की छाया पड़ती रही है। आप 1947 से लेकर आज तक देख लीजिए,—1947, 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, और अब यह 1977 निश्चित रूप से हिन्दुस्तान में अकाल का वर्ष है जिसका प्रारम्भ मधुबनी और दरभंगा से हो चुका है। इस आने वाले अकाल को रोकने के लिए सरकार को अभी से सक्षम होना चाहिए। आज दरभंगा, मधुबनी अकाल की लपेट में आ गए हैं, वहां पर लोग भूख से मरने जा रहे हैं। यदि जल्दी कार्यवाही नहीं होगी तो हज़ारों लोगों की जानें वहां जाने वाली है। इस लिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से उन की ज़िन्दगी की हिफ़ाज़त के लिए कार्यवाही करे, जिस से वहां की खेती आबाद हो सके और उन लोगों को राहत मिल सके।

12.58 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FOURTH REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : Sir, I beg to move :

> "That this House do agree with the Fourth Report of the Business Advisory Committee Presented to the House on the 27th July, 1977."

SHRI JYOTIRMOY BOSU : (Diamond Harbour) Sir, you will kindly recollect that in the Business Advisory Committee we agreed finally to list two other discussions, about the housing problem in Delhi which was raised by Mr. Kanwarlal Gupta and about Sundarbans.

MR. SPEAKER : We said we would consider at the next Meeting.

The question is :

"That this House do agree with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 27th July 1977."

The motion was adopted.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Sir, about the legislative part, I would like to draw your attention to Rule 343. Rule 343 says :

"No member shall anticipate the discussion of any subject of which notice has been given provided that in determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought befor the House within a reasonable time."

MR. SPEAKER: You are referring to Lokpal Bill ? I have examined your letter.

SHRI P. K. DEO : Let me finish my submission. I also draw your attention to rule 66 which says :

"A Bill, which is dependent wholly or partly upon another Bill pending before the House, may be introduced in the House in anticipation of the passing of the Bill on which it is dependent

Provided that the second Bill shall be taken up for consideration and passing in the House only aftr the first Bill has been passed by the Houses and assented to by the president."

Rule 67 deals with identical Bills.

13 hrs.

I am glad that the Home Minister is going to introduce a Bill under the name Lokpal Bill but these rules which I quoted, act as an estoppel, before he introduces his Bill. My Bill is a baby of the present Prime Minister when he acted as the Chairman of the Administrative Reforms Commission. It is a carbon copy of that Bill, and that Bill is being partly discussed. It is coming for discussion tomorrow and it will also be disposed of tomorrow, as only 2 hours have been allocated for it. Taking into consideration all these factors, I submit that we should not break the various rules which have been enshrined in this book. I submit that heavens will not fall if the Home Minister introduces the Bill on Monday, after my Bill is disposed of.

MR. SPEAKER : I have examined the scope of both the Bills. The two Bills are not identical. The point of order is over ruled. No further submissions are allowed.

SHRI P. K. DEO : My Bill may be improved upon by the Home Minister.

13.02 hrs.

LOKPAL BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS SHRI CHARAN SINGH : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the appointment of a Lokpal to inquire into allegations of misconduct against public men and for matters connected therewith.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli) : I want to say something.

MR. SPEAKER: You have written to me but your objections are unsustainable. you can move an amendment to the Bill.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: I have followed it. Let me put my views before the House.

MR. SPEAKER : Are you opposing the motion ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : The rules are clear. If there is legislative incompetence, he can raise it.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE : Why should the hon. Member interrupt me ?

The Speaker has allowed me. It is quite clear ....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Let us see the rules. The proviso to rule 72 says :

"provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

Mr Gotkhinde, you say that the Leader of the Opposition is not consulted.

*Published in Gazette of India Extraordnary, Part II, section 2, dated 28-7-77.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: It is a very serious matter.

MR. SPEAKER : You can move an amendment.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Not that. Let me place my views. I am opposing the motion for leave to introduce the Lokpal Bill, 1977, under rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, on the following grounds: (*Interruptions*)

Clause 4 of the Bill provides for the appointment of Lokpal. In the Notes on Clauses of the Bill, it is stated that the method of appointment of a Lokpal is in substance the same as provided in sub-clause (i) of clause 3 of the Lokpal and Lokayuktas Bill, 1971, with the variation that instead of consultation with the Leader of the Opposition in Lok Sabha, consultation with the Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha has been provided.

Clause 3 of the Lokpal and Lokayuktas Bill, 1971 which related to the appointment of Lokpal provided that :

> "The Lokpal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India and the Leader of the Opposition in the House of the People, or if there be no such Leader, a person elected in this behalf by the Members of the Opposition in that House in such manner as the Speaker may direct."

That was a very salutary provision with a view to treat the Opposition with due importance.

On 26-7-77, when the matter of not seating the Leader of the Opposition in the front row during the ceremony for swearing in of the President was raised in the Lok Sabha, the Prime Minister has said :

> "Personally and as head of the Government also, I have said always that we want to give full importance to the Opposition."

That was a gracious assurance..(*interruptions*) It seems, however, that the Government is, so soon, going back on that assurance by deleting the provision for consultation with the Leader of the Opposition in the matter of appointment of the Lokpal....(*interruptions*)

MR. SPEAKER : Please sit down. The objection is over-ruled.

The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the appointment of a Lokpal to inquire into allegations of misconduct against public men and for matters connected the rewith."

The motion was adopted.

SHRI CHARAN SINGH : I introduce† the Bill.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : Sir, I would like to seek a clarification. As regards the list of business for tomorrow, in the order paper you may have to change the order of business. My. hon. friend, Shri Deo, raised a point earlier, rather prematurely; he could have raised it later on, but he raised the point I would like to ask, Sir, in your wisdom and judgment, you will kindly bear this in mind that his Bill has been partly discussed This Bill has been long over due, and we welcome it with all our heart, because it promises to become a land-mark in the history of parliamentary democratic legislation in our country. In the list of business for tomorrow his Bill is also there on the Order Paper. I would be glad, and so would be my hon. friend, Shri Deo, and really the whole House, if discussion on that Bill is adjourned and the next Bill in order shown in the list of business for tomorrow is taken up.

MR. SPEAKER : You persuade him to do it.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : You may have to do it yourself, Sir.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : Sir, there has been one ruling on this point for your guidance. In the Fifth Lok Sabha there was a Constitution Amendment Bill and many Bills on the same subject given notice of by Private Members. At that time the Speaker had given the ruling that, as far as Private Members, Bills are concerned, even though such Bills are already there, they cannot obstruct the Bill which is brought by the Treasury Benches. Of course, it is left to the Member either to withdraw his Bill or not. But there is no difficulty, as far as procedure is concerned. Private Members' Bills cannot obstruct

†Introduced with the recommendation of the President.

[PROF. MADHU DANDAVATE]

any Bill that has come from the Government side.

MR. SPEAKER : I have already mentioned that.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : This Bill becomes infructuous.

MR. SPEAKER : Is he good enough to withdraw his Bill?

SHRI P. K. DEO : (Kalahandi) I have my bitter experience in the matter. I have been here for the last 20 years. The previous Government introduced an identical Lokpal and Lokayukta Bill in the Fourth Lok Sabha and the Fifth Lok Sabha, which never saw the light of day.

MR. SPEAKER : But this will see the light of day.

SHRI P. K. DEO : In the Fifth Lok Sabha also it was introduced.

MR. SPEAKER : The only question is whether you are thinking of withdrawing it.

SHRI P. K. DEO : No, Sir.

PROF. P. G. MAVALANKAR : (Gandhinagar): If he does not withdraw it, what happens? According to our procedure, it will automatically lapse.

MR. SPEAKER : If he does not withdraw it, we will decide what to do with the Bill.

PROF. MADHU DANDAVATE : In the Fifth Lok Sabha the Speaker had given a clear ruling that a Privte Members' Bill will be rejected when a similar Bill is brought forward by the Treasury Benches.

MR. SPEAKER : I will see what to do tomorrow. We will now adjourn for lunch till 2·15 p.m.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after lunch at seventeen minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MOTIONS RE: UNEMPLOYMENT PROBLEM—*Contd.*

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Mr. Deputy Speaker, Sir, Government has declared its aim of removing unemployment within ten years. This Motion focusses the attention of the Government and of all others on that statement as I understand it, but some of the hon. Members do not seem to think that this is possible or that this will be done. I have no quarrel with that kind of pessimism or scepticism. The question is by no means an easy one; I have no doubt about it. I cannot say that this question was not tackled in the past by previous Governments. They tried, but its consideration remained more on paper than in the actual field. Therefore, we do not want to get caught into mere propaganda. We will try to frame such plans as can be implemented. We can then convince the people that they are being implemented.

But when it is said that we must have a target date for giving right of work to all people, it cannot be until we have solved this problem. We cannot fix a date. I will not be able to give work to all the people all at once. It was also suggested that we give subsistence allowance to those who are not fully employed or who are partly employed. Is it realised that the amount required will be not less than 4000 crores a year? More than that, this will simply create a tendency not to work in those people who receive doles. This I saw in other countries where doles are in vogue. Therefore, the problem is not merely of subsistence but of giving them work. Work should, I think, be ultimately satisfactory work and not any work just enough to earn something everyday. This is how we have got to tackle it. But to begin with it may not be possible to give work to everybody. Even that could have been possible. As a matter of fact, I had proposed 15 years ago when I was the Finance Minister and the Third Plan was being considered, that in every State 25 to 30 or 50 lakhs, according the to size, should be set apart and every panchayat and every municipality should offer work to anybody who wants work. He does the work and takes the wage of course that would be a wage which would not be a large wage; it may be a small wage, smaller than what obtained in the market at that time, probably something similar to what we do in scarcity areas. But hardly any attention was paid to it by the Centre or the States. It remained merely a proposition. We do not want to commit any mistake. And, therefore, we have said that this problem can be solved only if we see that the villages are strengthened and that there is no unemployment in the villages. There is unemployment in the cities too. I am not saying that there is no unemployment in the cities. But in the cities, unemployment is more of the educated than of the uneducated. In the rural areas, there are more partly employed than totally unemployed. There are some totally unemployed also. But

some people have work only for two months in a year or three months or four months but not more than six mohths. This is how it is. Take, for example, Srinagar or Kashmir. When the tourists start coming, they work for five months and after five months, many of them remain idle. Therefore, there is that kind of unemployment which has also ruined us. Even if partial employment gives enough money for livelihood throughout the year, it is deleterious to the human personality and to the growth of human endeavour. It is, therefore, necessary that there should be full employment given to all people. In the villages, the smaller cultivator also is very partly employed; he has no full employment. Therefore, we can solve this problem only by enabling them to take up cottage industries and help them to do it. But they can be helped when they are willing to take it up and, therefore, this will have to be tackled more non-officially than officially. It is not Government administration which is going to tackle it completely. I do not think it is possible to do that. Therefore, we are trying to mobilise all non-official agencies which we have got to do it like Khadi Commission, Panchayats, municipalities — smaller municipalities I am talking of— and social service institutions which work for the welfare of the people. That is why we have to prepare to progress in a manner where all of them feel the necessary enthusiasm to take up this work and to see that the people take to it readily and take full part in the programme. Then alone we can make a dent on this problem. That is how I look at it.

This does not mean that we are excluding industries from all areas. That is not so. But I am certainly not in favour of having these industries in the villages which will disturb the whole atmosphere of the villages and vitiate it. But it must be a satisfying employment for the villagers. It does not mean that they should be treated as second-class citizens. That shouid not happen. Agriculture can be cultivated in a manner where it will begin to grow from prosperity to prosperity and even through cottage and small scale industries life in the country-side will improve because better methods an be devised progressively by farmers and artisans themselves. They have to be enabled to do these things.

This relates to education. Therefore, education has to be overhauled. But overhauling is easily said but not only easily done. We are engaged in that task. But unless wecreate an atmospehere for it, any planthat we make is not likely to succeed. It is, therefore, that one has got to go very warily aboutit but not rest complacently. On that score, I have no doubt. We have got to bring in urgency in this matter. That is what we are trying to to do. I think, our people have the capacity to do this and, I hope, with the cooperation of all people, we will be able to tackel this problem satisfactorily.

This is not a matter where politics should be brought in. That is what I would like to urge. Of course, when my hon. firend, Shri Chandrappan, brings in capitalism; another friend brings in communism and if we go on like that, the whole thing will be defeated. I would beg of them not to hinder this programme. There is no capitalism in it; there is no communism in it. This is what we have to see. Whether it is individual capitalism or whether it if State capitalism, it is capitalism. And State capitalism is worse than individual capitalism because there is no check on State capitalism. The State can check individual capitalists. But who is going to check the state ? Therefore, capitalism in that sense is not desirable either by the State or by individuals. Unless there is full democracy and full freedom assured to the people, I do not think we can make a proper progress as we want to make it. In that, I would certainly want the cooperation of all people. At any rate, if the bulk of the people give cooperation, I am not worried in that case because we can overcome the other opposition and also bring then round us. It should not be very difficult.

SHRI K. LAKKAPPA : (Tumkur) : I agree with you. But I want to know whether we can advocate capitalism of any nature, individual capitalism or State capitalism.

SHRI MORARJI DESAI : I would like to advocate a method which will take away the opposition from Mr. Lakkappa. That is all I should like to do. This is not a matter where we have an intellectual superiority in argument or otherwise. This is not how I am looking at the question. This question is most important for all of us and no Government can afford to neglect it. I do not say that the past Government also deliberately neglected it. I am not one of those persons who say that. Unfortunately, they were bound up with too many ideas which were more difficult than pracital. And it was more paper work than work in the field. That is why, it did not materialise. Unless you take all the people with you and they are enthused about it, it is not possible to succeed in this programme.

We have also to see that we produce all consumer goods in abundance because prices are related to it and if we do that and keep down that cost of

[Shri Morarji Desai]

production by efficiency, I am quite sure prices will be under full control. Then alone the poor will have a good deal or a fair deal. Otherwise, they will never have a fair deal, whatever one may do if prices go on rising.

There is one thing which has happened, which has gone against this country. It does not allow us to make much progress. The affluent countries in the world have all taken to a high cost economy and that is perhaps inevitable in the method that they have adopted. We are imitating them without realising the requirement of our country and we are also going into that high cost economy. That is why, we are finding it difficult. We must bring down the cost of production and also increase the production. Both are related to each other and there should be no waste. The kind of affluence which we see everywhere—I am not enamoured of it—is more of a handicap than an asset in my view. We should guard against it and then alone the disparity will disappear, Otherwise, the disparity will never disappear. Whatever one may do, that disparity will not disappear merely by the rod.

Then if you encourage corruption and nothing else but corruption than it is greatest canker from which we are suffering today. In all walks of life, wherever we see, there is adulteration and there is corruption. Even ideas were getting adulterated completely. This is what is happening. Therefore, we have got to see that we bring in an honesty of purpose in this task. Then alone we will achieve what we want to achieve. I can have, therefore, no quarrel with the hon. Members who have spoken on this motion. They, want that this programme should succeed. I welcome all suggestions in this matter for the plan to be made or the programme to be drawn up and it should be a common endevour. And I have no hesitation in saying that if we work that way, we are bound to tackle this problem successfully in ten years. That certainly is the time for which we ought to work. It is possible that ten years may become 12 years or ten years may become nine years. We should tackle in that manner; we should not be complacent about it, but we should not also be talking or working in the air. If our purpose is common and if we do not try to take advantage of each other due to some temporary situation, I am quite sure that this programme can be tackled. I am sure a good purpose would be served by discussion that is taking place on these motions. Beyond that, I hope this resolution will not be pressed.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : When will the Government come out with an outline of this programme ?

SHRI MORARJI DESAI : As quickly as we are able to do. We do not want to delay it. But, it is very difficult for me to give a time. If I give a time, then I must do it.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : This is an urgent problem.

SHRI MORARJI DESAI : We have given these guidelines to the Planning Commission, and they are working on it.

SHRI O.V. ALAGESAN (Arkonam) : When you come with the Annual Plan, will you be able to indicate the outlines ?

SHRI MORARJI DESAI : Before the end of this year, certainly. By the next budget, you are bound to know. If we do not do it by the next budget, it means that we have not succeeded in it ; we cannot go on postponing it indefinitely like this.

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore) : But, in the meantime, the unemployment problem is taking a serious form.

SHRI MORARJI DESAI : We are trying to tackle it in the meantime also, As I said, we should give work in the rural areas; we should give work to those who want to work. The work can be on roads, on sanitation, on buildings and on rural housing. We can do that and give the work to all people. In the same way, we can give work to the educated unemployed by pushing through the adult education programme by just enlisting all of them in this task. Then, that can also be tackled. These are the things on which we are trying to work.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I would like to bring to the notice of the hon. Prime Minister that those who are already in service are being thrown out. For example, the jute mills, one after the other, are being closed and thousands and thousands of workers are getting out of employment and there does not seem to be any wayout. We do not know how to tackle it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing unemployment and those who are not employed; you have brought up the problem of those who are employed, but are being thrown out.

SHRI MORARJI DESAI: We will try to take care of that also, but it would not be done in the way my hon. friend wants. We will have to change his attitude also; if he does not do it, I will

have nothing to do with him. Let me say that clearly.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I am prepared to go to any length, but I want you to take some action.

SHRI MORARJI DESAI: We will certainly find some wayout for that also.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): The Prime Minister has given the time limit for his outline as the next year budget and I fully appreciate that position. But I would request him to give us some indication for the kind of concrete schemes or programmes that he has in mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He was just enumerating some.

SHRI MORARJI DESAI: My hon. friend is a professor. Has any professor ever given any exact things and he wants me to do that ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Professors usually theorise.

SHRI MORARJI DESAI: He is a good professor; I would not say that he is not a good professor. If a professor becomes exact, he will cease to be a professor. That also is different.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Who taught you exactness ? Was it not your teacher ?

SHRI MORARJI DESAI: I have great respect for teachers, but I taught myself exactness, not my teacher; let me tell you that. It was the education in science which gave me exactness and I learnt it from that. That is why, one has to teach oneself and one can enable others to do that; one can help others to do that. Unless everybody learns himself, nobody can teach him. On that score, I have no doubt. That is why, I have been saying that we have got to create an atmosphere where people will be willing to do it. Then, we can help them to do it. This is what we have not attempted so far. This is what we have to attempt. That is why, I have profited by it and we are trying now to do it in that way. One has to be intensely practical in this matter and then tackle it taking into consideration the conditions in this country. That is what I want to do. We have one advantage. Our people are simple; they are easily satisfied. If they feel that they have a hope and they will get a fair deal, they will cooperate; I have no doubt in my mind, but we have to convince them about it and that is what we want to do. I would only request my hon. friends to have some patience with Government, so that we are able to put before you what is required to be done. I do not want to talk much; I want to do more, talking more will not do.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) : Kindly give us at least an outline of what you want to do ?

SHRI MORARJI DESAI : Do my hon. friends think that I have a proper scheme which I am not divulging ? I do not want to keep anything back, but I do not have an exact scheme just now. I have put my ideas before you what I want to do. This is the line. How can you want me to tell you that this is a, b, c, d, etc. ? That I will tell you at the end of the year and not earlier.

SHRI SAUGATA ROY : I want to know from the Prime Minister if the government has any work guarantee scheme on a national scale through which they will be able to provide either employment or unemployment dole to all the work-seeking people in the country. Is the government taking up any such work guarantee scheme ?

SHRI MORARJI DESAI : There will be no unemployment dole. On that score I have absolutely no doubt, whatever you may tell me....

SHRI SAUGATA ROY : It is good that you said it.

SHRI MORARJI DESAI : I have said it often and I will go on stating it, whether I am here or I am there—that makes no difference to me. I said that there also and I am saying it from here also. But, we will try to see that temporarily those who have no work are also given work, not what they want but some work. That is what we would like to do and that is our object and that is what the Planning Commission is engaged in. That also does not mean that we will be able to do that for all the people. That is not possible. I cannot make wild promises in this matter, but we want to do it and that is what we will do.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : From the reply it is my impression that the magnitude and gravity of the problem has not been seriously gone into. This is my feeling.....

MR. DEPUTY SPEAKER : What is the clarification you want ?

SHRI SAMAR MUKHERJEE : That is my feeling even after 30 years of our independence....

SHRI MORARJI DESAI : You want to give a lecture.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : It is not a question of lecture. We want that people must get jobs. If that is not done, we have to lecture not once, but day in and day out we have to speak on that.

My feeling is and what I also want to impress upon the Prime Minister is that the question of unemployment and the question of poverty are both interlinked and one cannot be solved without the solution of the other and the whole 30 years experience is....

SHRI MORARJI DESAI : Why don't you ask them?

SHRI SAMAR MUKHERJEE : I am asking you. I want to impress upon the Prime Minister....

SHRI MORARJI DESAI : This is not an occasion to impress upon me. You can ask for a clarification, nothing more than that.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : The question is that the whole process has to be reversed but the way the government is proceeding, the process cannot be reversed. Only some reliefs and some jobs here and there will not do. This type of attitude must change.

SHRI MORARJI DESAI : I am afraid my hon. friend has either totally misunderstood me or he has not paid attention to what I have said.

It is not correct to say that we do not understand the gigantic proportion of the problem. If I had not understood that, I would have made some definite statement just now. I know that the problem is gigantic and, therefore, difficult. Therefore, I do not want to get caught into some kind of a slogan. That is what I do not want to get done. That is why I have given only the general outline of what we propose to do. Beyond that I cannot say. And I shall be very grateful to my hon. friend Mr. Mukherjee if he gives me a plan for it. I will discuss it with him and I will take it if it is better than what I think. I will adopt it.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : We have some positive plans also and that we are prepared to place before you.

SHRI SAUGATA ROY : Why don't you take a leaf from Maharashtra ?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum) : I am very patient. But I want to know if nothing much can be done this year with regard to your promise that within ten years the unemployment problem will be solved, how will you be able to keep up your promise ?

SHRI MORARJI DESAI : That can be seen only when the plans are before you....(*Interruptions*) Not after ten years. Every year you will see that.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR : The Janata Government has said that they will try to solve the problem of unemployment within 10 years. Now, from your speech I understand that this year, whatever be your reason, there is not much scope for giving new employment in the present circumstances. If that is so, will you be able to keep your promise to give employment to all within ten years. One year is already over. You have to complete it in nine years. Let us have some idea.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : He said that immediate task is to meet the challenge of educated unemployed like doctors, engineers, and all that. You have no concrete package programme for this year or next year. The percentage of employment that you are going to provide is also not there. In view of all this will you kindly have an unemployment cess so that we can meet the challenge and we can minimise the unemployment problem ?

SHRI MORARJI DESAI : He has a suggestion of unemployment cess. I do not approve of that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : I will just cover one or two points briefly. Shri Bedabrata Barua said yesterday, "It is no use blaming the Congreess Party, although I admit that they committed certain mistakes."

Within thirty years of rule whatever rural economic structure was there which the Britishers had left, the whole thing has been destroyed. They have put more ideas on capital intensive industries. At the same time they have destroyed the labour intensive devices and labour intensive industries. The Unemployment Committee had gone into this problem at length. That unemployment Committee's Report has remained untouched. Here I would appeal to the hon. Prime Minister that this Unemployment Committee's

Report which was submitted to the Government be taken into consideration by the Government once again seriously and that will save a lot of trouble in formulating the Plan which the hon. Prime Minister proposes to bring before the House by the end of this year.

It is a matter of deep regret that even the figures of unemployment are not available because it proved to be unpalatable to the erstwhile ruling party. We would like to know what Shri Biju Patnaik has said about this.

To-day we have 125 sick textile mills. What is this sick industry business, we have yet to understand ? In olden days, as I have known, when an industry went sick, the owner's kitchen went dry. His motor car had to be sold. He had to reduce his expenses. They went broke. Now on the one hand industry becomes sick, on the other hand he spends Rs. 10 lakhs on the marriage of his dguahter. Now sick business has also become an industry. Making industry sick has become an industry also. What are they doing ? They are siphoning the book money. They are making the book money dry and black money swollen and fat. Demonetisation should be brought in. This was categorically recommended by the Wanchoo Committee in its interim Report in 1970. Mrs. Gandhi destroyed it. It was never allowed to see the light of the day. I place that copy on the table of the House.

Shri Biju Patnaik is not here. Unless that is done, sick business will not end.

Shri Biju Patnaik gives statistics. Rs. 3,000 crores will be required @ Rs. 4 per day for two crores of unemployed. Why not consider it as a productive investment on human resources ? This will, I have full faith, ultimately enhance productive capacity of the nation.

There should be a national unemployment fund and a cess on income above Rs. 12,000 on a slab basis. The higher the income, the higher should be the rate. It could be imposed by an enactment here. Government should apply its mind to this matter. We can go in for this employment insurance. With this insurance plus this cess, a combined effort could be made to ensure this. The unemployment people are at present starving and fighting for their survival. We have to see whether we can give them some amount of money which can give them something to keep them alive. I really expected much greater detail from the Government because although he has stated that they are not prepared to say anything or give out anything before the end of the year, you will understand this, that when we go back to the constituencies and face the people there, they are not willing to wait. The man who is starving is not willing to wait for another day more. He asks us : 'You are well looked-after; you dont know where the shoe pinches'. Therefore, they expect this Government to realise their difficulties. This problem has therefore become very acute.

Therefore, it is my request that in keeping with the promises which they have made before the electorate in their manifesto they should come forward with all the energy and resources at their command with a positive plan so that we can deal with this problem effectively.

The hon. Prime Minister talked about Adult Education. He talked about eradication of illiteracy. We should look to the problem of providing employment to the educated unemployed. We shall all be very happy if the hon. Prime Minister come before the House with a positive plan in this behalf as early as possible,—if possible, in the winter session,—and that is a thing which will be very much appreciated. You know the technicalities of this Motion and it is a matter which cannot be decided within the four walls of Parliament, through voting or pressing the button. Therefore I would request the hon. Prime Minister to make a categorical statement in this respect, on the lines which he has already made, that within 10 years the unemployment problem has to be solved. This is number one. Number two is this. When can we expect the follow-up work of enshrining right to work in the Constitution in the Fundamental Right chapter so that we can proceed ahead with all combined efforts in this direction ?

SHRI MORARJI DESAI : I have already said, 10 years. Only when that is done can it be enshrined in the Constitution.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: When can we expect the CPI(M) to come out with a plant for West Bengal ?

SHRIJYOTIRMOY BGSU : we d n't have economic powers. Let the Central Government come out with a target date,— ney convenient targnt date which they think desirable. this is my request.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has already told you.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I am not going to press it for voting. Let them say, the target date for enshrining right to work would be 10 years or 5 years or 3 years, whatever they think possible for them.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very happy because of two things. One is that the Members in this House generally expressed their serious concern about the problem. They came forward with concrete suggestions. That is a very good thing. But I am more happy because of the disarming frankness with which our Prime Minister talked today. I like that frankness of Shri Morarjibhai for which he is quite known. He came and told to this House and to the country that the Jantha Government does not have any concrete programme. He only-like many other people in the past—expressed good wishes and pious hopes that the problem will be solved. There is no dearth, Sir, if you look into history where you find such desires have been expressed by great people. That was the cherished goal of every religious preacher and philosopher. Our Prime Minister also shares that. But as a Prime Minister and as an Administrator of this country—as a leader of the party who got mandate from the people—I expected a more positive and for thright programme from the Prime Minister. I am disappointed there.

Sir, he said that even these days ideologies are also adulterated. Well, I see on that side the un-adulterated capitalist ideology is being pursued. (*Interruptions*)

Yesterday Mr. Biju Patnaik was here. Today—unfortunately for me—he is not present. He was pleading for private capital. I can understand that. His thought-provoking speech provoked me to probe into certain things. I have gone through the *Statesman* of 29th January, 1971 which reported the Bharatiya Kranti Dal Manifesto and that manifesto was described by *Hindustan Times* in an editorial on 18th February, 1971 that it bears the stamp of the thought of Shri Charan Singh—the hon'ble Home Minister today. What does that manifesto say, according to *Statesman* :

"The BKD believes that democracy is founded on ownership of property .."

It also believes that a wdse dispersion of private property is the only answers only assurance that democracy is safe and will endure."

(*Interruptions*)

Sir, about private property.....

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : जनाब मेरा पोंइंट आफ़ आर्डर है। अर्ज यह है जी कि आवड़ी अधिवेशन में डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म का प्रस्ताव पास हुआ था, और उस प्रस्ताव का नतीजा यह हुआ कि कुछ घरों में सरकार रह गई और कुछ घरों में पैसा रह गया। तो मैं समझती हूं कि अगर उसी का नाम डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म है तो हमारी पार्टी की आइडियालाजी ठीक है।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Sir, about private proprty, I would like to quote Karl Marx:

"With adequate profit capital is very bold, a certain 10% will ensure its employment anywhere, 20% certain will produce eagerness, 50% positive audacity, 100% will make it ready to trample on all human lows, 300% and there is not a crime at which it will scruple, nor a risk it will not run even to the chance of its owner being hanged."

It was Karl Marx who said this, a person who started the greatest revolution in the world, liberated mankind from poverty, unemployment and many other things.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Unfortunately in his days liberty was destroyed.

SHRI C.K.CHANDRAPPAN: I want to reiterate that unless you choose a different path, a path which is not the capitalist path, you will not succeed in solving the problem of poverty, unemployment and illiteracy. For solving the unemployment problem the hon. Prime Minister has said that will be done in 10 years and for illiteraty, it will be done in five years. On two subjects, we have bead discussions in this House. We have discussed one subject now and two weeks ago when we discuss the other subject, it was made clear that five years would not hold good. Nothing

will happen and even today with the announcement of the Prime Minister with his disarming frankness, there is no concrete programme, only philosophy. Then it makes it clear, it makes it explicitly clear that the problems of unemployment is going to remain with us for the coming decade, perhaps it is going to become more and more accentuated in the coming period. In the circumstances, I do not want to propose anything new. All that I want to propose is: have confidence in the people (*Interruptions*) Do not shout. I will not be shouted down. It will not solve the problem. Sir, I have confidence in the people.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: People have no confidence in you.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : People reposed confidence in you. My hon. friend Mr. Mishra will not dispute the fact that we heard for the last five years about the massive mandate which Mrs. Gandhi got from the people. Today Congressmen are not sitting there. Let him not forget that lesson. If you follow the same path and betrary the confidence bestowed in you by the people, I am sure you will face the same calamity, the same tragedy which the Congress Party and Mrs. Gandhi had faced. In 1971 Mr. Morarji Desai came into this House with a strength of 12 Members; he was sitting behind. But that was not the end of history; that was not the end of the story. Today he is Prime Minister. Let everybody keep that lesson in mind. Those who betray the confidence bestowed by the people will not be pardoned by history; they will be thrown into the dustbin of history by the people; let everybody including Prof. Dandavate remember that. Yesterday the esteemed Prime Minister told me that I was a pessimist. I am not a pessimist. I again wish him success, I do not want to press my motion to a vote, not that I will not get votes here. I will get votes from this side. Many will press the red button there with a pricking conscience. Yet I do not want to press my motion to a vote because I am giving you time. I am patient. Outside we will mobilise people. On the 2nd of next month, hundreds of young persons will come here, unemployed people from all over the country, and discuss the problem of unemployment. I hope you will find time to receive a delegation from them so that they can put forward their suggestions.

श्री एच॰ एल॰ पटवारी (मंगलदाई): आप के म.थ संजय गांधो आयेगा ।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Do not repeat the mistakes of Sanjay Gandhi. I conclude by saying that I wish him well again. Still I have my doubts whether you will succeed. The capitalist path had been pursued and many people went ahead through that path; many wisemen with boldness and more resources and power went through that path and every one of them perished. The only solution to this problem is, let me say once again, socialism.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are two amendments. He wants to withdraw. Has Shri Hukmdeo. Narain Yadav leave of the House to withdraw his amendments.

SOME HON. MEMBERS : yes.

Amendments Nos. 1 and 2 were by leave withdrawn

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I have already said in my speech that I want to withdraw my resolution.

MR. DEPUTY SPEAKER : Has Shri Jyotirmoy Bosu leave of the House to withdraw his resolution ?

SOME HON. MEMBERS : Yes .

The motion was by leave withdrawn.

MR. DEPUTY SPEAKER : Has Mr. Chandrappan leave of the House to withdraw his resolution ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

The motion was, by leave, withdrawn.

15·04 hrs.

MOTION *RE*: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): On behalf of Shri Charan Singh, I beg to move the following:

"That this House do consider the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively."

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): On a point of order, Sir

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Why should he move it on behalf of the Home Minister ? Has he taken your permission ? Is he a proxy or stepney minister ?

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : The Home Minister was here just now !

PROF. MADHU DANDAVATE: He was here. He was not feeling well and he has gone out for a few minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER: He has taken my permission. I have given him permission.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की यह परिपाटी रही है कि जब यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट पर डिबेट होती थी, तो गवर्नमेंट द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उस के साथ दी जाती थी। पहले 1966 तक ऐसा किया जाता रहा, और फिर 1972 में यह तय हो गया कि गवर्नमेंट द्वारा जो एक्शन लिया जाएगा, उस की रिपोर्ट भी संसद को उपलब्ध की जाएगी। मंत्री महोदय आज 1974 तक की रिपोर्ट्स बहस के लिए पेश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, उस की रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। जब तक वह रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती है, तब तक इस विषय पर बहस करने का कोई मतलब नहीं होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Actually we are now discussing the reports. It is not necessary that we should have the copies of the action taken reports. It is not statutorily reguired. You may refer during the debate to the action taken or not taken.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : What about substitute motions ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. members whose substitute motions to the Government Motion have been circulated may, if they desire to move their substitute motions, send slips to the Table within 15 minutes, indicating the serial numbers of their substitute motions they would like to move.

The time allotted is 12 hours.

SHRI HITENDRA DESAI (Godhra): Sir, we are discussing three reports together—20th, 21st and 22nd reports—covering four years. As was very rightly pointed out—it may not be a point of order, but it is certainly a point for the Government and the House to consider that there is no statement of the government indicating what action has been taken on the recommendations made in these reports. We would like to know whether there are statements indicating acceptance or rejection of these recommendations.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, rder There is too much noise in the House. Those who want to leave may leave silently.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, आवाज नहीं आ रही है।

श्री हितेन्द्र देसाई : आ जायेगी, आप जरा शान्त रहें।

चौधरी बलबीर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आवाज ठीक नहीं आ रही है और कोई मेम्बर कहता है तो यह हंसी में उड़ाने की बात नहीं है। आप सिस्टम को ठीक करिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि आप जरा बार-बार उठ कर आवाज न करें तो आपको सुनाई पड़ेगा।

SHRI HITENDRA DESAI : I will straight go to the last Report and the second Report. And before discussing the various details, I will refer to a survey made by the Madhya Pradesh Harijan Sewak Sangh, *vide* page 182 of the 22nd Report. They had a *padayatra* for 21 days in 527 villages of 11 districts in Madhya Pradesh. The names of these districts are given in the foot-notes. I will not take much time in a detailed investigation of it. It is very revealing that so far as entry into the temples was concerned, out of 527 villages, 140 villages

had no temples. Out of 437 villages, in 217 villages Harijans had no access to the temples.

So far as taking tea at the stalls was concerned, only 38 villages were there where Harijans were allowed to take tea. 124 villages denied Harijans even an entry into the tea stalls. If you go a little further, so far as barbers' services were concerned, out of 527 villages, only 49 villages catered to the needs of the Harijans in this regard. In regard to washermen's services, out of 527 villages, only 31 villages catered to that need. As far as equality of social status in the panchayats was concerned, the *padayatra* survey says that only in 299 villages was there equality of status for the Harijans.

This is the situation that prevailed not only in Madhya Pradesh, but in many parts of this country. I would now refer to an incident mentioned at page 187 about atrocities on Harijans. There are a number of incidents quoted there. I am picking up an incident which occurred at Ranmalpura village in the district of Surendragarh in the Saurashtra region of Gujarat. The incident took place on 22-6-1974. I will not give many details about it. I have personal knowledge of those incidents. As the wells from which the Harijans were taking water had dried up, they were using another common well: and the village people did not like that Harijans should use that well. (*Interruptions*). During the period of these reports, Congress government was not there; but I am not discussing this from that angle at all. I do not wish that the House should discuss it from that angle. On 22-6-1974 there was some quarrel between the women-folk of Harijans and caste-Hindus. The women-folk of caste-Hindus were enraged and they informed their menfolk; and after receiving that information, practically the whole village, armed with 'dharas', and lathis and other weapons, rushed towards the Harijans. They even saw to it that the houses were set on fire. 2 Harijans were killed, and they practically made a hell of that incident. As my hon. friend, Shri Kamath, was asking I may say that I was not in the Congress at that time; I was in the opposition. I went to that village Ranmalpura and I was happy that the leaders of all political parties went there. As it was under Rashtrapati Shasan the Governor went there immediately, the next day, and tried to solve some problems.

श्री नाथू सिंह (दौसा) : इसीलिए क्या आप कांग्रेस में चले गए ?

SHRI HITENDRA DESAI : If you want to know, I will tell you on some other occasion.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप अपनी और उनकी उम्र का खयाल कीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Reddy, I think Mr Hitendra Desai can reply to that.

SHRI HITENDRA DESAI: I am referring to this incident to show that atrocities have been there. There is no denying that. It is futile to discuss it on a political plane. Let us also, so far as this problem is concerned, try to look at it and try to grapple with this problem rather from an all-party point of view. My point is, when the Governor himself went there after the incident, he could pacify the Harijans. I could see for myself that the Harijans were pacified. I am quoting these two incidents, to start with, to show the real picture that exists in this country even today; not only during 1974 but even today. There is no much difference, so far as prevailing conditions are concerned.

I am worried about a certain trend which has taken place today. To start with, I will refer to this trend also. We are dealing with a population of 8 crores, according to the 1971 census, plus 4 crores of Scheduled Tribes. As rightly pointed out, the first report, the 20th Report, was presented to the House on 11-5-73. The second report was presented on the 28th August 1974. The last report was presented to this House on the 5th May 1976. And yet, I do not know whose fault it is, whoever is at fault, the fact remains that they were not discussed till today, that they are being discussed today. They are so late after the events, because those events happened almost 6 to 7 years ago. A remark was made "your Government". But that is not the point.

PROF. R. K. AMIN (Surendranagar) What is the point?

SHRI HITENDRA DESAI : I am coming to that. Why do you worry?

Shri Amin need not feel disturbed.

[Shri Hitendra Desai]

Therefore, even today we can say, even in those reports, presented so early, there are no statements of Government with regard to action taken by them on various recommandations. I tried to make a search in the library, I must frankly admit, and I got one statement about the 21st Report. We do not know what action has been taken on the various recommendations of the 22nd Report. Even today we do not know whether the Government have received reports for 1974-75 and 1975-76; of course, not for 1976-77. This shows the attitude of Government, not merely of this Government, but of all Governments.

When the budget was being discussed we were told that the annual Plan would be now raised by more than 25 per cent. I tried to get an idea of the provisions made for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the budget. The House would be pleased to know that in 1976-77, the Plan provision for the welfare of Scheduled Castes was Rs. 17 lakhs. In the present budget it is Rs. 20 50 lakhs. The revised estimates for 1976-77 was Rs. 24 85 lakhs. So far as the welfare of Scheduled Tribes is concerned, the revised estimate of 1976-77 was Rs. 27 71 lakhs. In the current year it is Rs. 29 66 lakhs. The total provision for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes in the present Budget is Rs. 1,60,63,000 against Rs. 144,86,000 earlier. There is no improvement worth the name. That is exactly what I am driving at. We could have certainly expected more provision to have been made in the present Budget inasmuch as even the corresponding increase in the various sectors is not taken care of.

Another trend which is disturbing is that there is practically an incomplete Council of Ministers and that there is no representation to the scheduled castes and scheduled tribes in it. We do not count the Defence Minister as representing the scheduled castes as, after all, his stature is very high. In the last Cabinet I understand that out of 60 Ministers, eleven represented the scheduled castes and scheduled tribes. I am sorry to say that in the present Cabinet, barring the Defence Minister, there is not one person who represents the interests of the scheduled castes and scheduled tribes. This is relevant for this reason that even the founding fathers of the Constitution envisaged certain things. For instance, article 164 of the Constitution lays down:

> "The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
>
> "Provided that in the States of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work."

So it is very necessary, and I am making this constructive suggestion, that there must be a Minister who is in charge of the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes. Now that we know that the Ministry is being expanded, I hope Government will consider this aspect also.

Another important trend which is worrying us all is the number of incidents involving Harijans. I am not merely referring to the number of incidents, and it would be very unwise to compare in numbers this immense problem about which every body is worried. We know for certain that exactly two months ago, on the 27th of May, practically at this hour or a little earlier, from 12 to 3 p.m., a very ghastly incident took place at Belchi. The Home Minister was pleased to make a statement in the House in which he said that after all it was something of a fight between two gangs of criminals. Then discussion took place in this House and in the Rajya Sabha also, and there is some consolation because the Home Minister later clarified or rather improved upon his earlier stand. This is what he said in the Rajya Sabha:

> "The dastardly incident was so grave that the Minister has no words to express his anguish over it. The Janata Party was determined to end such atrocities and see to it that the weaker sections of the society received justice. There might be certain economic reasons in the occurrence of such incidents, but the social malady of casteism with which our society was afflicted was the main reason behind such cases of atrocities and injustice."

He very clearly admits that position that the Belchi incident was not merely a clash between two gangs of criminals

it was something where the Harijans were oppressed. That point has been taken.

We are grateful to the various Members of Parliament who really visited that place. And I am proud to say that the Members belonging to all parties particularly that Committee was headed by the Secretary of the Janata Parliamentary Party and there were 7 other Members of whom three were from the Janata Party two from the Republican Party and two from the Congress Party: it was an all-party committee—have come to the following conclusion :

> "The fact-finding Committee of MPs on massacre of Harijans in Belchhi in Bihar has found that the Home Minister, Mr. Charan Singh's statement, based on the report of the State Government, that the incident was the result of a clash between two groups of hardened criminals was "totally false".
>
> The Committee has also held that the Government version that the gruesome murders were not based on caste and social inhibitions was "totally incorrect".

I will not read the whole of it because of shortage of time. At the end, it says:

> "We are of definite opinion that the police were in league with the culprits and deliberately delayed their arrival to the village so that the culprits may accomplish their misdeed. The reported statement of the Bihar Government that there was a clash between two groups of hardened criminals having long standing rivarly is totally false."

I am quite sure all the Members of this House will speak on this subject. But I would very strongly urge on the Home Minister to institute a judicial inquiry into the incident because in the Rajya Sabha he has said:

> "The Centre had suggested to Bihar Government that action should be taken now. There was the popular Government there. They had already appointed a committee consisting of Members of the Assembly. The Centre has urged the State Government to institute a judicial inquiry in to the incident."

Even thereafter, I have got a number of press cuttings. If I merely make a mention of them, it will take a long time of the House. Even reports coming from different parts of the country especially from UP, are, to say the least, alarming.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : The percentage is higher in M.P.

SHRI HITENDRA DESAI: I am glad that the Home Minister has given the percentage. I have never said at any point of time that there was no incident. I quoted an incident which has occurred in 1974 when the Janta Party was not in power. So, it is not the question of percentage but what attitude do we adopt. There was another incident in UP where after the party victory, the landowners have started troubling landless people. I do not want to quote in detail for want of time. But it is very clear that incidents have been taking place. The percentage may be less or more.

Lastly, I will refer to another incident which took place in Ramnagar village in Gorakhpur District on July 10. It was interesting to read the debate in the Assembly where an adjournment motion was tabled by Shri Chaudhari, a Janta Party Member and there was a debate on that. In the press report it is said:

> "The Janta Party member, Mr. Chaudhari, informed the House that a 'Yadava' youth accompanied by two sub-inspectors of police and other police personnel of the Maharajganj Police Station, arrived in the Ram Nagar village on July 10...."

Mr. Chaudhury further said:

> "After all the crops were cut, houses set on fire, the police thereafter lathi-charged the Harijans and also fire shots in the air to scare them. In all, 45 Harijans including 20 women sustained injuries some of them seriously. 11 Harijans including a 12-year old boy returning from school at that time were taken to the Maharajganj police sation and further beaten up by the police."

"It is a matter of shame for the Government", he said.

I think, the Government instead of comparing the earlier figures should immediately try to inspire confidence amongst specially the weaker sections of the Society. I would suggest the appointment of a Judicial Commission to investigate and inquire into the various incidents which have taken place in the last several months. That is my main suggestion. I will discuss other aspects so far as this Report is concerned. At this stage, I want to make some sug-

[Shri Hitendra Desai]

gestions for the hon. Minister to consider. Firstly, I have said about the appointment of a Judicial Commission. Secondly, I have also said about giving the charge of the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to a full-fledged Minister. Thirdly, I would recommend a separate Commissioner for Scheduled Castes and a separate one for Scheduled Tribes. I would very earnestly request the hon. Minister to bifurcate this post. Let us have two separate Commissioners, one for Scheduled Castes and another for Scheduled Tribes separately.

The hon. Minister is an experienced administrator. We have also experience of that. We know that the problems of Scheduled Castes are not the same as the problems of Scheduled Tribes. Their economy is different; their problems are different. I think, it will satisfy the sentiments of this House and the sentiments of all people with whom I have come in contact if we have two separate Commissioners, one for Scheduled Castes and another for Scheduled Tribes.

Now, I come to the actual Report. There are three Reports. Practically, the problems are the same and, for the sake of convenience, I will mainly refer to the last Report, the Twenty-second Report for the year 1973-74. Apart from the atrocities and untouchability to which I have referred, the main problem which we want to tackle and which we have been tackling so far is from the education point of view. If you refer to page 75 of the Report, you will find that so far as primary education is concerned, which is the main concern of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the enrolment is extremely poor. I will take the latest figures of 1973-74. As regards Classes 1 to 5, in the case of Scheduled Castes, it is 68·9 per cent and in the case of Scheduled Tribes, it is 59·3 per cent as against 90 per cent enrolment in the general sector. As regards Classes 6 to 8, the general enrolment is 40·4 per cent whereas in the case of Scheduled Castes, it is 22·1 and in the case of Scheduled Tribas, it is 15.7 And for classes IX to X, it is 25·4 per cent for the general, 11.5 per cent for the SC and 7·9 per cent for the ST. Scheduled Tribes are the worst, so far as education is concerned. Therefore, we have to go a long way even for universalisation of primary education and specially the attendance of girls has been very poor.

We can particularly see the problems of the tribals. The problems of the ST are very special problems and unless some special attention is given, these special problems will not be solved. From our experience in the various States, especially in Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh, there have been ashram type schools or what we call ashram schools. About it, a statement is given on page 29 of this Report. I am not going to read it out for the purpose, but it is clear that the States of Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra have faired much better than the other States. I would very earnestly request the Home Minister to consider the extension of these facilities where they are not available.

From our own experience, we find that the normal primary schools are not adequate enough for these tribals. These tribals have their own problems. Even their children have to work. About the ST persons, unless some residential schools and more and more funds are made available, you will not be able to spread education, so far as SC & ST are concerned. In Gujarat and Maharashtra, some of these ashram schools have been managed by private agencies, by persons who adopt constructive and Gandhian outlook.

AN HON. MEMBER: That is purely for the Harijans.

SHRI HITENDRA DESAI : It is mainly for the tribals. For instance, in an area like Danges, if you go there even today, you will not find whether any civilization exists there. For the normal schools, the dialects is different. The teachers will have to be trained in that dialect. The education will have to be given in that dialect. All these problems are there. It is not possible for me to go into all these questions, but I am particularly emphasising the recommendation which the Commission has made in this Report about the extension of these facilities. I would only refer to one paragraph which is on page 79. The only recommendation is that more and more ashram schools should be there. Similarly, a provision for the mid-day meal should also be there, because after all they are very poor in diet. The nutrition is not good and even for giving them incentives, this mi-day meal arrangement has been successful in both the States.

So far as scholarship is concerned, the main complaint has been about the delay, and on page 86 of the Report, the recommendation of the Commission is there. All attempts should be made to see that those who are entitled to scholarships get them without any delay, without any lengthy procedure.

AN HON. MEMBER: And in time.

SHRI HITENDRA DESAI: Of course, in time also. Then girls' hostels are absolutely necessary considering their life, their utter poverty and utter ignorance. You must have girls' hostels and the Commission's recommendation is there on page 81 of the Report. That is the very reason why I have raised an objection that unless we know whether the Government has taken any action on this recommendation, how can we say whether there is any improvement or not. That is the main point. I hope we will be able to know when the Home Minister will reply to our debate. I think he will agree; he will not bring politics, so far as these educational problems are concerned and see that the welfare activities of the Harijans and the Adivasis should be properly nurtured. There is one small point about the voluntary agencies. Some of the voluntary agencies are very good. But our only anxiety has been that, of late, some politics has gone into these. We must have a healthy practice of seeing that, so far as these activities are concerned, the voluntary agencies should be above political considerations. Then only we will be able to reap full benefit out of these.

Then I come to another question, a very vexed question, which has been discussed in this House off and on. I would not have much time to discuss it. I am referring to representation in the services of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. For recruitment made by open competition on an all-India basis, the reservation for Scheduled Castes is 15 per cent and that for the Scheduled Tribes is 7.5 per cent; in respect of recruitment in other cases, the reservation for the Scheduled Castes is 16·66 per cent and that for the Scheduled Tribes is 7.5 per cent. On page 97 of the Report, the statement is really illuminating. Only the day before yesterday, I think, the Railway Minister was very eloquent about what steps he had taken about recruitment to railway services, but he cleverly evaded the question as to what percentgage has been getting employment in the Railways. This is the statement; I will read the last year's figures. But before that, I would read from the latest statement published in the Annual Report of the Home Ministry, 1976-77, which was presented at the time of Budget discussion because that would give us the latest picture. There we find that, in 1976, the percentage employed in the case of Scheduled Castes in Class I—the reservation for the Scheduled Castes is 15 per cent and that for the Scheduled Tribes is 7.5 per cent; that norm, we have to keep in mind—was 3.46. The Railway Minister never gave these figures. Class II 5·41 per cent; Class III 11·31 per cent. I am reading from page 38 of the Report for 1976-77 of the Department of Personnel and Administrative Reforms. So far as the Scheduled Tribes are concerned, the picture is completely dark: the percentage of Class I employees is 0.68 per cent in 1976; Class II 0.74 per cent; Class III 2·51 per cent. This is the position.

15·48 hrs.

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

We have seen that not a day passes when Members are not anxious to know what exactly is the reservation percentage in the services. So far as IAS and IPS are concerned, the position is much worse. The Members may refer to page 39 of the same Report; I am not reading that for want of time.

Therefore, the position of the Scheduled Castes is bad and that of the Scheduled Tribes is much worse. Yet, as I was pointing out at the preliminary stage, the attitude of the Government, the attitude of those who have to employ them is hardly sympathetic. That is where we make a grievance of it.

Then I come to the public undertakings. There are a number of public undertakings; if I refer to them, I will take at least half an hour. I am not referring to that; some other hon. Members will do that.

The position about the LIC, Food Corporation, Railway etc. has been indicated in the report in a very exhaustive manner, so far as that aspect is concerned. From that it is clearly seen that even today those who are incharge, including the Government, I must say, are not quite serious to the problem. They do not see that something extraordinary has to be done if these quotas are to be properly filled in.

So far as the recruitment is concerned, I will lastly come to another suggestion which I am making to this House and to the hon. Home Minister, that he should specially try to create a cell, some machinery, which looks to the grievances of the scheduled castes and scheduled tribes in this respect and redresses them. Only then, the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes can be taken care of. I will go a step further. Apart from the Public Undertakings, State Government and Central Government offices, even the private undertakings should be compelled to see that sufficient men of scheduled castes and scheduled tribes are employed

[Shri Hitendra Desai]

by them. The Commissioner has made certain very valuable suggestions in this regard on page 163 of the report:

> "It is however, suggested that the Ministry of Industrial Development might consider the desirability of issuing suitable instructions to various employer organizations indicating the broad features of the scheme of reservation for scheduled castes and scheduled tribes and make it obligatory on the part of the various industrial, commercial private undertakings to implement the same."

This is also a very important point. The recommendation has been made in the report itself.

PROF. P. G. MAVALANKAR: (Gandhinagar): How to do that?

SHRI HINTENDRA DESAI: It is for the Government to come to some conclusion. It is not I who made this recommendation. It is already there in the report.

Much can be said about the representation of the scheduled castes and scheduled tribes on services, but I am quite sure, other hon. Members will take it up.

Another important question is about the land and forests. A lot of land has been distributed. Land reforms should be implemented promptly. Apart from that, the forest policy should be such that the tribals are involved in that and that will only save the forests from destruction.

About the housing problem, there has been a scheme for the allotment of house sites to the landless. I understand that 73 lakhs of house site have been allotted. Some construction work has also been going on. More and more provision should be made so far as the housing for the Harijans and scheduled castes and scheduled tribes is concerned.

Lastly, some progress has been made in the last few years. But much remains to be done and it will be the endeavour of all members her to see that at least we reach our goals in the near future about economic and social equality. It was, I think, Dr. Ambedkar who said before the passing of the Constitution, that we will be living in contradictions, contradictions in the sense that in the political arena we will have one man-one vote and one vote-one value but that it is not so in the case of economic and social spheres. Unless we do that, I am quite sure that even the big democratic structure which we have laboriously built in this House and outside is also likely to be blown off if we are not able to reach that goal. It is from that angle this aspect is important.

There are many others who want to speak. Therefore, I conclude by thanking you and the House for giving me this opportunity.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): I beg to move:—

That for the original motion, the following be substiuted, namely:—

> "This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively, recommends that the "BHATTARAS" in District Kalahandi of Orissa be recognised as BHOTTADAS as per item No. 5 in the Scheduled Tribes Order of 1950 as amended in the year 1956." (1)

SHRI S. KUNDU (Balasore : I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

> "This House, having considered the Twentieth, Twnry-first and Twnenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively, resolves that in case of formation of a Civil Rights Commission care should be taken to see that the constitutional protection given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is further strengthened." (3)

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa): I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends to the Government that the action on the Reports be taken within one month and suitable action be taken against the officials responsible for the delay in the implementation of the recommendations contained in the Reports." (5)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, notes the failure on the part of the present Government to take effective steps to prevent atrocities on Harijans during the last four months and requests the Government to order a judicial probe into such atrocities on Harijans; provide social security and implement the recommendations of the Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes without further delay." (6)

SHRI B. RACHIAH : (Chamarajanagar) I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty- second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, urges the Government to implement recommendations of the Conference of the Ministers of all the States incharge of Social Welfare and Backward Classes under the Chairmanship of the Minister of State in the Union Ministry of Home Affairs and to set up a judicial commission to inquire into the cases of social injustice harassment and atrocities committed on the Harijans and Adivasis during the last four months". (7)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : (Quilon) : I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely :-

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty- second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May 1973, 28th August 1974 and 5th May, 1976, respectively, recommends that the date of bringing into effect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, be notified without any further delay." (9)

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor) : I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty- second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends that firm and effective steps be taken immediately to put an end to violence and atrocities perpetrated against Harijans in several parts of the country." (10)

That for the original motion, the following be substituted, namely—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 res-

[Shri P. K. Kodiyan]

pectively, recommends that the steps be taken to strengthen and expand the organisation of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes so as to enable it to discharge its responsibilities in more effectie manner." (11)

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72, and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 be immediately enforced." '12'

SHRI L. L. KAPOOR (Purnea) : I beg to move :

That for the Original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends that:—

(a) a separate Ministry should be created for the protection of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and the recommendations made by Kaka Kalelkar Commission, 1955 on Backward Classes Should be accepted and the work relating thereto should also be entrusted to the aforesaid Ministry.

(b) the present schedules of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes should be enlarged and the recommendations made in the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be implemented within a definite period, at the most 5 years, and the steps taken in that direction as well as the outline of the time-bound programme should be placed on the Table of the House in the next session;

(c) the appointment and promotion of the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes on the various cadres in the Government and semi- Government establishments should be made in proportion to their population;

(d) these communities should be given preference in respect of various facilities provided by the Government for removal of economic dispartries such as financial assistance, licences, permits, quotas, contracts, lease etc;

(e) if any particular community is engaged in a profession or vecation, time- bound schemes shoui be prepared to carry on and develop that profession through provision of ficilities and rights connected therewith ; and

(f) the traditional culture, music, drama and other arts of these communities should be preserved and special efforts should be made to develop the same ; and the details of the progress made in the implementation of the above should be laid on the Table every six months." '19'

SHRI G. S. REDDY (Miryalguda) I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Trives for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74 laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively, urges the Government to set up a Commission to enquire into the condition of the converts to other religions from the Scheduled Castes origin with a view to determining the desirability of extending economic and educational benefits from the point of view of backwardness and other disabilities suffered by them." '23

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South Central) : I beg to move :

That for the original motion, the following be substituted, namely :—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May 1976 respectively, regrets only the partial implementation of Constitutional safeguards provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and Anglo-Indians by the previous Congress Government leaving most of the safeguards not fully implemented and thus bringing the Constitution of India into contempt and resolves to investthe Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with necessary powers to get those safeguards implemented, wherever they have remained partially or fully unimplemened, by taking up these matters with the Government."(24)

That for the original motion, the following be substituted, namely :-

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid, on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends to the Government to set-up such suitable machinery as to ensure full implementation of the Constitutional safeguards provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes, and Anglo-Indians together with the backlog by a time-bound Programme and that machinery should jointly work with the Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes elected by Lok Sabha".(25)

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely :—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively.

(a) regrets the denial of admission to the Central Hospital, Dhanbad to the Harijan sweepers, though employed in the collieries, for treatment ; and

(b) demands an enquiry by a Parliamentary Committee into all the atrocities committed on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Dhanbad coal field for the last two years." (26)

That for the original motion, the following be substituted, namely :-

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends to the Government to set-up suitable machinery to stop planned elimination of the Harijans and Adivasis from the employment in the collieries after nationalisation and to declare the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the colliery employmenton the date of nationalisation as the datum level." (27)

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, पिछले छः सालों में कमीशन की एक भी रिपोर्ट इस हाउस में डिस्कस नहीं हुई। मैं गृह मंत्री जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वह इस मोशन को हाउस में लाये और हमें मौका मिला कि हम इस रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। छः साल में एक भी रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई और आज हमारे सामने तीन रिपोर्टें हैं 1971-72 और 73 की। उसके बाद की तीन रिपोर्टें तो सबमिट ही नहीं हुई। 74, 75 और 76 की रिपोर्टें आई ही नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों वह सबमिट नहीं हुई? डिस्कशन की बात तो बाद में देखी जायेगी। वह अभी तक आई ही नहीं।

[श्री सूरजभान]

इस वक्त भी देश में कुछ एट्रोसिटीज हुई हैं हरिजनों पर, खास तौर से बिहार, यू० पी० और आंध्र प्रदेश में। मैं इन सब अत्याचारों की निन्दा करता हूं। खास तौर में जो बेलछी में हुआ वह घिनौना काण्ड है। मैं उसकी निन्दा करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ मित्र हैं जो इस घिनौनी घटना का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए जनता पार्टी जिम्मेदार है और कुछ लोग कहते हैं कि जनता पार्टी में भी होम मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं उन से पूछना चाहता हू और बताना चाहता हूं कि 1973–74 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में दो हरिजन जो नये तौर पर बुद्धिस्ट बने थे उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 जुलाई 1973 को जिला सहर्षा के मधुबन गांव में चार हरिजन महिलाओं को नंगी करके जुलूम निकाला गया था और उसके बाद लोहे की सलाखें गर्म करके उनके जिस्म को दागा गया था। उसके लिए तो चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में एक हरिजन नौजवान को एक दरख्त के साथ रस्सी से बांध कर उसके कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। उसके लिए तो चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार नहीं है। 1969 में तमिलनाडु के तन्जौर जिले के किलवेनमनी नामक स्थान पर 42 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया जिसमें छोटे बच्चे, औरतें और नौजवान सभी थे। बदकिस्मती की बात यह है कि जब वह केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट का एक बदकिस्मत फैसला आता है। हाई कोर्ट के फैसले में यह बात दर्ज है कि ऊंची जाति के आदमी ऐसा गुनाह नहीं कर सकते और वह सब के सब आदमी बरी हो गये, क्या उसके लिए भी चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार हैं? और पीछे नहीं जाता, 1974 की बात है गाजियाबाद के पास एक गांव है जिस में एक हरिजन नौजवान को आग जलाकर उसके हाथ-पांव तारों से बांध कर आग के ऊपर लटकाया गया और झुलस दिया गया। कमिश्नर की रिपोर्ट के अलफाज मैं आपको सुनाना चाहता हूं, यह उसकी इक्कसवीं रिपोर्ट है 1971 से 1973 तक की। उसका केवल एक वाक्य मैं पढ़ रहा हूं :

> "Finding fault with him on some lame excuse this Harijan youth was brutally burnt and rosted like a pig by hanging him over a burning fire."

16 hrs.

मैं अपने उन मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि इस इश्यू को सियासी रंगत मत दीजिए यह एक नेशनल इश्यू है। पार्टी लेवल से ऊपर उठाकर इसके ऊपर सोचा जाय। जो लोग यह कहते हैं कि इस के लिए जनता पार्टी या कोई और जिम्मेदार है यह बिल्कुल गलत बात है। मैं कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आज ही ये एट्रोसिटीज नहीं हुई हैं। ये गवर्नमेंट के अपने आंकड़े हैं। 1972 में 3302 एट्रोसिटीज हुई। ये रजिस्टर्ड और रिपोर्टेड केसेज हैं। 1973 में 6186 और 1974 में 11238 एट्रोसिटीज हुई। उसके बाद 75 और 76 में इमरजेंसी का साल आ जाता है। उसमें जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्टिंग हुई नहीं, लेकिन जो कुछ जानकारी है उसके हिसाब से फैमिली प्लानिंग के नाम पर लाखों हरिजनों को जिबा किया गया क्योंकि वे बोल नहीं सकते थे। इसके ज्यादातर शिकार गरीब हरिजन ही हुए हैं। मैं आज जब अपने इलाके में जाता हूं तो देखता हूं कि गरीब हरिजनों के घरों में कमाने वाला एक ही था जो कि नसबंदी का शिकार होकर आज चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी कुछ कमा नहीं सकती है और बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास आज कोई रोजगार या धंधा नहीं है। कम से कम ऐसे हार्ड केसेज में जो लोग नसबंदी के शिकार हुए हैं उनको गवर्नमेंट की ओर से उस समय से लेकर जब से उनका

ऑप्रेशन हुआ—उनका इलाज हो जाने तक कम से कम पांच रुपए की दिहाड़ी जरूर मिलनी चाहिए ताकि उनका गुजारा हो सके। आज देश में हरिजनों की हालत जैसी है उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं :

गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ
सजा तो जानते हैं पर खुदा जाने खता क्या है।

आज हरिजनों को जो सजा मिल रही है वह किस खता पर मिल रही है, यह उनको मालूम नहीं है।

एक बात से मुझे संतोष हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी का एक पत्र अखबारों में छपा था, उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री और यू०पी० के मुख्यमन्त्री को लिखा था कि जो भी इंसीडेंट्स हुए हैं—बेलछी के या दूसरे—वह हमारी जनता पार्टी के लिए, जनता पार्टी की सरकार के लिए और सारे मुल्क के लिए शर्म का बायस है। इसके अलावा गृह मंत्री, चौ० चरणसिंहने जी भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह हिन्दू समाज के माथे पर कलंक का टीका है। उनके अल्फाज बिल्कुल सही है और मैं इस सिलसिले में एक शेर पढ़ना चाहूंगा :

हर जख्म पे रख दी मुहब्बत ने जुबां आज
सदियों के दबाये हुए गम बोल उठे हैं।

इन एट्रोसिटीज और जुल्मों को रोकने के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहता हूं ताकि वह होने ही न पायें। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर झगड़े उजरत पर होते हैं। वे दिहाड़ी ज्यादा मांगते हैं तो उनके साथ मार-पीट होती है। मेरा सुझाव है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट को देहात के मजदूरों के संबंध में ज्यादा सख्ती के साथ लागू किया जाये। अगर यह होता है तो एट्रासिटीज को बहुत कुछ रोका जा सकेगा।

दूसरी बात यह है कि इमर्जेंसी में कुछ लोगों को प्लाट दिए गए थे—रिहायशी प्लाट, आज उन प्लाटों पर झगड़े हो रहे हैं। कामन लैंड में से वह प्लाट दिए गए थे और आज वह प्लाट उनसे छीने जा रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब और दूसरे कन्सर्ड मिनिस्टर्स से कहूंगा कि वे इस बात को डिक्लेयर करें कि इमर्जेंसी में या बीस प्वाइन्ट की तहत जो भी प्लाट दिए गए थे उन पर से किसी को उजाड़ा नहीं जायेगा।

तीसरी बात यह है कि सिविल राइट्स एक्ट, जिसको पहले अनटचेबिलिटी एक्ट के नाम से कहा गया था उसको अमेंड किया गया लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मालूम होता है कि आज तक उसके अन्तर्गत बने रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया। अमेंडमेंट किए हुए सालों हो गए हैं। अगर अब आप उन रूल्स को नोटीफाई कर दें तो बहुत कुछ सहूलियत हो जायेगी।

चौथी बात यह है कि सी०बी०आई० में एक सेल बनाया जाये जो इंडीपेंडेन्टली इंक्वायरी कर सके, ऐसी एट्रासिटीज को केवल पुलिस पर ही नहीं छोड़ना चाहिए।

पांचवीं बात यह है कि स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरीज़ के लेविल पर जिलों में जिलाधीश और एस०पी० को जाती तौर पर इन एट्रासिटीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाये। वे इंक्वायरी करके जवाब दें कि कहां कहां पर क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं। अगर यह कर दिया जाये तो मैं समझता हूं काफी ज्यादतियां बन्द हो जायेंगी।

इसके अलावा एक बात और है कि मोबाइल पुलिस स्कवेड की स्थापना होनी चाहिए जो घूम फिर कर देख सकें और

[श्री सूरज भान]

कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा यूनि-सिटीज के विक्टिम्स को मानेटरी हेल्प भी दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा कर रहा है।

अब मैं सर्विसेज के बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि आज तीस साल आजादी के बाद सर्विसेज की जो हालत है उसमें गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार क्लास वन में 3.46 परसेन्ट हैं, क्लास टू में 5.41 परसेन्ट हैं, क्लास थ्री में 11.31 परसेन्ट हैं जबकि शेड्यूल्ड कास्ट्स का उसमें रिजर्वेशन 15 परसेंट का है। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राईब्ज जिनका रिजर्वेशन 7.5 परसेंट का है वे क्लास वन में 0.68 परसेंट, क्लास टू में 0.74 परसेंट और क्लास थी में 3.93 परसेन्ट हैं। सीनियर क्लास वन में तो रिजर्वेशन है ही नहीं। मैं मांग करता हूं कि इसमें भी इनका रिज़र्वेशन होना चाहिए और अभी जो बैकलाग या शार्टफाल है उसको दूर करने के लिए मेरे तीन सुझाव हैं। यदि इनको आप मान लीजिए तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पांच साल में सारा बैकलाग पूरा हो जायेगा।

पहला सुझाव यह है कि आज कल अखबारों में जो एडवरटिजमेंट आता है, उसमें लिखा होता है—

If suitable SC and ST candidates are not available the post will be given to others.

मैं पूछना चाहता हूं— 30 सालों में भी आप इन को सूटेबिल नहीं बना सके, या सूटेबिल कैण्डीडेट सिर्फ शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही छांटना है, दूसरों में अनसूटेबिल कैण्डीडेट नहीं होते? मेरा सुझाव है कि अखबारों में यह लाइन छपनी ही नहीं चाहिये। अगर पहली बार में कैण्डीडेट नहीं मिलता है, तो सैकण्ड टाइम उस को नोटिफाई कीजिए और जब तक कैण्डीडेट नहीं मिलता है उस पोस्ट को खाली रखिये। तीन महीने खाली रखने से कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा। मैं भी सर्विस में रह चुका हूं, मुझे पता है कि पोस्ट्स कैसे सैंक्शन होती है, साल-साल और डेढ़-डेढ़ साल कोशिश करने के बाद पोस्ट सैंक्शन होती है। अगर साल-डेढ़ साल तक बिना उस पोस्ट के काम चलाया जा सकता है तो तीन महीने में भी काम चलाया जा सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जब तक कैण्डीडेट नहीं मिले, उन पोस्ट्स को खाली रखा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन अफसरों के दिमाग में यह बात पैदा होगी कि कैण्डीडेट नहीं लिया तो पोस्ट को खाली रखना पड़ेगा, तब फिर कैण्डीडेट जल्दी मिल जायेगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पी०एण्ड टी० में आलरेडी एक ऐसा सिस्टम है वहां सब की मैरिट के हिसाब से सीनियोरिटी लिस्ट बनती है। मान लीजिये किसी पोस्ट को रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है—उस हिसाब से एक जैनरल लिस्ट, एक शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट बना ली जाती है। उसके बाद जिन्होंने एफ० ए० या बी० ए० पास किया होता है, उन की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को दृष्टि में रखते हुए उनको प्राथमिकता दी जाती है। अगर यह सिस्टम पी० एण्ड टी० में कामयाब हो सकता है तो दूसरे विभागों में क्यों कामयाब नहीं हो सकता? अगर इस तरह से काम किया जाये तो उन का कोटा बहुत जल्दी पूरा हो सकता है।

तीसरा सुझाव—अगर किसी केस में यह साबित हो जाय कि रिज़र्वेशन के रूल्ज़ को जानबूझ कर वायोलेट किया गया है, the violation of these rules should be treated as breach of Service Conduct Rules.

अगर यह सज़ा मुकर्रिर कर दी गई तो कोई आदमी हरिजन आदिवासियों के हक पर छापा मारने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाय तो पांच वर्ष में तमाम बैकलाग पूरा हो सकता है।

शैड्यूल्ड कास्ट्स का केवल रिक्रूटमेंट का ही मसला नहीं है, बल्कि जहां एप्वाइन्टमेन्ट होता है, उन को गैर-अहम जगहों पर पोस्ट कर दिया जाता है। आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में सिलैक्शन होने के बाद उन को किसी ज़िम्मेदार जगह पर भेजने के बजाय सैक्रेटेरिएट में कलर्की करने की जगह पर भेज दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों में से कुछ लोगों को लाज़मी तौर पर डिस्ट्रिक्ट का हैड बनाया जाना चाहिये।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं—मुझे अफसोस है कि मैं इसे हाउस के सामने ला रहा हूं—यह पिछले साल का वाक्या है—राजस्थान की 6 आदमियों की डिमाण्ड थी, 6 आई०ए०एस० को लेना चाहते थे. इन के पास तीन आदमी थे—एक अदर कम्यूनिटी का और दो शैड्यूल्ड कास्ट्स के। रूल्ज़ के मुताबिक इन तीन आदमियों को राजस्थान में लगाया जा सकता था, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक आदमी अदर कम्युनिटी का और एक शैड्यूल्ड कास्ट का भेज दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने लिखा कि तीसरा आदमी भी भेज दें चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट का है, हमारी स्टेट का कैण्डीडेट है, उस को दे दीजिये, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने उन की इस बात को नहीं माना। अगर तीसरा आदमी अदर कम्युनिटी का होता तो वह लाज़मी तौर पर राजस्थान को मिल जाता लेकिन हरिजन होने के कारण उसे अपनी होम स्टेट में नहीं लगाया। इस से बड़ी ज्यादती और क्या की जायगी? क्या आदरणीय होम मिनिस्टर इस में इंसाफ करेंगे? हरिजनों के साथ कन्फर्मेशन और दूसरे मामलों में जो ज्यादतियां हो रही हैं, मैं उन की डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता—लेकिन इस तरह का ट्रीटमेन्ट आप की मिनिस्ट्री में इन लोगों को अभी भी मिल रहा है।

जहां तक प्रमोशन का ताल्लुक है—क्लाम 1 के बारे में मैं पहले बता चुका हुं। कई बार प्रमोशन का चांस आता है लेकिन उन को एवाइड किया जाता है। आप के यहां कायदा है कि नम्बर आफ़ पोस्ट्स के पांच गुना कैण्डीडेट्स को कंसीडर किया जाना चाहिए लेकिन जब देखते हैं कि इस में हरिजन कैण्डीडेट आ जायगा तो उस को घटा कर तीन गुना कर देते हैं। आप के यहां डिफेंस में ऐसा हो रहा है—मैंने इस सम्बन्ध में बाबू जगजीवन राम जी को लिखा और इन्सीडेंट कोट किया। उन का जवाब आया कि यह बात ठीक है—पांच गुना की बजाय तीन गुना ले रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले से चला आ रहा है, आगे के लिये इसको ठीक कर देंगे। सभापति महोदय, होना तो यह चाहिये कि पांच गुना की बजाय छः गुना कैण्डीडेट्स को कसीडर किया जाय, लेकिन यहां तीन गुना को ही कन्सीडर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि रूल्ज़ का इम्पलीमैन्टेशन सही तौर से होना चाहिये।

आज से 30 साल पहले जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, हमारे शरणार्थी भाई बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन एक करोड़ से कम थे, यहां आये। उनकी दयनीय हालत को देख कर यहां रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाई गई और उनको रिहैबिलिटेट

[श्री सूरज भान]

किया गया। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों साल से करोड़ों हरिजन और आदिवासी रिफ्यूजीज की हालत में इस देश में रह रहे हैं, क्या उन के लिए कभी कोई मिनिस्ट्री बनेगी? आज तक उन के लिए मिनिस्ट्री इसलिए नहीं बनी क्योंकि वें अच्छी तरह से नहीं रोये और उन्होंने अपनी बात को जोरदार शब्दों में नहीं कहा। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि उन की हालत सुधारने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए और जो भी ज्यादतियां उन पर विभिन्न विभागों में हो रही हैं, उन को वह मिनिस्ट्री देखे।

एजूकेशन के बारे में मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि कई जगहों पर उन को रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। सैनिक स्कूलों में उन के लिए रिजर्वेशन नहीं है और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अलीगढ़ के मैडिकल कालेज में भी उन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। हिन्दुस्तान भर के मैडिकल कालेजों में उन के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन अलीगढ़ मैडिकल कालेज में उन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है हालांकि गवर्नमेंट से उस को पूरी सपोर्ट मिलती है। मेरा कहना यह है कि तमाम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूटशन्स में उन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और जो भी रिजर्वेशन हो, उस का इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए। इस के अलावा स्कालरशिप का एमाउन्ट बढ़ना चाहिए। स्कालरशिप का एमाउन्ट मिलने में बड़ी देर हो जाती है। इसलिए हर ऐसे स्टूडेंट को एनटाइटिलमेंट कार्ड मिलना चाहिए और जब भी वह उस कार्ड को ले कर जाए, तो उस को फौरन स्कालरशिप मिलनी चाहिए। अगर हर स्टूडेंट को एनटाइटिलमेंट कार्ड मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि जो डिले स्कालरशिप मिलने में होती है, वह एलिमिनेट हो सकती है।

एकोनामिक कंडिशन्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्यों कि सब जानते हैं, लेकिन उन की हालत को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के स्टेंडिग इंस्ट्रक्शन नेशनेलाइज्ड बैंकों को है कि उन को लोन का एक-तिहाई हिस्सा डिफेन्शियल रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट पर दिया जाए लेकिन बड़े दुःख की बात है कि ये जो स्पेसीफिक इंस्ट्रक्शन्स गवर्नमेंट के हैं, उन का इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हरिजनों को एक-तिहाई लोन डिफेन्शियल पर मिलना चाहिए।

इस के अलावा मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नये बाजार बन रहे हैं, उन में कुछ दुकानें हरिजनों को भी दी जानी चाहिएं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ फीसदी दुकानें रिजर्व कर देनी चाहिए।

इस के अलावा मेरा सुझाव यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एजेन्सीज का कुछ फीसदी हिस्सा हरिजन और आदिवासियों को दिया जाए। मिसाल के तौर पर फेयर प्राइस शोप्स, कोयले के डीपू, तेल की एजेन्सियां, गैस की एजेन्सियां जो हैं, उन में से कुछ हिस्सा हरिजन और आदिवासियों को दिया जाना चाहिए।

जहां तक इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, उसमें भी कुछ फीसदी शेड हरिजन और आदिवासियों के लिए रिजर्व करने चाहिए। इस के अलावा हरिजन और आदिवासियों को आसान किस्तों पर कर्ज दिये जाने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी स्टेट्स में उन को आसान किस्तों पर कर्ज दिये गये हैं। इस के अलावा उन को कुछ तकनीकी मदद भी देनी चाहिए।

इस के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की सहूलियत के लिए कुछ प्रदेशों में हरिजन कल्याण निगम बने हैं। ऐसे निगम सब प्रदेशों में बनने चाहिए और उन को सरकार की तरफ़ से पूरी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और उन में कोई गोलमाल नहीं होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ हरिजनों के विरुद्ध फ्राड भी होता है। एडोप्शन के जरिए कुछ भद्र पुरुषों ने काफ़ी लाभ उठाया है। हरिजन के यहां एडोप्ट होकर सर्विसेज में और मेडिकल कालेज में उनको एडमीशन मिल जाता है ? इस तरह के एक नहीं बल्कि सैकड़ों केस मैं आपको बता सकता हूं लेकिन समय कम होने के कारण मैं उन को यहां नहीं बताना चाहता। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस तरह के ग़लत एडोप्शन को चैक किया जाए। इसी तरह से कोआपरेटिव बैंक्स और सोसइटीज़ कोआपरेटिव बैंक्स में हरिजनों के नाम पर बहुत बड़ा फ्राड हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां हरियाणा में एक गुलाब सिंह जैन, एक्स एम० एल० सी० थे, जो इन्दिरा जी को प्यारे हो गये। उन्होंने म्यूनिसिपलिटीज के एम्पलाइज जैसे स्वीपर्स के नाम पर पौने छः लाख रुपये का फ्राड किया। उनके पास एक बीघा जमीन नहीं है लेकिन दो हरिजनों के नाम पर 24,000, 24,000 हज़ार रुपये के ट्रेक्टर लेने के नाम पर रुपया हड़प लिया। इस तरह से उन्होंने 5 लाख 78 हज़ार रुपया हड़प लिया और हरिजनों के नाम पर फ्राड किया।

इसके अलावा पिछले दस साल में आल इण्डिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग ने 13,92,120 रुपये की गवर्नमेंट से ग्राण्ट ली। पता नहीं इस पैसे का उन्होंने क्या किया है। यह एक पोलीटीकल आर्गेनाइजेशन है और हो सकता है कि उस में से कुछ आदमी आज जनता पार्टी में टूट कर आ गये हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की जो पालीटीकल एक्टिवीटीज हैं चाहे वे डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की हों, उनको यह ग्राण्ट बिल्कुल बन्द होनी चाहिए। वह काम क्या करता है। प्रीतिभोज वगैरह पर ही खर्च किया जाता है और कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। माननीय हितेन्द्र देसाई जी ने कहा है कि हरिजन सेवक संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे तो पता नहीं है कि वह क्या अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पिछले दस साल का मुझे नालेज है। उसको 81 लाख 95 हजार 236 रुपये दिए गए है। इससे पहले कितने दिए गए मुझे पता नहीं है। प्रीतिभोज, पद यात्राओं वगैरह के नाम पर उसने यह 82 लाख रुपया खर्च कर दिया है।

शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमिश्नर की रिपोर्ट जो हमारे सामने है उस पर हम विचार कर रहे हैं। मुझे उन पर बड़ा रहम आता है। 1967 तक उसके सतरह रिजनल आफिसर्स थे, रिजनल आफिस होते थे जिन से उसको रिपोर्टें सभी राज्यों की मिलती रहती थीं। मैं उस सबकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन इन सतरह आफिसिस को एबालिश कर दिया गया और जो स्टाफ यहां पर काम करता था उसको डायरेक्टर जनरल बैक्वर्ड क्लासिस में डाल दिया गया। ऐसा करके उसको आइज़ और ईयर्ज़ से डिप्राइव कर दिया गया। एक मूर्ति साहब को वहां नियुक्त कर दिया गया था। हर साल उसको नाजायज़ तौर पर तरक्कियां दी जाती रही है और उसका कारण यह है कि वह पहले वाले जो राष्ट्रपति जो हुआ करते थे श्री वी० वी० गीरि जी उनके दामाद हैं। पांच साल में उनको बहुत ज्यादा प्रोमोशंज़

[श्री सूरज भान]

मिली हैं । बहुत सी धांधलियां उनकी हैं जिन में जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर को आपने अंधा बहरा तो पहले ही बना दिया था अब उसका गला भी काटा जा रहा है । इन पोस्ट्स को एबालिश करके किस तरह से राज्यों से उसके पास सही रिपोर्ट पहुंच सकती है ? अब आप सिविल राइट्स कमिशन बनाने की बात सोच रहे हैं और कमिश्नर की पोस्ट को एबालिश करने की बात कर रहे हैं । जैसा श्री हितेन्द्र देसाई ने कहा है, हमारी मांग भी यह है कि एक की जगह दो अलग अलग कमिश्नर दोनों जातियों के लिए होने चाहिएं । इसके बिना काम ठीक से नहीं हो सकेगा । लेकिन आज तो बात ही और चल रही है और यह कहा जा रहा है कि इस पोस्ट को भी एबालिश कर दिया जाए या उसको और काम दे दिया जाए । ऐसी स्थिति में वह कुछ भी नहीं कर सकेगा । आप सिविल राइट्स कमिशन बनायें, हमें खुशी होगी । लेकिन जहां तक कमिश्नर की पोस्ट का ताल्लुक है इसको स्ट्रैंगथन किया जाए, रिजनल आफिसर्स को ऐस्टोर किया जाए । सिविल राईट्स कमिशन बने, हमें एतराज नहीं है ।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर अमल किया जायेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज की समस्या हमारे देश की सब से जटिल समस्या है । यह प्रसन्नता की बात है कि चाहे यहां सदस्य इधर बैठें हों या उधर बठे हों या मेरे दायें बैठे हों उन की इस समस्या के बारे में एक राय है और सभी इसको राजनीतिक समस्या नहीं मानते हैं । सभी यह कहते हैं कि यह किसी राजनीतिक पार्टी की समस्या नहीं है वरन् सारे देश की समस्या है । सारा देश भी एक मत है इसके बारे में ।

स्वतन्त्रता के बाद जब देश का विधान बना तो हमारे विधान निर्माताओं ने हमारे विधान में एक नहीं आठ दस धारायें ऐसी इस में रखीं जो कि इनकी प्रगति के बारे में थीं, वीकर सेकशंज के सेफगार्ड के बारे में थीं, उनकी शिक्षा, स्टाइपेंड्ज, स्कालरशिप्स, उनके इंस्टीट्यूशंज बनाने के बारे में थीं उन में दिया हुआ है कि इनको ये ये सुविधायें दी जानी चाहियें । विधान निर्माताओं ने धारायें 29 (2), 31, 341, 342, 340, 275, 338 आदि रखीं । इन धाराओं ने इन लोगों को आगे ले जाने और इनकी प्रगति करने की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा एक अनटचबिलिटी आफेंसिस एक्ट बना जिस का संशोधन 1975 में किया गया और उस एक्ट को ज्यादा अच्छा बनाया गया । बहुत सी स्कीमें भी इनके वास्ते बनाई गई । पांचवीं योजना में करीब 208 करोड़ का प्रावधान किया गया शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लिए जबकि चौथी योजना में केवल 55 करोड़ का प्रावधान किया गया था । चार लाख स्कालरशिप्स पोस्ट मेट्रिक के वास्ते रखे गये । 1970-71 में पौने दो लाख ही रख गए थे । सीट्स भी इनके लिए रिजर्व की गई और सर्विस कंडिशंज में रिलेक्सेशन भी दिया गया । बहुत सी चीजें इस तरह से उनके लिए की गई । लेकिन 30 साल की आजादी के बाद भी आज हम यही कहेंगे कि जो कुछ हमारे विधान निर्माताओं ने हमसे अपेक्षा की थी, जो कुछ हम करना चाहते थे, वह कुछ हुआ नहीं । अधिकांश वह केवल कागज पर है । योजना है लेकिन वास्तव में उसका लाभ गरीब जनता

को, हरिजनों को, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं पहुंचा है। अगर यह मैं कहूं कि यह समस्या एक बहुत बड़ी बैफ़लिंग नेशनल प्रौब्लम है तो गलत न होगा और जिसको सुलझाना अत्यन्त आवश्यक है और जल्दी से जल्दी इसको सुलझाना चाहिए। यह समस्या सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेन्ज है और जनता पार्टी के लिए तो और भी ज्यादा क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि हमें वीकर सक्शन्स का ध्यान रखना है और जिसके आधार पर हम चुन चुन कर के यहां आये हैं।

सभापति जी, 30 साल की आजादी के बाद भी मैं थोड़े बहुत आंकड़े दूंगा, कुछ तो हमारे साथियों ने आंकड़े दिये हैं, जिससे स्पष्ट हैं कि आज भी हालत कोई अच्छी नहीं है। मेरे पास आंकड़े है जिनके मुताबिक क्लास 1 के सारे देश के अन्दर 31,428 अधिकारी हैं और इनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के 1,058 अधिकारी हैं जिसका परसेंटेज 3.36 परसेंट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केवल 169 अफ़सर हैं जिसका परसेंटेज 0.51 परसेंट है। इसी तरह से क्लास 2 में 47,630 अफसर हैं और शेड्यूल्ड कास्ट्स का 4०.35 परसेंटेज है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 0 48 परसेंटेज है। इसी तरह से क्लास 3 में 14 लाख 85 हजार 364 लोग हैं, इनमें से 1 लाख 50 हजार 58 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग है जो 10 परसेंट बैठता हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 2 परसेंट हैं। तो जहां पर साढ़े 22 परसेंट होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी के हिसाब से वहां पर केवल ढाई परसेंट 4 परसेंट और 10 परसेंट है और क्लास 4 में 13 परसेंट हैं। और 1975 में बढ़ कर के 3.4 परसेंट, 5.4 परसेंट, 11.3 परसेंट हो गया।

इसी तरह से जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि आज भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार होते हैं और वह दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। 1972-73 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3456 कमप्लेंट्स आयीं और 1973-74 में वह बढ़ कर के 4622 हो गई और मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से 1-1-74 से 10-6-74 तक 2,700 कमप्लेंट्स आयीं है जिसमें से 114 मर्डर के केसेज़ हैं, 127 रेप के केसेज़ हैं और 601 अनटचैबिलिटी के केसेज हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश में इन्सान इन्सान के साथ भेदभाव करता है। इन्सान इन्सान नहीं समझता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं विदेशों में गया वहां पर लोग बहुत सवाल पूछते हैं, हरएक चीज़ का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब वह यह सवाल पूछते हैं कि क्या आप के देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग छूने में एतराज करते हैं, यह क्यों है, क्या वह इन्सान नहीं हैं, तो इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। हम गरीबी का जवाब दे सकते हैं महंगाई का जवाब दे सकते हैं, बेरोज़गारी का और किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का चाहे इस देश का कोई छोटा या बड़ा नेता हो उसके पास कोई जवाब नहीं है। हम इन सब को इन्सान क्यों नहीं समझते हैं। हम इन्सान को छूने में क्यों शर्म महसूस करते हैं? यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।

मैं डा० अम्बेदकर के उस कथन को आपके सामने पढ़ता हूं जो उन्होंने विधान बनाते समय 25 नवम्बर, 1949 को दिया था।

"On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognising the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall,

[श्री कंवर लाल गुप्त]

by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions ? How long shall we continue equality in our socio-economic life ? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy when this Assembly has so laboriously built up."

अध्यक्ष जी, यह डाक्टर अम्बेदकर का है, जो कि विधान के बड़े निर्माता थे। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर यही हालत चलती रही तो हमारी डैमोक्रेसी खतरे में पड़ जायेगी, हवा में उड़ जायेगी और हमें मालूम भी नहीं होगा। यह खतरा इस देश को समझना चाहिए।

आज 30 साल के बाद क्या हुआ ? यह जो एक्ट बनाया गया है, इसके बारे में एक पीलमल कमेटी बनी थी। उसने यह सर्वे किया कि इस ऐक्ट के बारे में कितने लोगों को जानकारी है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब शहरों के लोगों से उन्होंने बातचीत की, 100 लोगों से पूछा तो केवल 12 लोगों को यह मालूम था कि इस तरह पर अनटचेब्लिटी ऑफेन्स एक्ट कोई है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्होंने 30 पुलिस अफसरों से पूछा कि क्या कोई ऐसा एक्ट है तो उनमें से सिर्फ 2 को मालूम था कि यह ऐक्ट है। इसका मतलब यह है कि कार्यवाही करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब पुलिस अफसरों को मालूम ही नहीं कि इस तरह का एक्ट भी है तो इस बारे में वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री हितेन्द्र देसाई ने बहुत अच्छी बात कही कि यह पार्टी का सवाल नहीं है। उन्होंने तो कहा, लेकिन अभी फ़ायर ब्रांड्ज आगे उसको पार्टी का सवाल बनायेंगे। मैं समझता हूं कि यह इन्सानियत के साथ खिलवाड़ होगा अगर इसको पार्टी का सवाल बनाया। यह देश का सवाल है, इसका हल इस देश में एक राय हो कर होना चाहिए। यह नेशनल कान्सेंसेश के आधार पर होना चाहिए, इसमें किसी भी पार्टी का मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन मझे यह सुन कर दुःख हुआ कि होम मिनिस्टर के खिलाफ यह मुद्दा उठाया गया कि बेलछी में जो हरिजनों पर अत्याचार हुआ उसको लेकर उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को एंटी-सोशल की शक्ल में पेश कर के पेश किया। यह अच्छा बात नहीं है। यह आप इन्सानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का सवाल उठायेंगे तो गरीबों को गुरबत का फायदा आप अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। परन्तु आज जनता उसको माफ नहीं करेगी।

श्री हितेन्द्र देसाई जो आंकड़े यहां दे रहे थे, क्या 4 महीने में चौधरी चरण सिंह उसको बराबर ला सकते हैं ? आपकी सरकार 30 साल तक रही, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं ? आप भी जिम्मेदार हैं, चौधरी चरण सिंह जी, मैं और मेरे पिता, दादा सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। पार्टियों से जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें सारा समाज जिम्मेदार है। इसलिए पार्टी का सवाल इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि सब पार्टियां बैठें और एक नेशनल कान्सेंसेस डवलप हो और किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाये।

प्राइवेट सैक्टर में, पब्लिक सक्टर में और गवर्नमेंट के बैंक्स में इसका सर्विस की

रेशियो बहुत कम है। मेरा सुझाव है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें कि जहां भी हरिजनों पर अत्याचार होता है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उसकी रिस्पौंसेब्लिटी की पिन-डाउन कर देना चाहिये कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी होगी और सजा मिलेगी। इसी तरह से सर्विसेज़ में जो सक्रैटरी आफ दी डिपार्टमैंट है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहीं पर भी एक साल के बाद, जितनी रिक्रूटमेंट हुई है, अगर उसमें कम रेशियों होगी तो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। अगर यह दो बातें की जायें तो मेरा ख्याल है कि यह चीज ठीक हो सकती है।

मैं चाहूंगा की चीफ मिनिस्टर्स की जो कान्फ्रेन्स होने वाली है,' हमारे गृहमंत्री जी यह समस्या उनके सामने रखें और उनसे विचारविमर्श करें और देखें कि क्या रास्ता निकल सकता है। इस के बारे में बहुत देर तक ढील नहीं दे सकते है और कोई कंकरीट स्टैप उठाना चाहिए। स्वयं इस सदन के सामने सरकार को आना चाहिए कि वह यह यह कदम उठाना चाहती है, यह यह काम करना चाहती है ताकि देश की यह बहुत बड़ी समस्या हल हो सके।

हमने इन लोगों की तरक्की के लिए संविधान में प्राविज़न रखे और बहुत सी स्कीमें बना कर करोड़ों रुपये खर्च किये लेकिन अभी तक यह एसेसमेंट नहीं हुआ कि इस क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हुई है। जब तक इस तरह का एक प्रापर एसेसमेंट नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस के लिए मैं किसी कमीशन की मांग नहीं करूंगा। कोई कमीशन यह काम नहीं कर सकता है। यह काम कि पापुलर लेवल पर एक कमेटी बनाई जाये बना कर ही किया जा सकता है। मैं मांग करता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बने, जो इस बात की जांच करे कि पिछले तीस सालों में इन लोगों की कितनी तरक्की हुई है, हम ने इस बारे में जो कुछ करना तय किया था, वह कहां तक पूरा हुआ है, और अगर नहीं पूरा हुआ है, तो क्यों नहीं पूरा हुआ है, और वह कमेटी यह सुझाव भी दे कि किन किन उपायों से हम उसे पूरा कर सकते हैं।

अभी भी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संत, महात्मा और आचार्य ऐसे हैं, जो इस बीसवीं सदी में भी कहते हैं कि इन पुराने रीति-रिवाजों को हाथ न लगाओ, ऐसा करने से पाप होगा। लाखों लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इन्सान और इन्सान के बीच में भेद करता है, वह सन्यासी नहीं हो सकता है, वह आचार्य या महात्मा नहीं हो सकता है, वह एक क्रिमिनल या वह इन्सान नहीं है —मैं उसे इन्सान नहीं मानता हूं। हमें उस देश की जनता में जागृति पैदा करनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है, सारा समाज उस के खिलाफ़ बगावत कर दे, और उसे बता दे कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे नहीं किया जायेगा, तो इस प्रकार के लोग और आगे बढ़ते जायेंगे और इस समस्या का हल नहीं होगा।

श्री हितेन्द्र देसाई ने गुजरात के कुछ आश्रमों का ज़िक्र किया। मुझे नहीं मालूम कि वे आश्रम किस तरह के हैं। मैंने उन्हें नहीं देखा है। लेकिन मैं ऐसा कोई भी आश्रम या स्कूल पसन्द नहीं करता हूं, जो केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए हो। इन लोगों को

[श्री कंवर लाल गुप्त]

सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानन्द ने भी, जो इस युग के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, इस समस्या को हल करने के लिए यह सुझाव दिया था कि सभी पाठशालाओं में सभी छात्र एक साथ शिक्षा लें, एक साथ खाना खायें और एक साथ रहें, ताकि हमारे समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच और गरीब अमीर की भावना खत्म हो जाये। गुरुकुल की सी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री हितेन्द्र देसाई : उन आश्रमों में कास्ट हिन्दूज भी जा सकते है।

श्री कंवर लाल गुप्त : जहां तक सर्विसिज का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की इकानोमिक कण्डीशन्ज सुधारे बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती है। आज स्थिति यह है कि जो गरीब हरिजन गांवों में रहते हैं, उन के बच्चे आई० ए० एस० के कम्पीटीशन में नहीं आ सकते हैं। इस लिए सरकार को कुछ कोचिंग सेंटर बना कर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे छः सात सैंटर इस वक्त हैं, लेकिन हर स्टेट में ऐसे बहुत से सेंटर कायम करने चाहिएं, जहां आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० और क्लास वन को पोस्ट्स के लिए कम्पीटीशन में बैठने के लिए स्पेशल कोचिंग दी जाये, ताकि वे दूसरों के मुकाबले में आ सकें। वैसे तो यह समस्या ऐसी है जिसका कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अमेरिका में जो निग्रोज थे उनकी भी यही हालत थी। उनको भी एक तरह से शूद्र माना जाता था लेकिन उन निग्रोज ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। वे अपने पैरों पर खड़े हो गये। उन्होंने अपने आप को आर्गेनाइज किया और गोरे लोगों के खिलाफ एक डिटरमिंड फाइट की। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग हरिजन भाइयों में काम करते हैं उन को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आर्गनाइज करना चाहिए और एक डिटरमिण्ड फाइट करनी चाहिए जिसमें हम सब लोग भी शामिल हों। इस तरह की जो कान्शस क्लास होगी वह इस तरह से लड़ाई लड़ेगी तो जो उस तरह के थोड़े से लोग हैं उनका किला ढह जायेगा और वह जमाना आयेगा जब इस तरह की समस्या नहीं होगी।

श्री राम देवी राम (पलामू) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आप हमें उन की मुखालिफत करने के लिए तो कहते हैं लेकिन आपने उनको बन्दूकों के लाइसेंस दिए हुए हैं हरिजनों को तंग करने के लिए। तो हरिजन उसके सामने उनकी मुखालिफत कैसे कर सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं खत्म कर रहा हूं। अभी इमरजेंसी के दिनों में हमारे उस तरफ के साथियों की जब सरकार थी तो उन्होंने यह कहा है कि 71 लाख मकानों के लिए जमीन दी गई है। मुझे नहीं मालूम कि वह कागज पर है या कहां है, लेकिन सरकार को इसके बारे में इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए। दिल्ली की कुछ रिपोर्ट मुझे मिली है कि यहां 2–3 जगह जो जमीन उनको दी गई है वहां कुछ लोग उनको मकान बनाने नहीं देते। तो सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसी जगह जो उनको दी गई हो उसमें उनको मकान बनाने की पूरी आजादी हो और जो बीच में आते हैं उनको कड़ी सजा मिले। मैं गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जनता सरकार एक ऐसी कांक्रीट चीज लायेगी जिससे इस समस्या के सुलझने में बहुत आसानी होगी और एक दिन वह आयेगा जब इस देश में यह समस्या नहीं रहेगी।

*SHRI A. MURUGESAN (Chidambaram): Hon. Mr. Chairman, Sir, I rise to participate, on behalf of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, in the discussion on the Annual Reports of the Commissioner for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As a member belonging to the Scheduled Caste, I would like to make a few suggestions for the amelioration of adversities being faced by my fellow-men throughout the length and breadth of the country. I start my speech by quoting some comparative statistics supplied by the Department of Personnel of the Government to substantiate that the strength of Scheduled Caste and Scheduled Tribe staff in different categories of Government services is steadily dwindling.

The staff belonging to the Scheduled Castes:

	Class I	Class II	Class III	Class IV
1-1-1973	921	1890	133552	16,948
1-1-1974	729	1593	134466	164535
The staff belonging to the Scheduled Tribes.				
1-1-1973	166	211	27208	40471
1-1-1974	134	164	30560	29114

From this, it is indisputable that the strength of staff belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is declining in all categories excepting Class III. I would like to know the reasons for this fall.

Sir, there are orders of the Government of India specifying 15% reservation in recruitment for Scheduled Castes and 7½% for Scheduled Tribes. Here also I am constrained to take recourse to the figures furnished by the Department of Personnel.

	Class I	Class II	Class III	Class IV
S.C.	3·58%	4·83%	10·34%	17·86%
S.T.	0·65%	0·50%	2·35%	4·24%

Excepting in Class IV, i.e. the category of Peons where there is fulfilment of reservation quota for Scheduled Castes, in all other categories of staff, it is confirmed that the Government's fiat has become futile both for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. On 25th of this month, this House gave its assent to the O.N.G.C. (amendment) Bill ensuring employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in the Oil and Natural Gas Commission eighteen years after its establishment. This shows the callous attitude of the Government in getting its directives implemented effectively. Whenever we raise the question of non-compliance of the reservation quota, immediately we are told that adequate number of qualified candidates belonging to S. C. and S. T. are not available. You will never get enough number of eligible candidates if the Universities do not implement your injunctions. The Universities have been directed to make 20% reservation in admissions for Scheduled Caste and Scheduled Tribes students. You know, Sir, that there are 110 Universities in our country. In as many as 65 Universities there is no reservation; in 35 there is reservation of 3% to 15%, and in 10 Universities only there is 20% reservation in admissions for SC and ST candidates. Similarly there is the notification of the Government that there is to be 5 % relaxation in the marks for SC and ST boys. It is regrettable that 61 Universities do not observe this notification, while 49 Universities give 5% relaxation in marks for SC and ST boys. In these circumstances, it is not surprising that you do not get enough number of eligible

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri A. Murugesan]

SC and ST candidates for appointment in Government services.

In regard to the competence of SC and ST candidates in Universities and I.I.Ts, the hon. Minister of Education has this to comment upon;

> "We find that these SC/ST students are not coming up to the standards prescribed for them. Therefore, even when they are admitted, they cannot keep pace with the method of teaching."

If this is the view of our Education Minister, you can well imagine what will be the impression of others in high society. I would like to make two suggestions here. One is that the hon. Education Minister should ensure that the SC and ST students are given extra coaching during spare time and during holidays. Secondly, the hon. Education Minister should direct the University Grants Commission to stop the grants to Universities which do not implement the Government's instructions in regard to SC and ST students. I am sure that our Home Minister will convey these suggestions to the Education Minister and also exert his good offices in getting them implemented.

When this is the state of affairs in higher education, let me narrate what obtains in primary education level. In Classes I to V, the enrolment of children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is only 60% and 57% respectively. The most distressing feature here is that the precentage of drop-out in Class V is as high as 50. In this, naturally the SC and ST children will be perdominating. This is the position obtaining in 1974. This also proves that the SC and ST people, are not marching ahead but marching backward. Sir, the children are the blossoming buds of humanity and if these buds are crushed like this, how and when fragrant flowers are going to bloom among the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities. I demand serious consideration of the Government of this frustrating feature in the educational growth of SC and ST children.

Sir, there is imperative need for amending Article 338 of the Constitution. You know, Sir, that the scheduled castes are spread throughout the length and breadth of the country and the scheduled tribes are secluded in the hilly regions. It has been found from experience that one Commissioner is unable to attend to the growing needs of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There should be two Commissioners, one for the Scheduled Castes and one for the Scheduled Tribes and the necessary constitutional amendment must be brought forward by the Government in this regard.

The Prime Minister has expressed his inclination in setting up a Minorities Commission. There is general apprehension that the constitutional safeguards of the SC and ST people might get corroded in this amorphous Minorities Commission. It is reported that some Janata Party Members have represented to the HomeMinister in this matter and I request the hon. Minister to clarify this point.

Sir, it is inexplicable why the Scheduled Caste members embracing Buddhism should not be entitled to the facilities and concessions being enjoyed by the weaker sections of our society. After all, Buddhism is the rebel child of Hinduism and Buddha himself was born in India. There is no justification at all for jeopardising the interests of Scheduled Caste people who have become Buddhists. I suggest legal safeguards for them.

A few thousands of Scheduled Caste people, hailing from Tamil Nadu, are working in Delhi and they are denied their legitimate concessions. The arguement advanced is that the names of those castes are not on the lists of Delhi State Government. To obviate such hardships, in the 5th Lok Sabha a Bill was introduced. That Scheduled Caste and Scheduled Tribe Bill must be got enacted by the Janata Government as early as possible. It is unfortunate that the first 100 days of Janata rule has been marred by Belchi and Meerut incidents in which many Harijans were killed in open daylight. At least as a matter of recompense for that, this Bill should soon become an Act.

There are no representatives belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Judiciary, in Ambassadorial appointments and also in gubernatorial posts. Recently the Janata Government appointed four Governors and not one of them belonged to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. As there are reserved constituencies for Lok Sabha, I demand that reservations must be made for SC and ST people in the Rajya Sabha and also in the Legislative Councils of the States.

Sir, the Parliamentary Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has submitted several Reports and many Action-Taken Reports. Yet the number of SC and ST staff is getting nibbled slowly but steadily. This is a life and death question of 12 crores of down-trodden people whose daily average income is just 92 paise. If the Government does not take interest in redressing the genuine grievances of the people who do not have two square meals a day, no clothes to hide their shame and are exposed to vagaries of weather without a shelter, then naturally the country will be in shambles shortly.

The Janata Party leaders, who swear that they are the heir-apparents to Mahatma Gandhi's heritage, must open new vistas of meaningful life for these people who were dear to the Father of the Nation. I am sure that the Central Government would also give legislative form to the ideal ONE COMMUNITY AND ONE GOD, which was enunciated by our late lamented leader Arignar Anna who continues to be the beacon light for four crores of Tamil people. 'Classless Indian Society' should be the ultimate objective to be achieved through constitutional process. Till then, the Central Govrnment must intiate economic and social welfare programmes with adequate amounts of money for the upliftment of 12 crores of downtrodden people who are falling fast into deepening depths of despair like water speeding down the stream.

With these words I conclude my speech.

श्री केशव राव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मैं इस ऐवान में आज अपने ख्यालात का इजहार करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह एक बड़ा अहम सवाल है । इस के बारे में अभी मेरे चन्द भाइयों ने कहा कि इस के लिये सभी जिम्मेदार हैं । मैं इस बात को मानता हूं । इस के लिये कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, पांच हजार सालों की अस्पृश्यता का यह कलंक जो हमारे सिर पर है, मुल्क पर है, इस के लिये हमारा समाज जिम्मेदार है, अब कब तक हम इस कलंक को ले चलना चाहते हैं, हमें इस को तोड़ना होगा । हमें इसके कारणों को ढूंढना होगा लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई भी सियासी पार्टी– चाहे मेरी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो– हम इस बुनियादी मसले को हल नहीं करना चाहते हैं । इस की क्या वजह है ? सदर साहब, एमर्जेन्सी आजकल खत्म हो गई है, मीसा खत्म हो गया है, हम आजाद हो गये, लेकिन इन अछूत लोगों पर, गरीब, दलित और पद-दलित लोगों पर यह मजहबी मीसा आज भी कायम है । प्रीसेन्सरशिप हमारे और आप के लिये उठ गई, लेकिन हजारों सालों से जो प्रीसेन्सरशिप उन पर लागू थी, वह आज भी बदस्तूर कायम है, हर गांव में, हर शहर में; हर जगह अभी भी उन पर आयद है । इस के लिये कौन जिम्मेदार है ? हिन्दू धर्म और हिन्दूइज्म इस के लिये जिम्मेदार हैं । हिन्दूइज्म के खिलाफ हम बोलने के लिये तैयार नहीं हैं । हिम्मत नहीं हैं । इस अस्पृश्यता का सोर्स क्या है ? अस्पृश्यता का सोर्स क्रिश्चियनिटी नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है इस्लाम नहीं है । यदि हम भारतीय संस्कृति' के बड़े अभिमानी हैं तो हम को यह भी मानना होगा कि इस कलंक के बानी हम हैं, हमारे पूर्वज हैं । इस लिये जब तक हिन्दू धर्म और हिन्दूइज्म के अन्दर से यह चीज नहीं निकलेगी, आप के तमाम इलजामात गलत हैं । सत्य-नारायण की महापूजा बनाने से या प्रीतिभोज करने से अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी, बल्कि ढोंग होगा, अस्पृश्य दलित लोगों पर जुल्म होगा, ज्यादती होगी । जिन मुट्ठी भर लोगों ने मजहब के नाम पर समाज में अपना उच्च स्थान बना लिया है और उन को गुलाम समझ कर, कंगाल समझ कर उन को भीख देना चाहते हैं, रियायत देना चाहते हैं, अपने कानून बनवाना चाहते हैं, अगर यही आप की तहजीब और तमद्दुन है तो वे लोग ऐसी तहजीब और तमद्दुन नहीं चाहते, ऐसे मजहब को नहीं मानना चाहते जो इन्सान और इन्सान में फर्क पैदा करता है । द्वेष निर्माण करता है ।

सदर साहिब, आप जानते हैं हमारे यहां दशावतार हुए हैं लेकिन कोई भी अवतार

[श्री केशव राव घोड़गे]

इन दलित लोगों का उद्धार करने के लिये नहीं हुआ, चाहे राम हों, कृष्ण हों। ऐसा कोई भी धर्म ग्रन्थ नहीं है जो यह बतलाये कि अस्पृश्यता नहीं करनी चाहिये। हमारे यहां शंकराचार्य हुए—क्या कोई भी शंकराचार्य यह कहने के लिये तैयार है कि अस्पृश्यता को नहीं मानेंगे? हमारे धर्म ग्रन्थों में वर्ण संकर, वर्ण भेद, का जिक्र आता है, इन मजहबी किताबों में यही पढ़ाया जाता है, वर्ण-संकर करना गुनाह है, अगर यह होता है तो हमें इन शंकराचार्य के मठों को, ऐसे धर्म ग्रन्थों को खत्म कर देना चाहिए। इन दशावतारों ने अस्पृश्यता को हटाने के लिये कुछ नहीं किया, मगर वर्णाश्रम का समर्थन किया, लेकिन हमारे यहां ऐसे अवतार हुए हैं— जैसे महात्मा बुद्ध, म0 कबीर, डा0 बाबा साहब अम्बेडकर, म0 ब वेश्वर महात्मा ज्योतिराव फुले, राजऋषि शाहु महाराज ऐसे—ये महात्मा थे, जो सही मायनों में इन्सानियत और धर्म इन्सानियत और मजहब को सामने लाये। गुरु गोविन्द सिंह जो अपनी कुर्बानी के साथ जब मैदान में उतरे, तो उन्होंने कहा कि इन्सान इन्सान में भेद करना अधर्म है। जो धर्म इन्सान इन्सान में भेद करता है उसे नहीं मानना चाहिए। अफसोस की बात है कि अगर दक्षिण अफ्रीका के अन्दर नीग्रो पर नाइंसाफी होती हैं, तो यू0 एन0 ओ0 के अन्दर हम आवाज उठाते हैं, रोडेशिया के खिलाफ हम नाकेबन्दी करना चाहते हैं मगर रोडेशिया जैसी हालत हमारे यहां हर जगह मौजूद है, हर गांव में मौजूद है, हर देहात में मौजूद है। फिर हमें क्या हक है रोडेशिया के खिलाफ बात करने का, हमें क्या हक है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बात करने का और यू0 एन0 ओ0 में आवाज उठाने का हमें क्या हक है जब खुद मेरे धर्म में यह बात है और हर दिल के अन्दर शंकराचार्य है? इसलिये हिन्दू धर्म में सुधार करना जरूरी है— Charity begins at home.

लिहाजा मैं आप से गुजारिश करूंगा कि आप उन को टाइम दीजिए, हिन्दूइज्म के जो वारिसदां हैं, उन को आप टाइम दीजिए कि एक साल के अन्दर पूरे शंकराचार्यों को गिरफ्तार करो और जो किताबों के अन्दर यह अस्पृश्यता है, वर्गभेद की बात है, इस को जला दो, खत्म कर दो। जब तक आप यह नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। उनको मत छोड़ो। अगर हम एक एमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो हम को कहा जाता है कि आप को अधिकार नहीं है, आप पंडित नहीं हैं, आप शास्त्री नहीं हैं। मेरा इस में क्या गुनाह है, सदर साहब। 20 साल के बाद 21 साल की उम्र होने के बाद मुझे वोट देने का हक मिला है मगर जाति और मजहब का सवाल ऐसा अजब है कि वह सब जगह आ जाता है। मां के पेट से पैदा होते वक्त भी मेरे साथ मेरा मजहब आ जाता है, मेरी जाति लगाई जाती है। उस के सेलेक्शन का सवाल नहीं है और उसमें कोई ओप्शन का सवाल नहीं है। ऐसी अजब चीज यहां पर है। लिहाजा इस बात को तोड़ना है और हिन्दूइज्म के अन्दर जो विषमता है जो अन्याय है, उस को खत्म करना है। किताबों में चाहे जो रहे, ज्ञानेश्वरी में रहे, दास बोध में रहे, मनुस्मृति, भगवद्गीता वेदान्त में रहे या किसी और किताब में रहे, जो किताब हमें गुलाम समझती है, उस किताब को जला देना हमारा फर्ज है। यह हमें करना चाहिए और आज दुनिया की यह मांग है मगर मैं गुजारिश करूंगा कि यह करने के लिए कितने तैयार हैं? आप एक कमीशन नहीं चाहे हजार कमीशन बना दें, उन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वर्णाश्रम को दफनाये बगैर इंकलाब का परचम आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं मुसलमान बन जाता हूं तो मुझे पानी देने के लिये तैयार हैं और अगर,

धर्मान्तर कर के क्रिश्चियन बन जाता हूं तो आप मेरी मदद करते हैं लेकिन अगर मैं हिन्दू अछूत हूं, तो मेरे लिए कोई चान्स नहीं है क्योंकि मैं दलित हूं, पददलित हूं । यह कौन सा तरीका है । बाबा साहब अम्बेडकर यहां चीख चीख कर बोले, मैं हिन्दू हूं मुझे इन्सानियत दीजिए, मुझे भाई-चारा दीजिए, मैं इसी हिन्दुस्तान का हूं, मूल पुरुष आदिवासी हूं, मेरा मेरे समाज का चूसना बन्द करो और केवल कागज पर नहीं, कान्स्टीट्यूशन के अन्दर नहीं बल्कि अमल के अन्दर मेरे और मेरे समाज के साथ भाई-चारे का व्यवहार करो, मगर वैसा नहीं किया गया । उन्होंने लादे हुए हिन्दू कोड बिल के खिलाफ आवाज उठा कर, उन पर गाली ग्लोज की गई । लिहाजा उनको धर्मान्तर करना पड़ा और उन्हों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । उसके बाद उन की शौहरत बनी नहीं । केन्द्रीय सरकार कहते हैं कि रहना है तो हिन्दू धर्म में रहो और अगर धर्मान्तर करते हैं, तो नाकेबन्दी की जाती है जैसा कि गांवों में दलित लोगों की नाकाबन्दी की जाती है । मैं प्रधान मंत्री जी से कहता हूं कि धर्मान्तर आज उन लोगों को मुआशी हालत नहीं बदली है । वे लखपति बनने के लिए धर्मान्तर नहीं किये थे । उन को आप किस बात की सजा दे रहे हो, यह मेरा आप से सवाल है । आज हिन्दू धर्म और हिन्दूइज्म के अन्दर इन्साफ नहीं है और भाईचारा नहीं हैं । आज देहात के अन्दर जिन्दा रहना मुश्किल है, शहरों के अन्दर रहना मुश्किल है । आज हरिजनों के लिए न वहां जगह है और न आसमान में जगह है । उन के लिए कहीं जगह नहीं है वे भूमिहीन निर्धन गरीब हैं । धर्मान्तर करने के बाद उन को आप मार देते हैं और उन की नाकेबन्दी कर देते हैं और उन की जो एकोनामिक कंडीशन है, वह और भी ज्यादा खराब हो जाती है । मैं आप को बताऊं कि महाराष्ट्र में एक गांव में एक श्मशानवटा की योजना है । यह स्कीम वहां पर है । उसी तरह से गांव में एक मसनवटा भी हो, एक कब्रिस्तान भी हो । मरने के बाद जाति के नाम पर दफनाया जाता है, जो जात वही जाति वह मरने के बाद भी रहती है, मुर्दे की छाती पर वर्ण रचाया जाता है और मरने के बा भी जाति को मरने नहीं दिया जाता है, वर्ण को मरने नहीं दिया जाता हैं । ऐसी हमारी आदर्श संस्कृति है । इस तरह से इस जात-पात को मरघट, शमशान भूमि पर भी कायम किया जाता है । अगर यह होता है तो हमारा फर्ज है कि इस को खत्म कर दिया जाएं । हम अगर नान-ब्राह्मण हैं, तो हम को कहा जाता है कि हम ब्राह्मणों के दुश्मन हैं । यह कहना गलत बात है । हिन्दुस्तान की सियासत को अगर देखा जाए, हिन्दुस्तान के रंग को अगर देखा जाए और हिन्दुस्तान की एकोनामिक पालिसी को अगर देखा जाए, हर जगह बेरहम संस्कृति नजर आएगी । हम लोग यह कहते हैं कि इस तरह की संस्कृनि गलत है ! इस में हमारा क्या इन्ट्रेस्ट है । दलित कहते हैं कि इस में हमारा स्थान कहां हैं ?

सभापति महोदय : आप रिपोर्ट के ऊपर ही बात कीजिए ।

श्री केशवराव धोंडगे : मैं बुनियादी बात कह रहा हूं । रिपोर्ट में भी यही हैं । इस को आप मानें या न मानें लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश का कल्याण हो तो आप को अस्पृश्यता को जड़मूल से नष्ट करना होगा । अस्पृश्य जो हैं उन में भी अस्पृश्यता समाज के लोग हैं और जो स्पृश्य हैं उन के अन्दर अस्पृश्य लोग हैं । इस वास्ते यह जो अस्पृश्यता है उस को आप को समूल नष्ट करना होगा । कमिश्नर की रिपोर्ट में किसी को दो टके की नौकरी दे देने से या कुछ पैसा किसी की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देने से यह कंलक दूर नहीं हो सकेगा । इस के लिए सब जिम्मेदार हैं । हमदर्दी का इजहार कर देने मात्र से यह समस्या हल नहीं हो सकेगी । उन्हें इन्साफ चाहिए । सक्रिय आप को इस के लिए

[श्री केशव राव घोडंगे]

करना होगा । ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को आप हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखें । हरिजन कल्याण का ढोल बजाते रहने से कोई फायदा नहीं है । जो बुनियादी चीज है उस पर आप को जाना होगा । सब लोग एक समान समझे जाने चाहियें । किसी मजहब में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होना चाहिए । यह जो उच नीच की बीमारी है मजहब में जो इस की चर्चा की गई है, उस पर आप को पावन्दी लगानी चाहिए । इस को खत्म करने का आप को कोई रास्ता निकालना चाहिए । अगर ऐसे कोई धर्म ग्रन्थों के खिलाफ या किसी धर्म मार्तंड के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बात कह देता है या लिख देता है तो उस के खिलाफ डिफार्मेशन का केस दायर कर दिया जाता है और उस को जेल जाना पड़ता है । इमोशनल इंटेग्रेशन की बात कही जाती है अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना नहीं लाई जा सकती है । जो हजारों सालों से मरे हुए हैं, दबे हुए हैं, पीड़ित हैं, और जो घोर अभाव की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, जो मर रहे हैं उन की भावनाओं का अभी तक आपने ख्याल नहीं किया है, उन की तकदीर आप ने बनने नहीं दी है । उन के पास न जमीन है न धन है । न दौलत है । कुछ भी उन के पास नहीं है । सच बोलने से किसी की भावना दुखती है तो भावनाओं का बीमा उतारिएगा । आप तो जानते ही हैं कि बंगला देश किस तरह से बना । पश्चिमी पाकिस्तान ने नाजायज तौर पर उस का शोषण किया । वहां पर शूर लोगों ने इसका विरोध किया, दलित समाज ने आवाज उठाई, बगावत की और जो अन्याय उस के साथ हो रहा था, उस के खिलाफ झंडा बुलन्द किया और नतीजा यह हुआ कि बंगला देश बना और वह पाकिस्तान से अलग हुआ । आज हमारे दलित लोग यही समझते हैं कि जो बजट बनता है वह उन के लिए नहीं बनता है, जो स्पृश्य लोग हैं उन के लिए बनता है, पार्लियामेंट हाउस भी उन के लिए है । उन का न सभापति है, न राष्ट्रपति है । एक दो मंत्री उन के ले लिए जाते हैं । इन लोगों को पीछे की पंक्ति में रखा जाता है । आगे की पंक्ति में आने का इन को अवसर नहीं दिया जाता है । इस तरह की चीजें जब तक रखेंगे तब तक आप कमिश्नर की तकरीर कर लें कोई लाभ नहीं होगा, वक्त जाया करना होगा । इस तरह से आप उन को इंसाफ नहीं दे सकेंगे । अगर यही हालत चलती रही तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोग बगावत कर देंगे और मांग करने लग जायेंगे कि दलितस्थान और बौद्धस्थान उनके लिए कायम किया जाए । ऐसी मांग करने का उन को हक रहेगा । बीसवीं सदी में भी इंसान को मसावी हकूक हासिल नहीं हुए हैं । मजहब के सामने सब समान होने चाहियें । नहीं हैं तो मजहब को खत्म करो । मैं इन मेरे दलित बौद्ध भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इन पर जो ज्यादतियां होती हैं, गांवों में होती हैं या कहीं और होती हैं उन का इन को डट कर मुकाबला करना चाहिए । मेरे गांव में भी होती हैं दूसरी जगह भी होती हैं । इन का इन को डट कर मुकाबला करना चाहिए । मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि समाज के अन्दर यह मसला हल नहीं होगा उस तरह से जिस तरह से आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आर टी सी से हल नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से, इकोनोमिक लिहाजा से जो कमजोर है उन की आप पूरी मदद करें अगर इस में ब्राह्मण और नान-ब्राह्मण का और किसी धर्म का सवाल नहीं होना चाहिए । इन को दबाए रखने से काम नहीं चल सकता है । किसी को गुलाम आप बनाए रखें इस तरह से काम नहीं चल सकेगा । दलित समाज कहता है कि आज हिन्दुस्तान आजाद है लेकिन मैं आजाद नहीं हूं । हिन्दुस्तान को आजाद हुए तीस साल हो गए हैं लेकिन मुझे आजादी नहीं मिली है । दूसरों के लिए एमरजेंसी खत्म हो गई है मेरे लिए नहीं हुई है । इस वास्ते आपको

बुनियादी बात जो है, जो बुनियादी मसला है उसको सामने रखना होगा और धार्मिक तौर पर ये लोग आजाद हों और शंकराचार्य हों या कोई और धर्माचार्य हों, मठ हो या मंदिर हो जहां कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है जातपात के आधार पर उसको बन्द किया जाए। ऐसा किया जाएगा तभी सही मानों में तमाम दलित समाज को न्याय मिल सकेगा। बौद्ध समाज की सहूलियतों को भी आप को चहिए कि आप जारी करें। यही अन्त में मैं आप से कहना चाहता हूं।

श्री युवराज (कटिहार): सभापति महोदय, आज हम यहां पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के तीन प्रतिवेदनों पर एक साथ विचार कर रहे हैं। यह ठीक है कि काफी दिनों के बाद, बहुत ही विलम्ब के बाद इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है और इसके बाद की दो रिपोर्टें अर्थात् 1974–75 और 1975–76 भी गृह मंत्रालय में आ गई होंगी। मैं आप से यह निवेदन करना. .

सभापति महोदय: आप आगे आ जाएं।

सभापति जी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज जिस रिपोर्ट पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं वह दो रिपोर्ट्स हैं और यह 700, 800 पन्ने की रिपोर्ट्स आयीं हैं और एक ही अनुशंसा को बार-बार दोहराया गया है। अगर 21वीं रिपोर्ट समय पर पेश हो जाती तो उस पर हम विचार कर सकते थे। लेकिन एक ही साथ 5, 6 सालों की रिपोर्ट आयी है। ऐसी व्यवस्था गृह मंत्रालय को करनी चाहिए कि जब रिपोर्ट इनके यहां कमिश्नर की तरफ से पेश हो तो वह तीन महीने के भीतर जब लोक सभा अधिवेशन में हो, उसे पेश किया जाय और जो अनुशसायें या टिप्पणियां आती हैं, जितना सम्भव हो उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाय।

17 hrs.

अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसके अतिरिक्त 1974–75, 1975–76, 1976–77 की, हम यह अपेक्षा करते थे कि, जो रिपोर्ट्स आ के यहां आयी हैं उनका रूपान्तरण करके आप पेश करेंगे और जो रिपोर्ट नहीं आयी है उसको मंगाने की कोशिश करेंगे। हम जब रिपोर्ट का सिहावलोकन करते हैं तो क्या देखते हैं कि जितने मुद्दे हैं चाहे वह शिक्षा के सम्बन्ध में हो, नौकरी के सम्बन्ध में हो, अत्याचार उत्पीड़न के सम्बन्ध में हो, उत्पीड़न के सम्बन्ध में हों, भूमि आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में हो, तमाम मुद्दों में अनुशंसायें आयी हैं, और हम यह कहने में संकोच नहीं करेंगे कि केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी पर दोष देने से हमारा काम नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल इस भावना को प्रतिबिम्बित करता है कि हम लोकतन्त्र के सबसे बड़े केन्द्रीय स्वरूप हैं, लोकतंत्र के विचारों को कार्यान्वित करते हैं? आपके मंत्रि मंडल में क्या एक भी आदिवासी आ सका? आपके मंत्रिमंडल में इतने दिनों के बावजूद भी जो भी हरिजन माननीय सदस्य आये हैं निर्वाचित हो कर उनमें से क्या आपने एक भी आदमी को लिया। और हम सवाल उठाना चाहते हैं, यह बहुत ही बुनियादी सवाल है। एक बाबू जगजीवनराम जी को लिया जो राष्ट्रीय कोटि के आदमी हैं। यह ठीक है कि वह हरिजन हैं और उनके आने से हरिजन का कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन मैं यह अपेक्षा करता था इस जनता पार्टी के केन्द्रीय मंत्रिमंडाल में एक हरिजन भी आवेगा। वह भी नहीं आया। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं हम एक सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। राजनीतिक समानता तो मिली लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता के हम अभी भी शिकार हैं। और यह लोकतंत्र का जो ढांचा है अगर हम अन्तरविरोधों को दूर

[श्री युवराज]

नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का ढांचा एक दिन गिर कर चूर चूर हो जायगा। हम 22 प्रतिशत आबादी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जिनकी आबादी देश का पांचवां हिस्सा हो उनकी इतने दिनों तक उपेक्षा नहीं कर सकते।

आये दिन इन पर जो अत्याचार हुए हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे निर्मल चरित्र पर बेलची का कांड एक ऐसा धब्बा है जिसे धोया नहीं जा सकता है। केवल बेलची का कांड ही नहीं, भागलपुर जिले में पथड्डा नाम की जगह पर 19 जून को एक घटना घटी मिनिमम वेजेज के नाम पर कि हमें निम्नतम मजदूरी दो। सारे गांव के चमार हरिजनों को घेर कर स्कूल में ले जा कर बन्द कर दिया गया, 30 मर्द और 20 महिलाओं को पीटा। अधोरी नामक चमार और जागेश्वर घायल हो कर आज भी अस्पताल में पड़े हैं। तिलिया नामक स्त्री भी अस्पताल में पड़ी है। इससे बड़ी दर्दनाक घटना और क्या हो सकती है। आज भी धनबाद कोलियरी के बारे में जब मैंने अमैण्डमेंट पढ़ना शुरू किया, माननीय सदस्य श्री ए० के० राय के संशोधन को देखा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है ---

"regrets the denial of admission to the Central Hospital, Dhanbad, to the Harijan sweepers. ..."

कोलियरी में जो हरिजन स्वीपर नौकरी करते हैं, झाड़ू देते हैं, उनके बीमार पड़ने पर धनबाद कोलियरी के अस्पताल में उनकी भर्ती नहीं हो सकती है। क्या गृह-मंत्री जी अपने जवाब के वक्त यह बतायेंगे कि क्या उन्होंने इस संशोधन के बारे में कोई इन्क्वायरी कराई है ? यदि कराई है तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री ए० के० राय बिहार के चुने हुए जन-कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिम्मेदारी से यह बात कही है। यह भी हमारे नाम पर एक कलंक है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो फाइनेन्शियल कार्पोरेशन्ज हैं, आंध्र, आसाम, केरल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आदि में वह भी रुपये के अभाव में हरिजनों को लोन नहीं दे सकते। नेशनलाइज्ड बैंकों से भी उनको सूद की कम दर पर ऋण नहीं मिल पाता है। यही नहीं, सैंट्रल सक्टर में, स्माल स्केल डैवलपमेंट कार्पोरेशन में भी इनको नाम-मात्र का ऋण दिया जाता है। जमीनों से यह बेदखल होते हैं। मौजूदा समाज का जो ढांचा है वह मिनिमम वेजेज भी इनको नहीं देता है। मार भी ये ही खाते हैं, शिक्षा में भी कम-से-कम जगह मिलती है, कम से-कम लोगों को नौकरी मिलती है। तो हम जिस सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं वह अन्तर्विरोधों का है और सामाजिक व आर्थिक क्रांति हो रही है। समाज में तनाव पैदा होगा और आन्दोलन सशक्त बनेगा। जब तक मौजूदा समाज का ढांचा नहीं टूट जाता है, जब तक हम पूर्वाग्रहों के रोग से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्कूल हैं और मैडिकल कालेज हैं। केन्द्रीय स्कूलों में जो इनकी स्थिति है उस पर भी विचार किया जाये। 170 केन्द्रीय स्कूल हैं जिनमें 1 लाख 29 लड़के कुल मिला कर शिक्षा पाते हैं, उनमें हरिजन कितने हैं ? उनमें हरिजन 2039 हैं यानी 2.38 प्रतिशत और आदिवासी 524 यानी 0.52 प्रतिशत। यह हमारी स्थिति है इस देश में केन्द्रीय विद्यालयों में और हम हरिजनों

के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं।

गांवों में जो माध्यमिक शिक्षा मिलती हैं, पैस जाते हैं, छात्रवृत्ति जाती है, क्या वह समुचित रूप से मिल पाता है? केवल गिरि जी के दामाद को गाली देने से हमारा काम नहीं होगा, हमें इस दोषपूर्ण व्यवस्था को बदलने की जरूरत पड़ेगी। हमारे जो संस्कार बने हैं, हमें आत्म-निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम हरिजनों और आदिवासियों के प्रति कितने ईमानदार और वफादार हैं और अपने मन में हमने पूर्वाग्रहों को कहां तक मिटाने की कोशिश की है।

इस देश में 105 मेडिकल कालेज हैं। आज भी लोकमान्य तिलक मेडिकल कालेज (सियोन, बम्बई), काकाकिया मेडिकल कालेज (वारंगल, आंध्र प्रदेश), रंगाराया मेडिकल कालेज (काकीनाडा), जमशेदपुर मेडिकल कालेज (बिहार), मेडिकल कालेज (शोलापुर, महाराष्ट्र), मेडिकल कालेज (गुलबर्गा, कर्नाटक), कस्तूरबा मेडिकल कालेज (मणिपुर), मेडिकल कालेज (देवनगरी) और मेडिकल कालेज (बेलगांव, कर्नाटक) में अनुशंसा के बावजूद हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20-सूत्री कार्यक्रम का बहुत प्रचार किया जाता था, लेकिन वास्तव में क्या काम किया गया, वह इन आंकड़ों से प्रकट हो जाता हैं। 1975 में क्लास वन में कुल नियुक्तियां 3116 हुई, जिन में हरिजनों के लिए 385 सुरक्षित स्थान थे, मगर केवल 293 हरिजनों की नियुक्ति हुई, और आदिवासियों के लिए 197 स्थान सुरक्षित थे, लेकिन केवल 70 आदिवासियों की नियुक्ति हुई। क्लास टू में 5183 कुल नियुक्तियां हुईं, जिन में 717 स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित थे, मगर केवल 550 व्यक्ति किये गये, और आदिवासियों के लिए 268 स्थान सुरक्षित थे, लेकिन केवल 72 व्यक्ति नियुक्त किये गये। तीसरी और चौथी श्रेणी की भी यही स्थिति थी।

माननीय सदस्य, श्री हुकम देव नारायण यादव, के एक प्रश्न के उत्तर में 13 जुलाई, 1977 को गवर्नमेंट की तरफ़ से बताया गया कि 1 जनवरी, 1976 तक भारत सरकार के अन्तर्गत क्लास वन के कुल कर्मचारी 37,151 थे, जिन में से हरिजन 1287 अर्थात् 3.46 प्रतिशत और आदिवासी 253 अर्थात् 0.68 प्रतिशत थे। इसी तरह उन्नति के सभी क्षेत्रों में ये लोग काफ़ी पीछे छूट गये हैं।

आज हमारे देश में गांवों की टोटल पापुलेशन में से 70 फ़ीसदी लोग खेती करते हैं, जिन में 40 फ़ीसदी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, और उन में से 30 हरिजन और आदिवासी हैं।

मैं मानता हूं कि तीन महीने में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं यह भी मानता हूं कि तीन महीने में हम अपने कानूनों को पूरी तरह इम्लीमेंट भी नहीं करा सकते, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी हैं। लेकिन नीति में तो हम परिवर्तन कर सकते थे। केवल नौकरशाहों को गाली दे कर हम जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। किसी ने ठीक कहा हैं कि पाप तो हम करते हैं, और दूसरों पर थोपते हैं। हमारे आचरण और संस्कार कितनी दूर तक इन उपेक्षित लोगों को अपनाने के लिए तैयार हो सके हैं, यही बुनियादी प्रश्न हैं।

आज केवल दो या तीन प्रतिशत हरिजन-आदिवासियों के पास जमीन हैं।

[श्री युवराज]

इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि ऐसा कानून बनाया जाये कि तीन एकड़ तक जमीन रखने वाले हरिजन-आदिवासियों की जमीन की बिक्री नहीं होगी। इस के अतिरिक्त उन्हें जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन दिये जायें। ऐसा न हो कि व महाजन के चंगुल में फंस जायें। पिछले वर्ष बहुत से बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का आन्दोलन छेड़ा गया था और सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किये थे। (व्यवधान) मेरा तो संशोधन था। आपने मुझे वक्त देकर बड़ी कृपा की। मैं जल्द ही अपनी बात खत्म करूंगा। केवल तकरीर देने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरी जो आहत भावना है वह व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जरूरत इस बात की है कि हरिजनों और आदिवासियों में जो आत्मविश्वास है उसे जागृत किया जाये और जो चोट खाया हुआ स्वाभिमान है उसे जगाया जाये। जब तक उसका स्वाभिमान और आत्मविश्वास नहीं जगेगा तब तक हम यहां केवल चर्चा कर संतोष की सांस ले सकते हैं लेकिन उनको राहत नहीं दिला सकते।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारा लैंड रिफार्म कानून है उसके लिए हम अपने मुख्य मंत्रियों से कहें कि जो मौजूदा कानून है उसमें तरमीम करें। अगर 10 प्रतिशत भूमिहीन हरिजनों को जमीन दे सकते है तो उसे देने के साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी। जो आपके बैंक्स हैं उन्हें उनको ऋण देने के लिए तैयार करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो रिजर्वेशन हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके प्रतिशत में वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी और साथ साथ जो हमारी संस्थायें हैं, चाहे कांग्रेस की हों चाहे जनता पार्टी की हों, उनके द्वारा एक सामाजिक आन्दोलन के रूप हरिजन और आदिवासियों के लिए, जो कि निर्बल हैं, एक सतत चेतना जागृत करने की जरूरत पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जिन बुनियादी सवालों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है अपने उत्तर में उन तमाम बातों को आप मद्देनजर रखेंगे और सारी बातों को स्पष्ट तौर से सभा में कहने की कोशिश करेंगे जिससे हिन्दुस्तान की जनता को इन बातों का पता लगे कि जनता सरकार के मंत्रिमंण्डल की एक स्पष्ट नीति और एक स्पष्ट दृष्टि है।

श्री मंगल देव (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई, सात वर्षों के बाद यह रिपोर्ट आई और वर्तमान सरकार के मंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक पहल की जिस से यह रिपोर्ट सदन के सामने चर्चा का विषय बन गई। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिन विषयों की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है मैं कोशिश करूंगा कि उन को दोहराना न पड़े। यह रिपोर्ट आई, इस में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हैं, उस में जाने से कोई लाभ नहीं। इन चार प्रतियों की रिपोर्ट में सारी समस्यायें नहीं लिखीं जा सकती और लिखने और जांच करने का एक बहुत दिनों का तरीका बना हुआ है। यह मोटी रिपोर्ट आ जाती है। प्रारम्भ में अभी किसी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि रिपोर्ट तो आई, रिपोर्ट टेबल पर पेश हुई लेकिन उस के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं उसके बारे में दो पन्ने की सूचना भी नहीं आई। इस से क्या बात समझ में आती है ? इरादा पर हमला करने का मन करता है, नीयत ठीक नहीं है। बहस यहां पिछले सदनों में होती रही हैं। देश की विधान सभाओं में बहस होती है। छोटी मोटी रिपोर्ट

आती है। लोग इन वर्गों की चिन्ता में कुछ भाषण करते हैं लेकिन मामला टस से मस नहीं होता। समाज इतना संस्कार-ग्रस्त हो गया है कि कानून बनाने में पहली चोरी होती है। उसमें छेद छोड़ दिया जाता है, भागने की फुर्सत रहती है और नौकर-शाही के हाथों में कार्यन्वयन के लिए दे दिया जाता है। छुआछूत के मामले का फैसला वह मजिस्ट्रेट करेगा जो पूर्व संस्कारग्रस्त है और गांव में जिसके यहां छूआछूत मानी जाती है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी आर्य समाजी हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि उन्होंने अपने तरीके से छुआ-छूत के बारे में कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। जहां तक छूआछूत का सवाल है, इस देश का हर पांचवां आदमी अछूत कहा जाता हैं और उस आदमी को यह समाज राजपाट, धन दौलत, नौकरी या रोजी रोटी नहीं देना चाहता क्योंकि वह उसको आदमी नहीं समझता, उसको वह छोटा समझता है, हीन समझता हैं और ईश्वर तथा भाग्य के भरोसे उसको छोड़ देता है। मेरी राय यह है कि अगर इस देश में जनतंत्र नहीं होता, वोट का मसला नहीं होता और घर घर जाने की आवश्यकता नहीं होती तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता और न यहां पर हम लोगों को कोई चर्चा करने का अवसर ही प्राप्त होता। अगर सरकार गांवों में कुवें बन-वाती है तो सावन भादों के महीने में बन-वाती है जिसका नतीजा यह होता है कि सारा बजट का पैसा खा लिया जाता है। तो जिस देश में पीने के लिए पानी की व्यवस्था न हो, चारपाई पर बैठना मना हो, गिलास-लोटे का मामला हो वहां पर गरीबों की आर्थिक हालत, सामाजिक और शैक्षिक हालत का विकास होना सम्भव नहीं है।

पुलिस के बारे में श्री रामानन्द जी ने एक दिन कहा था कि पुलिस की सुविधायें कम हैं, वह उनको मिलनी चाहिए, मैं उनसे सहमत हूं लेकिन पुलिस के अत्याचार गरीब वर्गों पर और अनुसूचित जातियों पर वैसे ही होते हैं जैसे गांवों में जमीदार गरीब आदमियों पर अत्याचार करता है। वहां पर जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है वैसा ही व्यवहार आज पुलिस भी इन लोगों पर करती है। पुलिस और दूसरे मुहकमों को सरकार कैसे सुधारती है उसमें मैं जाना नहीं चाहता। रिपोर्ट में अत्याचारों की चर्चा की गई है। बार बार रिपोर्टें आती हैं और उसमें अत्याचारों की चर्चा की जाती है और कहा जाता हैं कि समाज ठीक नहीं है। अत्याचारों की चर्चा करने से तो काम चलेगा नहीं। अत्याचार हो रहे हैं, यह गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट और सारा देश उसके लिए जिम्मेदार है। मैं बेलप्री काण्ड की चर्चा नहीं करना चाहता, वह काण्ड हो चुका है। दक्षिण भारत में 43 आदमी जला कर मार डाले गए, उसकी भी मैं चर्चा नहीं करता लेकिन न्यायालयों के जजों की न्यायप्रियता पर मुझे शक करने का हक है। हाईकोर्ट का जज 22 मुल्जिमों को यह कह कर छोड़ देता है कि जमीदारों के पास इतने नौकर हैं कि वह खुद झोपड़ी जलाने नहीं जायेगा। दूसरा तर्क यह दिया कि जब वे घर जला रहे थे तब वे नहीं जानते थे कि उन झोपड़ियों में आदमी भी हैं। इस पर उन गरीबों के वकील ने कहा कि आप यह भी मान लीजिए कि जलने वालों का भागने का इरादा नहीं था। वे इस प्रकार की हमारी हाई कोर्ट और न्यायमूर्तियां हैं। वे सैकड़ों पीढ़ियों से संस्कारग्रस्त हैं। केवल वहां बैठने से, ज्यादा डिग्रियां लेने से या अच्छे कपड़े पहनने से यह सब होने वाला नहीं हैं। इसके लिए तो कोई जरबर्दस्त तब्दीली लाने की जरूरत होगी।

हत्याओं के बारे में मैं सारे देश के आंकड़े तो नहीं जानता लेकिन उत्तर प्रदेश के

[श्री मंगल देव]

बारे में जानता हूं और उसकी तरफ चौधरी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यद्यपि उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा होगा और वे मुझ से ज्यादा जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में पहली जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974 तक 60 हरिजनों के कत्ल हुए--यह सरकारी रिपोर्ट में दिया है। इसीलिए मैंने इसकी चर्चा करदी। यह घटनायें कैसे हो रही हैं? वाराणसी में बेहड़ा काण्ड हड़ौरा काण्ड और गाजीपुर में शेरपुर काण्ड हुए। शेरपुर काण्ड में एक बिरादरी विशेष के आदमियों ने जुलूस निकाला और नारा लगाया--जिला प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन जिन्दाबाद। पुलिस कप्तान ब्राह्मण था तो सभी भूमिहरों ने जुलूस निकाले और भूमिहरों की भीड़ ने 26-27 हरिजन घरों के गांव को जला डाला था। पुलिस सुरक्षा में ढिलाई की थी। जिलाधीश हरिजन था और उसने उचित कार्रवाई करने की कोशिश की थी। इसलिए मुर्दाबाद कहा गया। और जान से मार डाला था, सम्पत्ति का नाश हुआ था। मैं इस बात से सहमत हूं कि चौधरी साहब इस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, सारा देश--इस के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब जब ऐसी बातें होती हैं--तो जनता पार्टी की जिम्मेदारी रोज-ब-रोज बढ़ती जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न के बारे में इन अदालतों पुलिसवालों या सरकारी अफसरों के बारे में हम लोगों को बड़ा भ्रम है। वे लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, टाई बांधते हैं, गिटिर-पिटिर बोलते हैं--हमारे डा० लोहिया साहब इस को गलालंगोट कहते थे --इन आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० अफसरों के कामों को देखें तो इन लोगों ने उन गरीबों के साथ जो अन्याय किया है, उस के लिए ये माफ़ करने लायक नहीं हैं। श्रीमन्, जनता के स्नेह से मुझे जनता में काम करने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि उनका चरित्र अभी तक नहीं बदला है। वे तनख्वाह के लिए काम करते हैं, खूबसूरती से बच निकलने की सारी तरकीबें उन के पास हैं, उन का पोवा मजबूत है। वे देखते हैं कि हमारा एम०पी० कौन है, हमारा मंत्री किस जाति का है--उस को अपना बना कर चलने की कोशिश करते हैं।

मैं चौधरी साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं--वे अपने कानून में कुछ परिवर्तन करें। हमारे यहां जो मुस्लिम मेहतर हैं, उन को हिन्दू मेहतरों के मुकाबले कम सुविधायें मिलती हैं। उन का कहना है कि हम भी उसी जिन्दगी में रहते हैं, जिस में हिन्दू मेहतर रहते हैं, हमारे बच्चे भी उसी जिन्दगी में रहते हैं, फिर हम को भी वे सुविधायें क्यों नहीं मिलती जो हिन्दू मेहतर को मिलती हैं। उन को भी उसी तरह से पानी की, आवास की, शिक्षा की और सुरक्षा की सुविधायें मिलनी चाहिए।

हमारे कई मित्रों ने नवबुद्धों के बारे में जिक्र किया। मैं उस को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं उन से सहमत हूं--उनको भी सभी सुविधायें मिलनी चाहिए। उन के आर्थिक और शैक्षणिक प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए। लेकिन यहां मेरी यह भी निश्चित राय है कि कोई भी जाति हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो--कोई भी हो, यदि किसी का लड़का गरीबी की वजह से न पढ़ पाता हो, तो हमें जातिवाद से ऊंचा उठ कर उन की मदद करनी चाहिए।

यहां चौधरी साहब से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं--अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के छात्रों को दसवं दर्जे तक स्कालरशिप अनिवार्य कर दिया

जाय, अभी यह अनिवार्य नहीं है। मैं और ऊपर की बात नहीं कहता, आप के बजट पर भार नहीं डालना चाहता, लेकिन दसवें दर्जे तक इसको अनिवार्य कर देने से उन को बहुत सुविधा हो सकती है। दसवें दर्जे का सर्टिफिकेट ले कर वे कहीं भी जा कर काम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस में आप थोड़ी उदारता बरतने की कृपा करेंगे।

हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि जो संस्थायें हैं, माफ़ कीजिये—ये जितनी संस्थायें हैं, सब पार्टी का प्रचार करने के लिए है। लाखों रुपया इन संस्थाओं को सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन दलित वर्ग को इन से कोई लाभ नहीं पहुंचा। यदि आप इन के खिलाफ़ जांच करायें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से गरीबों से वाउचर दस्तखत करा कर उन का सारा रुपया खा लिया जाता था। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जिम्मेदारी से कह सकता हूं—और हम से कोई सलाह ले तो सैकड़ों लोगों का चालान हो सकता है जो इन गरीब बच्चों का दूध, चावल, कपड़ा, चुरा लेते हैं और उन से वाउचर साइन करा लेते हैं, और अधिकांश पैसा खा जाते हैं।

खेत मजदूरों के रोजगार के बारे में कल हमारे बहुत से मित्रों ने चर्चा की। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जवाब देने में बहुत जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने 10 वर्ष की बात कही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं—आज कितने घरों में उपवास होता है, इस के कोई आंकड़े नहीं हैं। अब पहले जैसा राज्य तो है नहीं, जब राजा स्वयं घूम कर देखता था कि कहां कौन तड़प रहा है, कौन बीमार है, कहां उपवास हो रहा है। आज का राजा तो तहसीलदार और डिप्टी कलैक्टर की आंखों से देखता है जिन की आंखें फूटी हुई हैं, इस तरह की समस्याओं के लिए ठीक रिपोर्ट नहीं आती है। आज खेत मजदूरों की जो हालत है.....

MR. CHAIRMAN : You can continue tomarrow.

17.29 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Working of Vijaya Bank

MR. CHAIRAMN : I Call Shri Lakkappa for the Half-an-hour discussion.

SHRI K. MALLANNA (Chitradurga) : Rule 55, sub-clause (3) states that the Speaker shall decide whether the matter is of sufficient public importance to be put down for discussion, and may not admit a notice which, in his opinion, seeks to revise the policy of Government.

Sir, it is neither a matter of public interest nor of sufficient importance. It is only an individual interest. The main question arises from.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Order, order. Please sit down. This has already been admitted and it is put down for discussion to-day. I cannot sit in judgement ....(*Interruptions*)

SHRI K. MALLANNA : It can be raised at any stage.

MR. CHAIRMAN : Will you kindly sit down now ? It has already been admitted by the Speaker. Now, I cannot sit in judgment over his ruling. That is beyond my powers. The discussion will continue.

SHRI K. MALLANNA : Sir, the point of order can be raised at any stage.

MR. CHAIRMAN : There is no point of order. Will you kindly sit down ? Whatever you say cannot be taken down unless you explain to me as to what is your point.

SHRI K. MALLANNA : Sir, I will read out the unstarred question 4576....

MR. CHAIRMAN : What are you driving at ? Will you Kindly let me know that ?

SHRI K. MALLANNA : I am speaking.....

MR. CHAIRMAN : This may not go on like that. I call upon Shri Lakkappa now.

SHRI K. MALLANNA : Sir, my point is that this should not be discussed.

MR. CHAIRMAN : I am calling you to order. Please sit down.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I am raising a discussion about Vijaya Bank Ltd. Sir, this is one of the biggest financial institutions in this country. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Order, order. Mr. Lakkappa, you may go on now.

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, the other day, my friend, Shri Ravi has raised an issue on the basis of a starred question when the hon. Finance Minister evaded to give a pertinent answer to a pertinent question.

I would like to put it to you this that the Chairman of the Vijaya Bank Ltd. is not an ordinary man. He is controlling more than Rs. 200 crores in the bank. He is more powerful than the hon. Finance Minister of this country to-day. That is because he is not only controlling the higher-ups as also the V.I.Ps who are under his control. Let me now state the illegal activities of the Chairman of the Vijaya Bank Ltd. Sir, I won't make it an individual issue; nor will I make it a party issue. I would like to quote a certain statement made....

MR. CHAIRMAN : You are required to put certain questions.

SHRI K. LAKKAPPA : I would like to say that this is not a political issue. I will never raise any political issue. Shri Madhu Limaye, socialist Member said something about it. He is now a General Secretary of the Janata Party. Shri Limaye in the Lok Sabha cited seven instances one of which was a forged one hundred rupee note. Sir, the Chairman puts out these notes in various branches of the Vijaya Bank from Kanyakumari to Kashmir and it is revealed that hundred rupee notes were being circulated and cases are being launched. I would like to quote it for the benefit of the hon. Minister. On that day in reply to a question he said that this was a very technical offence. Sir, I would only cite the note's series 133477 and would not quote the rest. Sir, he is squandering the money belonging to the depositors. I would like to read out to you as to how the people have been patronised and how the public money has been misused. Sir, one Shri L.N.Mehta, is a close friend of the Chairman of the Bank. Shri Mehta carries on money-lending in the name of 'Mehata Brothers' and 'Popular Credit Corporation'. Overlooking all the instructions given by the RBI, the Chairman has sanctioned facilities to the extent of Rs. 50 lakhs to Mr. Mehata to purchase vehicles. In every case there is valuation report regarding financing and other securities and all these things had to be dealt with but regarding this Mr. Mehata no rules and regulations of the RBI have been observed.

Then there is the case of M/s. Cest Tyres Ltd. They were advanced a loan of Rs. 1 crore where even the ordinary rules and norms of the RBI have been flouted. I need not give all the details. The first inspection report of the RBI has revealed that loans to the tune of 5 per cent are irrecoverable. These loans have been advanced to all sorts of people patronised by the Chairman without taking any security.

The second inspection report reveals about squandering away of depositors' money. The public money is being looted by this bank. The second inspection report of the RBI says that 12·5 per cent—which comes to nearly Rs. 10 crores—of the deposit money has been squandered away. Here I would like to say a word about the rate of interest. Lesser and lesser rate of interest has been charged from various people by the Chairman—mind you, Chairman has no right to do it—resulting in an estimated loss of Rs. 5 crores to the bank. I can give all the details. The Chairman has no right. He has flouted all the norms.

Mr. Chairman, Sir, my next point is about the circulation of counterfeit currency notes. Currency notes worth over Rs. 40 lakhs were accepted by the bank as fixed deposits and these counterfeit notes were circulated to the benefit of the friends of the Chairman. This matter has figured in various newspapers including *Economic Times*, *Deccan Herald* and *Indian Express*. No action has been taken in this respect. No person holding such a responsible position would act in such an improper way.

Now, Sir, where has he kept this amount of money. He has kept it in foreign banks. It is reliably learnt that

the follwoing foreign bank accounts are being maintained by Mr. Shetty :

	A/C No.
1. The First National City Bank Doul Street, New York . . .	81390
2. Swiss Credit Bank, Lugano . . .	98710
3. Swiss Credit Bank, Turino	8089851

Sir, the remittances received were so heavy that the son-in-law of Chairman Dr. Taranath Shetty protested that the Federal Revenue Officials were after him in the States as to how so much amount has been put from this country there. They were searching for him.

Sir, the banks are run with the decisions of the Directors but here no decisions were taken by the Directors. By passing all the norms the money was given.

"The deep involvement of the Chairman with two notorious sumgglers i.e. Shri K.S. Abdula of Kesargod and Shri Sufi Ibrahim of Kasargod/ Mangalore and other smugglers can be found out from the records of the Bank by going into details of the large amount of loans sanctioned to the firms owned and controlled by the above-said two smugglers and their relatives".

AN HON'BLE MEMBER : Sir, he is referring to so many things.

SHRI K.P. UNNIKRISHNAN (Badagara) : It was also referred to by Mr. Madhu Limaye in the last House.

SHRI K. LAKKAPPA : Various malpractices have been found out and they have registered cases against them. The cases are pending before the Court. I would like to put a number of questions arising out of this fact.

1. Whether the Reserve Bank kept the inspection report in cold storage nearly for one year ?

2. Reserve Bank avoided deliberately investigating into the Income Tax prosecutions against Sunderram Shetty.

3. When forced, they hurriedly instructed their Bangalore Office to get some skeletons.

4. This report was handed over by Mr. P.N. Khanna to Mr. Sunderram Shetty for getting a favourable opinion from solicitors M/S Mulla & Mulla & Craigie Blunt & Carce.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayuikil): This opinion has been conveyed through telex.

SHRI K. LAKKAPPA: 5. Mr. Khanna wrote a letter to the Banking department saying the R.B.I. has obtained opinion from a leading soliciter from Bombay on Income-tax matters and that the Chairman cannot be held personally responsible for the lapses.

7. Mr. Khanna handed over the letter to Mr. Sunderram Shetty personally who flew back to New Delhi and handed over it to the department.

8. Banking department wrote a letter to Reserve Bank saying that they have no objection in the letter giving extension to Sunderram Shetty.

9. Department of Banking, (operations and development) Reserve Bank prepared an office note under the signature of Joint Chief Officers, U.K. Sarma & A. K. Bucher recommending extension of the term of Mr. Sunderram Shetty with certain conditions.

10. When Mr. Luther refused to sign the conditional extension of term to Mr. Sunderram Shetty, the Reserve Bank was forced to convey the conditions through telex.

11. The Reserve Bank has kept silent in spite of the fact that Mr. Shetty has flouted Reserve Bank directives.

Mr. CHAIRMAN : You are to make only a short statement. You have already taken 13 minutes.

SHRI K. LAKKAPPA : Why did not the Reserve Bank of India take action on the Inspection Report submitted in July 1976 ? The report had specifically stated that the Chairman is not fit person to hold office in view of his substantial responsibility for the irregularities and that Chairman had acted against the interests of the State and disregarded the advice and directions issued by the Reserse Bank of India and had caused loss to the Bank. Can the same R.B.I. recommend to the Government of India further continuance of the Chairman's term overlooking the inspection report and serious charges against the Chairman framed by Income Tax Department in connection with fictitious deposits held by the Vijaya Bank amounting to nearly

[Shri K. Lakkappa]

Rs. 3·0 crores? How can the Government approve of the R.B.I. recommendations for continuance of the Chairman's term when they know fully that the Inspection Report and the Income-tax Department cases against the Chairman are of a serious nature warranting Chairman's discontinuance? The hon. Finance Minister had said the other day that these were all of technical nature. Now I would like to refer to Income-tax Act of 1961.

Under Sec. 131 of the Income-tax Act 1961, the Income-tax Officer summoned the Accused No. 1 Bank to produce fixed deposit registers and interest payment receipts in respect of the said 17 depositors who had fixed deposit account in various branches of the accused No. 1 Bank. A number of persons have been involved and the cases in accordance with the Income-tax Rules and also Criminal Procedure Code have been pending against them. How can you come to the conclusion that these are all of technical nature? The moment you say that these are of technical nature, the whole country will be swindled by banks in which so many people have deposited their hard-earned money. If your attitude is like this, soft-pedalling this issue of atrocities and squandering of public money, other banks will start doing the same. Then all sorts of fixing norms, rules and regulations will mean nothing. Banks and financial institutions should reflect the aspirations of the people of the country. Banks should have the clear confidence of the country. Banks should also come to the help of the poor. Today huge amounts of money are being given by loans and advances to be squandered and the whole thing has been swindled. The rule is that after Rs. 60 crores there should be nationalisation. I do not know whether you believe in the philosophy of nationalisation. I should like to know whether recently the Reserve Bank has sent a circular note to the ministry that he had bypassed the conditions laid down. Sixteen officers had been unceremoniously removed. There is a condition. It should be referred to an independent body. Action should be taken. He has bypassed certain conditions laid down. Recently, two weeks back the Reserve Bank of India again gave a note. What action has the finance ministry taken? Will you kindly produce the first report, the second report and all the relevant records pertaining to the enquiry and place them on the Table. One man was killed, two men were killed. You enquire. Millions of people will be killed when public money is squandered. For nothing you appoint a commission of enquiry and give jobs to retired judges. Will you kindly have a high level judicial enquiry against those activities. Will you prove that you are not hand in glove with that or that you are not minimising the importance of the subject? Will you deal with the matter and set right the things that have gone wrong in the institution and save the depositors in the interest of the nation and in the interest of the finances of the people of this country.

MR. CHAIRMAN: Shri Unnikrishnan. Only a question.

SHRI VAYALAR RAVI: We wanted a discussion; no-day-yet-named motion is there but there is no time. 21 members gave notice.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I shall follow the convention in this House, I shall say something by way of an introduction. It is a very important issue and Mr. Lakkappa has covered most of the ground. It has been exposed before in this House also, by the administrative actions taken by the Finance Ministry under various Acts, for violations of Law, not excluding the Income-tax Act, and various other Acts. In particular the chairman has been carrying on criminal and malafide actions pertaining to the management of Vijaya Bank. I am not concerned with the past very much as with the present, particularly the role of the finance ministry and the Reserve Bank and also unfortunately the Finance Minister. While replying to the Starred Question No. 191 of Mr. Vayalar Ravi on 24th June, 1977 and when I pinpointed him he said that he had been given extension very recently during this government's period but it was not extension by government, a year's extension was given by the Reserve Bank. He tried to soft pedal the issue. That is the gravaman of the charge that I want to make. There was a Reserve Bank of India inspection report under section 36 of the Banking regulation Act of 1949. The whole government, the previous government also, and the present Janata government, what have they been doing? What is the Finance Ministry doing, Was it brought to the notice of the Ministry? The Finance Minister had a telephonic conversation with the Reserve Bank Governor. Could he deny this that he had not talked to the Reserve Bank Governor on this point? There was a telex message from the Chief Officer of the DBOD, Reserve Bank Bombay to the Chairman of Vijaya Bank: It said,

"you will be given extension provided you satisfy these conditions." That is dated 25-5-77. Two months have passed. A month has passed since the question came up here. Would the Finance Minister tell the House whether he has guaranteed the interests of depositors and the public at large by not insisting on the implementation of these conditions? Has it been implemented to this day? Was it implemented after the telex message was sent? What were his departments and the Reserve Bank doing? Who is hiding what? I want to know, after that telex message and after the repeated reminders, who has forced the Finance Minister's hands to keep silent? After this was raised in this House on 24th June, did he take action? Has it been implemented? Has action been taken against a criminal against whom charges are pending in income-tax cases and enforcement cases? His passport was withdrawn, but I do not know how he got it back. Perhaps Dr. Subramaniam Swamy might be able to tell us. We are not here to shield any one, whether it is Sanjay Gandhi or any Gandhi on this side or that side. Whoever is guilty, he must be brought to book. I thought that was your principle. If that is so, why did he remain silent? What is the Finance Ministry doing? What is the Reserve Bank doing? I want a categorical answer. There was a letter on the question of the Chairman's extension sent from the Finance Ministry (Banking Department) to the Reserve Bank. What is the Reserve Bank's reply? The Minister was a distinguished civilian and he knows that under section 10(AAA) of the Banking Regulations Act, 1949, you can remove any Chairman of any bank. Through the Banking Regulations Act, as amended, this Parliament has given enough powers to the Reserve Bank and to the Finance Ministry. He cannot run away saying, "The Reserve Bank has done it. I do not know any thing." That is what he tried to say on 24th June. I want a categorical answer to my question as to whether he was consulted and if so, what did he tell the Reserve Bank Governor? What does he propose to do? Is it true that these conditions have not been implemented to this day?

SHRI KONDAJI BASAPPA (Davangere) : This bank was started in 1931. In 1962, when the present incumbent took over as Chairman, there were hardly 21 branches with 176 employees and with a deposit of Rs. 1·81 crores. After he took over, in the course of seven years, the number of branches multiplied to 114, with 1160 employees and with fixed deposits of over Rs. 18 crores. Later, when he was appointed permanent executive head and permanent Chairman, it multiplied to 446 branches with 7500 employees and with a deposit of Rs. 221 crores. Under his dynamic functioning and guidance, the bank has grown from practically nothing into such a big bank. It is well-known throughout the country and outside also. It has also got an international division for dealing with affairs of foreign exchange. They have also established a training college. All these developments have been made by this bank. It is one of the best banks. Therefore, I feel that its functioning is all right.

MR. CHAIRMAN : Now Mr. Badri Narayan. Only 1 or 2 minutes please.

SHRI A. R. BADRI NARAYAN (Shimoga) : Mr. Chairman, Sir, I am aware of the functioning of this bank, because I happen to come from a district adjacent to the place from where this bank was started. It has been doing excellently well. It was started from scratch; and according to the reply given by the hon. Finance Minister, government are not aware of any case of corruption, excepting an income-tax case. We do not know the details of the income-tax case. It is a matter for the Court to find out whether offences have been committed, or not. It is a matter for examination. Regarding the complaint of the 16 officials, the Finance Minister has been pleased to say that an outsider acceptable to the Reserve Bank has been appointed. I think we have to wait for the results of the enquiry proposed to be conducted. Mr. Lakkappa has said so many things and made grave charges, and they have been corroborated by Mr. Unnikrishnan.

SHRI K. LAKKAPPA : The documents are there. (*Interruptions*)

SHRI A. R. BADRI NARAYAN : If the facts are as stated by Mr. Lakkappa and Mr. Unnikrishnan, it is a matter for detailed enquiry. But no allegations should be made, that cannot be substantiated.

I belong to an adjacent district. I know how this bank started from scratch. Having known the working of the bank, I would say that we should not go merely by such serious allegations made against it. (*Interruptions*) Let the Finance Minister enquire into them.

MR. CHAIRMAN : You should put only a specific question. You are not doing it.

SHRI A. R. BADRI NARAYAN : In view of the grave allegations made by Mr. Lakkappa and Mr. Unnikrishnan, will the hon. Finance Minister be pleased to have the matter enquired into in detail? If the Chairman of the bank could be observed on enquiry; he should have a chance. If he is found guilty dire action may be taken.

18 hrs.

SHRI A. K. KOTRASHETTI (Belgaum) : This discussion is regarding the funds of the Vijaya Bank There was an article in the *Blitz* on the 28th May 1977, making several allegations against the Vijaya Bank and its Chairman. In reply to that, on the 11th June, 1977, the Chairman of the Bank gave a rejoinder, and that led to specific questions here about those serious allegations.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhi Nagar) : Sir, on a point of order. I thought in a Half-an-Hour Discussion the member who is raising it will make a short speech and the other members who have given notice will ask brief and pointed questions so that the Minister will have adequate time to reply within that half an hour. Now you have stated that the House will adjourn at 5 minutes past 6. Then, where is the time for the Minister to answer? So, the whole purpose is defeated. Therefore, please give a ruling that the time is extended so that the Minister can give an adequate reply.

MR. CHAIRMAN : I have followed the point raised by Prof. Mavalankar. If the House agrees, the time can be extended till the reply of the Minister is over. I would request the Member to put the question.

SHRI A. K. KOTRASHETTI : Both on the 24th June 1977 and today certain allegations were made against the Bank and its Chairman. I want to know from the Finance Minister whether the allegations made in this House today and on the 24th June have been covered by the Inspection Report of the Reserve Bank, whether the Inspection Report is accessible to outsiders, if not how it has been leaked out and whether any action will be taken against those who have leaked it out.

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : Mr. Chairman, Sir, the statements that have been made by Shri Lakkappa and subsequently expanded by Shri Unnikrishnan contain a number of sweeping charges against the Chairman of the Vijaya Bank. Shri Unnikrishnan has gone further to say that I myself personally has somehow tried to shield him. Let me, first of all, assure this House that I have not any interest in shielding anybody. That is the first point I want to make.

Secondly, I think the misunderstanding has arisen because of my remark when I answered the question in the House that the offence was of a technical nature. I would like to remind the hon. Member in what context I had used the word "technical." The questioner had said that he was involved in a heinous crime. I pointed out that these offences related to cases against him in respect of failure to declare interest exceeding Rs. 400 in regard to various accounts. This is undoubtedly a matter which every bank is supposed to report in regard to anybody who has a deposit account.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : These were fictitious deposits and interest was paid on them.

SHRI H. M. PATEL : The hon. Member has far more information than I have. The Chairman of a Bank does not look to this crediting and sending intimation from branch offices. These were all, if you remember, from branch offices. I would say nothing more than that.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Will you give me one second?

SOME HON. MEMBERS : No, no.

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : He is misleading the House.

MR. CHAIRMAN : I will not allow. Order, order.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : He cannot mislead the House.

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record... Since the hon. Minister has yielded, will you kindly be brief?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : When I said he has shielded, I did not mean that he was colluding.

He just now said that the Chairman may not know some of these things. That is precisely what he said. In C.C 1334 of 1977 in the Court of the Chief Judicial Magistrate of Mangalore, the plaint filed by his department says :

"These omissions on the part of Accused Nos. 4 and 5 were also made under the instructions and guidance of Accused No. 2 (the Chairman)."

That is the crux of the problem. Fictitious deposits were collected. Interest was not paid by the Branch Managers in the branches. But interest was paid directly by the Chairman from the central office. That is the point.

SHRI H. M. PATEL : I was concerned at that time only with what I said in the reply that these were the charges. I had not seen this complaint to which you are referring.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : You must be fully posted with the facts. Otherwise, you are keeping us in the dark. Indeed, if the Minister does not have full facts and comes before the House, we are kept in the dark.

SHRI H. M. PATEL : There was no question of my not having to be prepared for this. I do not accept that I was not prepared. I was fully prepared.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Here is an evidence which was quoted.

SHRI H. M. PATEL : Will you please look up the question ? What was the question to which I was giving reply ? If you see those questions you will find that this is the complete answer. And that is why, I used the expression 'technical'

Mr. Lakkappa referred to the fact that there are foreign accounts. There is nothing at all to show or prove that these foreign accounts exist. Whatever may be the source of information of Mr. Lakkappa, let him hand over the papers to me. I will certainly inquire into it. The whole question proceeded from a report which was published in the Blitz. You may have other source of information. (*Interruptions*) I want to know which the facts are. He referred to the inspection report. The inspection report did not say....

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It says that he is an unfit person. (*Interruptions*)

SHRI H. M. PATEL : Inspection report does not make any such statement. Inspection report is not intended to make such a statement.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Why ?

SHRI H. M. PATEL : Of course, not.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Recommendatory notes accompanying inspection notes. It is an appendage and part of the main report.

SHRI H. M. PATEL : So, it is a different matter. (*Interruptions*).

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Place all the papers that were submitted by the Inspector. (*Interruptions*).

SHRI H. M. PATEL : Mr. Chairman, they do not let me answer in my own way. I have said in the beginning that I have no intention to keep back the facts. But I must also be accurate. If they choose not to be accurate, you would also say that I must accept the position. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Please let me reply.

SHRI H.M. PATEL: I am explaining and I am clarifying my own position as to in what circumstances, in what context, I said that it looked to me that those offences were technical. (*Interruptions*) The various points that have been made, the various information which I now possess, regarding the Vijaya Bank, does convince me and does satisfy me that it is necessary to go into all the facts relating to the Vijaya Bank. This is what I propose to do. I will be glad if you let me have any special information that you may have in your possession.

18·16 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha :

'In accordance with the provisions of sub-rule (6) of Rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance (No. 2) Bill, 1977, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th July, 1977, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations on the 19th July, 1977, and to state that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th July, 1977, recommended that the following amendments be made in the said Bill :—

Clause 3

1. That at page 5, clause 3 be *omitted*

Clause 13

2. That at pages 10-11, clause 13 be *omitted.*

Clause 15

3. That at page 12, *after* line 29, the following be *inserted*, namely :—

"(*iii*) the amalgamated company absorbs in full the staff and labour borne on the rolls of the amalgamating company at the time of amalgamation."

Clause 20

4. That at page 16, clause 20 be *omitted*.

Clause 21

5. That at pages 16-17, clause 21 be *omitted*.

THE THIRD SCHEDULE

6. That at page 45,—

(*i*) line 15, the brackets figures and letters "(3) (i), (3) (ii)" be *omitted*; and

(*ii*) lines 17-19, the words "Four rupees and sixty paise per thousand", "One rupee and sixty paise per thousand" be *omitted*.

FINANCE (No. 2) BILL, 1977

As Returned By Rajya Sabha

SECRETARY : Sir, I lay on the Table the Finance (No. 2) Bill, 1977 which has been returned by Rajya Sabha with amendments as recommended by that House.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18·17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 29, 1977/Sravana 7, 1899 (Saka).

GMGIPND—L—1819 L.S.—998·